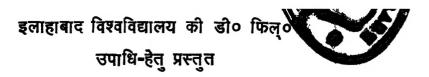
DEVELOPMENT PLANNING OF A BACKWARD ECONOMY A CASE STUDY OF PHULPUR TAHSIL, DISTRICT AZAMGARH (U. P.)

पिछड़ी अर्थ व्यवस्था का विकास नियोजन फूलपुर तहसील, जनपद आजमगढ़ (उ०प्र०) का विशेष अध्ययन





शोध-प्रबन्ध

निर्देशक:

डॉ॰ आर॰ एन॰ सिंह एम॰ए॰, डो॰फिल॰

प्रस्तुतकर्ताः रामकेश यादव एम० ए०

भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1992

सन्तुलित प्रादेशिक विकास की अवधारणा भारत जैसे वृहद् विकासक्षील राष्ट्र की आर्थिक आत्मिनिभैरता एवं स्वतंत्रता, राजनीतिक एकता एवं स्थिरता तथा सामा-जिक न्याय एवं तमता के लिए एक अपरिहार्य शर्त है। भौतिक एवं तां हकृतिक विषम-ताओं के इस देश में मात्र कुछ केन्द्रीय या राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र का एक साथ विकास सम्भव नहीं। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में बहुस्तरीय विकास-नियोजन की शुरूआत हुई । सुदूर ग्रामीण अंचलों में कृष्णि एवं दूसरे संसाधनों के सम्यक् विकास के द्वारा उत्पादकता बढ़ाकर लोगों की आय में वृद्धि करना, लोगों को रोजगार के नये अवसर प्रदान करना, परिवहन, स्वास्थ्य एवं विक्षा आदि सुविधाओं एवं सेवाओं में वृद्धि करके उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाना और अन्तू में क्षेत्र और उनके निवासियों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोडना आदि इसका प्रमुख लक्ष्य था । आगे चलकर समन्वित विकास की संकल्पना अर्थना स्त्रियों, नियोजकों, भूगोल विदों एवं अन्य तमाजविज्ञानियों के द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष की अर्थेट्यवस्था, के विभिन्न पहलुओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के समन्वित विकास की प्रभावी रणनीति स्वीकार की जाने लगी । प्रस्तुत अध्ययन इसी दिशा में किया गया एक विनम् प्रयास है।

अध्ययन के लिए चयनित प्रदेश - पूलपुर तहसील पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपद आजमगढ़ का एक भू-भाग है। यह एक अविकसित क्षेत्र है जहाँ की अर्थंट्यवस्था मूलत: कृष्ठि पर आधारित है, जनसंख्या का दबाव काफी अधिक है और द्वितीयक क्रियाएँ पूर्णत्या अविकसित अवस्था में हैं। प्रिक्षा एवं स्वास्थ्य - दोनों का ही स्तर काफी नीचे है। परिणामस्वरूप, यह प्रदेश विभिन्न प्रकार की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से आक्रान्त है। ऐसे प्रदेश के सन्तुलित विकास के लिये आधार स्तर पर

सद्यन विकास-नियोजन की आवश्यकता है। शोधकर्ता क्षेत्र की समस्याओं, सम्भाव-नाओं, आवश्यकताओं एवं सीमाओं से व्यक्तिगत रूप से परिचित है। इसने अध्ययन के लिए उक्त प्रदेश के चयन को अपेक्षाकृत् सरल बना दिया।

ग्रामीण मैदानी अंचल होने के कारण प्रस्तुत अध्ययन में क्षेत्र के कृष्टि-विकास को प्राथमिकता अवश्य दी गयी है, परन्तु साथ ही प्रादेशिक विकास के दूसरे सभी घटकों जैसे उद्योग, यातायात स्वं संचार, शिक्षा स्वं स्वास्थ्य आदि के सिम्मिलित स्वं समन्वित विकास पर बल दिया गया है। तहसील के विकास-नियोजन की सम्पूर्ण रूप-रेखा 'विकास-केन्द्र' सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गयी है। पलस्वरूप क्षेत्र में सेवा/विकास कार्यों स्वं उनके केन्द्रों के निधारण, केन्द्रीयता मापन, उनके पद-सोपान स्वं उनके द्वारा सेवित प्रदेश स्वं जनसंख्या का पूरा विश्लेष्ठण करने के पश्चात् क्षेत्र के विकास के लिए नये कार्यों स्वं केन्द्रों की संस्तुति की गयी है।

वर्तमान अध्ययन तैद्धान्तिक पक्षों को छोड़कर मुख्यतः क्षेत्रीय सर्वेक्षण, कार्यान-यीय अभिनेखों, ट्यिक्तिगत ज्ञान एवं सूचनाओं से प्राप्त तथ्यों एवं उनके विश्लेषण पर आधारित है। लघुहतरीय अध्ययन-क्षेत्र के लिये प्राथमिक किहम के आकड़ों का संग्रह आवश्यक हो जाता है। अध्ययन-प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित इस तरह के सभी आकड़े आजमगढ जनपद के विभिन्न विभागीय कार्यालयों से ट्यिक्तिगत हतर पर प्राप्त किये गये। जनसंख्या और उनकी कार्यात्मक संख्वना सम्बन्धी आँ कड़े आजमगढ जनपद की जनगणना हहतपुहितका, 1981 पर आधारित है। इन दोनों ही प्रकार के आँ कड़ों के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण एवं संश्लेषण में किसी तरह की विसंगति आने पर तथ्यों एवं परिणामों के सत्यापन हेतु ट्यिक्तगत सर्वेक्षण एवं साक्षा- सभी श्रेणी की सूचनाओं और समंकों को क्रमबद्ध ढंग से ट्यवस्थित करके सारणी-बद्ध किया गया । उनकी सम्यक ट्याख्या और उनसे प्राप्त होने वाले निष्कां के लिए विभिन्न प्रकार के मानचित्रों एवं आरेखों का निर्माण किया गया । कुछ आवश्यक स्थलों पर मात्रात्मक विधियों समीकरणों का भी प्रयोग हुआ है ।

सम्पूर्ण शोध-प्रबन्ध को विष्यानुसार कुन सात अध्यायों में संगठित किया गया अध्याय एक में विकास एवं नियोजन की मौलिक संकल्पनाओं के विवेचन-विश्लेषण के साथ भारत में नियोजन की पूठठभूमि एवं स्वरूप की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी द्वितीय अध्याय अध्ययन-प्रदेश की भौगोलिक संरचना - भौतिक एवं मानवीय की व्याख्या से सम्बन्धित है जो वस्तुतः प्रादेशिक विकास-नियोजन के लिए आधार-पटल तैयार करता है। अध्याय तीन में विकास के लिए चयनित/प्रयुक्त रणनीति के अनुसार प्रदेश में बह्तियों के हथानिक-कार्यात्मक संगठन का सम्यक् विश्लेषण कियो गया है। क्षेत्र में सेवा एवं विकास केन्द्रों का स्वरूप निर्धारण, उनकी स्थानिक रिक्तता की पहचान और तदनुसार नये सेवाकायों एवं केन्द्रों का सुझाव इस अध्याय के मुख्य विवेच्य विषय अध्याय चार में कृष्ण के वर्तमान प्रतिरूप का सम्यक् आकलन कर उसके भावी विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। पाँचवें अध्याय में क्षेत्र के तथा कथित उद्योगों के विश्लेषण के उपरान्त उसके औद्योगीकरण हेतु संसाधन एवं माँग के अनुरूप कुछ औद्योगिक इकाइयों एवं उनकी सम्भावित स्थितियों की विवेचना की गयी है। अध्याय छ: में प्रदेश की वर्तमान परिवहन एवं संचार व्यवस्था का विवेचन एवं भविष्य में उनके विकास के स्वरूप निर्धारण का प्रयास किया गया है। अन्तिम अध्याय में विक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुविधाओं एवं सेवाओं की वर्तमान दशा का विश्लेष्ठण कर क्षेत्र की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उनका विकास-नियोजन प्रस्तुत किया गया

है। अध्ययन-प्रदेश के सभी प्रखण्डों के समाकलित विकास-नियोजन में प्रस्तावित एवं संस्तृत लक्ष्यों को शताब्दी के अन्त सन् 2001 तक मूर्तरूप देने का सुझाव है।

मानचित्रों, आरेखों तथा सारणियों की सूची शोध-प्रबन्ध के प्रारम्भ में ही दे दी गयी है। यथास्थान उल्लिखित सन्दर्भों को प्रत्येक अध्याय के अन्त में संख्या, क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। ग्रन्थ के अन्त में कुछ आवश्यक परिशिष्ट भी दी गयी हैं।

शोध विष्ठाय के चयन से लेकर शोध-कार्य की समाप्ति तक विभिन्न चरणों में समय समय पर प्राप्त व्यक्तिगत एवं संस्थागत दिशा-निर्देश, पराम्ही एवं सहयोग के लिए आभार प्रदर्शित करना मैं अपना पुनीत कर्ताव्य समझता हूँ। सर्वप्रथम, मैं अपने गुर-प्रवर डाँ० आर०एन० सिंह, भूगोल विभाग के प्रति हार्दिक कृतझता ज्ञापित करता हूँ जिनके कुशल निर्देशन में मुझे शोध करने और उसे अन्तितम रूप देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपके अनवरत् प्रोत्साहन, विद्वत्तापूर्ण सुझावों तथा पाण्डुलिपि के आद्योपान्त अवलोकन के परिणामस्वरूप ही प्रस्तुत शोध-कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका है। मैं प्रोपेसर आर०एन० तिवारी, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूगोल विभाग एवं डाँ० सविन्द्र सिंह, अध्यक्ष, भूगोल विभाग का विशेष्ठरूप से आभारी हूँ जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर बहुमूल्य सुझाव एवं सहायता देकर मेरा उत्साहवर्द्धन किया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के केन्द्रीय पुस्तकालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने शोध-सम्बन्धी साहित्य उपलब्ध कराने में मेरी काफी सहायता की है। मैं आजमगढ़ जनपद एवं निचले स्तर के विभिन्न कार्यालयों, सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों एप

क्षेत्र के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों के प्रति भी अपना आभार च्यक्त करता हूँ जिनसे इस कार्य के सम्पादन में प्रत्यक्षा एवं परोक्षा रूप से सहायता प्राप्त हुई है। शोध-कार्य में विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक मदद के लिए मैं डाँ० राजमणि त्रिपाठी, शोध सहायक, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद, कु० रंजना दास, कु० पूनम श्रीवास्तव, श्री रमाशंकर मौर्य एवं श्री अशोक कुमार सिंह, शोध-छात्रार एवं छात्र-भूगोल विभाग को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। परमपूज्य पिता श्री सुक्खू यादव के प्रति किसी तरह का कृतज्ञता ज्ञापन मात्र औपचारिकता होगी जिनकी सत्तव प्रेरणा ने ही मुझे इस कार्य-योग्य बनाया।

अन्त में, मैं श्री रामबरन यादव को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने पूरी लगन और सावधानीपूर्वक अत्यन्त सी मित समय में शोध-कार्य की समग्र पाण्डुलिपि के टंकण का सराहनीय कार्य किया है।

विजयदशमी अक्टूबर 6, 1992 रामकेश यादन

विषय-अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
अ ा मुख		i- v
तारणी-सूची		xii-xiii
मानचित्रों एवं	अररेखों की सूची	xiv
अध्याय एक :	विकास-नियोजन : सैद्धान्तिक विवेचन	1 - 39
	। । प्रस्तावना	
	l·2 विकास-अर्थ एवं संकल्पना	
	(1) विकास की प्रकृति सवं प्रक्रिया-भौगों लिंक सन्दर्भ (2) विकास के तथ्य सवं सूचक (3) विकास सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त 1.3 नियोजन की अवधारणा (1) नियोजन के प्रकार	
	(2) नियोजन का स्तर 1.4 भारत में विकास-नियोजन एवं उसका स्वरूप 1.5 पिछड़ी अर्थट्यवस्था एवं उसके निर्धारक कारक	
	1.6 भारत में विकास-नियोजन सम्बन्धी अध्ययन सन्दर्भ	
अध्याय दो :	पूलपुर तहसील की भौगोलिक पूष्ठभूमि	40 - 77
	2.। प्रस्तावना	
	2.2 स्थानिक कारक एवं प्रशासनिक संगठन	
	2.3 भौ तिक लक्ष्ण	
	(।) संरचना एवं उच्चावच	
	(२) अपवाह-तंत्र	

- 2.4 जनवायु एवं वनस्पतियां .
- 2.5 मिद्दी एवं खनिज
- 2. 6 जनसंख्या प्रतिरूप
 - (।) वृद्धि
 - (2) वितरण
 - (3) धनत्व
 - (4) संरचना

(लिंग अनुपात, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, साक्षरता, नगरीय-ग्रामीण एवं व्यावसायिक संरचना)

2.7 बहती-प्रतिरूप (आकार-वर्ग, सद्यनता, अन्तरण) सन्दर्भ

अध्याय तीन : बस्तियों का स्थानिक-कार्यात्मक संगठन एवं नियोजन 78-126

- उ.। प्रस्तावना
- 3.2 विकास सेवा केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य
- 3.3 केन्द्रीय कायों का पदानुक्रम
- 3.4 विकास सेवा केन्द्रों का निर्धारण
- 3.5 विकास सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम
- 3.7 सेवा केन्द्रों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप
- 3.8 विकास केन्द्रों के सेवा-प्रदेशों का सीमांकन
- 3.9 प्रस्तावित विकास सेवा केन्द्र सन्दर्भ

पृष्ठ संख्या

अध्याय चार : कृषि एवं कृषि-विकास हेतु नियोजन

127-177

- 4.। प्रतावना
- 4.2 तामान्य भूमि-उपयोग
 - (।) शुद्ध बोया गया क्षेत्र
 - (2) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र
- 4.3 फ्तल प्रतिरूप
 - (।) विभिन्न वर्गीय पसलें
 - (क) खरीफ
 - (छ) रबी
 - (ग) जायद
 - (2) फ्तन प्रतिरूप में का निक परिवर्तन
- 4. 4 शस्य-संयोजन
 - (।) शस्य-को टि निर्धारण
 - (2) शस्य-संयोजन प्रदेश
 - (३) शहय-गहनता
- 4.5 वर्तमान कृषा और हरितक्रानित की भूमिका
- 4.6 कृषा-विकास नियोजन
 - (।) भूमि-उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार
 - (2) कृष्णि का ट्यवसायीकरण एवं गहनीकरण
 - (3) पशुपालन
 - (4) आधारभूत कृषि सुविधाओं की उपलब्धता
 - (क) सिंचाई
 - (ख) उर्वरक एवं उन्नितिशील बीजों का प्रयोग
 - (ग) कीट एवं खरपतवार नाशक दवार
 - (घ) नवीन कृषि यन्त्र

- (ड) फ्तल-बीमा योजना
- (च) कृष्णि एवं पशुपालन सेवा केन्द्रों का स्थानिक नियोजन

सन्दर्भ

अध्याय पाँच : औद्योगिक संरचना एवं विकास-नियोजन

178-210

- 5.। प्रस्तावना
- 5.2 क्षेत्रीय औद्योगिक संरचना
- 5.3 लघू स्तरीय इकाइयाँ
- 5. 4 औद्योगिक संभाट्यता
- 5.5 औद्योगिक नियोजन एवं प्रस्ता वित उद्योग
 - (।) संताधन-आधारित उद्योग
 - (2) माँग-आधारित उद्योग (कृषि औजार उद्योग, कृषि रक्षा रसायन उद्योग, एल्यूमी नियम उद्योग, बिजली के उपकरण सम्बन्धी उद्योग, साबुन तथा कागज उद्योग? आदि)

सन्दर्भ

अध्याय छ: : परिवहन एवं संचार-व्यवस्था

211-248

- 6-। प्रस्तावना
- 6.2 परिवहन के माध्यम
 - (1) रेल मार्ग
 - (2) सड़क परिवहन

- 6.3 सडक धनत्व
- 6.4 सड़क अभिगम्यता
- 6.5 सङ्क सम्बद्धताः
- 6.6 यातायात प्रवाह
- 6.7 परिवहन नियोजन एवं प्रस्तावित मार्ग
- 6.8 संचार च्यवस्था
 - (।) ट्यक्तिगत संवार
 - (2) जनसंचार
- 6.9 तंचार नियोजन सन्दर्भ

अध्याय सात : प्रमुख सामाजिक सेवार एवं उनका नियोजन

249 - 287

- 7.। प्रस्तावना
- 7.2 विक्षा
- 7.3 साक्षरता
- 7.4 औपचारिक विद्वा का स्वरूप
- 7.5 अनौपचारिक विक्षा
- 7.6 वर्तमान विशा की समस्याएँ
- 7.7 विद्यालयों का शैक्षाणिक एवं स्थानिक स्तर
- 7.8 शैक्षाणिक नियोजन
 - (।) जनसंख्या प्रदेषण एवं छात्रों की भावी संख्या
 - (2) विद्यालय स्तर के अनुसार नियोजन
- 7.9 स्वास्थ्य सेवाएँ

पूष्ठ संख्या

- 7. 10 स्वास्थ्य सुविधाओं का वर्तमान स्वरूप
- 7.11 स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ
- 7.12 चिकित्सा सुविधाओं का सामान्य मापदण्ड
- 7.13 स्वास्थ्य सेवाओं का नियोजन
- 7.14 जनसंख्या नियन्त्रण सन्दर्भ

परिश्रिष्ठट

i - xi

सारणी सूची

- 2.। पूलपुर तहसील का प्रशासनिक संगठन
- 2.2 पूनपुर तहसील में जनसंख्या-वृद्धि
- 2.3 विभिन्न प्रकार के जनसंख्या धनत्वों की तुलना
- 2.4 जनसंख्या की संशिलाद संरचना
- 2.5 जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना
- 2.6 पूनपुर तहसील में ग्राम-आकार वर्ग
- 2. 7 गाँवों की सघनता एवं अन्तरण
- उ.। केन्द्रीय विकास कार्य
- 3.2 केन्द्रीय कार्य एवं कार्याधार जनसंख्या सूचकांक
- 3.3 केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम
- 3.4 पूलपुर तहसील में निर्धारित सेवा केन्द्र
- 3.5 केन्द्रीय कार्यों का तूलनात्मक मान
- 3.6 सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक
- 3.7 सेवा केन्द्रों का पदानुक्रमीय स्तर
- 3.8 सेवा केन्द्रों से निकटतम पडोसी सेवा केन्द्र की दूरी
- 3.9 प्रस्तावित सेवा केन्द्र
- 4.। पूनपुर तहसील में सामान्य भूमि उपयोग, 1990-9।
- 4-2 खरीफ के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का विवरण, 1990-91
- 4.3 रबी की पसलों का प्रतिरूप, 1990-91
- 4.4 पसल प्रतिरूप में कालिक परिवर्तन

- 4.5 शस्य को दि, 1990-91
- 4.6 तहसील में उर्वरकों का विवरण, 1988-89.
- 4·7 विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित **क्षे**त्र
- 4.8 जोतों की संख्या एवं आकार
- 4.9 प्रस्ता वित पसल-चक्र
- 5.। पूलपुर तहसील की औद्योगिक संरचना
- 5.2 पंजीकृत नघु उद्योग
- 6.। पूनपुर तहसील में सडकों की लम्बाई, 1989.
- 6.2 प्रमुखं सम्पर्क मार्ग
- 6.3 न्याय पंचायत स्तर पर सडकों का धनत्व
- 6.4 नागपुर और बम्बई योजना द्वारा निर्धारित सड़क अभिगम्यता मानदण्ड
- 6.5 पक्की सड़क अभिगम्यता, 1989.
- 6.6 महत्त्वपूर्ण सेवा केन्द्रों से पक्की सड़कों की सम्बद्धता मैद्रिक्स
- 6.7 प्रस्ता वित पक्की सडकें
- 6.8 प्रस्तावित खडंजा मार्ग
- . 6.9 तहसील में उपलब्धता ट्यक्तिगत संचार सेवार, 1989.
 - 7.। पूलपुर तहसील में साक्षारता का प्रतिशत
 - 7.2 विदालयों की वर्तमान रूपरेखा, 1987-88.
 - 7.3 तहसील के लिए रैक्ष्णिक मापदण्ड
 - 7.4 फूलपुर तहसील में वर्ष 2001 में संभावित जनसंख्या
 - 7.5 विद्यालयों की भावी रूपरेखा, वर्ष 2001.

मान चित्रों एवं आरे हो। की सूची

(LIST OF MAPS AND DIAGRAMS)

- 1.1 Demensions of Integrated Development-Model
- 2.1 Phulpur Tahsil Administrative Sub-Divisions
- 2.2 Population Growth, 1961-2001
- 2.3 Distribution of Population, 1981
- 2.4 Density of Population, 1981
- 2.5 Size-Distribution of Settlements
- 3.1 Phulpur Tahsil-Hierarchy of Service Centres
- 3.2 Ranking of Service Centres
- 3.3 Growth Centres and their Regions
- 3.4 Proposed Growth Centres
- 4.1 Phulpur Tahsil General Land Use, 1990-91
- 4.2 Cropping Pattern, 1990-91
- 4.3 Crop-Combination Regions, 1990-91
- 4.4 Spatial Pattern of Banking Facilities
- 5.1 Phulpur Tahsil Proportion of Household Industrial Workers to Total Main Workers, 1981.
- 5.2 Distribution of Small-Scale Units, 1990-91
- 5.3 Proposed Industries with their Location
- 6.1 Phulpur Tahsil Transport Network
- 6.2 Road Density Per Hundred Km2
- 6.3 Road Density Per Lakh Population
- 6.4 Frequency of Buses on Metalled Roads
- 6.5 Proposed Transports Network
- 7.1 Phulpur Tahsil Literacy Distribution, 1981
- 7.2 Educational Facilities, 1987-88
- 7.3 Proposed Educational Foci
- 7.4 Spatial Pattern of Medical Facilities

अध्याय एक

विकास नियोजन : सद्धान्तिकं विवेचन

। । प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों, भौतिक सांस्कृतिक विविष्टताओं एवं राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार अपने सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है किन्तु सभी प्रयासीं के बावजूद विशव के विभिन्न राष्ट्रों के विकास-स्तर में काफी असमानता पायी जाती है। एक और जहाँ कुछेक राष्ट्र पूर्णरूप से विकतित हैं, वहीं दूसरी और विशव के अधिकांश राष्ट्र विकास की इस दौड़ में काफी पिछड़े हुए हैं। विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों के मध्य असमानता का अन्तर इतना अधिक है कि यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जो राष्ट्रों या क्षेत्रों के असमान विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इन्हीं सन्दर्भों में विकास एवं नियोजित विकास की संकल्पना की प्रासंगिकता उभरकर सामने आने लगती है। क्षेत्रीय पिछ्डापन, ग्रामीण-नगरीय असंतुलन, सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में आय में विष्यमता, संसाधनों के वितरण एवं उपभोग में स्थानिक असंतुनन आदि सभी समस्याएँ सीधे विकास से सम्बन्धित हैं। विकास की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिमध ने इसे विश्व की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या माना है जिसका निराकरण प्रत्येक अविक-तित राष्ट्र, क्षेत्र, समाज व व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है। भारत जैसे विकास-शील राष्ट्र में क्षेत्रीय/स्थानिक असन्तुलन की स्थिति लम्बी ऐतिहासिक,सामाजिक एवं सारकृतिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं के कारण और भी अधिक जटिल है। क्षेत्रीय पिछड़ेपन के निराकरण-हेतु आवश्यक है कि उन विधिष्ट समस्याओं एवं गतिरोधों

की पहचान की जाय जो क्षेत्र के असंतुलित विकास के लिए उत्तरदायी हैं। प्रस्तुत
अध्याय में नियोजित विकास की संकल्पना का विश्लेषण इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में करने
का प्रयास किया गया है।

1.2 विकास-अर्थ एवं संकल्पना

किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या की निरन्तर गतिश्वील क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रतिबिम्ब होता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान वातावरण के साथ समायोजन, सुधार एवं परिवर्तन – ये तीन क्रियार लगभग साथ-साथ एक दूसरे को प्रभावित करती हुई चलती हैं और अपनी सम्पूर्णता में एक गतिमान चक्र का आभास देती हैं जो सदैव भूपटल पर परिवर्तन की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। किसी भी क्षेत्र का यह स्वरूप-परिवर्तन ही वस्तुतः विकास है।

भौगोलिक सन्दर्भ में विकास की अवधारणा काफी ट्यापक रूप ने नेती
है जिसके अन्तर्गत वे सभी तथ्य, जिनका केन्द्रबिन्दु आवश्यक रूप में मानव ही होता
है जैसे आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण तथा
सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण आदि समाहित किये जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव
के क्रिया-क्लापों का सकारात्मक एवं वांछित गति ही विकास का मूल या उत्स
है। ये क्रिया-क्लाप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विभिन्न रूपों
में द्यदित हो सकते हैं, परन्तु मनुष्य के समस्त क्रिया-क्लापों में आर्थिक क्रियार निश्चय ही सवांपरि हैं। वस्तुत: मनुष्य की आर्थिक क्रियार ही उसकी अन्य
कियाओं का स्वरूप निर्धारित करती हैं। यही कारण है कि विकास का तात्पर्य

तामान्य रूप से आर्थिक विकास से ही लगाया जाता है किन्तु भौगोलिक सन्दर्भ में विकास को आर्थिक प्रगति का पर्याय मात्र मान लेना एवं प्रति व्यक्ति उत्पादन या आय को ही इसका पैमाना समझना भामक है। इससे विकास-संकल्पना की व्यापकता प्रभावित होती है। वस्तुत: विकास एक बहु-आयामी संकल्पना है जो परिवर्तन के साथ-साथ प्रगति का भी वोतक है। आधुनिक सन्दर्भों में विकास के कई गुणात्मक पहलू होते हैं जिसे केवल कुल राष्ट्रीय उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि या प्रगति के साथ सामाजिक उन्नयन, समता, न्याय, स्वास्थ्य, विक्षा, प्रादेशिक संतुलन एवं कुल पर्यावरणीय प्रबन्धन सम्पूर्ण विकास के प्रमुख घटक हैं। यही कारण है कि आजकल नियोजक आर्थिक वृद्धि को महत्त्वपूर्ण मानते हुए भी अपना ध्यान विकास के सामाजिक एवं प्रादेशिक पहलुओं पर केन्द्रित करने लगे हैं।

विकास के प्रति इस नवीन दृष्टिकोण एवं नवीन चेतना ने विकास की अव-धारणा को वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक अति महत्त्वपूर्ण विषय बना दिया है। पिछले कई दशकों से विकास की संकल्पना विचारकों एवं नियोजकों के मध्य विचार एवं वाद-विवाद का विषय रही है। इस सन्दर्भ में महबूब उल-हक महोदय² के निम्न विचार का उल्लेख करना काफी युक्तिसंगत होगा -

"... the problem of development must be defined as a selective attack on the worst forms of poverty. Development goals must be defined in terms of progressive reduction and eventual elemination of malnutrition, disease, illiteracy,

care of our GNP because it would take care of poverty. Let us reverse this and take care of poverty because it will take care of the GNP. In other words, let us worry about the content of GNP even more than its rates of increase.

इसी सन्दर्भ में Dudley Seers दारा उठाये गये कुछ भूलभूत मुद्दे उल्लेखनीय हैं। किसी भी देश के विकास के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा जा सकता है, वह है - गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के उन्मूलन के लिए क्या हो रहा है ? अगर इन तीनों में एक सीमा तक कमी आयी है तो निश्चय ही सम्बद्ध देश विकास के दौर से गुजर रहा है और, अगर इन केन्द्रीय समस्याओं में से किसी एक या सभी की दशा में और गिरावट आयी है तो परिणाम को विकास की संज्ञा देना हास्यास्पद होगा भले ही प्रति व्यक्ति आय दुगुनी क्यों न हो गयी हो।

विश्व स्तर पर विकास की अनेक नवीन परिभाषार प्रस्तुत की गयी हैं एवं नये उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। विश्व अम संगठन (ILO 1976-1977) ने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को ही विकास का मुख्य उद्देश्य छोषित किया है। अत: यह स्पष्ट है कि विकास की संकल्पना एकांगी न हो कर समाकलित है। वास्तव में विकास एक सकारात्मक व्यवहारिक शब्द है जिसका अभिप्राय मानव जीवन के विविध पहलुओं में हुए गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों से है। इसके अन्तर्गत विक्षा स्वास्थ्य, प्रविक्षण, राजनी तिक जाग्रहकता, पूँजी निर्माण के साधन, पर्यावरणीय संरक्षण

अादि तभी को तमाहित किया गया है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इह्मप्रकाश एवं मुनीत रजा में ने विकास को कार्य अथ्वा कार्यों की एक श्रृंखना या प्रक्रम माना है जो मानव जीवन में शीद्य ही तामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय सुधार नाता है अथ्वा भविष्य में जीवन की तंभावना में वृद्धि करता है। इससे भी बढ़कर मानव और मानवीय मूल्यों से तम्बन्धित सभी तथ्यों को विकास के अन्तर्गत समाहित किया जा रहा है क्यों कि इनके अभाव में विकास के मून उद्देश्यों - आर्थिक समता, तामाजिक न्याय तथा पर्यावरण में गुणात्मक सुधार की प्राप्ति अकल्पनीय है। गलतुंग ने विकास की बिल्कुन ही नई व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके अनुसार विकास की संकल्पना तामाजिक विषयों का वह क्षेत्र है जिसमें भूतकान का अध्ययन इतिहास, वर्तमान का अध्ययन तमाजशास्त्र, अर्थसास्त्र एवं भूगोन आदि तथा भविष्य का अध्ययन भविष्यशास्त्र (Futurology), आदि विषयों के अन्तर्गत एक तथा किया जाता है।

मिश्रा, सुन्दरम एवं राव⁶ के अनुसार विकास समाज एवं अर्थट्यवस्था में मात्रात्मक विस्तार के अतिरिक्त उनमें वांछित गित से वांछित दिशा में संरचनात्मक परिवर्तन से सम्बद्ध है। मानव के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण से उसका गहरा सम्बन्ध है। विकास की अब तक की सबसे ट्यापक ट्याख्या माइकेल पी॰ टोडारो⁷ ने निम्न शब्दों में की है -

"Development must, therefore, be concieved as a multidimensional process involving major changes in social structures, popular attitudes and national institutions, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and the eradication of absolute poverty. Development, in its essence, must represent the entire gamut of change by which an entire 'Social' system, tuned to the diverse basic needs and desires of individuals and social groups within that system, moves away from a condition of life, widely percieved as unsatisfactory towards a situation or condition of life regarded as materially and spiritually better."

(।) विकास की प्रकृति एवं प्रक्रिया - भौगोलिक सन्दर्भ

जहाँ तक भौगोलिक संदर्भ में विकास की प्रकृति का प्रश्न है, यह पूर्णतावादी है जो विकास की प्रक्रिया को बहु-स्तरीय, बहु-विभागीय एवं बहु-वर्गीय स्वरूप प्रदान करता है। बहु-स्तरीय स्वरूप से अभिप्राय क्षेत्रीय पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों से है जैसे गाँव, विकासखण्ड, तहसील, जिला आदि। बहु-विभागीय से तात्पर्य अर्थट्यवस्था या सामाजिक उन्नयन के विभिन्न खण्डों या उपविभागों के विकास से है यथा कृष्टि, उद्योग, स्वास्थ्य, पिश्वा, परिवहन, संचार आदि। बहु-वर्गीय विकास का अभिप्राय समाज के विभिन्न वर्गों - गरीब, शोषित, पिछड़े वर्गों के आर्थिक-सामाजिक उन्नति से है। प्रस्तुत माडल (चित्र । ।) से विकास के इस बहु-आयामी प्रकृति पर एक सीमा तक प्रकाश पड़ता है।

विकास की प्रक्रिया अपनी सम्मूर्णता में अत्यधिक जटिल हो जाती है।

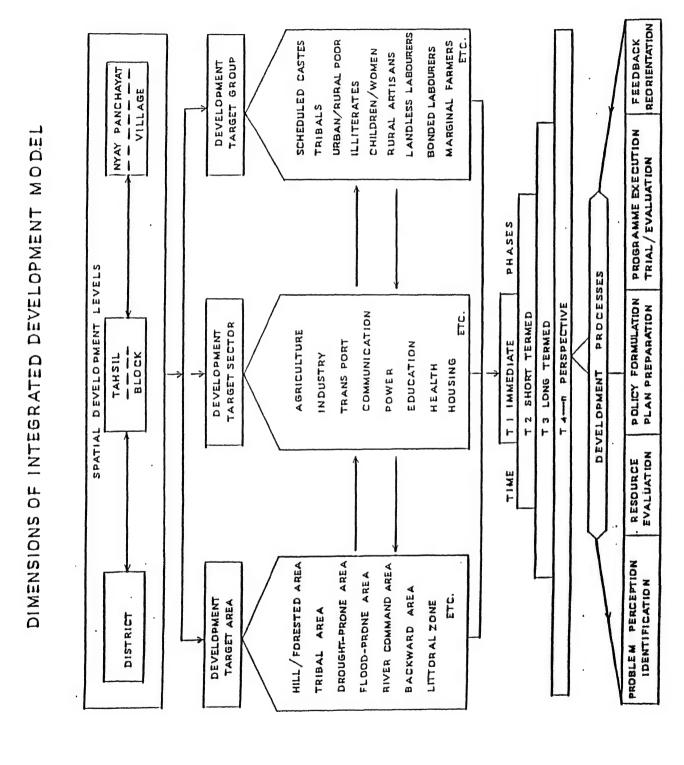


Fig.1-1

परनतु मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, चातुर्य, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों एवं सहयोगी प्रयासों के सहारे इसे सहज एवं स्वाभाविक बना सकता है। साथ ही नवीन तक-निकों को अपना कर इस प्रक्रिया को मानवीय संदर्भ में अधिक कल्याणकारी बना सकता है। विकास की प्रक्रिया कुछ विशेष्ठा तथ्यों पर आधारित एवं कुछ निश्चित शक्तियों द्वारा संचालित होती है, जो एक दूसरे से सम्बन्धित रहती हैं।

विकास की प्रक्रिया संकेन्द्रण और प्रकीर्णन दो विवरति स्वभाव वाली सहगामी स्थानिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित होती हैं। संकेन्द्रण की प्रवृत्ति केन्द्राभिमुखी शक्तियों द्वारा संयालित होती है जबकि प्रकीर्णन की प्रवृत्ति केन्द्रापसारित
शक्तियों की परिणाम होती हैं। यद्यपि दोनों प्रवृत्तियाँ विवरीत स्वभाव वाली
होती हैं किन्तु ट्यवहार में ये अलग-अलग न क्रियाशील हो कर एक साथ ही कार्य
करती हैं। किसी हेन्न विशेष्ठ की विकास-प्रक्रिया के अन्तर्गत मानवीय क्रियाओं का
स्थानिक प्रबन्धन इन दोनों ही शक्तियों की सापेक्षिक तीव्रता एवं संतुलन द्वारा
संयालित होता है। जिन हेन्नों में केन्द्राभिमुखी शक्तियाँ प्रकल रहती हैं वहाँ
क्रियाओं का संकेन्द्रण कुछ विशेष्ठ केन्द्रों में होने लगता है। प्लत: अपेक्षाकृत कुछ बड़े
नगरीय केन्द्रों का उद्भव होता है जो अविकसित हेन्न के लिए विकासकेन्द्र के रूप में
कार्य करते हैं। इसके विपरीत, जिस हेन्न में केन्द्रापसारी शक्तियाँ अधिक सक्रिय
रहती हैं वहाँ क्रियाओं का सकेन्द्रण सम्पूर्ण हेन्न में छोटे व मध्यम नगरीय केन्द्रों के
रूप में होता है जो सम्पूर्ण हेन्न के विकास का माध्यम बनते हैं।

सामान्यतः किसी क्षेत्र के समाकित विकास के लिए उपर्युक्त दोनों शक्तियों का साथ-साथ समान रूप से सक्रिय होना वांछित है किन्तु हर्धमैन⁸ जैसे विद्वानों ने

किसी पिछडी अर्थट्यवस्था के विकास के लिए केन्द्रीय संकेन्द्रण की प्रक्रिया को अधिक उचित माना है। वस्तुत: प्रक्रिया विशेष्ठ का युक्तिसंगत होना क्षेत्र के विकास-स्तर एवं अवस्था पर निर्भर करता है। यदि अर्थट्यवस्था नितान्त पिछड़ी है तो प्रारम्भ में एक सीमा तक केन्द्रित संकेन्द्रण की प्रक्रिया कार्य करती है लेकिन उसके बाद विकेन्द्रित संकेन्द्रण की प्रक्रिया अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। विकेन्द्रित संकेन्द्रण सम्यक् एवं संतुलित स्थानिक विकास की आवश्यक शर्त है।

(2) विकास के तथ्य एवं सूचक

विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ निश्चित तथ्य होते हैं जो क्षेत्र विशेष्ठ में विकास की दिशा, स्तर एवं स्वरूप को निर्धारित करते हैं। सामान्यतः आर्थिक-विकास को प्रभावित करने वाले तीन आधारभूत तथ्य हैं - प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं संस्थारें। परन्तु इन तथ्यों को समाकलित विकास जैसी जटिल प्रक्रिया का निर्धारक मान लेना विकास की संकल्पना का सरली-करण करना होगा। वस्तुतः विकास की त्यापक संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में विकास के स्तर एवं दिशा को निर्धारित करने वाले सूचकों को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। ये सूचक व्यक्ति, समाज, समय तथा स्थान के सन्दर्भ में भिन्न-भिन्न हे। सकते हैं। इस दिशा में कई एक विद्वानों द्वारा विभिन्न तथ्यों के प्रभाव के अनुसार विकास के स्तर को दर्शाने वाले सूचकों की विस्तृत सूची बनाने का प्रयास किया गया है। भव्यका ने ऐसे सूचकों का व्योरा दिया है जो व्यक्ति के सामाजिक एवं व्यक्तिगत कल्याण को समाहित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं रोजगार, संचार, निर्मित वस्तुओं का उपभोग, नगरीकरण, प्रति व्यक्ति आय आदि। संयुक्त

राष्ट्र संघ के विकास शोध संस्थान (UNRISD) ने अपनी सूची में 16 सूचकों को सिम्मिलित किया गया है जिसमें उपभो कता वस्तुओं को अपेक्षाकृत कम महत्त्व प्रदान किया गया है । Berry 1 ने 1960 में आर्थिक के विक्षलेडण में परिवहन, उर्ज़ा का उपभोग, कृष्टि उत्पाद, संचार, व्यापार, जनसंख्या तथा सक्न राष्ट्रीय उत्पाद को प्रमुख सूचकों के रूप में प्रयुक्त किया है । Adelman एवं Morris 2 ने कृत 41 सूचकों का प्रयोग किया है जिनमें कृष्ठ सामाजिक तथा राजनीतिक हितों से सम्बन्धित हैं । इसके विपरीत Harbinson, Maruhnic एवं Resnick 3 ने विकास के सूचकों के अपने चुनाव में मानव संसाधन विकास पर अधिक बन दिया है । निष्ठकर्ष रूप में कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र या राष्ट्र के विकास स्तर की विशेष्टकर सामाजिक एवं व्यक्तिगत कल्याण के संदर्भ में जितनी विश्वसनीय छवि विकास के इन कारकों द्वारा प्राप्त होती है, उतनी मात्र प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंक्डों द्वारा नहीं।

(3) विकास सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त

पिछले कई दशकों में समय-समय पर विभिन्न अर्थशा स्त्रियों, समाजशा स्त्रियों, भूगोल विदों तथा विकास नियोजकों द्वारा विकास से सम्बन्धित अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। प्रस्तुत विवरण में भौगो लिक दृष्टिद कोण से महत्त्वपूर्ण स्वं प्रादेशिक विकास के लिए प्रासंगिक कतियय सिद्धान्तों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है।

(क) मिरडल का 'संचयी कायों त्पादन प्रतिमान

मिरडल महोदय 4 ने सन् 1956 में विकास सम्बन्धी अपना 'संचयी कायों-त्पादन प्रतिमान' प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रादेशिक विभेदनशीलता आर्थिक विकास का स्वाभाविक प्रतिपल होती है। क्यों कि एक प्रदेश विना दूसरे को हानि पहुँचाये कभी भी विकास नहीं कर सकता है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में -

"If things were left to market forces unhampered by any policy interferences industrial production, commerce, banking, insurance, shipping and indeed almost all those economic activities which in a developing economy tend to give a bigger than average return and, in addition, science, art, literature, education and higher culture generally - would cluster in certain localities and regions leaving the rest of the country more or less in a backwater."

उनकी यह मान्यता है कि किसी स्थान पर एक बार किसी भी कारण से चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित या ऐतिहासिक, विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने पर कार्यों के संचयी प्रभाव, केन्द्राभिमुखी शक्ति एवं गुणक प्रभाव के कारण वह सतत् बढ़ती जाती है। फलतः निरन्तर बढ़ती हुई औद्योगिक इकाइयाँ दितीयक किस्म की औद्योगिक अवस्थापना को जन्म देती है और केन्द्रीय प्रदेश का निर्माण होने लगता है। सामाजिक इकाइयाँ इस प्रक्रिया को कुछ और प्रोत्साहन देती हैं जिससे स्वयंपोधी आर्थिक प्रगति होने लगती है। आस-पास के अपेक्षाकृत निर्धन प्रदेशों से संसाधनों का प्रवाह केन्द्रीय प्रदेश की और बढ़ने लगता है जिसे मिर-इल महोदय ने 'Back wash effect' कहा तथा इसके परिणामस्वरूप अभिवर्धित केन्द्रीय प्रदेश से फैलने वाले संभावित विकास को 'Spread effect' की संज्ञा दी जिसके माध्यम से अन्तत: सम्पूर्ण प्रदेश का विकास होता है।

इस प्रकार उन्होंने विकास की तीन स्थितियाँ बतायों। पहली स्थिति को प्रारम्भिक औद्योगिक स्थिति कहा जब प्रादेशिक विष्यमतार न्यूनतम होती हैं। दूसरी स्थिति में संचयी कारक सर्वाधिक प्रभावी होते हैं, परिणामस्वरूप प्रदेश विशेष्ठ अन्य प्रदेशों की तुलना में तीव्र गित से विकसित होता है एवं संसाधनों के वितरण में असंतुलन भी बढ़ने लगता है। तृतीय अवस्था में निस्तारण प्रभाव के कारण स्थानिक विष्यमतार कम होने लगती हैं।

यद्यपि मिरडल के इस मॉडल के गुणात्मक स्वरूप की तीव्र आलोचना की गयी एवं इसे अवास्तविक बताया गया तथापि विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों/ प्रदेशों के अन्तर को स्पष्ट करने में यह मॉडल काफी सक्षम है।

(छा) रोष्टोव का आर्थिक प्रगति की अवस्थाओं का सिद्धान्त

ध्राप्त Rostow ने सन् 1960 में अपने तिद्वानत 'The Stages of Economic Growth' का प्रतिपादन Kart Marx के आ थिंक तिद्वानत के

विकल्प के रूप में किया । इनका यह सिद्धान्त नवीन तकनीकों के सन्दर्भ में किसी प्रदेश में सामियक आर्थिक प्रगति का विश्लेषण करता है । उन्होंने किसी प्रदेश में पाँच कृत्रिम अवस्थाएँ बतायी हैं - । रूद्वादी समाज, २ उमर उठने की पूर्ण अवस्था, उ उमर उठने की अवस्था, 4 चमों तक्ष्र प्राप्त करने की अवस्था और 5 अधिकतम उपभोग की अवस्था।

पहली अवस्था में उन्होंने एक ऐसे अविकतित रूदिवादी समाज की कल्पना की है जो विज्ञान एवं तकनी की विकास में पिछड़ा हुआ है एवं उसका ज़ूकाव मुख्यत: भौतिक विश्व की ओर है। इसका मुख्य व्यवसाय निर्वाहन कृषि है तथा संभावित संसाधनों की खोज भी अधिक नहीं हो पायी है। इसके बाद द्वितीय अवस्था के दौरान संक्रमण की स्थिति रहती है जिसे उन्होंने उमर उठने की पूर्व स्थिति कहा । जब आर्थिक विकास प्रारम्भ होता है तथा ट्यापार का भी विस्तार होता है। वाह्य प्रभाव के कारण परम्परागत तकनीकों के साध-साथ नवीन तकनीकों का प्रयोग होने लगता है। तृतीय अवस्था में निर्णायक 'Take off' की स्थिति आती है। जब प्राचीन परम्पराओं का स्थान पूर्णतया नवीनताएँ लेने लगती हैं तथा आधुनिक औद्योगिक समाज एवं संस्कृति का जन्म होता है। फ्लतः अनेक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होती हैं तथा राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थार एवं मान्यतार बदलने लगती हैं तथा स्वयंपोधी प्रगति आरम्भ हो जाती है। चौथी अवस्था में औद्योगिक समाज ससंगठित एवं परिपक्व हो जाता है। पूँजी न्यास बदलने लगता है। नवीन औद्योगिक इकाइयों के विकास के साथ कुछ पुरानी इकाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। ्वृहद् नगरीय प्रदेश विकसित होने लगते हैं तथा यातायात संरचना अत्यधिक जिल

होने लगती है। पाँचवी अवस्था में आर्थिक प्रगति अपने चर्मों तक्यों में पहुँच जाती है। उत्पादकता अत्यधिक हो जाती है और समाज का ध्यान उत्पादन की समस्याओं से हटकर उपभोग की समस्याओं पर केन्द्रित होने लगता है। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही संसाधनों का वितरण सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए होने लगता है।

यह सिद्धान्त पूँजी-निर्माण की विधि की ट्याख्या तो करता है, किन्तु इन पाँचों अवस्थाओं में सम्बन्ध को स्थापित करने वाले तत्त्व की ट्याख्या नहीं करता है। आलोचकों ने इस सिद्धान्त में मार्क्स के सिद्धान्त के खण्डन का निरर्थक प्रयास माना है। फिर भी यह स्पष्टत है कि साधारण तथा विकसित देशों के विद्यले-षण में यह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है किन्तु विकासोन्मुख देशों में क्या यह प्रक्रिया कार्य करती है ? विचारणीय प्रश्न है। निश्चित रूप से तृतीय विश्व के कई देश प्रथम तीन अवस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) विकास-ध्रव सिद्धानत

पिछले कुछ दशकों में तृतीय विश्व के विकास के सन्दर्भ में अनेक विचार—धाराओं का प्रतिपादन किया गया है जिसमें Perroux महोदय द्वारा सन् 1955 में प्रतिपादित 'विकास ध्रुव' का सिद्धान्त सबसे महत्त्वपूर्ण है जिसे भौगोलिक परि— प्रेक्ष्य में प्रस्तृत करने का श्रेय बाउडविले 7 को है। यह सिद्धान्त विकास के विकेन्द्रित केन्द्रीकरण की प्रक्रिया तथा 'Top down approach' का समर्थन करता है। स्वयं Perroux के अनुसार —

"Growth does not appear everywhere and all atonce; it appears in points or development poles, with variable intensities; it spreads along diverse channels and with varying terminal effects to the whole of the economy."

इस सिद्धान्त के अनुसार किसी अविकतित प्रदेश या क्षेत्र जिसे Perroux ने सूक्ष्म आर्थिक प्रदेश (Micro-Economic Space) कहा है, का विकास, विकास की सुविधाओं से युक्त चुने हुए विकास ध्वां के माध्यम से संभव है। उनके अनुसार स्विधा-सम्पन्न ऐसा केन्द्र आकर्षण और विकर्षण की प्रक्रिया से गुजरेगा जिसके कारण वहाँ से विकास की किरणें प्रस्फुटित होंगी और 'Trickle Down' प्रक्रिया द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास होगा । बाउड विले ने ऐसे ध्रुवों की पहचान उन केन्द्रिय बह्तियों के रूप में किया है जिनमें दूसरी बह्तियों को प्रभावित करने की पूर्ण क्षामता है। उनके अनुसार उपलब्ध सुविधाओं की संख्या एवं क्षेत्रीय आकार के अनुसार ये केन्द्र विभिन्न स्तर के होंगे। इनमें सबसे बड़ा केन्द्र अपने से छोटे केन्द्रों के माध्यम से सबसे छोटे केन्द्रों को प्रभावित करेगा तथा सबसे छोटे केन्द्र से आस-पास के अविक-सित केन्द्र प्रभावित होंगे और सम्पूर्ण प्रदेश में विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। इस प्रकार विकास-धूव द्वारा विकास की ऐसी श्रृंखना वन जायेगी जिससे सम्पूर्ण प्रादे-शिक विकास को गति एवं दिशा मिलेगी। अपनी इन्हीं विशेष्ठाताओं के कारण स्था-निक विषामताओं को दूर करने में यह सिद्धान्त भूगोन विद्यों, अर्था स्त्रियों एवं नियो-जकों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं मान्य है। इसके बावजूद इस सिद्धान्त की कटु आलोचना की गयी है। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया गया है कि एक अविकसित क्षेत्र को विभिन्न स्तर के विकास-ध्रुवों की अवस्थापना के लिए धन कहाँ से प्राप्त होगा ? यदि ऐसा संभव भी हो जाता है तो भी ये विकास ध्रुव तब तक अपने कार्यों में सफ्ल नहीं हो सकते जब तक उस प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या की आर्थिक क्षामता इतनी न हो कि वह उन केन्द्रों में विकसित विभिन्न सेवाओं को संरक्षण प्रदान कर सके। ताल्पर्य यह है कि किसी अविकसित क्षेत्र में इस तरह के विकास-ध्रुवों की उत्पत्ति एवं विकास उनकी माँग और पूर्ति पर निर्भर करती है।

1.3 नियोजन की अवधारणा

विषय के वर्तमान परिद्शय में जहाँ कोई भी राष्ट्र या प्रदेश विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है, नियोजन विकास का पर्याय बन गया है। नियोजन विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया है जिसके बिना विकास संभव नहीं है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोगों और उद्देश्यों के अनुसार नियोजन का अर्थ भी बदलता रहा है। इसीलिए Faludi महोदय है ने नियोजन को बहुआ यामी बताया है। उनका विचार है कि नियोजन की संकल्पना ट्यक्तिनिष्ठ, क्षेत्रनिष्ठ तथा तथ्यनिष्ठ है जो सन्दर्भों के अनुसार बदलती रहती है। भारी भवाइन महोदय है नियोजन को परिभाष्टित करते हुए लिखा है – नियोजन निर्णय प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष्ठ में ट्याप्त अनेक क्रियाओं के मध्य आदर्श समन्वय स्थापित करना है। आर०एन० सिंह एवं अवधेश कुमार 20 के मतानुसार नियोजन से तात्पर्य किसी कार्य को सुचारू रूप से सम्मन्न करने हेतु सुट्यव स्थित पद्धित के निर्माण करने की प्रक्रिया से है। नियोजन की ट्यापक ट्याख्या भारतीय योजना आयोग 21 (Planning Commission of India) द्वारा प्रस्तुत की गयी है –

"Planning involves the acceptance of a clearly defined system of objectives in terms of which to frame over all policies. It also involves the formation of a strategy for providing the realisation of ends defined. Planning is essentially an attempt at working out a rational solution of problems, an attempt to co-ordinate means and ends; it is thus different from the traditional hit - and miss methods by which reforms reconstruction are often undertaken.

निष्ठका रूप में कहा जा सकता है कि नियोजन, उपलब्ध संसाधनों के प्रबन्धन एवं समुचित उपयोग की एक पूर्ण निश्चित क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक निर्धारित अविधि में वांछित सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

विकास नियोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया सामान्यतः पाँच चरणों में सम्पादित होती है। प्रथम चरण के अन्तर्गत नियोजक उन समस्याओं की पहचान करते हैं जिनके आधार पर वे अपनी योजना का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। द्वितीय चरण में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतार निर्धारित की जाती हैं। सामान्यतः प्राथमिकतार इस प्रकार तय की जाती हैं कि उद्देश्य की पूर्ति कम से कम समय में संभव हो सके। इसके लिए वैकल्पिक नियोजन मॉडलों में से चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। तृतीय चरण में योजना क्रियान्वयन के सबसे सस्ते तरीके का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे कम से कम मूल्य चुकाकर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

यौथा चरण सम्पूर्ण प्रक्रिया में निर्णायक होता है जिसके अन्तर्गत योजना का कार्यान्वयन अगरम्भ होता है, जिसमें योजना के भौतिक एवं वित्तीय पक्ष में समायोजन का प्रयास किया जाता है। अन्तिम चरण में कार्यान्वयन प्रगति के क्रमागत मूल्यांकन की व्यव-स्था की जाती है जिससे यह पता चलता रहे कि योजना का कार्यान्वयन पूर्ण निर्धा-रित रणनीति के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं।

(।) नियोजन के प्रकार

नियोजन जैसे बहुआयामी संकल्पना के भौगोलिक आयाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । विकास की कोई भी योजना किसी न किसी क्षेत्र, समाज तथा अर्थट्यवस्था से सम्बन्धित होती है जिसका आधार भूतल होता है और यही भौगोलिक अध्ययन का केन्द्रबिन्दु है । इसीलिए Freeman²² महोदय का मत है कि भौगोनिक आधार नियोजन के लिए अनिवार्य है । प्रत्येक योजना का मूलाधार सूचनाएँ होती हैं, जिनके विश्लेष्ण से ही प्राथमिकताएँ एवं योजनागत लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । इन सूचनाओं का मूल श्रोत भूगोल ही है । यह सम्बन्धित विषयों को सूचनाओं के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति करता है । यह तथ्य वातावरण-नियोजन के संदर्भ में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है क्यों कि भूगोल ही एकमात्र विषय है जो ज्वातावरण को एक समष्टिट के रूप में देखता है ।

वैसे तो विभिन्न आधारों पर नियोजन को कई उपवर्गों में बाँटा जा सकता है, जैसे - अविध के आधार पर - अल्पकालिक, दीर्घकालिक तथा परिप्रेक्ष्य नियोजन; कार्यक्रम अन्तर्वस्तु के आधार पर - आर्थिक नियोजन एवं विकास नियोजन; संगठना तमक दृष्टित से आदेशा तमक एवं निर्देशा तमक नियोजन ; नियोजन प्रक्रिया की दृष्टित से मानकीय नियोजन एवं पद्धतिशील नियोजन ; तत्त्वों के आधार पर प्रखण्डगत तथा स्थानिक नियोजन तथा नियोजन के स्तर के आधार पर एकल स्तरीय एवं बहुस्तरीय नियोजन आदि आदि । परन्तु भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में नियोजन के निम्न प्रकार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं -

- (क) विभागीय या प्रखण्डगत नियोजन (Sectoral Planning) वस्तु/वर्ग सापेक्ष
- (ख) प्रादेशिक/स्थानिक नियोजन (Regional/Spatial Planning) क्षेत्र/स्थान सापेक्ष
- (ग) समयाविधि नियोजन (Temporal Planning) समय सापेक्ष

(क) विभागीय या प्रखण्डगत नियोजन

जब किसी राष्ट्र या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था या तमाज के किसी वर्ग या तथ्य विशेष्ठा के विकास के लिए नियोजन किया जाता है तो उसे प्रखण्डगत नियोजन की संज्ञा दी जाती है। इसमें हम विकास के लिए तथ्यों का अलग-अलग चुनाव करते हैं। पहले किसी एक वर्ग को लेते हैं और सम्यक् दृष्टिंद से उसके भरपूर विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। देश की प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजनाओं में इसी पद्धति का अनुसरण किया गया। इसलिए प्रथम में कृष्ठा एवं दितीय में उद्योग-धन्धों के विकास को प्राथमिकता दी गयी। इसमें पूँजी निवेश की व्यवस्था निर्धारित नी तियों के अनुसार

चयनित वर्ग/विभाग/खण्ड के उत्थान के लिए ही होती है। कुल मिलाकर अर्थट्यवस्था के उस प्रखण्ड विशेष्य को प्राथमिकता दी जाती है। उस विभाग के एक सीमा तक विकितित होने के बाद ही दूसरे विष्य का चुनाव होता है। नियोजन की इस प्रक्रिया में संतुलित या समाकलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी समय लगता है किन्तु सामान्य स्तर से काफी पिछड़े वर्ग या खण्ड को आधार रेखा तक पहुँचाने में यह नियोजन प्रक्रिया काफी उपयोगी साबित होती है।

(ख) प्रादेशिक नियोजन

पूँकि भौगोलिक अध्ययन का केन्द्र बिन्दु भूतल ही है इस लिए भूगोल के संदर्भ में स्थानिक आधार पर निर्धारित प्रादेशिक नियोजन का महत्त्व अत्यधिक है। प्रादेशिक नियोजन के अन्तर्गत प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर किसी स्थान विशेष्ठ की मूलभूत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास-हेतु विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रादेशिक नियोजन का लक्ष्य किसी क्षेत्र विशेष्ठ के भौतिक एवं मानवीय दोनों संसाधनों को सन्दर्भ में रखकर ऐसी नीति का निर्धारण करना है जिसे सरलतापूर्वक कार्यरूप में परिणत करके क्षेत्र का समुचित विकास किया जा सके।

ममफोर्ड²³ महोदय के अनुसार - प्रादेशिक नियोजन उन समस्त क्रिया-क्लापों का चेतन निर्देशन तथा सामूहिक समाक्लन है जो पृथ्वी के स्थान संसाधन तथा संरचना के रूप में उपयोग पर आधारित है। प्रदेश का व्यवस्थित विकास तथा उसका अन्य प्रदेशों से अधिक सूक्ष्म सम्बन्ध स्थापित करना प्रादेशिक नियोजन का कार्य है।

प्रादेशिक नियोजन का महत्त्व उन राष्ट्रों के लिए अधिक है जहाँ राष्ट्रीय योजना में क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य समाहित रहता है। राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत ही प्रादेशिक नियोजन द्वारा किसी क्षेत्र विशेष्ठ के विकास-गति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। संतुलित प्रादेशिक विकास इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। बड़े एवं विषय प्रदेशों से युक्त राष्ट्रों के लिए इस प्रकार की योजना राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टिटयों से काफी लाभदायक सिद्ध हुईं हैं।

(ग) समयावधि नियोजन

विकास की किसी भी योजना में लगने वाला समय, नियोजन के स्तर एवं स्वस्प को निश्चित करता है। नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगने वाली अविधि के अनुसार नियोजन ता त्का लिंक, अल्पका लिंक, दीर्धका लिंक एवं परिप्रेक्ष्यमूलक हो सकते हैं। ता त्का लिंक नियोजन के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष्ठ की उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाता है, जिनकी तुरन्त आवश्यकता है या जिनकी ओर तुरन्त ध्यान न देने से भविष्य में उनके अत्यधिक जिल्ल होने की संभावना रहती है। अल्पका लिंक नियोजन में क्षेत्र विशेष्ठ की कुछ वर्तमान समस्याओं का निवारण तो संभव है, लेकिन इसके द्वारा उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, समाज एवं राजनीतिक दांचे में संरचना त्मक एवं संस्थात्मक परिवर्तन लाना संभव नहीं है। इसके विपरीत, दीर्ध-का लिंक नियोजन में अर्थव्यवस्था, समाज के संरचना त्मक तथा संस्थात्मक परिवर्तन के साथ-साथ बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रतिव्यक्ति उत्पादन में वृद्धि आदि समस्याओं का निराकरण भी समाहित रहता है। परिप्रेक्ष्य नियोजन के अन्तर्गत उन समस्याओं के निराकरण के उपाय किए जाते हैं जिनके भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना रहती है। वस्तुतः परिप्रेक्ष्य नियोजन का उद्देश्य उन तमाम समस्याओं को उत्पन्न होने

से रोकना है जिनके सुदूर भविष्य में उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पर्यावरण या संसाधनों के नियोजन के पीछे कुछ इसी तरह का उद्देश्य होता है।

(2) नियोजन का स्तर

क्षेत्र एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नियोजन के स्तर में काफी विविधता पायी जाती है। सामान्यतः क्षेत्र के आकार एवं स्वरूप के अनुसार नियोजन वृहत्, मध्यम एवं लघु स्तरीय हो सकते हैं। नियोजन के इन सापेक्षिक स्तरों के अन्तर्गत ही नियोजन का प्रारूप एक स्तरीय एवं बहुस्तरीय होता है। किसी राष्ट्र के सन्दर्भ में विकास-नियोजन वृहत् एक एवं केन्द्रीय स्तर का होता है जिसमें राष्ट्र का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं सभी तथ्य समाहित रहते हैं। इसी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अनेक मध्यम एवं लघु स्तर की बहुस्तरीय योजनाओं के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र के नियोजित विकास की रूपरेखा तैयार की जाती है।

वस्तुतः बहुस्तरीय नियोजन, नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होता है।
नियोजन का यह बहुस्तरीय स्वरूप क्षेत्र के आकार, प्रशासनिक प्रतिरूप, भौगोलिक
स्वरूप तथा क्षेत्रीय संरचना आदि तथ्यों पर निभीर करता है। भारतीय सन्दर्भ में
नियोजन के सामान्यतः निम्न सापेक्षिक स्तर स्वीकार किये जाते हैं -

- (क) केन्द्रीय स्तर (राष्ट्रीय स्तर)
- (ख) अन्तरेन्नीय स्तर (राज्य स्तर)
- (ग) अन्तर्धानीय स्तर (जिला स्तर)
- (घ) स्थानीय या सूक्ष्म स्तर (तहसील/विकासखण्ड स्तर)

(च) आधार स्तर (न्याय पंचायत/ग्राम स्तर)

सामान्यतः विकास की प्रक्रिया वृहत् स्तर से नद्दा स्तर की ओर उन्मूख होती है। ज्यों-ज्यों नियोजन का स्तर द्धता जाता है क्षेत्र का आकार भी द्धता है परन्तु उसमें सिम्मिनत होने वाले तथ्यों की संख्या बढ़ती है। अन्ततः वह एक गाँव एवं गाँव से सम्बन्धित सभी या अधिकांश तथ्यों तक सीमित हो जाता है। समाकिनत क्षेत्रीय विकास की परिकल्पना इसीनिए नद्दा स्तरों पर ही संभव हो पाती है।

1.4 भारत में विकास-नियोजन एवं उसका स्वरूप

भारत में नियोजन का इतिहास यथिष काफी प्राचीन है तथापि आधुनिक सन्दर्भों में विकास-नियोजन के प्रचलित मानदण्डों के अनुसार योजनाबद्ध तरी के से देश का विकास स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही संभव हो सका । प्रागैतिहासिक काल में सिन्धु घाटी की सभ्यता से प्राप्त प्रमाणों से नगरों के योजनाबद्ध तरी के से विक-सित होने का आभास होता है । संभव है कि तत्कालीन नियोजन आधुनिक समा-किलत क्षेत्र नियोजन से परे मात्र कुछ विशिष्ट मानव बहितयों के लिए ही किया जाता रहा हो ।

यह तत्य है कि वर्तमान स्वरूप में विकास-नियोजन की परिकल्पना बीसवीं शता ब्दी की देन है, परन्तु भारत में इसका प्रयोग काफी विलम्ब से हुआ है जिसका एकमात्र कारण विदेशी शासन एवं शासकों का निहित स्वार्थ रहा है। उपनिवेश-वादी शक्तियाँ न केवल भारत के आर्थिक विकास के प्रति सदैव उदासीन रहीं, बल्कि

अपनी शोषक नीति के अन्तर्गत भारत के आधिक एवं तामाजिक ढाँचे को यथातंभव बदलकर विकृत् करने में तदैव तत्पर रहीं। परिणामस्वरूप भारत की परम्परागत् अर्थ व्यवस्था एवं उस पर आधारित सामाजिक ढाँचा निरन्तर कमजोर होता गया।

यद्यपि भारत में योजनाबद तरी के से विकास का कार्य स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ही संभव हो सका तथापि नियोजित विकास के प्रति जागरूकता काफी पूर्व ही उत्पन्न हो गयी थी। सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ के प्रतिरूप पर नियोजित विकास के सूत्राधार एमं० विशेषवरैया थे। उनकी पुस्तक 'Planned Economy India' सन् 1934 में प्रकाशित हुई । उसके बाद सन् 1938 में पं0 जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय नियोजन समिति' का गठन किया गया । इसी श्रृंख्ला की अगली कड़ी के रूप में सन् 1944 में ए० दलाल के संरक्षण में नियोजन और विकास विभाग का सूजन हुआ। सन् 1946 की अन्तरिम सरकार के अधीन नियोजन सलाहकार परिषद् का निर्माण हुआ तथा सन् 1947 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य-क्रम समिति की नियुक्ति की गयी। अन्ततः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् लम्बी ब्रिटिश दासता एवं राष्ट्र विभाजन से विरासत में मिली देश की जर्जर अर्थव्यवस्था एवं ध्वस्त सामाजिक स्थिति के उत्थान के लिए सन् 1950 में प्रधानमंत्री पं जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 'योजना आयोग' का गठन किया गया जिसका उद्देश्य नियोजित तरीके से देश की आर्थिक स्थिति सुधारना, सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, बीमारी एवं कुपोधण का उन्मूलन, लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, धन एवं आय का युवितसंगत दंग से वितरण, सभी को समान अवसर प्रदान करना, बेरोजगारी दूर करना, प्रदूषण-

रहित पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था तथा समता एवं सहयोग के आधार पर आदर्श समाज का निर्माण करना था। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। अप्रैल, 1951 में देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारम्भ हुआ।

प्रथम पंचवधीय योजना (1951-56) में दो मुख्य उद्देश्य थे। देश की अर्थंट्यवस्था में विभाजन एवं युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को समाप्त करना तथा एक संतुलित एवं समाकलित विकास प्रक्रिया की शुरूआत करना। इस योजना में कृष्ठि के विकास तथा अर्थंट्यवस्था में स्पीतिकारी प्रवृत्तियों पर अंतुशालगाने में काफी सफलता प्राप्त हुईं। द्वितीय पंचवधीय योजना²⁴ (1956-61) में समाजवादी विचारधाराओं के धरातल पर नियोजन का प्रारूप तैयार किया गया - जिसमें व्यक्तिगत लाभ की तुलना में सामाजिक उपलब्धियों पर राष्ट्रीय आय एवं रोजगार की तुलना में राष्ट्रीय आय एवं सम्पत्ति के वितरण में समानता पर विशेष कल दिया गया। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि आर्थिक विकास का फायदा पहले समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त वर्ग को मिले। साथ ही, सम्पत्ति एवं आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में क्रमा: कमी होती जाय।

इसके बाद की सभी योजनाओं की पृष्ठभूमि में यही विचारधारा सक्रिय रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गयी किन्तु औद्योगिक विकास में विदेशी मुद्रा की कमी विशेष्ठ रूप से बाधक रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) का लक्ष्य भी आधारभूत उद्योगों का विकास करना था जिससे देश में औद्योगिक संस्कृति का ढांचा तैयार हो सके। इसके पश्चात् भारत-पाक

युद्ध (1965), रूपये का अवमूल्यन एवं लगातार दो वर्डी पड़ने वाले सूखे के कारण पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम एकाएक दूट गया । परन्तु अगले तीन वर्षा (1966-69) के दौरान विकास का कार्य वार्षिक योजनाओं के माध्यम से जारी रहा। सन 1969 में पुन: चौथी पंचवर्जीय योजना (1969-74) 'गरीबी हटाओ ' जैसे नये लोक-प्रिय नारों के साथ जोर शोर से लागू की गयी। इस योजना के परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किये गये। परन्तु यह योजना केन्द्र में सरकार-परिवर्तन होने के कारण अपना कार्यकाल पूरा न कर सकी । योजना के दौरान देश में आपात हिथति लागु होने से काफी राजनीतिक अहिथरता रही । सन् 1977 में केन्द्र में आयी जनता सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया । परन्तु उनके द्वारा निर्मित छठीं पंचवर्षीय योजना के अपना पूर्ण रूप लेने से पहले ही केन्द्र में एक बार फिर सरकार बदल गयी। फ्लस्वरूप छठीं पंचवर्षीय योजना अन्तत: । अप्रैल, १९८० में लागू हुई । सातवीं योजना (१९८५-९०) में उर्ज़ा के अधिक उत्पादन एवं उर्ज़ा के नवीन सोतों के विकास की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया । इसके बाद एक बार पुन: केन्द्र में सरकार के परिवर्तन एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) सही समय पर आरम्भ न होकर अपेक्षाकृत् देर से लागू हो सकी ।

भारत में विकास नियोजन का स्वरूप बहुस्तरीय होते हुए भी अत्यधिक केन्द्रीय प्रकृति का है। वस्तुत: नियोजन का सम्पूर्ण प्रारूप केन्द्रीय स्तर पर ही तैयार किया जाता है तथा राज्य सरकार एवं अन्य स्तर की इकाइयाँ इस नियोजन प्रक्रिया में केवल कार्यान्वयन के समय ही शामिल होती हैं। देश की प्रथम तीन योजनाओं के निर्माण में केन्द्र सरकार ने अग्रणी भूमिका निभायी। चौथी पंचवर्षीय योजना
में कुछ राज्यों ने स्वतन्त्र रूप से नियोजन प्रारूप तैयार करने का प्रयास किया। लेकिन
चूँकि राज्यों की अपनी कोई स्वतंत्र नियोजन म्ह्यीनरी नहीं है और राज्य वित्तीय एवं
अन्य संसाधनों के लिए लगभग पूरी तरह केन्द्र पर निर्भर है इसलिए स्वतन्त्र रूप से
योजना बनाना उनके लिए एक औपचारिक अभ्यास मात्र रह जाता है। राज्य स्तर
पर नियोजन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए योजना आयोग ने सन् 1972 में कार्यक्रम
बनाया²⁵ जबिक जिला स्तर पर नियोजन के निर्देश इससे भी पहले सन् 1969 में दिये
जा चुके थे। ²⁶ इसी की अगली कही के रूप में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गव
स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सन् 1978-85 के दौरान तहसील एवं
विकासखण्ड स्तरीय नियोजन का प्राविधान कियां गया। ²⁷

छठीं पंचवधीय योजना में विकेन्द्रित नियोजन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिना। इस योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष्ठ जोर दिया गया और योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत पत्र में राज्य से निचले स्तरों विशेष्ठकर जिला एवं विकासखण्ड स्तर की योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी। चूँ कि भारत में निचले स्तर पर किसी निष्ठिचत नियोजन संस्था का अभाव है इसलिए नियोजन में काफी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जिले स्तर तक्कोनियोजन का विकेन्द्रीकरण एक सीमा तक ठीक है परन्तू इससे नीचे के स्तरों पर नियोजन में कई समस्याएँ हैं। तहसील या विकासखण्ड मूलतः योजनाओं को उमर के निर्देशानुसार कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं, फ्लतः उनके पास स्वतन्त्र रूप से योजना बनाने की क्षमता नहीं है। साथ ही, सभी विकासखण्ड समान रूप से

संताधन सम्पन्न भी नहीं होते हैं जिससे उन्हें नियोजन इकाई बनाया जा सके ।
भारत जैसे विकासगील देश में जहाँ सभी स्तर पर न तो नियोजन संस्थाएँ हैं और न
ही इसके लिए आधारभूत द्वांचा उपलब्ध है, विकासखण्ड एवं गाँव वास्तव में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त है न कि योजनाओं के निर्माण के लिए । फिर
भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका नियोजन तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर ही ठीक से
लिया जाना संभव है, जैसा कि 5 नवम्बर, 1977 को 'विकासखण्ड स्तर पर
नियोजन' हेतु दांत्वाला कमेटी ने सुझाव दिया है - । कृष्ठि एवं सम्बन्धित
क्रियाएँ, २ गौण सिंचाई, उ. मृदा संरक्षण एवं जल-प्रबन्ध, भ. पशुपालन एवं
मुर्गीपालन, ५ मत्सयन, ६ वानिकी, ७ कृटीर एवं लघु उद्योग, १० स्थानीय सुविधा
अधार, १। सार्वजनिक सुविधाएँ - (क) पेय जल आपूर्ति (ख) स्वास्थ्य एवं
पोष्ठण (ग) शिक्षा (घ) आवास (य) सफाई (द) स्थानीय परिवहन (ज) जनकल्याण कार्यक्रम, और १२ स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण एवं स्थानीय जनसंख्या के
कौशन में वृद्धि आदि।

1.5 पिछडी अर्थटयवस्था एवं उसके निर्धारक कारक

पिछड़ी अर्थटयवस्था का प्रत्यय मुख्यतः भारत जैसे तीसरी दुनियां के विकास-शील देशों के साथ जुड़ा हुआ है तथा विश्व के निर्धन देशों की तमाम समस्याओं का पर्याय बन गया है। सामान्यतया 'अर्थटयवस्था' शब्द का तात्पर्य किसी प्रदेश या क्षेत्र के आर्थिक तन्त्र से है परन्तु भौगोलिक संदर्भों में इसका प्रयोग बहुत ट्यापक अर्थों में किया जाता है। अर्थटयवस्था शब्दावली का प्रयोग किसी क्षेत्र या स्थान के समाष्टियत् स्वरूप की अभिट्यक्ति के लिए किया जाता है जिसमें आर्थिक तंत्र के साथ-सम्बन्धित क्षेत्र के अन्य सभी-भौगोलिक तथ्य समाहित होते हैं। अतः शोध-प्रबन्ध के विषय में भौगोलिक शब्दावली 'पिछ्डा क्षेत्र' का प्रयोग न करके 'पिछ्डी अर्थ -ट्यवस्था' का प्रयोग किया गया है।

अविकसित अथवा पिछड़ी अर्थं=यवस्था की कोई निश्चित निरपेक्षा परिभाषा नहीं दी जा सकती है। विकास की संकल्पना की भारति ही यह एक तुलना त्मक विचार है। साधारण अर्थ में पिछड़ी अर्थंट्यवस्था का तात्पर्य आर्थिक सन्दर्भों में उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यक-ताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। अर्थं=यवस्था के पिछड़ेपन की तीव्रता का अनुमान ऐसे लोगों की संख्या के आधार पर लगाया जा सकता है। पिछडी अर्ध-च्यवस्था के पीछे सर्वाधिक सक्रिय तथ्य कृष्टि एवं उद्योगों का पिछडापन होता है। यह पिछ्डापन भौतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के अविकसित होने का परिणाम कहा जा सकता है। भौतिक संसाधनों से तात्पर्य किसी स्थान के उच्चावच, जलवायु,अपवाह, वनस्पति, मिट्टी एवं खनिज आदि से है। जो क्षेत्र भौतिक संसाधनों में निर्धन होते हैं, ऐसे क्षेत्रों की अर्थंटयवस्था के पिछड़ेपन को दूर करना एक जिटल समस्या होती है। सांस्कृतिक संसाधनों में सम्पूर्ण मानवीय क्रिया कलाप समाहित होते हैं। कुछ क्षेत्र भौतिक संसाधनों की दृष्टित से तो धनी होते हैं परनतु मानव प्रबन्धन के अभाव में उनकी अर्थंटयवस्था पिछड़ी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में समुचित विकास नियोजन के द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्थं=यवस्था के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है।

किसी क्षेत्र की अर्थट्यवस्था पिछड़ी है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कुछ निश्चित मापदण्ड होते हैं, उसी के आधार पर अर्थट्यवस्था के पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जाता है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था के पिछ्डेपन की कसौटी आर्थिक होती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रतिव्यक्ति कम उत्पादन, कृष्णि पर अत्यधिक निभैरता, औद्योगिक पिछ्ड़ापन, उपभोक्ता की कम दर, बचत की कमी, पूँजी की कमी, जनसंख्या का अधिक दबाव स्वंतीच्र वृद्धि दर, बेरोजगारी, तकनीकी पिछ्ड़ा-पन, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति स्वंजनजातियों का अनुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात, परिवहन, संचार, जल विद्युत, अन्य सेवाओं स्वंसुविधाओं की कम उपलब्धता तथा विद्या का निम्न स्तर आदि किसी पिछ्ड़ी अर्थव्यवस्था के प्रतीक स्वं निर्धारक तथ्य माने जाते हैं। 28

पिछडी अर्थट्यवस्था के उपर्युक्त निर्धारक तथ्य मुख्यत: अर्थट्यवस्था के सांस्कृतिक पक्षा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें प्राकृतिक तत्वों की जो किसी अर्थट्यवस्था के पिछडेपन के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं, अवहेलना की गयी है। साथ ही, कार्यरत जनसंख्या का अनुपात जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू को भी नजर अंदाज किया गया है। अत: स्पष्ट है कि पिछडी अर्थट्यवस्था के निर्धारण में क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात, जलवायु की अनुकूलता, उच्चावच, जल, वन तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता आदि तथ्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

उपर्युक्त सभी मानदण्डों के आधार पर भी पिछडी अर्थटयवस्था का निर्धारण एक जटिल कार्य है। इसमें मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है।

(1) पिछड़ी अर्थंटयवस्था की अवधारणा एक तुलनात्मक विचारधारा है अतः उस

क्षेत्र का स्तर ज्ञात होना आवश्यक है जिसकी तुलना में किसी अर्थट्यवस्था का पिछड़ा-पन ज्ञात किया जाय। उदाहरण के लिये यदि किसी ब्लाक या तहसील का पिछड़ा-पन ज्ञात करना है तो राष्ट्र, राज्य या जनपद में से किसकी तुलना में ज्ञात किया जाय १ भारत में जहाँ बहुस्तरीय नियोजन प्रयोग में है, यह क्षेत्र सम्मूर्ण राष्ट्र भी हो सकता है अथवा योजना आयोग द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय स्तर की भी अपनाया जा सकता है।

(2) पिछड़ेपन के निधारक मानदण्डों की तीमा क्या हो ? यह प्रश्न भी विचारणीय है अर्थात् किसी निर्धारक तथ्य का वह कौन ता औतत हो, जितते नीचे रहने वाले क्षेत्र पिछड़े एवं उमर रहने वाले विकत्तित कहे जायें। मानदण्डों की मानक तीमा भी या तो राष्ट्रीय औतत हो या फिर योजना आयोग द्वारा तमय-तमय पर निर्धारित तीमा। इन्हीं को आधार मानकर हम किसी अर्थट्यवस्था को पिछड़ा अथवा विकतित निर्धारित कर सकते हैं।

उपर्युक्त दोनों बातों का निर्धारण व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। यदि इसका निर्धारण कर भी लिया जाय तो भी अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन वास्तविक रूप से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा करने से मात्र तुलना त्मक रूप से क्षेत्रीय असंतुलन का ही आभास मिलेगा। वस्तुत: इसके लिये उचित यह है कि किसी क्षेत्र का पिछड़ा-पन उसी के वातावरणीय दशाओं में विभिन्न तथ्यों के सन्दर्भ में ज्ञात किया जाय। तात्पर्य यह है कि क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों एवं दशाओं के सन्दर्भ में सम्बन्धित क्रियाओं की विकास संभाव्यता का कितना अंश विकसित किया जा चुका है, ज्ञात किया जाय। यदि कुल संभाव्यता से 50 प्रतिशत से कम भाग विकसित किया गया है तो वह क्षेत्र

उक्त क्रिया विशेष के सन्दर्भ में पिछड़ा कहा जा सकता है किन्तु समुचित आकड़ों के अभाव में और निरन्तर बढ़ते मानव ज्ञान और प्रविधि के परिप्रेक्ष्य में प्रदेशों के पिछड़ेपन की पहचान का यह तरीका भी बहुत ट्यवहारिक नहीं हो पाता।

1.6 भारत में विकास नियोजन सम्बन्धी अध्ययन

यद्यपि विश्व रंगमंव पर विकास नियोजन की अवधारणा का आविभाव काफी पहले ही हो चुका था परन्तु भारत में इसके अध्ययन के प्रति जागरूकता पिछले दो-तीन दशकों की ही ह¢ना है। इस सन्दर्भ में भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संतुलित प्रादेशिक नियोजन का प्रारूप तैयार होना काफी महत्त्वपूर्ण है। इसी दौरान 'राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान' (National Institute of Community Development) हैदराबाद द्वारा वनमाली महोदय का शोध-प्रबन्ध प्रका शित हुआ जिसमें सामाजिक सुविधाओं के प्रादेशिक नियोजन पर बन दिया गया था । तन् 1970 में ए०एन० बोरा³⁰ ने तंत्रथागत तीमाओं और तम-स्याओं का विश्लेष्ण किया । इसी सन्दर्भ में सन् 1972 में भारतीय जनगणना ने भी काफी तराहनीय कार्य किया जब शताब्दी मोनोग्राम के रूप में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में समाकलित विकास कार्य के सन्दर्भ में रायवर्मन³। तथा चन्द्रशेखर³² के लेख उल्लेखनीय हैं। इसके बाद भारत के विकास-नियोजन पर अनेक गोहिठया, सम्मेलन इत्यादि सम्पन्न होने लगे और नधु प्रदेशी स्तर (Micro Regional Level) पर समाकलित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को लागू करने की तिफारिशें की जाने लगीं। इस सन्दर्भ में एक शोध अध्ययन एस0 ब्राम्हे³³ द्वारा प्रस्तृत हुआ जिसमें सूक्ष्म क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन के प्रक्रम के सम्बन्ध में अनेक निष्कर्ष निकाले गये । विकास नियोजन के बढ़ते हुए शोध-कार्यों में सन् 1972 में एल०के० सेन³⁴ द्वारा सम्मादित एक पुस्तक शोध-जगत् के लिये प्रस्तुत हुई जिसे 'मील का पत्थर' कह सकते हैं । इसमें लघुस्तरीय प्रादेशिक नियोजन, आधारभूत सुविधायें, विकास एवं परिवर्तन-प्रक्रम की प्रवृत्तियां, संकल्पनायें, अवधारणायें एवं विधियां तथा प्रादेशिक नियोजन के प्रक्रम, समस्याओं के आयाम एवं तकनी की सूत्रों आदि पक्षों पर व्यापक तौर पर लेखों और विशिष्ट अध्ययनों का समावेश किया गया ।

पश्चिमी बंगाल तरकार द्वारा कुछ प्रादेशिक विकास के कार्यक्रमों को अप-नाया गया । इस सन्दर्भ में सी०आर० पाठक³⁵ द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार इन योजनाओं में विशेष्ट बल ग्रामीण कृष्टि विकास की नीतियों को स्पष्ट करने पर दिया गया ।

यह तो निर्विवाद सत्य है कि आठवें दशक में भारतीय सामुदायिक विकास संस्थान (NICD), हैदराबाद का समाकलित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नियमन, उसकी नीति निर्धारण तथा भावी शोधकार्य संगलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सन् 1971 में एल०के० सेन तथा जी०के० मिश्रा³⁶ द्वारा सम्मादित शोधग्रन्थ इसी संस्थान के तत्त्वावधान में प्रकाशित हुआ, जिसमें कृष्टि, उद्योगों एवं सामाजिक सुविधाओं के विकास के लिये भविष्य में पड़ने वाली आवश्यकता के स्तर को परखते हुये विद्युत शिक्त की मात्रा के नियोजन का कार्य एक नीतिपरक दृष्टिद कोण से किया गया है।

विकास-नियोजन एवं समाकलित क्षेत्र विकास-नियोजन की संकल्पनाओं में यद्यपि अनेक प्रकार के समाज विज्ञानियों का योगदान रहा है किन्तु अर्थवा स्त्रियों एवं भूगोल वेत्ताओं की भूमिका विशेष्ठ रूप से सराहनीय रही है। मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में अर्थवास्त्री एम०एल० पटेल³⁷ ने लघु प्रदेशीय स्तर पर समाकलित क्षेत्र विकास के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किये। सन् 1976 में एल०एस० भद्द³⁸आदि द्वारा सम्पादित एक शोधग्रन्थ हरियाणा के करनाल क्षेत्र में लघुस्तरीय प्रदेश के समा-किलित विकास के सन्दर्भ में प्रकाशित हुआ। इस कार्य के द्वारा शोध कार्य में सांख्यिकी विधियों का भौगोलिक अध्ययन में प्रयुक्त व्यवहारिक पक्ष सफलता के साथ स्पष्ट हुआ।

सन् 1977 में भारतीय संगठन संस्थान (Indian Institute of Planning Administration) द्वारा भी जिला नियोजन से सम्बन्धित अपने कुछ प्रकाशन प्रस्तुत किये गये । इनमें एस० मुण्डल विश्व एवं के० एन० काब्रा 40 द्वारा लिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । इतना ही नहीं, योजना आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कुछ अध्ययन विकास खण्ड स्तर पर भी सम्मादित किये गये जिनमें पी० राय एवं बी०आर० पटेल 41 (1977) का सम्मादित कार्य विशेष्ठ रूप से उल्लेखनीय है। ब्लाकस्तर पर किये गये अध्ययनों में वे सभी तथ्य सम्मिलित किये गये हैं जो अभी तक जिला स्तरीय अध्ययनों में विश्लेष्ठित किये जाते रहे । उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त पिछले एक दशक में समाकलित विकास-नियोजन के सन्दर्भ में विभिन्न विश्व विद्यालयों, शोध संस्थानों एवं संस्थाओं द्वारा अनेकानेक शोधग्रन्थ, शोधमत्र एवं रिपोर्ट आदि प्रकाशित हुए हैं जिससे देश में विकास-नियोजन के अध्ययन के प्रति जागरूकता एवं आकर्षण का पता चलता है । प्रस्तुत शोधग्रन्थ में उनकी विस्तृत सूर्यी देना न तो सम्भव है और न ही समीचीन ।

_____:0::-----

सन्दर्भ

- 1. Smith, D.M.: Human Geography: A Welfare Approach, Arnold Heine Mann, Iondon, 1984.
- 2. Haq, Mahbub Ul.: "Employment and Income Distribution in the 1970's: A New Perspective", Pakistan Economic and Social Review, June-Dec., 1971, p. 6.
- 3. Seers, Dudley: 'The Meaning of Development', Eleventh
 World Conference of the Society for International Development, New Delhi, 1969, p. 3.
- Prakash, B. and Raza M.: Rural Development: Issues to Ponder, Kurukshetra, 32(4), 1984, pp. 4-10.
 - 5. तिवारी, आर०सी० तथा त्रिपाठी, एस० : 'समन्वित ग्रामीण विकास-भौगो लिक दृष्टिंकोण' - ग्रामीण विकास : संकल्पना, उपाणम एवं मूल्यांकन, अस० आसंह, पी० एवं तिवारी, ए०, पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र, इलाहा बाद, 1989, पृष्ठ 46-48 (उद्धृत)।
 - 6. Mishra, R.P., Sundram, K.V. and Prakash Rao, V.L.S.:

 Regional Development Planning in India:

 A New Strategy, Vikas Publishing House,

 New Delhi, 1974, p. 189.
 - 7. Todaro, Michael, P.: Economic Development in the Third World, New York: Longman Ine, 1983, p. 70.
 - 8. Hirschman, A.O.: Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University Press, 1958.
- 9. Hagen, E.E.: A Framework for Analysing Economic and
 Political Development in Robert Asher, (ed.)
 Development of Emerging Countries, Washington
 B.C., Booking Institution, 1962, pp. 1-38.

- 10. United Nations Research Institute for Social Development;

 Contents and Measurement of Social Economic

 Development, Geneva Report No. 70.10.1970.
- 11. Berry, B.J.L.: An Inductive Approach to the Regionalization of Economic Development in N. Ginsburh (ed.)

 Essays on Geography and Economic Development

 Research Paper 62, University of Chicago, 1960.
- 12. Adelman, and Morris, C.T.: Society, Politics and Economic Development, Baltimore, The John Hopking Press, 1967.
- 13. Harbinson, F.H., Maruhnic, J. and Resnick, J.R.: Quantitative Analysis of Modernisation and Development, Princeton, N.J.: Industrial Relations Section, Department of Economics, Princeton University, 1970.
- 14. Myrdal, G.: Economic Theory and Under-Development, London, 1957.
- 15. Rostow, W.W.: The Stages of Economic Growth, London, Cambridge University Press, 1962, p. 2.
- 16. Perroux, F.: La Nation de Croissance. Economique Applique Nos, 1-2, 1955.
- 17. Boudeville, T.R.: Problems of Regional Economic Planning, Edinburgh University Press, 1966.
- 18. Faludi, A.: Planning Theory, Pergamon Press, Oxford, 1973.

- 19. HillHorst, J.G.M.: Regional Planning: A Systems Approach, Rotterdom University Press, 1971.
- 20. सिंह, आर०एन० एवं कुमार, ए० : "भारतीय नियोजन प्रणाली एवं ग्रामीण विकास : एक समीक्षा", भूसंगम, 2 (1), इलाहाबाद ज्योग्राफिकल सोसाइटी, इलाहाबाद, 1984, पूष्ठ
- 21. Government of India, Planning Commission, First Five Year Plan, 1951, p. 7.
- 22. Freeman, T. W.: Geography and Planning, Fourth Edition, University Library, London, 1974.
- 23. Mumford, L.: The Culture of Cities, New York, 1938, pp. 371-374.
- 24. Planning Commission, Government of India, Second Five Year Plan, 1956, p. 22.
- 255 Singh, A.K.: Planning at the State Level in India, Commerce Pamphlet 25, 1970, p. 39.
- 26. Planning Commission: Guidelines for the Formulation of District Plans, U.P. Government Edition, 1969, pp. 1-2.
- 27. Vaishnav, P.H. and Sundram, K.V.: Integrating Development Administration at the Area Level in Planning Commission Report of the Working Group on Block Level Planning, 1978, p. 2.
- 28. Chand, M. and Puri, V.K.: Regional Planning in India, Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1983, p. 331.

- 29. Banmali, S.: Regional Planning for Social Facilities:

 An Examination of Central Place Concepts
 and their Application A Case Study of
 Eastern Maharastra, NICD, Hydrabad, 1970.
- 30. Bose, A.N.: Institutional Bottlenecks The Main
 Barrier to the Backward Area, Indian
 Journal of Regional Science, Vol. 2, No. 1,
 1970, p. 45.
- 31. Roy, Burman, B.K.: 'Towards an Integrated Regional Frame',
 Economic and Socio-Cultural Dimensions of
 Regionalization, Census of India, 1971,
 Monograph No. 7, New Delhi, 1972, pp.27-50.
- 32. Chandrashekhar, C.S.: Balanced Regional Development and Planning Regions, Census of India, 1971, Monograph No. 7, New Delhi, 1972, pp.59-74.
- 33. Brahme, S.: Approach to Rural Area Development, Indian Journal of Regional Science, Vol. 4, No.1, 1972, pp. 6-11.
- 34. Sen, L.K. et al. (eds.): Readings on Micro-Level Planning and Rural Growth Centres, NICD, Hydrabad, 1972.
- 35. Pathak, C.P.: Integrated Area Development: A Case for Rural Agricultural Development, Geographical Review of India, Vol. 35, No. 3, Sept,1973, pp. 222-231.
- 36. Sen, L.K. and Misra, G.K.: Regional Planning of Rural

 Electrification: A Case Study of Surya

 Pet Taluk, Nalgoda District, Andhra Pradesh,

 NICD, Hydrabad, 1974.

- 37. Patel, M.L.: Dilemma of Balanced Regional Development in India, Bhopal, 1975, pp. 34-35.
- 38. Bhat, L.S. (et al.): Micro Level Planning: A Case Study of Karnal Area, Haryana, India, K.B. Publication, New Delhi, 1976.
- 39. Mundle, S.: District Planning in India, I.I.P.A., New Delhi, 1977.
- 40. Kabra, K.N.: Planning Processes in the District, I.I.P.A., New Delhi, 1977.
- 41. Roy, P. and Patil, B.R. (els.): Mannual for Block Level Planning, Macmillan Co., Delhi, 1977.

____:0::----

अध्याय दो

पूलपुर तहसील की भौगोलिक पृष्ठभूमि

2. । प्रतावना

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की गणना देश के पिछड़े प्रदेशों के रूप में की जाती रही है। वस्तुतः पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन देश के लिए एक कहावत (Legend) का रूप ले चुका है। आजमगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश के इसी पूर्वी अंचल का एक भाग है। पूलपुर तहसील आजमगढ़ जनपद में स्थित होने के कारण इसका अपवाद नहीं। यहाँ की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था परम्परागत कृष्णि पर आधारित है। उद्योग-धन्धों का बहुत ही कम विकास हुआ है। पिक्षा का स्तर भी दूसरे क्षेत्रों की तुलना में काफी निम्न है। यातायात के साधन भी पिछड़ी अवस्था में हैं। इस प्रकार पूलपुर तहसील एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था का शब्दशः प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत अध्याय का मूख्य उद्देश्य विकास-नियोजन के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन प्रदेश की आधारभूत भौगोलिक जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.2 स्था निक कारक एवं प्रशास निक संगठन

पूलपुर तहसील उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की एक पिछड़ी तहसील है जो इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। तहसील का केन्द्रविन्दु पूलपुर करूबा है जो कुँवर नदी के बार किनारे पर स्थित है। पूलपुर तहसील 25048 6" से 26016 2" उत्तरी अक्षांश तथा 82040' 6" से 82056' 15" पूर्वी देशान्तर के मध्य, मध्य गंगा घाटी के निचले भाग – गंगा-धाघरा दो आव में स्थित है। दोंस नदी इस तहसील की उत्तरी सीमा तथा गाँगी नदी दक्षिणी सीमा निधारित करती है। तहसील की सीमाओं का निधारण पूर्व में आजमगढ़ जनपद की आजमगढ़ तहसील, उत्तर-पश्चिम

में सुल्तानपूर जनपद, उत्तर में फैजाबाद जनपद, उत्तर-पूर्व में बूद्धनपुर तहसील, दिक्षण-पूर्व में लालगंज तहसील तथा दिक्षण एवं दिक्षण पश्चिम में जौनपुर जनपद करते हैं। इस तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 701.60 वर्ग कि0मी० है। जो जनपद के कुल भौगो-लिक क्षेत्रफल का मात्र 16.58 प्रतिशत है।

सम्पूर्ण अध्ययन प्रदेश को 4 विकासखण्डों - पवर्ड, पूलपुर, मो टिनगंज तथा
अहरौला में विभाजित किया गया है । अहरौला विकासखण्ड को दो भागों अहरौला I तथा अहरौला II में विभक्त किया गया है । कुछ वर्ष पहले 19.4.89
को नयी तहसील बूद्रनपुर बन जाने के कारण अहरौला II विकासखण्ड बूद्रनपुर तहसील में चला गया । मुख्यालय सहित अहरौला विकासखण्ड का 30 प्रतिप्रात भाग पूलपुर तथा
70 प्रतिप्रात भाग बूद्रनपुर तहसील में स्थित है । यही 30 प्रतिप्रात भाग अहरौला(1)
विकासखण्ड के नाम से जाना जाता है । मा टिनगंज विकासखण्ड कुन 235.39 कि0मी0²
सहित देश्रमल में सबसे बड़ा है । अन्य विकासखण्डों-पवर्ड, पूलपुर, तथा अहरौला(I)का भौगों लिक देश्रमल क्रम्या: 206.99, 188.88 तथा 61.36 कि0मी0² है । तहसील के ये विकासखण्ड 38 न्यायपंचायतों में विभक्त हैं (चित्र 2.1) । पुन: ये न्याय पंचायतें 329 ग्राम सभाओं तथा ये ग्राम सभार्थ 525 ग्रामों में विभक्त हैं जिनमें 30 गैर आबाद गाँव भी समाहित हैं । तहसील का मुख्यालय एकमात्र नगरीय केन्द्र है जो 8.98
कि0मी0²× देश्रमल पर पैता है । तहसील का कुल ग्रामीण भौगों लिक देश्रमल 692.62

पूलपुर टाउन एरिया का क्षेत्रफल जिला जनगणना हस्तपु स्तिका में 8.98 वर्ग कि0मी0 दशाया गया है जबकि क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार यह क्षेत्रफल लगभग 2 कि0मी0² है ।

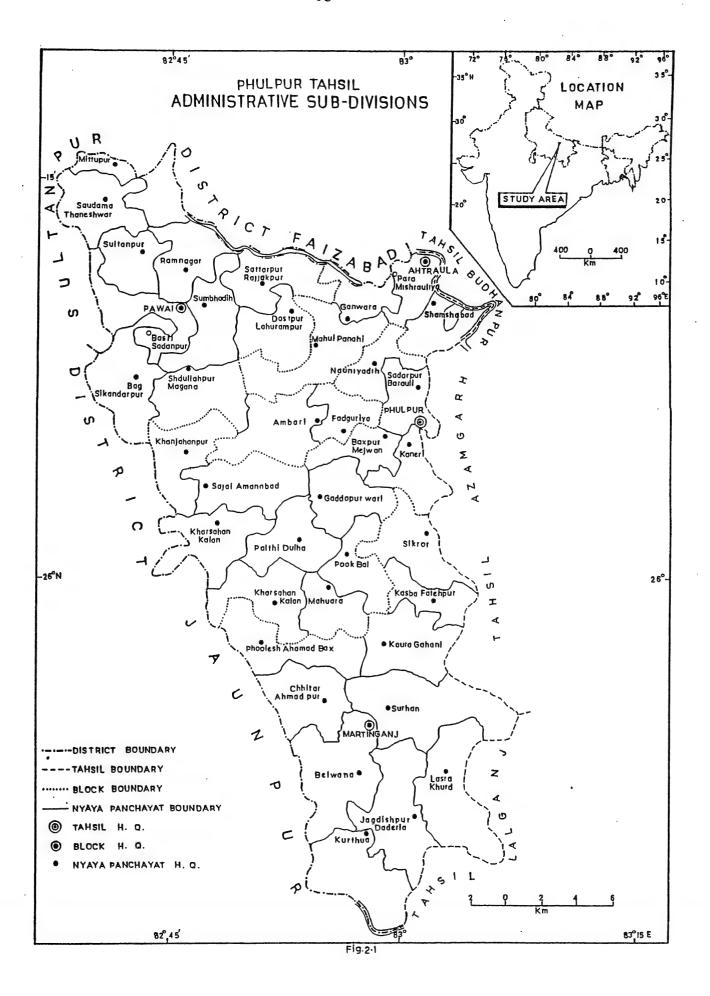
सारणी २.। पूनपुर तहसील का प्रशासनिक संगठन

विकास खण्ड	भौगो लिक ध्रेन्नफ्ल क्लियी० ²	क्ल. न्याय पंचायते	ग्राम सभार	, जाम भ	गैर आबाद ग्राम	कुल अन्बाद ग्राम
 पवई फूलपुर 	206. 99 188. 88	12 12	116 9 6	18 I 176	8 12	173 164
 मा टिनगंज 	235. 39	10	80	104	7	97
4. अहरौला (1)	61.36	4	37	64	3	61
पूलपुर नगरीय पूलपुर तहसील	8.98 701.60	- 38	- 329	- 525	- 30	- 49 5

द्वोत: जिला जनगणना हस्तपूरितका, प्राथमिक जनगणना सार, आजमगढ़, भाग ≯ाा В

2.3 भौतिक लक्षण

किसी भी क्षेत्र के अध्ययन में उसकी भौ मिकीय संरचना का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। धरातनीय उच्चावच, जल प्रवाह खं मुदा संरचना को नियन्त्रित करने के साथ ही भौगोलिक पर्यावरण का एक विशिष्ट तत्त्व होने के कारण यह मनुष्य की



समस्त आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है।

(।) संरचना एवं उच्चावच

संरचना की दृष्टित से तहसील का सम्मूर्ण भूभाग मैदानी है जो मध्य गंगा धादी के निचले भाग-गंगा-धाधरा दोआब में स्थित है। इसका निर्माण धाधरा एवं उसकी सहायक निद्यों दारा लाए गये अवसादों के जमाव से हुआ है। अपेक्षाकृत पुराने अवसादों का जमाव उच्च भागों में हुआ है जिसे 'बाँगर' के नाम से अभिहित किया जाता है। अत्यन्त नूतन अवसादों का जमाव आज भी निर्द्यों के कछारी भागों में हो रहा है जिसे 'खादर' के नाम से जाना जाता है। बाँगर एवं खादर के नाम से जाना जाता है। बाँगर एवं खादर के सी मा को पृथक करना किन कार्य है फिर भी सामान्यत: बाँगर क्षेत्र वह उच्चवर्ती भाग है जहाँ निर्द्यों का जल नहीं पहुँच पाता है जबिक खादर क्षेत्र प्रतिवर्ध बाद के समय जलमगन हो जाते हैं और इन क्षेत्रों की मिद्दी प्रतिवर्ध नवीन होती रहती है। इस मैदानी भूभाग में निक्षेपित अवसादों की मोटाई में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। इस मैदानी भूभाग में अवसादों की औरत मोटाई 1500 से 3000 मीटर तक है। 2 अन्तक्ष्तिरत अवसादों में क्ष्यरी, बालू एवं पंक प्रमुख हैं। 3 उसर क्षेत्रों में कंक्ड तथा रेड की प्रधानता पायी जाती है।

उच्चावचन की दृष्टित से सम्पूर्ण तहसील एक उदासीन समतल मैदान के रूप में है। सागर तल से इस मैदानी भूभाग की उँचाई कहीं भी 350 मी० से अधिक नहीं है। अनाच्छादन के कारकों विशेष्ठात: बहते हुए जल ने कई स्थानों पर अपरदन की क्रियाओं द्वारा मैदान की उदासीनता को भंग किया है। क्षेत्रीय भिन्नता निदयों एवं उसके समीपवर्ती भागों में देखी जा सकती है।

(२) अपवाह तंत्र

इस मैदानी भूभाग का सामान्य दाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ है। इस मैदानी भूभाग के उत्तरी भाग में बहने वाली प्रमुख नदी टोंस तथा इसकी सहायक नदिया मझुई, कुँवर तथा ओंगरावती हैं। मझुई नदी को मंगर नदी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदिया वेसों तथा गांगी हैं। इन नदियों में ग्रीष्म मृतु में जल की मात्रा काफी कम हो जाती है जबकि वर्षा काल में ये नदियां अपनी प्रलयंकारी बाद के लिए प्रसिद्ध हैं।

(क) टोंस नदी

तहसील के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी टोंस है ।

प्राचीन काल में अत्यन्त गहराई के कारण इसे तम्सा के नाम से जाना जाता था ।

यह नदी पूलपुर तहसील में माहुल से 9.6 कि0मी0 उत्तर-पूर्व में प्रविष्ट होकर द्याद्यरा नदी के समान्तर प्रवाहित होती हुई जिले के पूर्वी भाग में द्याद्यरा नदी में मिल जाती है । इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदिया, महुई, कुंवर तथा ओंगरावती हैं । ओंगरा-वती नदी की उत्पत्ति कोइला तालाब से हुई है, तहसील के मध्यवर्ती भाग से प्रवाहित होती हुई यह खुरासों के निकट महुई नदी में मिल जाती है जबकि महुई म्रष्ठि दुवाष्या आश्रम के पास टोंस नदी में मिलती है । कुंवर नदी तहसील में पिश्चम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई निजामबाद के पास दत्तात्रेय नामक स्थान पर टोंस नदी में मिल

जाती है।

(छ) अन्य नदियाँ

तहसील के दिक्षणी भाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख निद्या वेसो तथा गांगी हैं। बेसो नदी मार्टिनगंज विकासखण्ड के मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती है जबकि गांगी नदी मार्टिनगंज विकासखण्ड के दिक्षणी भाग में। इसकी उत्पत्ति कोदहरा के अर्रा वर्रा तालाब से हुई है। आगे चलकर ये दोनों निद्या गंगा नदी में मिल जाती हैं।

2. 4 जलवायु एवं वनस्पतियाँ

अध्ययन प्रदेश के उपोष्ण किटबन्ध में स्थित होने से यहाँ की जलवायु मानसूनी है। हिमालय की समीपता के कारण यह उसके प्रभाव सेमुक्त नहीं है। पूरे
वर्ष में स्पष्टत: दो ब्रतुएँ - ग्रीष्म एवं शीत पायी जाती हैं। जनवरी माह वर्ष का
सबसे ठण्डा महीना होता है। जनवरी माह का औसत उच्चतम दैनिक तापमान
23.3 सेठग्रे० तथा औसत दैनिक न्यूनतम तापमान 9.7 सेठग्र० होता है। कभी-कभी
न्यूनतम तापमान गलनांक भी के नीचे पहुँच जाता है तथा पाला पहने की घटनाएँ
घटित होती हैं। मई का अन्तिम तथा जून का प्रथमाई वर्ष का सबसे गर्म महीना
होता है जब तापमान लगभग 46 सेठग्रे० तक पहुँच जाता है।

तहसील में आर्द्रता सम्बन्धी मासिक आंक्ड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मानसून हवाओं में 85 प्रतिशत या इससे अधिक आर्द्रता पायी जाती है जबकि ग्रीष्म श्रुत में अपराह्न के समय यह आर्द्रता केवल 12 से 17 प्रतिशत तक होती है । तह्तील की औत्तत वार्धिक वर्षा 1333 मि०मी० है। वर्षा का 90 प्रति-शत भाग मानसून हवाओं से प्राप्त होता है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई-अगस्त में होती है। विभिन्न जलवायुविक तत्त्वों के सम्मिलित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष को सामान्यत: 5 भागों में बाँटा जा सकता है -

- ग्रीष्म काल (मध्य मार्च से मध्य जून)
- 2. वर्षा काल (मध्य जून से सितम्बर)
- 3. ग्रीष्म-भीत संक्रमण काल (अक्टूबर से नवम्बर)
- 4. शीत काल (दिसम्बर से मध्य फरवरी)
- 5. शीत-ग्रीष्म संक्रमण काल (मध्य परवरी से मध्य मार्च)।

मार्च 2। के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। इसी के साथ अध्ययन क्षेत्र में ग्रीष्म बतु का आरम्भ हो जाता है। तापक्रम में शनै: शनै: वृद्धि होने लगती है जो मई के उत्तरार्द्ध तथा जून के प्रथमार्द्ध में अपने चर्मों त्कर्ष पर होती है। उस समय तापक्रम 460 सेठग्रेठ से उमर पहुँच जाता है। इस समय अध्ययन क्षेत्र में धून भरी तेज सूखी गर्म हवाएँ भी चलने लगती है जिसे 'लू' के नाम से जाना जाता है। कभी-कभी अप्रैल तथा मई के महीनों में मानसून के पूर्व भी वर्षा हो जाती है जिसे 'आम की बौछार' या काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है।

जून के उत्तरार्द्ध में मानसून के आगमन के साथ वर्षा ब्रतु का आरम्भ होता है। तापक्रम में शनै: शनै: गिरावट आने लगती है तथा सापेक्ष आर्द्रता बद्धने लगती है। तहसील की अधिकांश वर्षा मध्य जून से सितम्बर के बीच प्राप्त होती है किन्तु कभी-कभी बीच में तूखा भी पड़ जाता है। वर्षा का सर्वाधिक भाग जुलाई-अगस्त में प्राप्त होता है।

सितम्बर 15 के बाद मानूसून का लौटना प्रारम्भ हो जाता है। 23

सितम्बर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। तापक्रम तथा सापेक्ष आर्द्रता में कमी आने लगती है। अक्टूबर तथा नवम्बर माह ग्रीष्टम तथा शीत ब्रुत् के बीच संक्रमण काल के रूप में पहचाने जा सकते हैं। इस दौरान कुछ वायुमण्डलीय अस्थिर-ताओं के अतिरिक्त वायुमण्डल स्वच्छ तथा सुहावना होता है।

दिसम्बर से मध्य परवरी तक शीत श्रृत होती है। जनवरी माह वर्ष का सबसे ठण्डा महीना होता है। मौसम सामान्यतया शुष्टक होता है किन्तु कभी-कभी पिश्चम से आने वाले चक्रवातों से तहसील में शीत श्रृत में भी वर्षा हो जाती है। यह वर्षा अल्प मात्रा में होती है किन्तु रबी की पसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। शीत श्रृतु में कभी-कभी पाला भी पड़ जाता है।

बनस्पतियों के वितरण में भौतिक कारकों - वर्षा, तापमान एवं मिद्दी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तहसील में वे प्रायः सभी वनस्पतियां दृष्टिगोचर होती हैं जिनका आविर्भाव मध्य गंगा के मैदान विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ है। तहसील में जंगलों का पूर्णतः अभाव है, वनों के नाम पर केवल उपवन हैं। तहसील के मध्यवर्ती भाग में फ्लदार वृक्ष यथा आम, जामुन, महुआ तथा कटहल आदि की अधिकता है जबकि दक्षिणी भाग में शीशम, नीम, महुआ, पीपल, तथा बरगद आदि वृक्ष पाये जाते हैं। सड़कों के किनारे यूकेलिप्टस तथा आम एवं

नदियां के तटवर्ती भागों में बबूल की प्रधानता है।

शता ब्दियों से कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए वनों की उन्मुक्त कटाई की जाती रही है। भारत सरकार ने यद्यपि हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया है किन्तु इसके बावजूद यह परम्परा थोड़े बहुत अन्तर के साथ आज भी जारी है। तहसील में मात्र 386.7। हे क्टेअर भूमि पर वन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की वंजर भूमि पर बब्लू तथा बेर के वृक्षों की अधिकता है। ग्रामीण अधिवासों के पास बांसों के झुरमुट भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं जिनका उपयोग मकान निर्माण तथा गृह उपयोगी वस्तुएँ बनाने के लिए किया जाता है।

तहसील में सर्वाधिक वन पूलपुर विकासखण्ड में 148.96 है क्टेअर भूमि पर हैं । इन वनों के सर्वाधिक क्षेत्र खंजहापुर, रम्मोपुर तथा चमांवा गावों में देखे जा सकते हैं जहाँ पर पलाश, वेर तथा बांस के वृक्षों की अधिकता है । तहसील में सबसे कम वन मार्टिनगंज विकासखण्ड में 57.29 हे क्टेअर भूमि पर है । पवई विकासखण्ड में 97.52 हे क्टेअर भूमि पर वन हैं । इनका सर्वाधिक क्षेत्रपल खंडौरा, हमीरपुर तथा अंडिका गांवों में है । अहरौला विकासखण्ड जिसका 6139 हे क्टेअर भूमि पूलपुर तहसील में है, के मात्र 82.94 हे क्टेअर भूमि पर वन हैं । सर्वाधिक क्षेत्रपल पर वन अोरिल गांव में हैं ।

वर्तमान दशक में वातावरण संरक्षण अभियान और सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत मानव द्वारा लगाये गये यूकेलिप्टस वृक्षां की प्रधानता है । ये वृक्षा सड़कों के किनारे तथा गाँवों की परती भूमि पर देखे जा सकते हैं ।

2.5 मिट्टी एवं खनिज

अध्ययन प्रदेश के मध्य गंगा द्याटी के गंगा-द्याद्यरा दोआब में स्थित होने के कारण यहाँ की मिद्दी का निर्माण नदियों द्वारा निक्षेपित अत्यन्त नूतन अवसादों से हुआ है। इस प्रकार की मिद्दी में जीवों के अवशेष्ठ अधिक पाये जाते हैं तथा यह मिद्दी बहुत उपजाऊ है। मिद्दी के कण तथा उर्वराशक्ति के आधार पर अध्ययन प्रदेश की मिद्दी को 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है -

- ।. ब्लुई मिट्टी
- 2. ब्लुई दोमट मिट्टी
- मिंद्री
- 4. दोमट मिद्टी
- 5. रेहयुक्त उसर भूमि

प्राय: नदियों के समीपवर्ती भागों में ब्लुई मिट्टी पायी जाती है। इस मिट्टी में बालू के कणों की मात्रा 40 प्रतिशत या इससे अधिक तथा कणों के अपेक्षा कृत बड़े होने के कारण जल ग्रहण करने की क्षामता अधिक होती है। यह मिट्टी मूणफ्ली तथा सकरकन्द की कृष्ण के लिए अधिक उपयुक्त है।

बलुई मिट्टी के समीपवर्ती भागों में बलूई दोमट मिट्टी पायी जाती है। इस मिट्टी में बालू के कण अत्यन्त महीन व सीमित मात्रा में होते हैं। मिट्टी का रंग भूरा व कहीं-कहीं मटमैला होता है। यह मिट्टी गन्ना, अरहर, चना, मटर और गेहूं आदि की कृष्ण के लिए उपयुक्त है।

मिट्यार दोम्ट मिट्टी का विस्तार संकरी पट्टी के स्वार टोर्डिटी के समिता समीपवर्ती भागों में है। मटमैले रंग की इस मिट्टी में जलधारण करने की क्षामता अत्यधिक होती है तथा कृष्टि की दृष्टिट से उपयोगी है।

दोम्ट मिद्दी का निर्माण बालू, 'क्ले' तथा शिल्ट से हुआ है। इस प्रकार की मिद्दी के कण अत्यन्त महीन तथा इनका संगठन अत्यन्त सचन है। हल्के पीले भूरे रंग की इस मिद्दी में जल धारण करने की क्षमता अधिक है। यह मिद्दी धान, गेहूँ तथा गन्ने आदि की कृष्य के लिए काफी उपयुक्त है।

शाहगंज से आजमगढ़ जाने वाली सड़क के दक्षिणी भूभाग में उसर भूमि की अधिकता है। यह मिद्दी स्थान-स्थान पर 'केशिका' क्रिया के कारण क्षार की अधिकता से रेह में परिवर्तित हो गयी है। कृष्णि के दृष्टि कोण से यह मिद्दी अनुप-जाऊ है किन्तु वर्तमान समय में सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग करके मिद्दी को कृष्णि के अनुकूल बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में तहसील की मिद्दियाँ उर्वरता हास की समस्या से ग्रस्त हैं क्यों कि कृष्णि में उपयुक्त पसल चक्र नहीं अपनाया जा रहा है।

अध्ययन प्रदेश में खिनजों का तो पूर्णतया अभाव है। कंक्ड़, रेह तथा बालू को यदि खिनजों की श्रेणी में रखा जाय तो ये कुछ मात्रा में तहसील में उपलब्ध हैं। कंकड़ सामान्य रूप से मार्टिनगंज व पूलपुर विकासखण्डों के उसर क्षेत्रों एवं बंजर भूमि में पाये जाते हैं जिनका उपयोग सड़कों के निर्माण में होता है। उसर क्षेत्रों में रेह की भी प्रधानता है जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में धोबी एवं निम्न वर्ग के लोग कपड़ा धूलने में करते हैं। रेह का प्रयोग सद्दी बनाने और तम्बाकू उद्योग में भी होता है।

मिट्यार दोम्ट मिट्टी का विस्तार संकरी पट्टी के रूप दे हैं के समिता कि समिपवर्ती भागों में है। मटमैले रंग की इस मिट्टी में जलधारण करने की क्षामता अत्यधिक होती है तथा कृष्टि की दृष्टित से उपयोगी है।

दोम्ट मिद्दी का निर्माण बालू, 'क्ले' तथा शिल्ट से हुआ है। इस प्रकार की मिद्दी के कण अत्यन्त महीन तथा इनका संगठन अत्यन्त सद्यन है। हल्के पीले भूरे रंग की इस मिद्दी में जल धारण करने की क्षमता अधिक है। यह मिद्दी धान, गेहूँ तथा गन्ने आदि की कृष्णि के लिए काफी उपयुक्त है।

शाहगंज से आजमगढ़ जाने वाली सड़क के दिक्षणी भूभाग में उसर भूमि की अधिकता है। यह मिद्दी स्थान-स्थान पर 'केशिका' क्रिया के कारण क्षार की अधिकता से रेह में परिवर्तित हो गयी है। कृष्ठि के दृष्टिदकोण से यह मिद्दी अनुप-जाऊ है किन्तु वर्तमान समय में सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग करके मिद्दी को कृष्टि के अनुकूल बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में तहसील की मिद्दियाँ उर्वरता द्वास की समस्या से ग्रस्त हैं क्यों कि कृष्टि में उपयुक्त पसल चक्र नहीं अपनाया जा रहा है।

अध्ययन प्रदेश में खिनिजों का तो पूर्णतया अभाव है। कंक्ड़, रेह तथा बालू को यदि खिनिजों की श्रेणी में रखा जाय तो ये कुछ मात्रा में तहसील में उपलब्ध हैं। कंकड़ सामान्य रूप से मार्टिनगंज व पूलपुर विकासखण्डों के उसर क्षेत्रों एवं बंजर भूमि में पाये जाते हैं जिनका उपयोग सड़कों के निर्माण में होता है। उसर क्षेत्रों में रेह की भी प्रधानता है जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में धोबी एवं निम्न वर्ग के लोग कपड़ा धूलने में करते हैं। रेह का प्रयोग सददी बनाने और तम्बाकू उद्योग में भी होता है।

बालू का उपयोग पक्के मकानों के निर्माण में होता है।

2.6 जनसंख्या प्रतिरूप

पृथ्वी के समस्त भौतिक गुणों एवं उसके स्वरूप को परिवर्तित करने में मानव का अपना विशेष महत्त्व है । मानव एक ऐसा भौगो लिक कारक है जिसके सन्दर्भ में ही दूसरे सभी भौगो लिक तथ्यों का अध्ययन होता है । द्विवार्था (1953) के अनुसार मानव ही अध्ययन का केन्द्र बिन्दु है जिसके माध्यम से अन्य सभी भौगो लिक तत्त्वों का विवेचन किया जाता है तथा उनका अर्थ एवं महत्त्व मानव में ही निहित है । वस्तुत: जनसंख्या, के विभिन्न पहलुओं – विकास, धनत्व, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषतार आदि तथ्यों के विश्लेष्ण से ही किसी क्षेत्र की समस्याओं को जाना जा सकता है तथा उनका निदान एवं समाधान प्रस्तृत किया जा सकता है ।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार तहसील की कुल जनसंख्या 648022 थी जिसमें से वर्तमान बूद्रनप्र तहसील के कोयलसा, अतरौलिया तथा अहरौला(II) विकास खण्डों की जनसंख्या निकाल दी जाय तो वर्तमान पूलपुर की जनसंख्या 362150 होगी जिसमें 98.58 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण एवं 1.42 प्रतिशत नगरीय है ।

(।) जनसंख्या-वृद्धि

जनसंख्या-वृद्धि से तात्पर्य किसी क्षेत्र की पूर्व जनसंख्या की तुलना में बढ़ी हुई वर्तमान जनसंख्या से है । पूर्व जनसंख्या की तुलना में वर्तमान जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई - इसका गणना प्रति दशाब्दी या प्रतिवर्ध की दर से प्रतिशत में करते हैं । जनसंख्या वृद्धि के विश्लेष्ठण द्वारा क्षेत्र की सामान्य मानवीय विशेष्ठाताओं का बोध

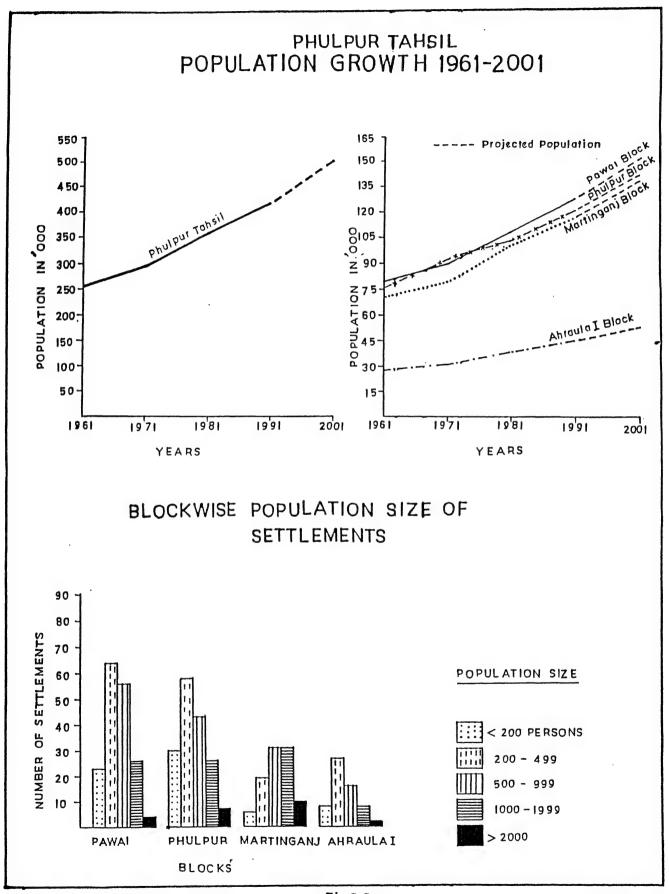


Fig.2·2

होता है। यह किसी क्षेत्र की सामाजिक एवं आधिक दशा को प्रकट करती है। जनसंख्या वृद्धि पर मुख्यतया दो तथ्यों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है -

- (क.) प्राकृतिक वृद्धि
- (छा) आवास-प्रवास

प्राकृतिक वृद्धि का सीधा सम्बन्ध जन्म एवं मृत्यु दर के अनुपात से है जबिक आवास-प्रवास जनसंख्या-स्थानान्तरण को दर्शांते हैं।

सारणी 2.2 से स्पष्ट है कि फूलपूर तहसील में वर्ष 1951 से 1981 तक प्रत्येक दशक में जनसंख्या में लगातार तीव्र वृद्धि हुई है किन्तु तहसील में राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा जनपदीय जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम बृद्धि हुई है । विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण उच्च जनम दर, निम्न मृत्युदर, कृष्टि गहनता, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के फ्लस्वरूप संक्रामक एवं असाध्य बीमारियों पर नियन्त्रण है ।

स्पष्ट है कि वर्ष 1961-1971 के दशक में पुरकों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में कम वृद्धि हुई है। वर्ष 1971-1981 के दशक में पुरकों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। यह इस बात का द्योतक है कि जी विका अर्जन एवं नौकरी आदि के लिए बड़ी मात्रा में पुरकों का बाह्य स्थाना न्तरण हुआ है जो अध्ययन प्रदेश की जीर्ण अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

विकातेखण्ड स्तर पर वर्ष 1961 की तुनना में वर्ष 1971 में सबसे तीव्र

सारणी 2.2

फूलपुर तहसील में जनसंख्या वृद्धि, 1951-81

 	विका सखण्ड 	क्रन जैनसङ्घा 1951	ਜ਼ੁੰਗ ਯੋਜਸੁਣਧਾ 1961	पुरस	महिला	क्ल जैनसङ्घा 197 ।	पुरस्र	महिला	क्ल अनुसङ्घा 198 ।	ন ধ্ৰ	महिला
1											
·	पवडी	i	79022	38778	40544	91103	45614 (17.63)	45849 (13.03)	110683 (22.49)	54922 (20.41)	55761 (22.58)
5	मूनपुर सन्तर्भ	i	76877	37047	39830	92727 (20.61)	45849 (22.79)	47238 (18.60)	104186 (12.36)	50456 (10.92)	53730 (13.74)
ĕ.	मा टिनगंज	ı	71350	33444	37906	80242 (12.46)	38411 (14.85)	41831 (10.35)	102485 48696 (27.71) (26.78)	48696 (26.78)	53789 (28.59)
÷	अहरौला(1)	ı	27912	13716	96141	32349 (15.90)	16048 (17.00)	16301	39660 19632 (22.60) (22.33)	19632 (22.33)	20028 (22.86)
i	तहसील फूनपुर	ħ0£ħ0ħ	255161	122985	132176	296421	145562 (18.36)	150859	362150 176304 (22.17) (21.12)	176304 (21.12)	158846 (23.19)
	अन्यमगढ्ड जनपद	2106557 (15.33)	2408052	1185008	1223044	2857484 (18.66)	1431267 (20.78)	(16.61)	1426217 3544130 1753826 (16.61) (24.03) (22.54)	753826 22.54) (1790304
i	उत्तर प्रदेश							11086	110862013 58819276 683997512 353502987		52042737
i					1						* 42 43 45 46 46 40 43 64

म्रोत : ।. जिला जनगणना हरतपुरितका, आजमगढ भाग 📶 छ, १९६१, १९७१, १९८१

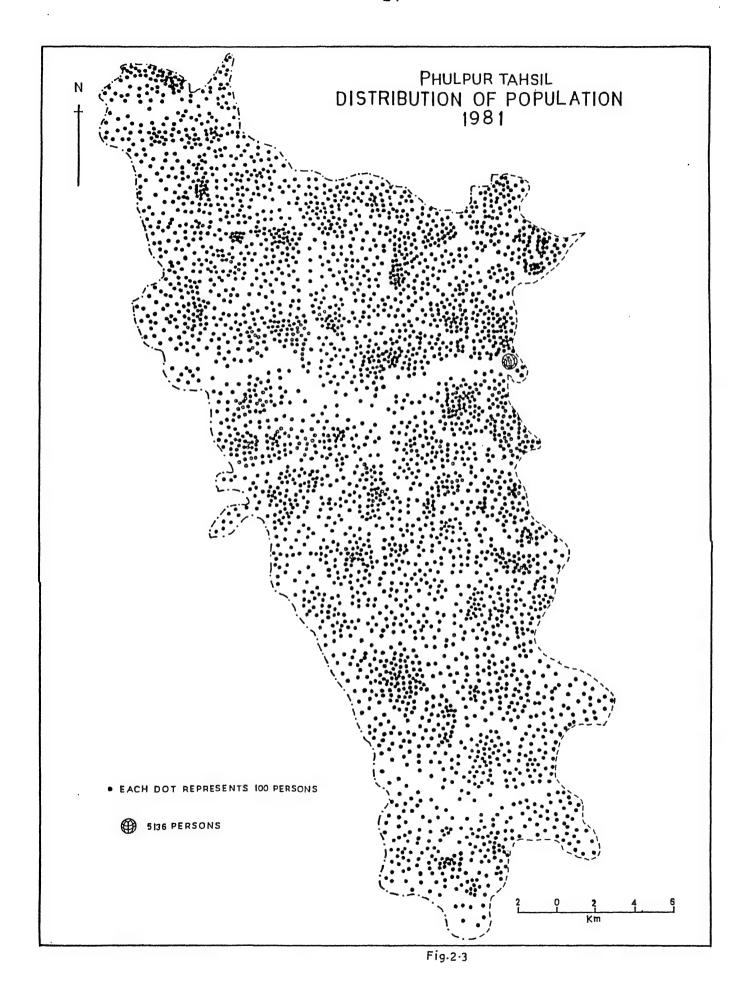
2. डिस्टिक्ट गजेटियर, जनपद आजमण्ड

टिप्पणी : कोठठक की संख्यारें प्रति हशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दशांती हैं

जनसंख्या वृद्धि दर पूलपुर विकासखण्ड में रही जो 20.6। प्रतिशत थी जबिक सबसे कम वृद्धि दर 15.29 प्रतिशत पवर्ड विकासखण्ड में रही । वर्ष 1971-8। के दशक में विकासखण्ड स्तर पर सबसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर 27.2। प्रतिशत मार्टिनगंज में और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर 12.36 प्रतिशत पूलपुर में रही । सामान्य रूप से प्राकृतिक वृद्धि दर का जनसंख्या-विकास पर विशेष्ठ प्रभाव रहा है।

(2) जनसंख्या वितरण

जनसंख्या वितरण किसी क्षेत्र विशेष्ठा के प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों के सन्दर्भ में होता है। पर्यावरणीय परिस्थितियां जनसंख्या वितरण प्रतिह्मप पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं जबिक प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या के स्थानिक वितरण को अधिक प्रभावित करते हैं। तदनुसार जनसंख्या वितरण का क्षेत्रीय प्रतिह्म विकीण, केन्द्रक या पुञ्जीभूत आदि हो सकता है। जनसंख्या वितरण को क्षेत्रीय वितरण को प्रदर्शित करने की अनेक विधियां हैं जिसमें भूगोलविद सांख्यिकीय विधि का अधिक प्रयोग करते हैं। पूलपुर तहसील में जनसंख्या वितरण का क्षेत्रीय प्रतिह्म ज्ञात करने के लिए विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या की गणना की गयी है। सारणी 2.2 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक जनसंख्या ।10683 पवर्ड विकासखण्ड की है जो तहसील की कुल जनसंख्या का 30.56 प्रतिप्रात है। सबसे कम जनसंख्या 39660 अहरौला(I) विकासखण्ड की है जो कुल जनसंख्या का 10.95 प्रतिप्रात है। पूलपुर तथा मार्टिनगंज विकासखण्डों की जनसंख्या तहसील की कुल जनसंख्या का क्रमण: 28.77 तथा 28.30 प्रतिप्रात है। तहसील में जनसंख्या का वितरण चित्र संख्या 2.3 में दिखाया गया है।



कृषि प्रादेशिक अर्थंट्यवस्था की मेरदण्ड है, इस लिए कृषि को प्रभावित करने वाले घटकों का जनसंख्या वितरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है । कृषि-योग्य भूमि की उपलब्धता, मिद्दी की उर्वरता तथा गहनता, भूमिगत जल-तल, सिंचाई-हेतु जल की उपलब्धता आदि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण घटक हैं। तहसील में अभी तक किसी स्तर की कोई नगरीय औद्योगिक प्रगति नहीं हुई है। फलत: हाल में जनसंख्या वितरण की जो नवीन प्रवृत्तियाँ दृष्टिटगत हुई हैं वे भी जन-संख्या वितरण को प्रभावित करने वाले इन घटकों की संपुष्टिट करती हैं।

तहसील में 1981 की जनगणना के अनुसार न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या वितरण जनसंख्या आकार वर्ग के आधार पर निम्न है -

जनसंख्या आकार वर्ग	 न्याय पंचायत
(क.) 14000 से अधिक	माहुल (अहरौलाम विकासखण्ड)
(खः) 12000 से 14000	सुरहन (मार्टिनगंज विकासखण्ड)
(ग.) 10000 से 12000	मिन्तूपुर, सत्तारपुर रज्जाकपुर, साद्गलाहपुर, मैगना,
	बाग तिकन्दरपुर, अम्बारी (पवर्ड विकासखण्ड) सजर्ड
	अमानबाद, राजापुर (पूनपुर विकासखण्ड) कौरागहनी,
	छितर अहमदपुर, जगदीशपुर ददेरिया, नप्तरा खुर्द, बेन-
	वाना (मार्टिनगंज विकासखण्ड)

जनसंख्या आकार वर्ग

न्याय पंचायत

(६६) ८००० से 10000

शास्त्राबाद (अहरौला I विकासखण्ड) रामनगर, सुम्हा-डीह, बस्ती सदनपुर (पवर्ड विकासखण्ड) खंग्रहापुर, सदरपुर बरौली, कनेरी, गद्दोपुर बारी, पल्थी दुल्हापुर, खरसहन कला, पुकवाल (फूलपुर विकासखण्ड) सिकरौर, फुलेश अहमद बका, कुरुथुवा (मार्टिनगंज विकासखण्ड)

(इ.) 8000 से कम

पारा मिश्रौ लिया, गनवारा (अहरौला I विकासखण्ड) दोस्तपुर लहुरमप्र, सुल्तानपुर, सौदमा धानेशवर, पदगुड़िया (पवर्ड विकासखण्ड) बक्सपुर मेजवा, महुआरा, नोनियाडीह (पूलपुर विकासखण्ड) कस्बा पतेहपुर (मार्टिनगंज विकासखण्ड)।

(3.) जनसंख्या धनत्व

जनसंख्या द्यात्व जनसंख्या प्रतिरूप का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। किसी प्रदेश में प्रति इकाई पर जनसंख्या का कितना दबाव पड़ रहा है, इसका सम्यक् विश्लेषण जनसंख्या द्यात्व के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। जनसंख्या द्यात्व धरातल पर औसत जनसंख्या वितरण को दर्शाता है। जनसंख्या द्यात्व पर क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों जैसे मिद्दी, वर्षा, जलवायु तथा आर्थिक संसाधनों का विशेष्ठ प्रभाव परिलक्षित होता है। जनसंख्या धनत्व किसी क्षेत्र में जनसंख्या की केन्द्रीयता को मापने की एक विधि है।

सारणी 2.3 पूलपुर तहसील में विभिन्न प्रकार के जनसंख्या धनत्वों की तुलना

(धनत्व/कि0मी 02) गणितीय का यिक कृष्टि पोषण धनत्व धनत्व धनत्व धनत्व स्तरीयमान को दि 534.72 756.76 200.08 1095.65 पवर्ड 10 2 स्तरीयमा न 3 2 2 3 551.59 750.30 172.81 1177.51 पूलपुर 2. 2 3 3 2 10 स्तरीयमान 435.38 598.91 143.37 874.67 मा दिनगंज 3. 3 16 स्तरीयमान अहरौल Т(1) 646. 35 835. 83 200. 17 1204. 37 स्तरीयमान पूनपुर तहसील 516.18 718.99 175.19 1066.40

स्रोत: (I) जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, प्राथमिक जनगणना सार, आजमगढ़, भाग <u>प्रा</u> B, 1981.

तां खियकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1981.

^{(3.} वार्षिक मण योजना, जनपद आजमगढ़, 1991.

(क) गणितीय धनत्व

गणितीय जनसंख्या धनत्व किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उसके कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात का द्योतक है। तहसील का औसत गणितीय धनत्व 516.18 व्यक्ति/कि०मी०² है। तहसील के अहरौला(1) विकासखण्ड में 646.35 व्यक्ति/कि०मी०² उच्च गणितीय धनत्व पाया जाता है जिसका कारण उच्च जनमदर, निम्न मृत्युदर एवं स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसार है। सबसे न्यून गणितीय धनत्व मार्खिनगंज विकासखण्ड में 435.38 व्यक्ति/कि०मी०² है जिसका कारण उसर भूमि का अधिक होना एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है (चित्र संख्या 2.4)।

(ख) का यिक धनत्व

कायिक धनत्व प्रति इकाई कृष्णि की जाने वाली भूमि पर सम्पूर्ण जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। तहसील का औसत कायिक धनत्व 718.99 व्यक्ति/
किंगि02 है। अहरौला(1) विकासखण्ड में उच्चतम कायिक धनत्व 835.83 व्यक्ति/
किंगि02 है। इसका कारण कृष्णि भूमि की अपेक्षाकृत कमी एवं जनसंख्या का अधिक होना है। न्यूनतम कायिक धनत्व 598.9। व्यक्ति/किंगि02 मार्टिनगंज विकास खण्ड में है। यहाँ पर कायिक धनत्व के कम होने का कारण कृष्णि योग्य भूमि की कमी एवं जनसंख्या का विरल होना है। पवई तथा पूलपुर विकासखण्डों का कायिक धनत्व कम्माः 756.76 तथा 750.30 व्यक्ति/किंगि02 है।

(ग.) कृषि धनत्व

कृषि धनत्व कृषि कार्य में संनग्न जनसंख्या तथा कृषि में प्रयुक्त क्षेत्रपल के

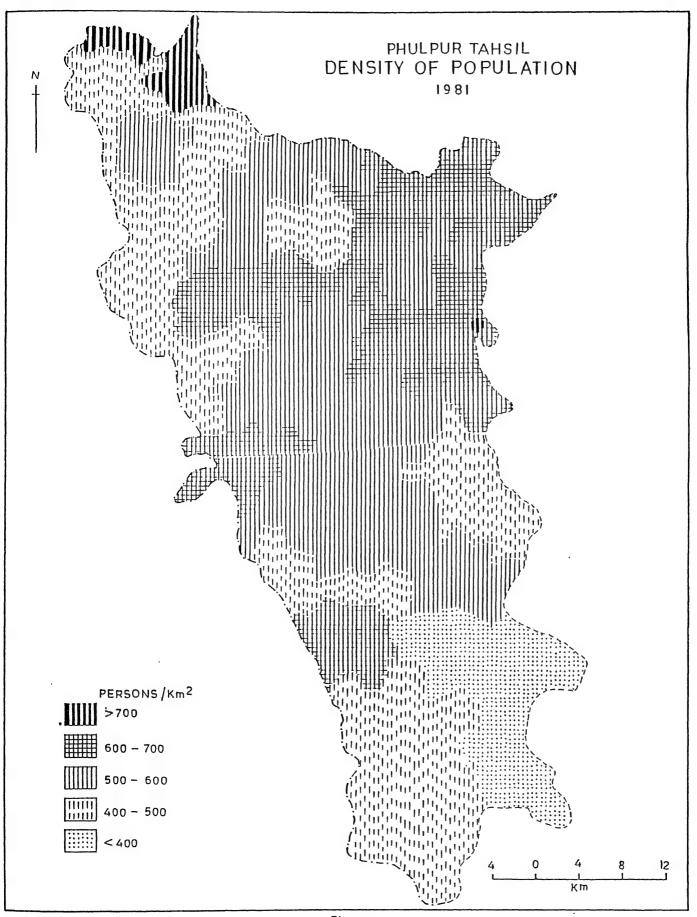


Fig.2.4

अनुपात का योतक है। तहसील का औसत कृष्य झनत्व 175. 19 व्यक्ति/कि०मी०² है। उच्च कृष्य धनत्व अहरौला(I) विकासखण्ड में 200. 17 व्यक्ति/कि०मी०² है। यहाँ पर कृष्य धनत्व अधिक होने का कारण कृष्य भूमि का कम होना एवं कृष्य में संलंग्न जनसंख्या का अधिक होना है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयाँ बहुत ही कम हैं, अधिकांश जनसंख्या कृष्य पर ही आश्रित है। सबसे कम कृष्य धनत्व 143.37 व्यक्ति/कि०मी०² मार्टिनगंज विकासखण्ड का है। यहाँ पर कृष्य धनत्व कम होने का कारण जनसंख्या का न्यून होना तथा कृष्य क्षेत्र का अधिक होना है। अन्य विकासखण्डों – पवई तथा पूलपुर का कृष्य धनत्व क्रमा: 200.08 तथा

(दा) पोषण दानत्व

पोषण धनत्व सम्पूर्ण जनसंख्या एवं खाद्यान्न में प्रयुक्त भूमि के अनुपात का द्योतक है। तहसील का औसत पोषण धनत्व 1066. 40 व्यक्ति/कि0मी0² है। तहसील में उच्चतम पोषण धनत्व 1204. 37 व्यक्ति/कि0मी0² अहरौला(I) विकासखण्ड में पाया जाता है। इसका कारण जनसंख्या की अधिकता एवं खाद्यान्न उत्पादन में संलग्न भूमि की कमी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्रपल पर जनसंख्या की निभैरता अधिक है। न्यूनतम पोषण धनत्व 874. 67 मार्टिनगंज विकासखण्ड में है। फूनपुर तथा पवई विकासखण्डों का पोषण धनत्व क्रम्झा: 1177. 51 तथा 1095. 65 व्यक्ति/कि0मी0² है।

सारणी 2.3 में विभिन्न धनत्वों की गणना की गयी है जिसमें विकासखण्डों

के प्रत्येक धनत्व को स्तरीयमान दिया गया है। पुन: इन स्तरीयमानों का योग करके उनका को टिक्रम निधारित किया गया है। को टिक्रम के आधार पर अध्ययन प्रदेश को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है -

उच्च धनत्व

अध्ययन प्रदेश में उच्च धनत्व अहरौला (1) विकासखण्ड में पाया जाता है ।

मध्यम धनत्व

इस वर्ग के अन्तर्गत को टिक्रम गणना के आधार पर पवर्ड तथा पूनपुर विकास खण्ड आते हैं क्यों कि इन विकासखण्डों के विभिन्न धनत्वों के स्तरीयमान का योग 10 है तथा इन विकासखण्डों के स्तरीयमान द्वितीय तथा वृतीय क्रम के हैं।

निम्न धनत्व

अध्ययन प्रदेश में निम्न धनत्व मार्टिनगंज विकासखण्ड में पाया जाता है।
मार्टिनगंज विकासखण्ड में जनसंख्या धनत्व कम होने का कारण क्षेत्र का अनुपजाऊ
मिद्री उसर तथा बंजर भूमि की अधिकता तथा सिंचाई के साधनों में कमी का
होना है।

(4) जनसंख्या संरचना

जनसंख्या की भौतिक विशेष्ठाताओं में लिंगानुपात सर्वप्रमुख है। इसके माध्यम से किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में स्त्री-पुरुष्ठा अनुपात ज्ञात किया जाता है। लिंगानुपात में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार तहसील का औसत लिंगानुपात 1085 था जो आजमगढ़ (1031) तथा उत्तर प्रदेश राज्य (885) के लिंगानुपात से अधिक है। तहसील के नगरीय क्षेत्र में यह लिंगानुपात मात्र 977 है। विकासखण्ड स्तर पर सबसे अधिक लिंगानुपात मार्टिनगंज में 1105 था जबिक सबसे कम पवर्ड में मात्र 1015 था। अन्य विकासखण्डों फूलपुर तथा अहरौलाता)का लिंगानुपात क्रम्सा: 1065 तथा 1020 था। लिंगानुपात के विक्रलेखण से स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक है। क्षेत्र के दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत कम उपजाऊ और उत्तर भूमि की अधिकता के कारण जीविकोपार्जन हेतु पुरुष्ठ वर्ग का स्थानान्तरण कलकत्ता एवं मुम्बई जैसे महानगरियों में अधिक हुआ है।

किसी भी प्रदेश का तामाजिक एवं आर्थिक विकास उस क्षेत्र की जाति संरचना पर निर्भर करता है। व्यावसायिक संरचना में अनुसूचित जातियों का विशेष महत्त्व है। तहसील की कुल जनसंख्या का 22.90 प्रतिवात भाग अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत है जिनमें 47.07 प्रतिवात पुरुष्य तथा 52.53 प्रतिवात महिलाएँ हैं। अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक प्रतिवात पवर्ड विकासखण्ड में पाया जाता है जो विकासखण्ड की कुल जनसंख्या का 24.52 प्रतिवात हैं। इनमें 48.38 प्रतिवात पुरुष्य तथा 51.62 प्रतिवात महिलाएँ हैं। अनुसूचित जातियों का सबसे कम प्रतिवात पुरुष्य तथा 51.62 प्रतिवात महिलाएँ हैं। अनुसूचित जातियों का सबसे कम प्रतिवात (21.59) अहरौला(L)विकास-खण्ड में है जिनमें पुरुष्यों तथा महिलाओं का प्रतिवात क्रम्बा: 48.04 तथा 51.96 है। पूलपुर तथा मार्टिनगंज विकासखण्डों में अनुसूचित जातियों का कुल जनसंख्या में प्रतिवात क्रम्बा: 22.53 तथा 22.05 है। सारणी 2.4 से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों में

स्त्रियों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। इसका प्रमुख कारण नौकरी की तलाश में पुरुष वर्ग का क्षेत्र के बाहरी प्रदेशों में प्रवास आदि है।

सारणी 2.4

		पूलपुर तह	सील में जन	संख्या की	संशिलष्ट स	रचना, 198	
							(प्रतिशत में)
den dett	विवरण		अहरौन FI विकास- खण्ड	पवडी विकास- खण्ड	मुनपर विकास- खण्ड	मा टिनर्ग्न विकास- खण्ड	तहसील फूलपुर
1.	अनुसू चित	जाति	21.59	24. 52	22. 53	22. 05	22.90
	पुरम		48.04	48.38	46.32	45.95	47.07
	महिला		51.96	51.62	53. 68	54. 05	52.93
2.	साक्षरता		22.09	22.68	23. 29	20. 42	22. 16
	पुरद्य		78.58	77. 45	75.00	76. 42	76. 53
	महिला		21.42	22.55	25.00	23.58	23. 47
3.	जनसंख्या	ग्रामीण	100.00	100.00	95.30	100.00	98.58
	जनसंख्या	नगरीय	-	-	4.70	-	1. 42
4.	लिंगा नुपा	त प्रतिहर	TT 1020	1015	1065	1105	1085
	लिंगानुपा	त प्रतिहर	नार पूनपुर	नगरीय क्षे	1		977

म्रोत: जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, आजमगढ़, भागप्रा 3 - 1981 से संगणित।
साक्षारतो के माध्यम से किसी भी प्रदेश के विकास के स्तर को निर्धारित

किया जा सकता है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार तहसील में कुल 22.16

प्रतिप्रात जनसंख्या साक्षर थी जिनमें 76.53 प्रतिप्रात पुरुष्ठ तथा 23.47 प्रतिप्रात महिलाएँ थी। साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिप्रात पवर्ज विकासखण्ड 22.68 में है जिसमें

पुरुष्ठों तथा स्त्रियों का प्रतिप्रात क्रम्पा: 77.45 तथा 22.55 है। सब्से कम साक्षरता

20.42 प्रतिप्रात मार्टिनगंज विकासखण्ड में है जिसमें पुरुष्ठों तथा महिलाओं का प्रतिप्रात

क्रम्प्रा: 76.42 तथा 23.58 है। देश के अन्य भागों की तरह अध्ययन प्रदेश में भी

साक्षरता का प्रतिप्रात महिलाओं की तुलना में पुरुष्ठों में अधिक है।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार वर्तमान तहसील की कुल जनसंख्या
362150 है जिसमें 98.58 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण तथा 1.42 प्रतिशत नगरीय है ।
नगरीय जनसंख्या के इस प्रतिशत का प्रतिनिधित्व मात्र पूलपुर करबा करता है ।
इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र में नगरीकरण एवं औद्योगीकरण की गति
काफी धीमी है और पूरा प्रदेश कृष्टा व्यवस्था पर आधारित मात्र ग्रामीण अंचल है।

किसी प्रदेश के अध्ययन में वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या की व्याव-सायिक संरचना का विशेष्ठा महत्त्व है। इससे अध्ययन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सही इलक प्राप्त होती है। व्यावसायिक संरचना की दृष्टिद से तहसील की कुल जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या तथा अकार्यशील जनसंख्या (Non Workers) में विभक्त किया गया है। तहसील में इनका प्रतिशत क्रम्श: 36.37 तथा 63.63 है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 65.09 प्रतिशत पुरुष्ठा तथा 34.9। प्रतिशत महिलाएँ हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या को पुनं: दो भागों - मुख्य कार्यशील जनसंख्या तथा सीमान्त कार्यशील

सारणी 2.5 पूनपुर तहसील में जनसंख्या की ट्यावसायिक संरचना, 1981

				ny dagai dalah pada Mena dilah selah Siling (
विव रण	अहरौन १८८)	पवर्ड	फूनपुर	मा टिनगज	तहमील
	विकासखण्ड	विकासखण्ड	विकासखण्ड	विकासङ्गड	फूलपूर
1	2	3	4	5	6
।. कुल कार्यशील जनसंख्या	15814	38986	37944	38972	131716
	(39.87)	(35.22)	(34.71)	(38.03)	(36.37)
पुरम्ब	10051	2681 2	25349	23528	85740
	(63.56)	(68.77)	(66.81)	(60.37)	(65.09)
महिला	5763	12174	12595	15444	45976
	(36.44)	(31.23)	(33.19)	(39.63)	(34.91)
(I) मुख्य कार्यशील जनसंख्या	11739	31820	27621	26264	97444
	(74.23)	(81.62)	(72.79)	(67.39)	(73 . 98)
पुरम	9404	25641	23708	21607	80360
	(80.11)	(80.58)	(85.83)	(82.27)	(82.47)
महिला	2335	6179	3913	4657	17084
	(19.89)	(19.42)	(14.17)	(17.73)	(17.53)
(कः) खेतिहर कृष्टाक	7886	24596	20725	20613	73820
	(67.18)	(77.30)	(75.03)	(78.48)	(75.76)
पुरस्य	6964	20474	18523	18184	64145
	(88.31)	(83.24)	(89.38)	(88.22)	(86.89)
महिला	922	4122	2202	2429	9675
	(11.69)	(16.76)	(10.62)	(11.78)	(13.11)
(⁽ ख.) खेतिहर मजदूर	2561 (21.82)	4667 (14.67)	3385 (12.26)	39 20 (14.93)	-
पुरवा	1341 (52.36)	2880 (61.71)	2006 (59.26)		
महिला	1220 (47.64)	1787 (38.29)	1379 (40.74)	1932 (49.29)	6318

	2	3	Ц	5	6
(गः) कुटीर एवं गृह- उद्योग में संलग्न	210 (1.79)	583 (1.83)	480 (1.74)	410 (1.56)	1683 (1.73)
पुरव	184 (87.62)	461 (79.07)			
महिला	26 (12.38)	122 (10.93)		197 (48.05)	
(घः) अन्य कायों में संलग्न		1974 (6.20)			
पुरस्व	915 (84.5 7)	1826 (92.50)			
महिला		148 (7.50)			644 (8.69)
(II) सीमान्त कार्यशील जनसंख्या		7166 (18.38)			
पुरद्य	647 (15.88)	1171 (16.34)	1641 (15.90)		5380 (15.70)
महिला		599 5 (83.66)			
2. अकार्यशील जनसंख्या	23846 (60.13)	71697 (64.78)	713 7 8 (65.29)		230434 (63.63)
पुरदा	9581 (40.18)	28110 (39.21)		25168 (39.63)	
महिला		43587 (60.79)			139870 (60.69)

होत: जिला जैनगणना हस्तपुरितका, आजमगढ़, भाग XIII ७, १९८१ से संगणित। टिप्पणी: कोष्ठक की संख्यार प्रतिशत दशांती हैं। जनसंख्या (Marginal Workers) में बाँटा गया है। इनका प्रतिशत क्रमा: 73.98 तथा 26.02 है। मूख्य कार्यशील जनसंख्या को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है -

- (क) ढोतिहर कृष्ठाक,
- (ख) छेतिहर मजदूर,
- (ग) कुटीर एवं गृह उद्योग में तंनगन
- (घ) अन्य कार्यों में तंनगन

मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 75.76 प्रतिष्ठात खेतिहर कृष्ठिक और 14.9। प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं, जबिक 1.73 प्रतिशत जनसंख्या कुटीर एवं गृह उद्योग तथा 7.60
प्रतिशत अन्य कार्यों में लगी हुई है । अध्ययन प्रदेश में सीमान्त कार्यशील जनसंख्या
तथा अकार्यशील जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी पुरुष्ठों की तुलना में अधिक है
जबिक कुल कार्यशील जनसंख्या तथा मुख्य कार्यशील जनसंख्या में पुरुष्ठों की भागीदारी
महिलाओं से अधिक है (देखिये सारणी 2.5) । समाज के निम्न वर्ग में महिलाएं
अपने घरेलू कार्यों के बाद अतिरिक्त समय में पूरक आय जुटाने के लिए कृष्ठा के विभिन्न
क्षेत्रों में कार्य करती हैं और पुरुष्ठों की अपेक्षा उन्हें कम मजदूरी दी जाती है ।

2.7 बस्ती प्रतिरूप

धरातल पर बहितयां मानवीय समूहों एवं उनके कायों की हथानिक अभि-ट्यिक्त हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में विकसित मानव की ये प्रथम मौलिक रचनाएँ हैं। अधिवास एक अवस्थिति है जो पृथ्वी पर निश्चित स्थान ग्रहण करती है तथा स्थान के साथ इसका एक निश्चित सम्बन्ध होता है। विविध भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों के अधिवासों में विवि-धता एवं विभिन्नता मिनती है किन्तु कुछ सामान्य विशेष्ट्राताओं जैसे बहित्यों का आकार, अन्तरण तथा गहनता आदि के परिप्रेक्ष्य में उनका सिम्मिन्त अध्ययन किया जाता रहा है। अध्ययन प्रदेश की समस्त जनसंख्या विभिन्न आकार की मानवीय बिस्तियों में निवास करती हैं। इनमें कुछ बहित्यां बहुत छोटे आकार, कुछ मध्यम आकार, कुछ दीर्ध तथा कुछ बृहदाकार की हैं। कार्यों की प्रकृति एवं आकार के आधार पर बहित्यों को ग्रामीण तथा नगरीय दो भागों में विभक्त किया जा सकता है -

(।) ग्रामीण बहितयाँ

पूलपुर तहतील को जनसंख्या की दृष्टि से नितान्त ग्रामीण कहा जा सकता है क्यों कि यहाँ की कुल जनसंख्या का 98.58 प्रतिग्रात भाग क्षेत्र में विस्तीण विभिन्न आकार की 495 ग्रामीण बस्तियों में निवास करता है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण अध्ययन प्रदेश में इन बस्तियों का प्रतिरूप संहत प्रकार का है। औसतन प्रति बस्ती में 680 व्यक्ति निवास करते हैं जबकि प्रत्येक बस्ती द्वारा आवृत्त क्षेत्र का औसत मात्र 1.32 वर्ग किंठमीं है। प्रदेश में 235 लघु आकार की बस्तियाँ हैं जिनकी जनसंख्या 500 से कम है। इनमें 67 अत्यन्त लघु आकार की बस्तियाँ समाहित हैं जिनकी जनसंख्या 200 से भी कम है (चित्र संख्या 2.5)।

मध्यम आकार की बहितयों की संख्या 146 है जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक किन्तु 1000 से कम है। दीर्घ आकार की बहितयों की संख्या 91 है जिनकी जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच है। बृहदाकार बहितयों की संख्या मात्र 23 है,

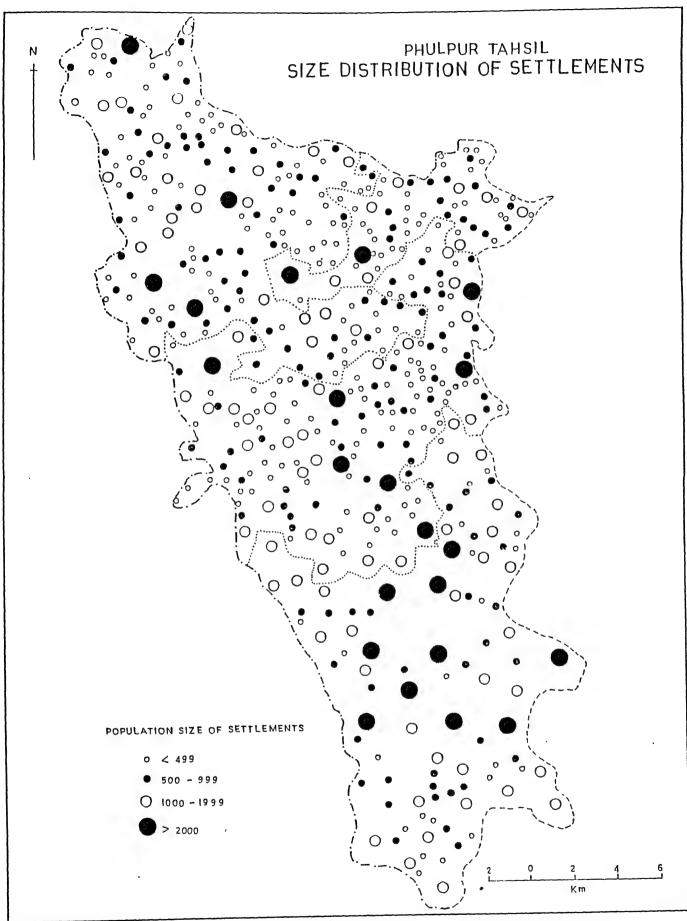


Fig.2.5

जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है। सामान्य तौर पर बहितयों का यह आकार परिवहन जाल की उपलब्धता से प्रभावित है।

सारणी 2.6 पूनपुर तहसील में ग्राम आकार वर्ग, 1981

gen des	विकासहण्ड	200 से कम जनसङ्घा वाले ग्राम (अत्यन्त लधु आकार)	200 से 499 तक(नद्ध आकार्य	500 से 999 तक (मध्यम अएकार)	1000 में 1999 तक (दोई अरक्टर)	2000 से अधिक (बृहदाकार)	क्ल ग्राम संख्या
1.	पवर्इ	23	64	56	26	4	173
2.	पूनपुर	30	58	43	26	7	164
3.	मा टिनगंज	6	19	31	31	10	97
4.	अहरौला I	8	27	16	8	2	61
-							
	पूनपुर तहसील	67	168	146	91	23	495

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, आजमगढ़, 1990.

' (कः) <u>बस्तियों की सद्यनता</u>

बस्तियों के अवस्थापन को बस्तियों की सद्यनता द्वारा और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। बस्तियों की सद्यनता का तात्पर्य प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रपल पर विस्तृत बस्तियों की संख्या से है। प्रति 100 वर्ग कि0मी0 में बस्तियों की संख्या से है। प्रति 100 वर्ग कि0मी0 में बस्तियों की संख्या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की गयी है -

$$AV = \frac{TW}{A}$$

AV = औतत गाँवों की संख्या प्रति 100 वर्ग किं0मीo

Tw = कुल गाँवों की संख्या

A = पूरे प्रदेश का क्षेत्रफ्ल

अध्ययन प्रदेश में 100 वर्ग कि0मी0 हेन्न में गाँवों की संख्या ज्ञात करने पर औसत रूप से 76 गाँव आते हैं (सारणी 2.7) । विकासखण्ड स्तर पर अध्ययन

सारणी 2.7 पूलपुर तहसील में गाँवों की सधनता एवं अन्तरण, 1981

	<u>विकासखण्ड</u>	प्रति गाँव जनप्तक्याः भार	प्रति १०० वर्ग किएमी० मे गावा की सहनता	प्रति गाँव का ऑसत क्षेत्रफ (क्लिमी०) ²	बहितयोँ का अन्तरण (कि०मी०)
1.	पवर्ड पूलपुर	612 592	87. 0 93. 0	1.14	1. 15
3. 4.	मार्टिनगंज अहरौलार	985 620	44. 0 104. 0	2. 26 0. 96	1. 62
	पूनपुर तहसील	680	76.0	1.32	1. 23

म्रोत: सां खियकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1990 से संगणित।

करने पर ज्ञात होता है कि सबसे अधिक गाँव अहरौला(1) विकासखण्ड में हैं जहाँ पर 104 गाँव प्रति 100 वर्ग कि0मी0 का औसत आता है जबिक सबसे कम 44 गाँव प्रति 100 वर्ग कि0मी0 का औसत मार्टिनगंज विकासखण्ड का है जिसका प्रमुख कारण गाँवों का दूर दूर स्थित होना है। भूमि की अनुवंरता, उसर एवं बंजर भूमि की अधिकता सिंचाई साधनों का अल्प होना भी काफी हद तक इसको प्रभावित करता है।

(छा) बहितयों का अन्तरण

गाँवों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप के सन्दर्भ में ग्रामीण बस्तियों का अन्तर-रण एक सार्थक तत्त्व है । मात्रात्मक अभिव्यक्ति और सैद्धान्तिक विवेचन में भी इसका विशेष्ठा महत्त्व है । अन्तरण की उपयोगिता एक सीमा तक प्रादेशिक विकास नियोजन के सन्दर्भ में भी है । उपयोगी अवसंखना (Infrastructure) उपलब्ध कराने तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं और सेवा केन्द्रों के निधारण एवं नियो-जन के सम्बन्ध में बस्तियों के अन्तरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । 6

ग्रामों का सैद्धान्तिक अन्तरण ग्रामीण बहितयों के प्रति इकाई धनत्व पर आधारित होता है। सर्वप्रथम 1940 में राविन्तन और वारनेत महोदय ने अधि-वातों के क्षेत्रीय प्रतिरूप की प्रवृत्ति एवं प्रकृति को मापने का प्रयत्न किया। राज-स्थान के ग्रामीण अधिवातों के अन्तरण में डाँ० ए०वी० मुख्जिं ने भी राविन्तन एवं वारनेत द्वारा प्रतिपादित सूत्र को कितपय तंशोधनों के साथ अपनाया। सन् 1944 में ईं०ती० माथर ने एक और उपयोगी सूत्र का प्रतिपादन किया जित्रका उपयोग भारत के विभिन्न शोधकत्तां औं ने किया। बहितयों का अन्तरण डाँ० माथर द्वारा

प्रतिपादित सूत्र से निकाला गया है। सूत्र निम्न है -

 $Hd = 1.0746 \sqrt{A/N}$

Ha = सैद्धान्तिक अन्तरण

A = प्रदेश का क्षेत्रपल

N = बस्तियों की संख्या

बस्तियों की सधनता एवं अन्तरण में विपरीत सम्बन्ध होता है। यदि सधनता कम है तो अन्तरण बद्धता है और यदि सधनता बद्धती है तो अन्तरण कम हो जाता है।

बह्तियों की सद्यनता एवं अन्तरण के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि तहसील में ग्रामीण अधिवासों का वितरण लगभग समान है। यह समान वितरण प्रतिरूप क्षेत्र की समतल मैदानी प्रकृति, मिद्दी की उर्वरता, जलापूर्ति एवं परिवहन के साधनों की उपलब्धता का परिचायक है। वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक एवं सांस्कृतिक कारक मुख्य हैं। कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारक बह्तियों के जातिगत बसाव की व्यवस्था को भी निधारित करते हैं।

(2) नगरीय बस्तियाँ व

पूलपुर तहसील में नगरीयकरण का स्तर बहुत ही कम है। तहसील में पूलपुर कस्बा ही एकमात्र नगरीय क्षेत्र है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार तहसील की मात्र 1.42 प्रतिश्वेत जनसंख्या नगरीय थी जो पूलपुर टाउन एरिया में सक्रेन्द्रित थी। पूलपुर टाउन का क्षेत्रपल 8.98 वर्ग कि0मी0 है जिसमें 603 आवासीय मकान स्थित हैं और कल जनसंख्या 5136 है।

सन्दर्भ

- Census of India, District Census Hand Book, Primary Census Abstract, Part XIII-B, District Azamgarh, 1981.
- Singh, R.L.: India A Regional Geography, N.G.S.I., Varanasi, 1991, p. 190.
- Singh, Balwant: Uttar Pradesh District Gazetteer, Azamgarh, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, 1971, p.6.
- 4. Ibid, p. 4.
- 5. Hagget, P. : Locational Analysis in Human Geography, Arnold London, 1979, p. 50.
- 6. Mukerjee A.B.: Spacing of Villages in Upper Ganga Yamuna Doab, 1974, p. 22.
- 7. Robbinson A.H. & Barnes J.A.: A New Method for the

 Representation of Dispersed Rural Population, Geographical Review 30, 1940,

 pp. 134-137.
- 8. Mukerjee, A.B.: Spacing of Rural Settlements in Rajasthan:
 A Spatial Analysis, Geographical Outlook,
 Agra-1970, pp. 1-20.
- 9. Mathur, E.C.: A Linear Distance Map of Farm Population in United States, A.A.A.G., Vol. xxxiv, 1944, pp. 173-180.

अध्याय तीन

बिस्तयों का स्थानिक-कार्यात्मक संगठन एवं नियोजन

उ.। प्रस्तावना

विकसित एवं अविकसित प्रदेशों में ट्या एत प्रादेशिक असंतुलन को समा एत करने के उद्देश्य से विभिन्न आकार की विकासात्मक नीतियों का प्रस्ताव समय-समय पर सरकार द्वारा किया जाता रहा है। फिर भी नगरों एवं गाँवों के मध्य क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के प्रयासों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। इसी असमानता के कारण बड़े पैमाने पर कार्यशील जनसंख्या का स्थानान्तरण गाँवों से शहरों की ओर होता रहा है जो भारतीय जनसंख्या की एक मुख्य समस्या है। गाँवों से शहरोन्मूछी स्थानान्तरण की समस्या का समाधान ग्रामीण बस्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक अधः संरचना के विकास में ही निहित है। यह विकास कुछ ऐसी बह्तियों के माध्यम से ही किया जा सकता है जहाँ पर आधुनिक विकास की सभी संभव आधारभूत सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का अधिकतम केन्द्रीकरण हुआ हो । इस दृष्टिट से सेवा - के द्र एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्यों कि इन केन्द्रों के माध्यम से ही किसी क्षेत्र का समन्वित विकास किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सेवा-केन्द्र प्रणाली के अध्ययन पर विशेष बल दिया जा रहा है। सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं का सम्पादन तथा स्थानिक कार्यात्मक संगठन संभव होता है। प्रस्तृत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र जो एक पिछड़ी अर्थंट्यवस्था का प्रती है - में ऐसी ही आधारभूत बस्तियों को पहचानने एवं निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। साथ, ही, विकास के लिए उत्तरदायी सेवा-केन्द्रों की रिक्तता को ध्यान में रहाते हुए नवीन विकास-केन्द्रों का नियोजन

ा प्रस्तुत किया गया है जिससे सम्पूर्ण तहसील का विकास एक योजनाबद्ध तरी के से

उ. ? विकास सेवा - केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

कृष्ण अर्थंटयवस्था की प्रधानता वाने क्षेत्रों में सेवा-केन्द्र स्थानिक विकास की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास-सेवा केन्द्रों का प्रादुर्भाव कुछ बहितयों में उनकी विधिष्ट हिथतियों के कारण विभिन्न कार्यों के सकेन्द्रण से होता है। ऐसी ही बहितयां अपने सम्बन्धित कार्यों द्वारा समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती हैं जिससे इन्हें सेवा-केन्द्र के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः सेवा-केन्द्र ऐसे अधिवास होते हैं जो अपने चतुर्दिक समीपवर्ती क्षेत्रों में उपभो क्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवा-केन्द्र अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से परिवहन सुविधाओं एवं अन्य सेवा कार्यों द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार के सेवा-केन्द्रों या बहितयों की पहचान सर्वप्रथम मार्क जैफरसन³ ने 'केन्द्र स्थ्वा' के रूप में किया था। आगे चलकर क्रिस्टालर महोदय (1933) ने 'केन्द्र स्थ्वा सिद्धान्त' का प्रतिमादन

विकास-सेवा केन्द्र या केन्द्रस्थां पर अनेक कार्य उद्भूत होते हैं जिनमें से कुछ कार्य मात्र उस केन्द्र स्था की जनसंख्या की सेवा करते हैं जबिक दूसरे कार्य सेवा केन्द्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या की सेवा करते हैं। मात्र अपनी ही जनसंख्या की सेवा करने वाले कार्यों को सामान्य कार्य तथा वाह्य क्षेत्रों की जनसंख्या की सेवा करने वाले कार्यों को आधारभूत कार्य कहा जाता है। जिन बह्तियों में आधारभूत

वार्ध पाये जाते हैं उनकी अवस्थित बहितयों के मध्य में केन्द्रीय हो जाती है जिससे हैं 'केन्द्रस्थल' के रूप में जाना जाता है। ये सभी केन्द्रस्थल जनसंख्या, केन्द्रीयता अथा सेवा क्षमता में समान आकार के नहीं होते हैं बल्कि केन्द्रस्थलों पर अधिक मात्रा एवं संख्या में सेवाओं का संकेन्द्रण होता है तो कुछ केन्द्रों पर इनकी संख्या और मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। वस्तुत: जहां अधिक मात्रा में सेवाओं का एकत्रीकरण होता है वहां पर अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सेवाएं केन्द्रीभूत होती हैं। इसके विपरीत जहां कम सेवाएं प्राप्त होती हैं वहां पर सेवाओं का स्तर भी निम्न होता है।

केन्द्रीय कार्य सभी बहितयों में समान अनुपात में नहीं पाये जाते हैं और न ही उनका हतर समान होता है। केन्द्रीय कार्य वे कार्य हैं जो अपनी प्रकृति व स्वभाव के कारण कुछ ही बहितयों में पाये जाते हैं। राजकुमार पाठक के अनुसार केन्द्रीय कार्य वे कार्य हैं जिसके लिए जनसंख्या का स्थानान्तरण होता है। यह स्थानान्तरण दैनिक, मासिक, वार्षिक, अस्थायी या स्थायी आदि किसी भी रूप में हो सकता है। केन्द्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य सेवा-केन्द्र एवं समीपवर्ती क्षेत्रों का विकास करना है। अतः ऐसे आधारभूत कार्यों को 'केन्द्रीय विकास कार्य(Central Growth Function) कहना अधिक उपयुक्त होगा।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन प्रदेश पूलपुर तहसील की आर्थिक-सामाजिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन, कृष्णि एवं पशुपालन, शिक्षा एवं मनोरंजन, परिवहन तथा संचार वित्त तथा वाणिज्य से सम्बन्धित 30 कार्यों को 'केन्द्रीय विकास कार्य' के रूप में

चुना गया है। सम्पूर्ण तहसील में ट्याप्त इन कार्यों को उनकी प्रवेशी जनसंख्या

(Entry point population) संत्पत जनसंख्या (Saturation point

population) और अवसीमा या कार्याधार जनसंख्या (Threshold population)
के साथ सारणी 3.1 में दर्शाया गया है।

<u>सारणी उ.।</u> केन्द्रीय विकास कार्य

		पदेश में	प्रवेशी	संवष्टत	अवसीमा/ .
का र्य		कुले संख्या	जनसङ्या	जनसंख्य 🛚	अवसीमा/ कार्याधार जनसंख्या
1		2	3	Ц	5
 -	प्रशास निक कार्य	natio camp with nive local data local data.			
	।. तहसील मुख्यालय	t	5136	5136	5136
	2. विकास खण्ड केन्द्र	4	777	5136	2957
	3. न्याय पंचायत केन्द्र	38	346	4110	2228
	4. पुलिस स्टेशन	2	1898	5136	3517
	5. पुलिस चौकी	3	1006	1585	1296
ভা	कृष्णि एवं पशुपालन				
	6. पशु अस्पताल	4	777	5136	2957
	7. बीज एवं उर्वरक केन्द्र	43	346	5136	2741
	 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र 	6	861	5136	2999
	9. शीत भण्डार	1	5136	5136	5136

1		2	3	4	5
11	विक्षा एवं मनो रंजन				
	10. प्राथमिक विद्यालय	198	19	4110	2065
	।।. सी नियर बेसिक स्कूल×	32	267	4110	2189
	12. हाई स्कूल	6	953	4110	2532
	13. इण्टरमी डिएट	12	534	3329	1932
	। 4. छ वि गृह	1	5136	5136	5136
티	<u>चिकित्सा</u>				
	 पंजीकृत च्यक्तिगत क्लीनिक 	15	261	3359	1810
	 परिवार एवं मातृ विष्णु कल्याण केन्द्र 	4	777	5136	2957
	17. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4	771	5136	2957
	18. औष्टालय	2	953	1585	1269
ਵ•	परिवहन एवं संचार				
	19. बस स्टाप	54	215	5136	2676
	20. बस स्टेशन	ı	575	575	575
	21. रेलवे स्टेशन १हाल्ट सहित।	3	1006	5136	3075
	22. डाक्टर	42	42	4110	2076
	23. डाक स्वं तारधर	8	12	5136	2574
	24. दूरभाष	2	1006	5136	3071
	24. दूरभाष	2	1006	5136	30

[×]ती नियर बेतिक स्कूल से तात्पर्य जूनियर हाई स्कूल से है।

	2	3	4	5
च वित्तीय कार्य				
25. संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10	68 I	5136	2913
26. राष्ट्रीयकृत बैंक	14	441	5136	2789
27. जिला सहकारी बैंक	3	1304	5136	3220
28. भूमि विकास बैंक	I	5136	5136	5136
छ च्यापार एवं वाणिज्य				
29. पु⇔कर बाजार केन्द्र	57	21	4110	2066
30 . थो क बाजार केन्द्र	3	1006	5136	307 I

3.3 केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम

केन्द्रीय कार्यों के पदानुक्रम से तात्पर्य सेवा केन्द्रों में पाये जाने वाले केन्द्रीय कार्यों एवं सुविधाओं को विभिन्न श्रेणियों में एक क्रम में रखकर उनका तुलनात्मक मान निर्धारित करने से है । केन्द्रीय कार्यों पर दो बातों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है -

- ।. केन्द्रीय कार्यों की संख्या एवं प्रकार
- 2. कार्यों का स्तर

केन्द्र स्थलों की केन्द्रीयता कुल कार्यों की संख्या से न प्रभावित हो कर कार्यों

के स्तर से विशेष्तत: प्रभावित होती है। किसी खास स्तर के कार्यों की अधिक संख्या युक्त केन्द्र कम जनसंख्या की सेवा करते हैं जबिक अपेक्षाकृत उससे उच्च स्तर के कार्यों की कम संख्या युक्त केन्द्र अधिक जनसंख्या की सेवा करते हैं। किसी सेवा-केन्द्र में उच्च स्तर के कार्यों की कम संख्या होते हुए भी केन्द्रीयता अधिक होगी जबिक निम्न स्तर के अधिक कार्यों की संख्या होते हुए भी उसकी केन्द्रीयता कम होगी। सेवा-केन्द्रों के पदानुक्रम तथा केन्द्रीय कार्यों के पदानुक्रम में सीधा सम्बन्ध होता है।

एल०के० सेन के निर्यालगुड़ा तालुका के अध्ययन में कायों का पदानुक्रम कायों के सापे क्षिक मान के आधार पर निर्धारित किया है। प्रस्तुत अध्ययन में कार्याधार जनसंख्या सूचकांक को केन्द्रीय कार्यों के पदानुक्रम के निर्धारण का आधार बनाया गया है। अवसीमा या कार्याधार जनसंख्या किसी प्रदेश में किसी कार्य को सुचारू रूप से सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है, जो प्रदेश में सम्बन्धित कार्य की प्रवेशी जनसंख्या तथा संतृप्त जनसंख्या का गणितीय माध्य है। यह वह अवसीमा है जिस पर वह कार्य सभी बहित्यों में होना चाहिए। प्रवेश जनसंख्या (Entry Point Population) से तात्पर्य उस निम्नतम जनसंख्या से है जिस पर किसी बस्ती में कोई कार्य शुरू होता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उस जनसंख्या से उमर सभी बहित्यों में वह कार्य पाया जाता हो। लेकिन जनसंख्या की एक ऐसी सीमा आती है जिसके उमर वह कार्य प्रत्येक बस्ती में पाया जाता है। इसे संतृप्त जनसंख्या (Saturation Point Population) कहते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में कार्याधार जनसंख्या सूचकां क की गणना रीडमुड्य विधि द्वारा की गयी है। इस विधि में कार्याधार जनसंख्या को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है, तत्पश्चात् सबसे कम कार्याधार जनसंख्या वाले कार्य की जन-संख्या से सभी कार्यों की कार्याधार जनसंख्या में भाग देकर कार्याधार जनसंख्या सूचकां क जात किया गया है। पुन: कार्याधार जनसंख्या के अलगाव बिन्दुओं को ध्यान में रखकर कार्यों के चार पदानुक्रम निर्धारित किये गये हैं। सारणी 3.2 में

सारणी 3.2 केन्द्रीय कार्य एवं उनका कार्याधार जनसंख्या सूचकांक

-			
केन	द्रीय कार्य	कार्याधार जनसंख्या	कार्याधार जनसंख्या सूचकांक
-	l	2	3
١.	तहसील मुख्यालय	5136	8.93
2.	भूमि विकास बैंक	5136	8.93
3.	शीत भण्डार	5136	8.93
4.	७ विगृह	5136	8.93
5.	पुलिस स्टेशन	3517	6.12
6.	जिला सहकारी बैंक	3220	5. 60
7.	थोक बाजार केन्द्र	3071	5. 34
8.	रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित)	3071	5. 34
9.	दूरभाष	3071	5.34
0.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	2999	5.32

١

1		2	3
-	······································		
11.	विकासखण्ड केन्द्र	2957	5. 14
12.	परिवार एवं मातृषिष्ठा कल्याण केंद्र	2957	5. 14
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2957	5. 14
14.	पशु अस्पताल	2957	5. 14
15.	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29 13	5. 07
16.	राष्ट्रीयकृत बैंक	2789	4.85
17.	बीज एवं उर्वरक केन्द्र	2741	4. 77
18.	बस स्टाप	2676	4. 65
19.	डाक एवं तारधर	2674	4. 48
20.	हाई स्कूल	2532	4. 40
21.	न्यायपंचायत केन्द्र	2228	3.87
22.	सी नियर बेसिक स्कूल	2189	3.81
23.	ड । कद्यर	2076	3.61
24.	पुटकर बाजार केन्द्र	2073	3.60
25.	प्राथमिक विद्यालय	2065	3. 59
26.	इंग्टरमी डिएट. कालेज	1932	3.36
27.	पंजीकृत ट्यक्तिगत क्लीनिक	1810	3.15
28.	पुलिस चौकी	1296	2.75
29.	चिकित्सालय/औषधालय	1269	2.21
30.	बस स्टेशन	575	1.00

केन्द्रीय कार्य, उनकी कार्याधार जनसंख्या तथा कार्याधार जनसंख्या सूचकांक दशाया गया है। सारणी 3.3 में कार्यों के चार पदानुक्रम निर्धारित किए गये हैं।

सारणी 3.3 कार्यों के पदानुक्रम

पदानुक्रम	कार्याधार जनसंख्या सूचकांक	केन्द्रीय कायों की संख्या
प्रथम	6. 12 से 8. 93	5
द्वितीय	4. 40 से 5. 60	15
वृतीय	2.75 से 3.87	8
चतुर्ध	1.00 से 2.21	2

3. 4 विकास-सेवा केन्द्रों का निधारण

भारत में विकास सेवा-केन्द्रों के निधारण एवं प्रतिरूपों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दबाओं का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। प्रारम्भिक अध्ययनों में विकास सेवा-केन्द्रों का निधारण करते समय निम्न स्तर के सेवा-केन्द्रों की और ध्यान नहीं दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में निम्न स्तर के विकास सेवा-केन्द्रों की पहचान तथा उनका निधारण करने का प्रयास किया गया है। विकास सेवा-केन्द्रों के निधारण से तात्पर्य किसी दिये गये प्रदेश में वितरित बहितयों में से उन बहितयों की पहचान है जो सेवा-केन्द्रों के रूप में कार्य-रत हैं और अपने समीपवर्ती बहितयों को सेवार प्रदान करती हैं। ऐसी बहितयों

या तेवा केन्द्रों का निर्धारण एक जिल्ल प्रक्रिया है। आज तक तेवा-केन्द्रों के पहचान या निर्धारण से सम्बन्धित किसी विशिष्ट या मानक सिद्धान्त का प्रति-पादन नहीं किया जा तका है। सेवा केन्द्रों का आकार क्या हो, यह भी निश्चित नहीं हो पाया है। यद्यपि सिद्धान्ततः सेवा-केन्द्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आतान सी लगती है किन्तु च्यावहारिक रूप में इनमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। सेवा केन्द्रों के अध्ययन में तीन बड़ी एवं परस्पर विरोधी समस्यार अध्ययनकत्तां के सम्हाउपस्थित होती हैं -

- (1) सेवा-केन्द्रों की पहचान
- (2) सेवा-केन्द्रों की केन्द्रीयता मापन
- (3.) सेवा-केन्द्र प्रदेशों का सीमां कन

इसके अतिरिक्त सेवा-केन्द्रों के चुनाव में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी उपस्थित होती हैं -

- (1) किसी भी प्रदेश में उन बहितयों या केन्द्रों की संख्या बहुत अधिक होती है जिनमें से सेवा-केन्द्रों का चुनाव करना होता है।
- · (2) बहितयों की विपुल जनसंख्या भी सेवा-केन्द्रों के निर्धारण में जिटल समस्या उपस्थित करती है। यह सुनिध्चित कर पाना किठन हो जाता है कि जनसंख्या की किस सीमा पर सेवा-केन्द्रों का निर्धारण किया जाय।
 - (3) वां छित और कड़ों की अनुपल ब्धाता भी एक समस्या है। यदि वां छित आ कड़े

आवश्यकतानुसार प्राप्त भी हों जायं तो परिमाणा त्मक मापदण्डों का उपयोग संभव नहीं हो पाता है।

(4) सेवा-केन्द्रों के निर्धारण में सबसे बड़ी समस्या प्रशासन की दृष्टि से विभाजित एवं परिभाषित क्षेत्रीय इकाइयों की है। कभी-कभी राजस्व गाँवों
के नाम वास्तविक बस्ती के नामों से मेल नहीं खाते। उदाहरणस्वरूप
अध्ययन में मार्टिनगंज नाम की एक बस्ती है जिसका नाम जिला जनगण्ना
हस्तपुस्तिका तथा लेख्याल खसरा मिलान में 'बनगाँव' मिलता है जो
वास्तविक बस्ती के नाम से मेल नहीं खाता। इसी प्रकार कुछ गाँव कई
पुरवों में विभक्त होते हैं जो अलग-अलग इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं।
कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक सातत्य बस्ती कई राजस्व गाँवों
में विभक्त होती हैं। सिद्धान्ततः वह सेवा-केन्द्र के रूप में कार्य करती
हैं किन्तु कई राजस्व गाँवों का अंग होती है। ऐसे में सेवा केन्द्रों के
नामकरण की भी समस्या सामने आती है। इस प्रकार उपर्युक्त समस्याओं
के रहते सेवा-केन्द्रों की वास्तविक पहचान संभव नहीं हो पाती है।

विकास-सेवा केन्द्रों के निर्धारण में विगत वर्षों में कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विकास-सेवा केन्द्रों का निर्धारण विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों यथा केन्द्रीय सेवाओं की उपस्थिति, केन्द्रीयता तथा केन्द्रीयता सूचकांक, जनसंख्या आकार में परिवर्तन, कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात, केन्द्रीय कार्यों की कार्याधार जनसंख्या तथा बहितयों के सेवा क्षेत्र आदि आधारों पर किये हैं। एस० वनमाली ते, सेन , नित्यानन्द , खान 3, एस०वी० सिंह , कुमार एवं

शर्मा । अदि विद्वानों ने सेवा केन्द्रों का निर्धारण कार्यों के संकेन्द्रण एवं औसत कार्याधार जनसंख्या के आधार पर किया । जीठकेठ मिश्र । ने प्राथमिक कार्याधार जनसंख्या के आधार पर सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया है । डाँठ राजकुमार पाठक । ने सेवा केन्द्रों का निर्धारण करते समय बहितयों की केन्द्रीयता को आधार बनाया । डाँठ जगदीश सिंह । ने जनसंख्या आकार और कार्यों की उपस्थिति के आधार पर सेवा – केन्द्रों का निर्धारण किया । आलम ने जनसंख्या आकार तथा दत्ता 20 ने परिवहन सूचकांक को सेवा – केन्द्रों के निर्धारण का आधार बनाया ।

प्रस्तुत अध्ययन में सेवा केन्द्रों का निधारण केन्द्रीय कार्यों की उपित्थिति, कार्यों की औसत कार्याधार जनसंख्या तथा परिवहन द्वारा बित्तियों की परत्पर सम्बद्धता के आधार पर किया गया है । सर्वप्रथम केन्द्रीय कार्यों को सम्मादित करने वाली बित्तियों में से उन्हीं बित्तियों का चयन किया गया है जिनकी जनसंख्या सम्बिन्धित कार्यों की कार्याधार जनसंख्या से उमर है तथा किन्हीं तीन केन्द्रीय कार्यों को (पुटकर बाजार, प्राथमिक विद्यालय खंबस स्टाप को छोड़कर) सम्मादित करती हैं; सेवा केन्द्रों के रूप में चुना गया है । पुटकर बाजार, प्राथमिक विद्यालय तथा बता स्टाप जैसे कार्यों को आधार नहीं बनाया गया है क्यों कि ये सुविधार अधिकां शा बित्तियों में उपलब्धा है तथा इनका कार्यात्मक मूल्य भी 2 अंक से कम है (सारणी 3.5) । साथ ही उन बित्तियों को भी सेवा केन्द्रों के रूप में चुना गया है जिनका कार्यात्मक मूल्य किन्हीं तीन केन्द्रीय कार्यों को सम्मादित करने वाली बित्तियों के कार्यात्मक मूल्य के उमर है, भी ही वे केवल एक या दो ही केन्द्रीय कार्य सम्मादित करती हों । इन मापदण्डों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में मूलपुर करबा सहित 40

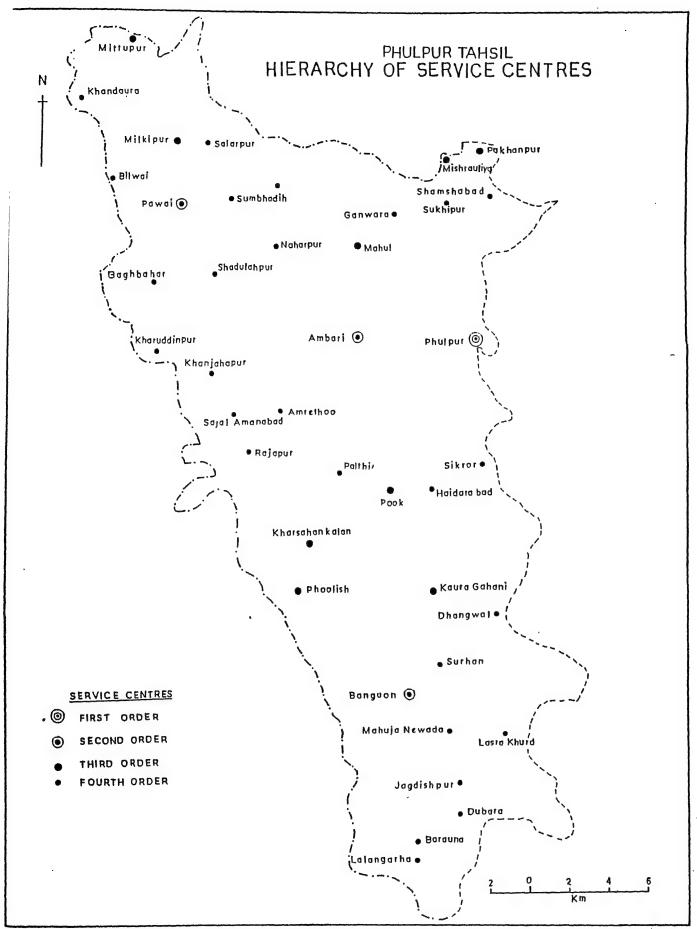


Fig.3-1

सेवा केन्द्रों का जनसंख्या आकार तथा सम्मादित होने वाले कार्यों की संख्या सारणी 3.4 में दिखायी गयी है। इनकी स्थानिक अवस्थितियां चित्र 3.1 में दशायी गयी है।

सारणी 3.4 पूनपुर तहसील में निर्धारित सेवा केन्द्र

संव 🏻		जनसंख्य ा, 1981	सम्पादित होने वाले केन्द्रीय कार्यों की संख्या
	1	2	3
1.	पूनपुर	5136	20
2.	पवर्ड	1898	13
3.	अम्बारी	1006	11
4.	वनगाँव	2485	11
5.	मा हुल	3329	7
6.	खरसहन कला	1585	. 7
7.	मित्तूपुर	3 159	6
8.	प क्खनपुर	777	6
9.	पूक	2838	5
10.	तिकर ौ र	1423	5
11.	पुलेश	1723	5
12.	कौ रा गहनी	2846	5
13.	लसरा खुर्द	2965	Ц
14.	पल्थी -	2004	14
15.	राजापुर	1525	4

		2	3
16.	ख्जहापु र	2302	4
	सुरहन	4110	3
	रू सुम्हाडीह	3004	3
	वेलवाई वेलवाई	1029	3
	गनवारा	745	3
	शम्भाबाद	1893	3
	मिल्कीपुर	575	3
	पारा मिश्रौ निया	809	3
	वागवहार	2683	3
	মज র্ৱ	1084	3
	जगदीभापुर	1950	3
	धेरद् दी नपुर	1664	2
	हैदराबाद	756	2
29.	ध्यवल	675	2
30.	महुजा नेवादा	2728	2
	सादुल्ला हपुर	441	2
32.	सुखीपुर	894	2
33.	वरौना	1295	2
34.	नाहरपुर	, 828	2
35.	ढं डौरा	953	2
36.	रामापुर	681	l
37.	सला रपुर	624	ı
38.	लालनगाइा	12	1

	2	3
39. दुबरा	1106	
40. अमरेथू	1464	

3.5 केन्द्रीयता एवं मान निर्धारण

केन्द्रीयता की संकल्पना विकास-सेवा केन्द्रों के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेवा का सापेक्षिक महत्त्व एवं उनका पदानुक्रम केन्द्रीयता पर निर्भर करता है। किसी केन्द्र की केन्द्रीयता उसके द्वारा सम्पादित कार्यों की संख्या, गुण तथा जनसंख्या आकार पर निर्भर करती है। 21 जनसंख्या आकार तथा केन्द्रीयता में धनात्मक सम्बन्ध होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आकार में बड़े केन्द्रों की केन्द्रीयता भी अपेक्षाकृत अधिक हो या छोटे केन्द्रों की केन्द्रीयता कम हो।

केन्द्रीयता मापन एक जिल्ल किन्तु व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है । इसकी गणना एक या एक से अधिक आधारों पर की जाती है । केन्द्रों की केन्द्रीयता मापन हेतु अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्वानों ने अलग-अलग विध्यां अपनाया है । सर्वप्रथम किस्टालर विश्व में दक्षिणी जर्मनी के केन्द्र स्थाों की केन्द्रीयता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक केन्द्र की प्रदेश की सेवा के लिए आवश्यक देलीफोन सम्बद्धता (Telephone Connections) की संख्या ज्ञात किया । देलीफोन संख्या के आधार पर केन्द्रीयता ज्ञात करने के लिए उन्होंने निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया –

$$Z_Z = T_Z - E_Z \frac{T_Q}{E_Q}$$

जहाँ पर 22 = केन्द्रीयता सूचकां क

Tz = स्थानीय देलीफोन संख्या

Ez = कुल स्थानीय जनसंख्या

Tg = क्षेत्रीय देलीफोन संख्या

Eg = कुल क्षेत्रीय जनसंख्या

इस प्रकार की केन्द्रीयता सूचकांकों के आधार पर क्रिस्टालर ने दिक्षणी जर्भनी में 7 प्रकार के केन्द्रस्थां वाला पदानुक्रम प्रस्तुत किया । इसकी सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि छोटे केन्द्रस्थां में टेलीफोन सेवा उपलब्ध ही नहीं थी । इस आलोचना के बाद क्रिस्टालर ने फुटकर बाजार पर आधारित एक दूसरी परि-माणात्मक विधि का सहारा लिया जो निम्न है -

$$Ct = St - Pf \frac{Sr}{Pr}$$

जहाँ पर Ct = केन्द्रीयता सूचकां क

st = स्थानीय प्टकर बाजार में लगे ट्यक्तियों की तंख्या

Pf = केन्द्र स्थान या नगर की जनसंख्या

sr = प्रदेश में पुट कर बाजार में लगे ट्यक्तियों की संख्या

Pr = प्रदेश की जनसंख्या

इसके अतिरिक्त व्रश²³ (1953), इनकन²⁴ (1955), कार्टर²⁵ (1955), उल्भेन²⁶ (1960), हार्टले और स्मैल्स²⁷ (1961) आदि विद्वानों ने किसी स्थान पर पाये जाने वाले सम्पूर्ण कार्यों के आधार पर केन्द्रीयता की गणना की जबकि प्रेसी²⁸ (1953) ने केन्द्रों के आकर्षण शक्ति के आधार पर तथा ग्रीन²⁹ (1948), केरूथर्स³⁰ (1957) ने आकर्षण शक्ति के साथ-साथ सेवा केन्द्रों की विभिन्न केन्द्रों से परिवहन सम्बद्धता को भी ध्यान में रखा है। वाशिंगटन के स्नोहों मिंग काउण्द्री के अध्ययन में बेरी और गैरीसन³¹ (1958) ने केन्द्रों के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण कार्यों उनके कार्याधार जनसंख्या तथा पदानुक्रम को भी ध्यान में रखा है। सिद्दाल³² ने 1961 में पुटकर और थोक बाजार के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। प्रेस्टन³³ (1971) ने पुटकर बाजार तथा औरत पारिवारिक आय के आधार पर केन्द्रीयता माडल प्रस्तुत किया।

भारतीय अध्ययनों में केन्द्रीय कार्यों की केन्द्रीयता का मापन अधिकांशतः केन्द्रीय कार्यों की संख्या पर आधारित रहा है। कार्यों की संख्या के आधार पर विश्वनाध³⁴ (1963), ओं oपींठ सिंह³⁵ (1971), प्रकाशराव³⁶ (1974), जगदीश सिंह³⁷ (1976) आदि विद्वानों ने केन्द्रीयता मापन का सराहनीय कार्य किया। केन्द्रों की परस्पर यातायात सम्बद्धता के आधार पर बहुत ही कम प्रयास हुआ है, जिसमें जैन³⁸ (1971) तथा ओं oपींठ सिंह³⁹ (1971) का कार्य उल्लेखनीय है। डाँठ ओं ठपींठ सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के नगरों तथा ग्रामीण बाजारों के अध्ययन में केन्द्रीयता ज्ञान करने के लिए निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया –

 $C = \frac{N}{P} \times 100$

जहाँ पर ^C = केन्द्रीयता सूचकांक

N = व्यापार पर निर्भर जनसंख्या

P = कुल जनसंख्या में ट्यापारिक जनसंख्या

सामान्यतः भूगोन वेत्ताओं ने केन्द्रीयता निर्धारण हेतु बैंक, विक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन तथा संगर सेवाओं, और प्रशासनिक इकाइयों को सिम्मिन्ति ह्या से आधार माना है। प्रस्तुत अध्ययन में सम्पूर्ण तहसीन में गुने गये 30 केन्द्रीय कार्यों में से सभी को बराबर महत्त्व का माना गया है तथा प्रत्येक कार्य को 100 मान दिया गया है किन्तु उनके प्रति इकाई महत्त्व को दर्शाने के लिए तहसीन में पाये जाने वाले प्रत्येक केन्द्रीय कार्य की कुल संख्या से 100 को विभक्त किया गया है। इस प्रक्रिया से कार्यों का उचित सापे क्षिक महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण स्वरूप तहसीन में प्राथमिक विद्यालय का मान इस प्रक्रिया से 0.50 इकाई है तो इण्टर-मिरिडिस्ट कालेज का मान 8.30 है जो वास्तविक दशाओं के अनुरूप जान पड़ता है। विभिन्न कार्यों का महत्त्वानुसार मान सारणी 3.5 में दिखाया गया है।

प्रारम्भिक अध्ययनों में सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम निधारण उनमें मिलने वाली समस्त सुविधाओं एवं सेवाओं के आधार पर किया जाता रहा है। सेवा-केन्द्रों का प्रदेश-जिसका उचित प्रतिनिधित्व सेवित जनसंख्या करती है, कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। वस्तुत: उच्च स्तर के कायों का सेवा क्षेत्र बड़ा होता है। ⁴⁰ प्रस्तुत अध्ययन में केन्द्रों की केन्द्रीयता मापने के लिए कार्यों के स्तर तथा केन्द्रों द्वारा सेवित जनसंख्या को भी

सारणी 3,5 केन्द्रीय कार्यों का तुलनात्मक मान

-				
केन्द्री	य कार्य	प्रदेश में कुल जनसंख्या	प्रदेश में उनका महत्त्व	प्रति इकाई महत्त्व
Ī		2	3	4
			. Arms when allow made came days have gater came days gifted game de	
(क) तेत्र	ग्तिनिक कार्य			
1.	तहसील मुख्यालय	ł	100	100.00
2.	विकास खण्ड केन्द्र	4	100	25.00
3.	न्याय पंचायत केन्द्र	38	100	2.60
4.	पुलिस स्टेशन	2	100	50.00
5.	पुलिस चौकी	3	100	33.30
(ख)कृर्	ध एवं पशुपालन			
6.	पशु अस्पताल	4	100	25.00
7.	बीज एवं उर्वरक केन्द्र	43	100	2.30
8.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	6	100	16.70
9•	शीत भण्डार	1	100	100.00
(ग) [घा	क्षा एवं मनोरंजन			
10.	प्राथमिक स्कून	198	100	0.50
11.	सी नियर बेसिक स्कूल	32	100	3.10
12.	हाई स्कूल	6	100	16.70
13.	इण्ट रमी डिएट	12	100	8.30
j 4.	छ विगृह	1	100	100.00

	2	3	4
(घ) चि कित्सा			
।5. पंजीकृत टयक्तिगत क्लीनिक	15	100	6.70
 परिवार एवं मातृ प्रिष्ठा कल्या 	ण केंद्र 4	100	25. 00
17. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4	100	25. 00
18. औ ष्ट ालय	2	100	50.00
(ड)परिवहन एवं संचार			
19. बस स्ट ा प	54	100	1.90
20. बस स्टेशन	1	100	100.00
21. रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित)	3	100	33.3 0
22. डिक्टार	42	100	2. 40
23. डाक एवं तारघर	8	100	12.50
24. दूरभाष	2	100	50.00
(च) <u>वित्तीय कार्य</u>			
25. संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10	100	10.00
26. राष्ट्रीयकृत बैंक	14	100	7.10
27. जिला सहकारी बैंक	3	100	33. 30
28. भूमि विकास बैंक	1	100	100.00
(छ) ट्यापार एवं वाणिज्य			
29. पुटकर बांजार केन्द्र	57	100	1.80
30. थोक बाजार केन्द्र	3	100	33.30

ध्यान में रखा गया है। केन्द्रों के महत्त्व की गण्ना सेवा केन्द्रों द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यों को महत्त्वानुसार अंक प्रदान कर पुन: उन्हें जोड़कर की गयी है जिसे कार्यात्मक अंक कहा गया है। कार्यों का महत्त्व प्रदेश में व्याप्त उनकी संख्या पर निभीर करता है।

कार्यात्मक सूचकां कं की गणना प्रदेश में ट्याप्त सबसे कम कार्यात्मक अंक से सभी केन्द्रों के कार्यात्मक अंकों में भाग देकर की गयी है जिससे उनके सापे क्षिक महत्त्व को आसानी से समझा जा सके (देखिये सारणी 3.6)। प्रत्येक केन्द्र की कुल सेवित जनसंख्या को सबसे कम सेवित जनसंख्या वाले केन्द्र की जनसंख्या से भाग देकर सेवित जनसंख्या सूचकां क ज्ञात किया गया है जो सेवा केन्द्रों के सापे क्षिक महत्त्व को समझने के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रत्येक सेवा-केन्द्र के कार्यात्मक सूचकां क तथा सेवित जनसंख्या सूचकां क का योग कर केन्द्रीयता अंक प्राप्त किये गये हैं। इन केन्द्रीयता अंकों को सबसे कम केन्द्रीयता अंक से भाग देकर केन्द्रीयता सूचकां कं प्राप्त किया गया है जो केन्द्रों के सापे क्षिक महत्त्व को सरलतम रूप में प्रक्ट करता है। विभिन्न सेवा-केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकां क सारणी 3.6 में दिखाया गया है।

[×] कार्यात्मक सूचकां क से ता त्पर्य कार्यात्मक अंक सूचकां क से है।

^{××} केन्द्रीयता सूचकांक से तात्पर्य केन्द्रीयता अंक सूचकांक से है।

सारणी 3.6 सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक

	विकास सेवा केन्द्र	क्ल से वित वैस्तियाँ	कायि,त्मक अंक	का या दिसक सूचका क	मे वित् जनमृष्ट्या	भेवित् जनसङ्घा सुयकाक	केन्द्रीयता अंक	केन्द्रीयता सूचका क
	1	2	3	4	5	6	7	8
						and admit where there is now which facts		
١.	पूलपुर	90	761.40	104.30	53491	42.69	146.99	51.39
2.	पवर्इ	16	254.10	34.80	13593	10.85	45.65	15.96
3.	अम्बारी	38	202.50	27.73	22953	18.32	46. 05	16.10
4.	वनगाँव	16	186.80	25. 58	20206	16.13	41.71	14. 58
5.	पक्छनपुर	6	119.00	16.30	3150	2.51	18.81	6. 58
6.	मिल्की पुर	113	113.80	15.58	6358	5. 0 7	20. 65	7. 22
7.	खरसहन क्ला	23	96.80	13.26	17777	14.18	27. 44	9.59
8.	खण्डौरा	6	58.30	7.99	2898	1.83	9.82	3. 43
9.	माहुल	23	53.50	7.32	9917	7.91	15. 23	5. 32
10.	ख्जहापु र	10	41.50	5. 68	5694	4. 54	10. 22	3. 5 7
11.	मित्तूपुर	15	38.80	5.31	12692	10.34	15. 65	5. 47
12.	विलवाई	5	38.00	5. 20	3463	2.76	7.96	2. 78
13.	पूक	16	35.70	4. 89	10928	8.72	13.61	4.76
14.	सुरहन	7	29.00	3.97	7918	6.32	10. 29	3.60
15.	पुलेश	7	27.80	3.81	9593	7.66	11.47	4.01
16.	तिकर ौ र	10	17.50	2. 39	9051	7. 22	9.61	3.36

	l	2	3	4	5	6	7	8
17.	 पारामिश्रौ लिया	3	17. 40	2, 38	1253	1.00	3. 38	1. 18
18.	गनवारा	12	17. 40	2. 38	9739	7.77	10. 15	3. 55
19.	पल्थी	9	17.30	2.36	7816	6. 24	8.60	3.01
20.	कौ रा गहनी	9	17.10	2.34	15903	12.24	14. 58	5. 10
21.	राजापुर	17	14.40	1.97	9095	7.26	9.23	3. 23
22.	सजर्ड	5	13.20	1.80	4150	3.31	5.11	1.79
23.	लालनगाइा	7	12.50	1.71	4984	3.98	5. 69	1.99
24.	है स्द्दीनपुर	8	12.40	1.70	4363	3. 48	5.18	1.81
25.	सादुल्ला हपुर	11	12.00	1.64	9360	7. 47	9.11	3.19
26.	नाहरपुर	11	11.40	1.56	9834	7.85	9.41	3. 29
27.	रामापुर	14	10.00	1.37	8222	5.56	6.93	2. 42
28.	दुबरा	6	10.00	1.37	5878	4. 69	6.06	2. 12
29.	अमरे थू	10	10.00	1.37	6155	4.91	6. 28	2. 20
30.	सुखी पुर	5	9.50	1.30	2751	2. 20	3.50	1. 22
31.	बरौना	13	9.50	1.30	7500	5.99	7. 29	2. 55
32.	लस रा खुर्द	3	9.40	1.29	545 I	4. 35	5. 64	1.97
33.	महुजा नेवादा	3	9.10	1.25	5130	4. 09	5. 34	1.87
34.	धग्वल	8	9.10	1.25	8045	6. 42	7. 67	2. 68
35.	हैदराबाद	6	9.10	1.25	2017	1.61	2.86	1.00

	2	3	4	5	6	7	8
36. सलारपुर	11	8.30	1.14	4639	3.70	4.84	1.69
37. व ा ग वहार	6	8.00	1.10	2335	1.86	2.96	1. 03
38. जगदीभपुर	8	7.30	1.00	8475	6.76	7.76	2.71
39. शम्शाबाद	5	7.30	1.00	4141	3.30	4. 30	1.50
40. सुम्हाडीह	4	7.30	1.00	5232	4.18	5. 18	1.81

3.6 विकास सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम

अधिवातों के स्थानिक अध्ययन में पदानुक्रमीय व्यवस्था का विशेष महत्त्व है। एल०एत० भद्ध भी के अनुतार बिस्तयों को तापे क्षिक महत्त्व के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करना पदानुक्रम है। प्रायः बिस्तयों के कायों, आकारों एवं उनकी पारस्परिक दूरियों के बीच परस्पर धनिष्ठ तम्बन्ध पाया जाता है। वस्तुतः देखा गया है कि उच्च स्तर के सेवा केन्द्र दूर-दूर स्थापित होते हैं जबिक निम्न स्तर के सेवा केन्द्र पात-पात। किस्तालर भें की यह मान्यता रही है कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह उच्च स्तर के केन्द्रों से निम्न स्तर के केन्द्रों की ओर होता है। उच्च स्तर के केन्द्र कुछ विशिष्ट कार्य सम्मादित करते हैं जो निम्न स्तर के केन्द्रों में नहीं पाये जाते। क्रिस्तालर की मान्यता के विपरीत निम्न स्तरीय केन्द्र भी उच्च स्त्रीय केन्द्रों को कुछ सेवार प्रदान करते हैं। पदानुक्रमीय व्यवस्था में उच्च स्तर तथा निम्न स्तर के सेवा केन्द्र परस्पर सम्बद्ध होते हैं तथा उनमें एक

कार्यात्मक संप्रिनष्टता पायी जाती है। अतः सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम का निर्धारण केन्द्रीयता सूचकांक तारतम्य को खण्डित करने वाले अलगाव बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। सारणी उ.६ के सूक्षम अवलोकन से उ अलगाव बिन्दु प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर अध्ययन क्षेत्र में 4 पदानुक्रम पाये जाते हैं (सारणी उ.७)।

सारणी 3.7 सेवा केन्द्रों का पदानुक्रमीय स्तर

पदानुक्रमीय स्तर	केन्द्रीयता सूचकांक वर्ग 	सेवा केन्द्रों की संख्या
प्रथम	51.39 से उमर	i
द्वितीय	14. 58 से 16. 10	3
वृतीय	4.01 से 9.59	8
चतुर्थ	1.00 से 3.60	28
		one and and man and and and and and and and and and a

अध्ययन प्रदेश में प्रथम स्तर का केन्द्र मात्र एक, द्वितीय स्तर के तीन, वृतीय स्तर के आठ तथा चतुर्थ स्तर के 28 सेवा केन्द्र हैं (देखिये चित्र 3.2)। यह विचारणीय तथ्य है कि प्रस्तुत अध्ययन में कार्यों के पदानुक्रम तथा सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम स्तर एक दूसरे के विपरीत हैं।

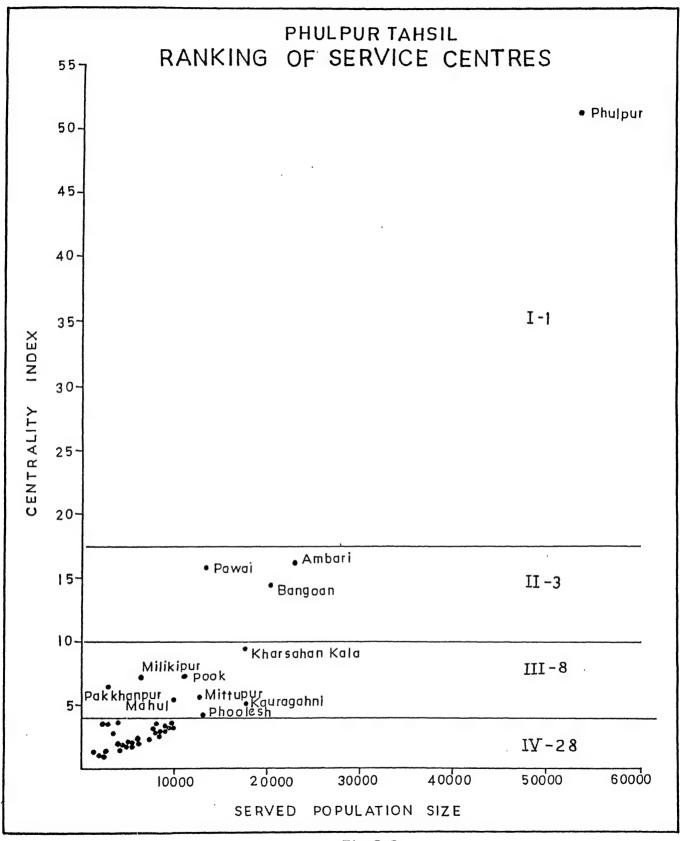


Fig.3·2

51.39 से अधिक केन्द्रीयता सूचकांक वाले सेवा-केन्द्रों को प्रथम स्तर प्रदान किया गया है। प्रथम स्तर के अन्तर्गत मात्र एक सेवा केन्द्र पूलपुर है जो अध्ययन प्रदेश में सबसे बड़े केन्द्र स्थल के रूप में विद्यमान है। इसका केन्द्रीयता सूचकांक 51.39 है। इसके दारा प्रदेश की 101 बस्तियों को सेवा प्रदान की जाती है। छोटे स्तर के कार्यों के अलावा प्रदेश के कई विशिष्ट कार्य मात्र यहीं स्थित हैं। इसके दारा प्रदेश की 14.77 प्रतिशत जनसंख्या को प्रत्यक्षरूप से सेवा प्रदान की जाती है।

दितीय स्तर के अन्तर्गत तीन सेवा-केन्द्र अम्बारी, पवर्ड तथा वनगांव आते.

हैं जिनके कार्यात्मक सूचकांक क्रम्बा: 16.10, 15.96 तथा 14.58 हैं । इन केन्द्रों पर कार्यात्मक पदानुक्रम के लगभग दितीय स्तर के कार्य तथा उससे निम्न स्तर के कार्य सम्मादित होते हैं । अम्बारी सेवा-केन्द्र 38 बस्तियों की 22953 जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है जो तहसील की सम्मूर्ण जनसंख्या का 6.34 प्रतिवात है । पवर्ड सेवा-केन्द्र 16 बस्तियों की 13593 जनसंख्या की सेवा करता है जो सम्मूर्ण जनसंख्या का 3.75 प्रतिवात है । वनगांव सेवा केन्द्र 16 बस्तियों की 20206 लोगों को सेवा प्रदान करता है जो सम्मूर्ण जनसंख्या का मात्र 5.58 प्रतिवात है ।

पदानुक्रम के तीसरे स्तर में उन सेवा केन्द्रों को समाहित किया गया है जिनका केन्द्रीयता सूचकांक 4.01 से 9.59 के मध्य है। इसके अन्तर्गत आठ विकास-सेवा केन्द्र आते हैं। इनमें सर्वाधिक केन्द्रीयता सूचकांक 9.59 खरसहन क्ला सेवा-केन्द्र का है जो 23 बहितयों की 17777 लोगों की सेवा करता है जो सम्पूर्ण तहसील का 4.91 प्रतिश्रात है। सबसे कम केन्द्रीयता सूचकांक 4.01 पुलेश सेवा केन्द्र का है

जो 7 ग्रामीण बस्तियों की 9593 लोगों की सेवा करता है जो कुल जनसंख्या का 2.65 प्रतिश्रात है ।

चतुर्थ स्तर के पदानुक्रम में उन सेवा केन्द्रों को समाहित किया गया है
जिनका केन्द्रीयता सूचकांक 1.00 से 3.60 के मध्य है । इन सेवा केन्द्रों पर मात्र
कुछ बेसिक सुविधाएँ ही उपलब्ध हैं । इस प्रकार के सेवा-केन्द्रों की सर्वाधिक संख्या
28 है । चतुर्थ स्तर के सेवा केन्द्रों में सर्वाधिक 3.60 केन्द्रीयता सूचकांक सुरहन
सेवा-केन्द्र का है जबकि सबसे कम केन्द्रीयता सूचकांक 1.00 हैदराबाद का है ।

स्पष्ट है कि अध्ययन प्रदेश के सेवा केन्द्रों का वितरण 1,3,8 एवं 28 के अनुपात में है जो क्रिस्टालर के K -3 नियम से बहुत कुछ साम्य रखता है । यदि सेवा-केन्द्रों का किंचित पुनर्गठन कर दिया जाय तो प्रादेशिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता आ सकती है ।

3. 7 सेवा केन्द्रों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप

भूगोल के अन्य तत्त्वों की भाँति सेवा केन्द्रों का स्थानिक वितरण भी क्षेत्र विशेष्ठा के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। अध्ययन क्षेत्र में विकास सेवा केन्द्रों का स्थानिक वितरण बहुत ही असमान है। यह अनियमित वितरण जनसंख्या और बहितयों के धनत्व में भिन्नता के कारण है क्यों कि सामान्यतया विकास केन्द्रों का स्थानिक वितरण इन्हीं पर निभीर करता है। 43 विकास सेवा केन्द्रों या बहितयों का स्थानिक वितरण प्रतिक्ष्य मापने के लिए अनेक सांख्यिकीय विद्या प्रचलित हैं किन्तु भूगोल में अधिकांश विद्वानों ने प्रमुख परिहिथितिकीय विशेष्ठा

क्लार्क एवं इवान्स⁴⁴ 1954 द्वारा प्रतिपादित निकटतम पड़ोसी विश्लेषण विधि (Nearest Neighbour Analysis Method), का ही अधिक प्रयोग किया है। भूगोल के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम डेसी⁴⁵ तथा किंग⁴⁶ ने किया। अन्य विद्वानों में व्रश एवं वेसी (1959), स्टीवर्ट (1958) तथा हैगेट (1967) मुख्य हैं।

विकास सेवा केन्द्रों के स्थानिक वितरण अध्ययन में प्रत्येक केन्द्र के निकटतम पड़ोसी की गणना सीधी रेखा द्वारा की जाती है। निकटतम पड़ोसी केन्द्र किसी भी आकार वर्ग का हो सकता है, केन्द्रों के आकार तथा पदानुक्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विकास सेवा-केन्द्रों के निकटतम सेवा केन्द्रों की दूरी सारणी 3.8 में दी गयी है जिसकी गणना मानचित्र संख्या 3.1 पर आधारित है।

सारणी 3.8 से स्पष्ट है कि विकास सेवा केन्द्रों की निकटतम पड़ोसी दूरी की अधिकतम सीमा पूलपुर 6.6 कि0मी०, अम्बारी 5.4 कि0मी० और लसरा खुर्द 4.8 कि0मी० सेवा केन्द्रों के बीच है। न्यूनतम दूरी लालनगाड़ा 1.00 कि0 मी० तथा बरौना 1.00 कि0मी० सेवा केन्द्रों के मध्य है। सेवा केन्द्रों की स्थानिक दूरी सा03.8 में दिखायी गयी है।

सारणी 3.8 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 14 विकास सेवा केन्द्र 3 से 4 कि0 मीठ की दूरी पर स्थित है । अध्ययन क्षेत्र में ष्टकोणीय व्यवस्था के लिए आदर्श दूरी की गणना साथर⁴⁷ द्वारा प्रतिपादित निम्न सूत्र से की गयी है -

> Hd = $1.0746 \sqrt{A/N}$ = $1.0746 \sqrt{701.6/40}$ = $1.0746 \sqrt{17.54}$

 $= 1.0746 \times 4.19$

= 4.50

जहाँ मव = आदर्श औसत दूरी

A = प्रदेश का क्षेत्रपत

N = बह्तियों या सेवा केन्द्रों की तंख्या

तिद्वान्ततः सेवा केन्द्रों के मध्य की औसत दूरी 4.50 कि0मी० होनी चाहिए किन्तु सेवा केन्द्रों के मध्य औसत दूरी 2.98 कि0मी० है। वास्तविक औसत दूरी आदर्श दूरी की 66.22 प्रतिशत है। सेवा केन्द्रों के वितरण प्रतिरूप को किंग महोदय द्वारा प्रतिपादित निम्न सूत्र से ज्ञात किया गया है –

 $Rn = 2 \overline{D} \sqrt{N/A}$

 $Rn = 2 \times 2.98 \sqrt{40/701.6}$

 $= 5.96 \sqrt{.057}$

 $= 5.96 \times .024$

= 0.143 कि0मी0

जहाँ D = सेवा केन्द्रों के बीच की निकटतम औसत दूरी

N = सेवा केन्द्रों की संख्या

A = प्रदेश का क्षेत्रपल

सारणी 3.8 विकास सेवा केन्द्रों से निकटतम पड़ोसी की दूरी

वि क 	ास सेवा केन्द्र	दूरी कि0मी0	विक	ास सेवा केन्द्र	दूरी किंग्मी 0
1.	पूलपुर	6.60	21.	राजापुर	3. 40
2.	पवर्ड	3.00	22.	सजई अमानबाद	3. 40
3.	अम्बारी	5. 40	23.	लालनगाड़ा	1.00
4.	बनगाँव (मा टिनगंज)	2.00	24.	बैस्द्दीनपुर अली	2.80
5.	प व्हानपुर	1.40	25.	सदुल्ला हपुर	3.80
6.	मिल्की पुर	3. 40	26.	नाहरपुर	3.80
7.	खरसहन क्त Г	3.80	27.	रा मापुर	3. Q 0
8.	खण्ड ौ रा	4. 00	28.	दुबरा	3.00
9.	मा हुल	2.80	29.	अमरेथू	3. 40
10.	खं जहा पुर	2.60	30.	सुखीपुर	2.00
11.	मित्तूपुर	4 . 0 0	31.	बरौना	1.00
12.	विनवाई	4. 00	32.	नप्तरा खुर्द	4.80
13.	पूक(पुष्पनगर)	3.00	33.	महुजा नेवादा	1440
14.	सुरहन	2.00	34.	धग्वल	3.40
15.	पुलेश	3.80	35.	हैदराबाद	2. 60
	तिकरौर	2. 40	36.	सल । रपुर	2.00
17.	मिश्रौ लिया	1.40	37.	बागबहार	2.80
18.	गनवारा	2.80	38.	जगदी भ्रमुर	1.60
19.	पत्थी	3.00	39.	शमा बाद	3. 20
20.	कौरागहनी	3. 20	40.	सुम्हाडीह 	2.00

टिप्पणी: विकास सेवा केन्द्रों से निकटतम पड़ोसी की दूरी मानचित्र 3.1 से संगणित

यदि सेवा केन्द्रों के Rn का मान 0 आता है तो सेवा केन्द्रों का वितरण पूर्ण गु छन के रूप में होगा । यदि मान 1.00 से कम है तो वितरण असमान होगा तथा यदि मान 1.00 से 2.15 के मध्य है तो वितरण समान होगा अर्थात् यह साधारण षह्भुजीय जालयुक्त वितरण को प्रकट करेगा । अध्ययन क्षेत्र में Rn का मान 0.143 है जो सेवा केन्द्रों के असमान वितरण को दर्शाता है । अतः आवश्यक है कि कुछ नये सेवा केन्द्रों को विकसित किया जाय जो क्षेत्रीय अन्तर्सम्बन्धों को मजबूत कर क्षेत्र के विकास को नयी दिशा और गित प्रदान कर सकें।

3.8 विकास-केन्द्रों के सेवा-प्रदेशों का सीमांकन

विकास केन्द्रों के प्रभाव प्रदेशों के सीमांकन से तात्पर्य उनके द्वारा सेवित जनसंख्या तथा क्षेत्र के निर्धारण से हैं । प्रत्येक विकास केन्द्र अपने समीपस्थ यतुर्दिक क्षेत्रों को वस्तुरूँ और सेवारूँ प्रदान करता है । इनके द्वारा सेवित इस प्रदेश को विभिन्न नामों से अभिहित किया जाता है । प्रत्येक विकास केन्द्र का अपना एक निश्चित सेवा क्षेत्र होता है जो सेवाओं के पदानुक्रम, संख्या तथा गुण पर आधारित होता है । विकास केन्द्रों पर अनेक कार्य होते हैं तथा प्रत्येक कार्य का प्रभाव-परिसर (Range of Influence) अलग-अलग होता है । अर्थात् प्रत्येक कार्य का अपना एक अलग सेवा क्षेत्र होता है । ऐसी दशाओं में सेवा केन्द्रों के प्रभाव प्रदेश का सीमांकन करना एक दुष्ट कार्य हो जाता है । पिर भी विकास सेवा केन्द्रों के प्रभाव प्रदेश के निर्धारण में भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने अनेक विधियाँ अपनायी हैं जिन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है –

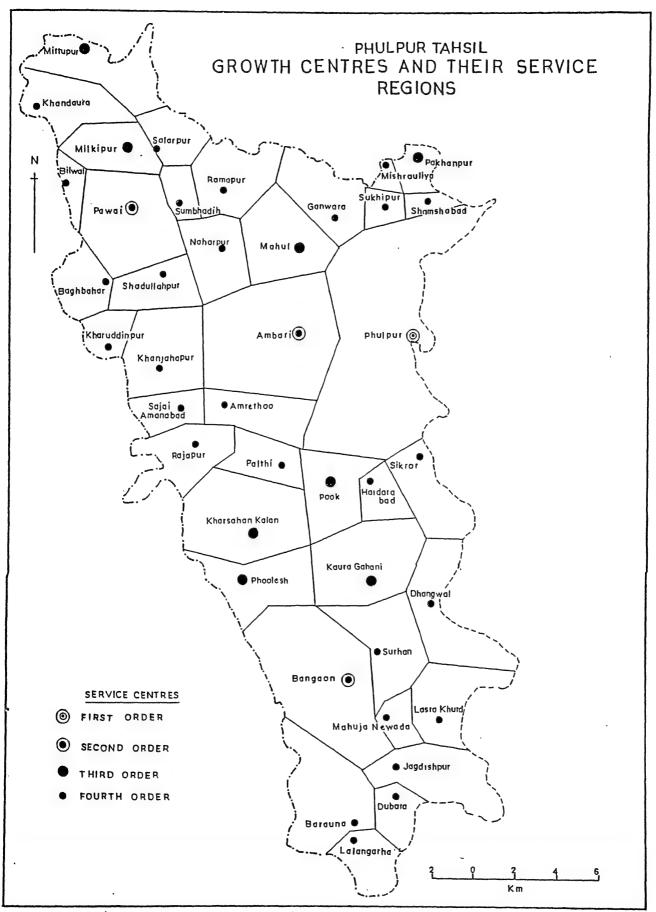


Fig.3-3

- अानुभविक या गुणा त्मक विधियाँ
- 2. तेद्वा नितक या सांख्यिकीय विधियाँ

आनुभविक विधियाँ विकास केन्द्र से सम्बन्धित परिवहन एवं संचार साधनों, समाचार पत्रों, बैंक खातों, पुटकर एवं थोक ट्यापार तथा वस्तुओं की अगपूर्ति आदि के विश्लेष्ण से सम्बन्धित हैं जबिक सांख्यिकीय विधियाँ गणितीय आकड़ों यथा केन्द्रों की केन्द्रीयता, दूरी, जनसंख्या आदि पर आधारित होती हैं। आंकड़ों तथा सूचनाओं की अनुपल ब्धता के कारण अध्ययन प्रदेश में आनुभविक विधियों का प्रयोग कर पाना संभव नहीं है। अत: अध्ययन प्रदेश के सेवा-केन्द्रों के प्रदेशों का निधारण सांख्यिकीय विधि पर आधारित है।

प्रस्तुत अध्ययन में विकास सेवा केन्द्रों के प्रभाव प्रदेशों का सीमांकन पीठ डीठ कन्वसं विध (Breaking Point Method) पर आधारित है जिसे कुछ संशोधनों के साथ प्रयुक्त किया गया है। कन्वर्स महोदय ने जहाँ दो नगरों के बीच अलगाव बिन्दु निर्धारण में दोनों नगरों की जनसंख्या का प्रयोग किया है वहीं अध्ययन प्रदेश में दो सेवा केन्द्रों के मध्य अलगाव बिन्दु का निर्धारण कार्यात्मक सूचकांक के आधार पर किया गया है। अध्ययन प्रदेश में विकास केन्द्रों के प्रभाव प्रदेश में विकास केन्द्रों के प्रभाव प्रदेशों का सीमांकन पीठडीठ कन्वर्स द्वारा प्रतिपादित निम्न सूत्र पर आधारित है –

 $B = \frac{d}{1 + \sqrt{CA/CB}}$

'в = दो सेवा केन्द्रों के बीच अलगाव बिन्दु

व = दो सेवा केन्द्रों के बीच की सीधी दूरी

CA = बड़े केन्द्र का केन्द्रीयता सूचकांक

СВ = छोटे केन्द्र का केन्द्रीयता सूचकां क

उपर्युक्त विधि द्वारा प्रत्येक विकास केन्द्र का सेवा प्रदेश निर्धारित किया गया है। विकास केन्द्रों के ये प्रभाव क्षेत्र बहुभुज आकृति का निर्माण करते हैं। इन बहुभुज आकृतियों के बीच की बहितयों की संख्या को जोड़कर प्रत्येक विकास केन्द्र की सेवित बहितयों की संख्या ज्ञात की गयी है। पुन: प्रत्येक केन्द्र द्वारा सेवितक बहितयों की जनसंख्या का योग कर सेवित जनसंख्या की गणना की गयी है(देखिए सारणी 3.6)। अध्ययन प्रदेश में विकास केन्द्रों द्वारा सेवित बहितयों की औसत संख्या 12 है तथा प्रत्येक विकास केन्द्र औसत रूप से 9054 लोगों को सेवा प्रदान करता है।

3.9 प्रस्तावित विकास सेवा केन्द्र

सेवा केन्द्रों के माध्यम से किसी भी क्षेत्र के सम्यक् प्रादेशिक विकास के सन्दर्भ में तीन बातें उल्लेखनीय हैं -

- (अ) क्षेत्र में विकास-सेवा केन्द्रों की समुचित संख्या,
- (ब) सेवा केन्द्रों का सन्तुलित प्रादेशिक वितरण, एवं
- (स) सेवा केन्द्रों में सह-संबंधातमकः पदानुक्रम ।

किसी भी क्षेत्र में विकास केन्द्रों पर जितनी अधिक मात्रा में आवश्यक सुवि-धार (वस्तुर या सेवार) सुलभ होंगी उस क्षेत्र का उतना ही अधिक विकास होगा।



Fig.3·4

किन्तु उल्लेख्नीय है कि प्रत्येक अधिवास सेवा केन्द्र नहीं हो सकता क्यों कि किसी भी सेवा के पोषण के लिए जनसंख्या की एक न्यूनतम सीमा होती है। सेवा केन्द्रों के नियोजन के लिए आवश्यक है कि प्रदेशों में उनके वितरण एवं कार्यात्मक रिक्तता को भी ध्यान में रखा जाय। प्रस्तावित विकास केन्द्रों की अवस्थिति का निर्धारण बस्तियों के जनसंख्या आकार, बस्तियों में स्थित आधारभूत केन्द्रीय सुविधाएं, परिवहन साधनों की सुलभता, एवं यातायात अभिगम्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है (सारणी 3.9)।

सारणी 3.9 तहसील में प्रस्तावित विकास सेवा केन्द्र

विकास केन्द्र	जनसंख्य ा । १८ ।	वर्तमान सेवार	प्रस्ता वित सेवार
ा. अ ो रिल	4126	प्रा० वि०, पु०व ८० के०	वी०उ०के०, हा०स्कू०, प्रा०स्वा० उ०के०, यू०बैं०
2. भाँदो	3359	प्रा0वि0	प० अरुप०, सी० बे०रु कू०, प्रा०स्वा० उ० के०
उ. कोहड़ा	2680	प्रा० वि०, सी०वे०स्कू०, डा०६०	प०क्ठम०केठ, इ०काठ, प०मा० वि० कठउ०के०, संदेशग्रा०बैंठ, पु०वा० केठ
4. बखरा	2620	प्रा० वि०, ब०स्टे०, डा०६०	वि०ख० के०, प० अरुप०, हा० रु कू०, दूर० के०
5. नर्वे	2574	प्रा० वि०, ब०स्टे०, डा०६०	वी०उ०के०, सी०बे०स्कू०, प०व्य० क्नी०, पु०बा०के०

विक	ास केन्द्र	जनसंख्या । 98 ।	वर्तमान सेवार	प्रस्ता वित सेवा एँ
6.	रम्मौपुर	2201	प्रा० वि०	प्राटस्वा०उठके०, इ०का०, पुरवाठके०
7.	सदरपुर बरौन	T2035	न्या०प०के०, प्रा०वि०, वी०उ०के०	सी 0 बे0 वि०, ड TOE10, सं0क्षे0ग्रा 0 बैं0, पु.0 बा 0 के0
8•	बूढ़ा कुतुब्अली	1859	प्रा० वि०, सी० बे० स्कू०	प0अस्प0, प0व्य0 ब्ली०, परि० नि० के0, पु.0बा०के0
9.	भो रमऊँ	1846	प्रा० वि०, डा०६०	न्या ०प० के०, सी० बे० स्कू०, प० व्य० क्वी०, पु० बा० के०
10.	छि त्तेपु र	1241	प्रा० वि०, यू०बैं०	प०कृ०ग०के०, कृ०स०स०, सी०बे०स्कू०, प० नि०के०, डा०६०, पु०बा०के०
11.	करबा फ्तेहपुर	1629	प्रा० वि०	पु०चौ०, औष्ठा, पु०बा०के०
12.	बरा	1579	प्रा० वि०	प०कृ०ग०के०, डा०००, पु०बा०के०
13.	गोधना	1571	प्रा० वि०, ड ७०६०	सी० बेंo स्कूo, पo च्यo क्नीo, पूo बाo केo
14.	कुसावा	1488	ब०स्टे०, पू०बा०के०	पु०चौ०, वी०उ०के०, प्रा० वि०, प० च्य० क्वी०, डा०६०
15.	गोवाई	1479	प्राठ वि०, सी० बे ० स्कू०, इ र ० हा०	प०अस्प०, वी०उ०के०, सं०क्षे०ग्रा०बैं०, पु०बा०के०
16.	बस्ती चकगुलर	T1359	न्या ०पं०के०, वी ०उ० के०, प्रा० वि०	पण्ट्या क्वीं 0, पणमाण विश्व कव्य ० के०, डाण्डा०, पुणबाणके०
17.	कल र फतपुर	13 14	प्रा०वि०	पु०चौ०, प०अस्प०, वी०उ०के०, सी० वे०स्कू०, डा०६०, पु०बा०के०
18.	कु स् ध् चा	1210	न्या०पं० के०, वि०उ० के० प्रा० वि०, पु०बा० के०	, पु॰चौ॰, सी॰बे॰स्कू॰, डा॰ता॰च०, यू॰बें॰

विक	ास केन्द्र	जनसंख्या 1981	वर्तमान सेवार	प्रस्ता वित सेवा एँ
19.	बिला र मऊँ	1148	प्रा0वि0	वीठउ०के०, सीठबेठरकू०, प्राटस्वा० उ०के०, यूठबें०, फुठबाठकेठ
20.	बिइंहर	1072	प्रा0वि0	पुण्यौ०, वी०उ०के०, हा०स्कू०, औष्ण, पुण्डा०के०
21.	भरचिकया	1058	3T0EØ	वीठउ०के०, प्रा० वि०, औष्ठा०, पू० बा०के०
22.	नौहड़ा	1 229	प्रा०वि०, डा०६०	प०क्०ग०के०, सी०बे०स्कू०, प०ट्य० ब्ली०, पु०बा०के०
23.	बनहर	987	प्रा० वि०	ती०बे०स्कू०, प०ट्य० ब्ली०
24.	पलिया माफी	966	प्रा० वि०, सी० बे० स्कू०, डा० हा०	न्या ०प० के०, शी० भ०, प्रा०स्वा० के०, ब०स्टे०, पु०बा० के०
25.	नो नियाडी ह	937	न्या ०५० के०, वि०उ० के०	प्राव वि०२, माव वि१० क० उठ के ०, डाव ६०, संब्हेर ग्राव्हें ०, पुरु बाव के ०
26.	डीहपुर	885	प्रा०वि०	प० नि०उ०के०, डा॰चा०, पु०बा०के०
27.	ईशापुर	850	प्रा० वि०, डा० ६०	प०अस्प०, सी०बे०स्कू०, यू०बैं०, पु० बा०के०
28.	नाटी	463	प्रा० वि०	पु०चौ०, वी०उ०के०, ती०बे०स्कू०, ब०स्टे०, पु०बा०के०
29.	पिछौरा	462	प्रा०वि०,डा०च०	पुठचौठ, पठअस्पठ, सीठबेठस्कूठ, पुठबाठकेठ

विकास केन्द्र	जनसंख्य ा । १८।	वर्तमान सेवार	प्रस्ता वित सेवार
30. क्नेरी	418	न्या,०प०के०, वी०उ०के०	प्रा०वि०२, सी०बे०स्कू०, मा० भा०क० उ०के०, क्षेण्या०बैं०

शब्द संकेत

বি০ভা০ কৈ০	-	विकास खण्ड केन्द्र	अर्वे हा		अ दिशालय
न्या ०प० के०	•••	न्याय पंचायत केन्द्र	ब०स्टे ०	_	बस स्टेशन
पु0व1ै0	-	पुलिस चौकी	3 TOED	•	डाक्टर
प०अस्प०	***	पशु अस्पताल	ತ್ರಾಗ್≎ಕ್ರ	_	डाक एवं तारधर
वी ०३० के०	-	वीज एवं उर्वरक केन्द्र	दूर0के0	_	दूरभाष केन्द्र
प०कृ०ग०के०	-	पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	यू0बैं0	_	यू नियर बैंक
शी0भ0	_	शीत भण्डार	पु०बा ० के०	_	पुटकर बाजार केन्द्र
कु०स०स०	-	कृषि तहकारी तमिति	सं०क्षे0ग्रा०बैं०)_	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्रा० वि०	-	प्राथमिक विद्यालय	प०च्य० क्ली०)_	पंजीकृत व्यक्तिगत क्लीनिक
सी ० बे० स्कू०		सी नियर बेसिक स्कून	प्राण्स्वा०के०)_	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
ET 07 क 0		हाई स्कूल	प0 नि0 के0	-	परिवार नियोजन केन्द्र
<u>\$0</u>o T0		इण्टरमी डिस्ट कालेज	प० नि०उ ० के०	-	परिवार नियोजन उपकेन्द्र
प०मा ० झा० क०उ ० के०		- 6	प्रावस्वा ० उव्हेव	-	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र

अधिकांश प्रस्ता वित विकास केन्द्रों पर कुछ निम्नस्तरीय केन्द्रीय कार्य पहले से ही सम्पादित होते हैं। प्रस्तावित १ विकास केन्द्रों पर प्राथमिक विद्यालय तथा डाक्टर साथ-साथ हिथत हैं। छित्तेपुर प्रस्तावित सेवा केन्द्र पर यूनियन बैंक आफ इण्डिया की शाखा कार्यरत है। प्रस्तावित विकास केन्द्रों में से 5 न्याय पंचायत केन्द्र हैं। प्रस्तावित कुरुथ्वा विकास केन्द्र पर 4 निम्न स्तरीय केन्द्रीय सेवार (न्याय पंचायत केन्द्र, पुटकर बाजार केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय तथा बीज कीटनाशक एवं उर्वरक केन्द्र) स्थित हैं। 8 प्रस्तावित विकास केन्द्रों पर 3 निम्न स्तरीय केन्द्रीय सेवार तथा 10 केन्द्रों पर 2 सेवार सम्मन्न होती हैं। शेष्ट्रा प्रस्तावित सेवा केन्द्रों पर कोई न कोई एक सेवा अवश्य उपलब्ध है।

तहतील के सम्यक् विकास के लिए आवश्यक है कि प्रस्ता वित विकास केन्द्रों को वर्ष 2001 तक पूर्ण विकसित कर दिया जाय । इनमें से उसर के 13 प्रस्ता वित विकास केन्द्रों को 1995 तक विकसित करने की महती आवश्यकता है । अध्ययन प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए वर्तमान सेवा केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं में भी गुणा त्मक एक परिमाणा त्मक उन्नयन की आवश्यकता है ।

-----:0::----

सन्दर्भ

- 1. Pathak, R.K.: 'Environmental Planning Resources and Development', Chugh Publication, Allahabad, 1990, p. 54.
- 2. Babu, R.: 'Micro-Level Planning: A Case Study of Chhibramau Tahsil (Farrukhabad District, U.P.)' Unpublished D. Phil Thesis, Geography Department, Allahabad University, 1981.
- 3. Jefferson, M.: 'The Distribution of Worlds City Folks', Geographical Review, Vol. 21, p. 453.
- 4. Christaller, W.: Die Zentralen Orte in Suddent Schland,
 Jena, G. Fisher, 1933, Translated by C.W.
 Baskin, Englewood Cliffs, N.J., 1966.
- 5. Op.cit.; Fn.. I, p. 55.
- 6. Sen, L.K. : 'Planning of Rural Growth Centres for
 Integrated Area Development A Case
 Study in Miryalguda Taluka; NICD, Hyderabad,
 1971, p. 92.
- 7. Op.Cit, Fn. I., p. 61.
- 8. Hagget. P. etal: Determination of Population Threshold for Settlement, Functions by Readmuench Method, Professional Geographer, Vol.16,1964,pp.6-9

- 9. Roy, P. and Patil, B.R. (Ed): 'Manual for Block-Level Planning', Mackmillan, New Delhi, 1977, p. 25.
- 10. Wanmali, S.: Regional Planning for Social Facilities A Case Study of Eastern Maharashtra, NICD,
 Hyderabad, 1970.
- 11. Op.Cit. Fn. 6, p. 92.
- 12. Nityanand, P. and Bose, S. 'An Integrated Tribal Development Plane for Keonjhar District, Orrisa', NICD, Hyderabad, 1976.
- 13. Khan, W. Etal.: 'Plan for Integrated Rural Development in Pauri Garhwal, NICD, Hyderabad, 1976, pp. 15-21.
- 14. Singh, S.B.: 'Spacial Organisation of Settlement Systems'
 National Geographer, Vol. XI, No. 2, 1976,
 pp. 130-140.
- 15. Kumar, A. and Sharma, N.: 'Rural Centres of Services',

 Geographical Review of India, Vol. 39, No.1,

 1977, pp. 19-29.
- 16. Mishra, G.K.: 'A Methodology for Identifying Service

 Centres in Rural Areas, Behavioural Sciences

 and Community Development, Vol. 6, No. 1,

 1972, pp. 48-63.
- 17. Op.Cit. Fn. 1, p. 61.

- 18. Singh, J.: Central Places and Spacial Organisation in A Backward Economy-Gorakhpur Region: A Case Study Integrated Regional Development, Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakhpur, 1979.
- 19. Alam, S.M., Gopi, K.N. and Khan, W.A.: 'Planning for Metropoliton Region of Hyderabad: A Case Study, S.P. Chatterjee etal (ed.), Proceedings of Symposium on Regional Planning, National Committee of Geography, Calcutta, 1971.
- 20. Dutta, A.K.: 'Transportation Index in West Bengal A

 Means to Determine Central Place Hierarchy'

 National Geographical Journal of India,

 Vol. 16, No. 3 & 4, 1970, pp. 199-207.
- 21. Prakash Rao, V.L.S.: Problems of Micro-Level Planning'
 Behavioural Sciences and Community Development, Vol. 6, No. 1, 1972, p. 151.
- 22. Op.Cit., Fn. 4.
- 23. Brush, J.E.: 'The Hierarchy of Central Places in South-Western Wisconsin', Geographical Review, Vol. 43, No. 3, 1953, pp. 380-407.
- 24. Duncun, J.S.: 'New-Zeeland Towns as Service Centres, N. Z.G., Vol. 11, 1955, pp. 119-138.
- 25. Carter, H.: Urban Grades and Spheres of Influence in South-West Wales, Scot Geography Mag., Vol. 71, 1955, pp. 43-58.

- 26. Ullman, E.L.: Trade Centres and Tributary Areas of Phillippines, Geographical Review, Vol. 50, 1960, pp. 203-218.
- 27. Hartley, G. and Smailes, A.E.: 'Shopping Centres in Greater London Areas', Trans. Inst. Br., Geog. 29, 1961, pp. 201-203.
- 28. Bracey, H.E.: Towns as Rural Science Centres', Trans, Inst.
 Br. Geography 19, 1962, pp. 95-105.
- 29. Green, F.H.W.: 'Motor Bus Centres in South-West England Considered in Relation to Population and Shopping Facilities', Trans., Inst. Br. Geog. Vol. 14, 1948, pp. 57-69.
- 30. Carruthers, W.I.: 'A Classification of Service Centres in England and Wales', Geographical Journal, Vol. 123, 1957, pp. 371-385.
- 31. Berry, B.J.L. and Garrison, W.L.: 'The Functional Bases of the Central Hierarchy', Economic Geography, Vol. 34(2), 1958, pp. 145-154.
- 32. Siddal, W.R.: Wholesaler Ratial Trade Ratios as Index of Urban Centrality', Economic Geography, Vol. 37, 1961.
- 33. Preston, R.E.: 'The Structure of Central Place Systems', Economic Geography, Vol. 47(2), 1971, pp. 136-155.

- 34. Vishwanath, M.S.: A Geographical Analysis of Rural
 Markets and Urban Centres in Mysore,
 Ph.D. Thesis, B.H.U., Varanasi.
- 35. Singh, O.P.: 'Towards Determining Hierarchy of Service Centres A Methodology for Central Place Studies, N.G.J.I, Vol. xvii (4), 1971, pp. 165-167.
- 36. Rao, V.L.S.P.: Planning for an Agricultural Region, In New Strategy Vikas, New Delhi, 1974.
- 37. Singh, J.: 'Nodal Accessibility and Central Places
 Hierarchy A Case Study in Gorakhpur
 Region, National Geographer, Vol. XI(2),
 1976, pp. 101-112.
- 38. Jain, N.G.: 'Urban Hierarchy and Telephone Services in Vidarbh (Maharashtra), N.G.J.I., Vol. 17 (2 & 3), 1971, pp. 134-137.
- 39. Op.Cit. Fn.36.
- 40. Op.Cit. Fn. 2.
- 41. Bhatt, L.S. Etal.: Micro-Level Planning A Case Study of Karnal Area, Haryana India', Vikas, New Delhi, 1976.
- 42. Op.Cit. Fn. 4.
- 43. Sharma, R.C.: 'Settlement Geography of the Indian Desert', K.B.P., New Delhi, 1972, p. 180.

- 44. Clark, P.G. and Evans, F.G.: 'Distance to Nearest Neighbour as a Measure of Spacial Relationship in Population', Ecology 35, 1964,
 pp. 445-453.
- 45. Daccey, M.F.: 'The Spacing of River Towns', A.A.A.G. 50, 1960, pp. 59-61.
- 46. King, L.J.: 'A Quantitative Expression of the Pattern of Urban Settlements in Selected Areas of United States' Tijdscrift Voor Economische en sociale Geografie, 53, 1962, pp. 1-7.
- 47. Mather, E.C.: 'A Linear Distance Map of Farm Population in United States', A.A.A.G. 34, 1944, pp. 173-180.
- 48. Converse, P.D.: 'New Law of Retail Gravitation', Journal of Marketing, Vol. 14, 1949,

--::0::----

अध्याय चार

कृषि एवं कृषि-विकास हेतु नियोजन

4.। प्रस्तावना

अध्ययन प्रदेश एक कृष्णि प्रधान तहसील है। यहाँ की अर्थट्यवस्था मुख्यरूप से कृष्णि पर आधारित है। क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या का १। प्रतिवात से अधिक भाग कृष्णि एवं उससे सम्बन्धित कार्यों में लगी हुई है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 72.76 प्रतिवात भाग पर कृष्णि की जाती है। अस्तु, कृष्णि यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का साधन एवं अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि मिद्दी की गन्ध भी उनके संस्कार में रची-बसी हुई है।

देश में कृष्ण के विकास के लिए किये गये प्रयासों का प्रभाव यहाँ की कृष्ण पर भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है। विभिन्न विकास-योजनाओं के अन्तर्गत कृष्ण का यन्त्रीकरण तथा उन्नतःशील बीजों, उर्वरकों, खरपत्तवार एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग प्रारम्भ हुआ जिसके फ्लस्वरूप कृष्णि का विकास सम्भव हो सका किन्तु यह विकास वह वांछित गति न पा सका जो क्षेत्र की बद्धती हुई जनसंख्या के भरण-पोष्णण के लिए पर्याप्त हो। कृष्णि का विकास पूँजी, तकनीक तथा संगठन जैसे सामाजिक आर्थिक संसाधनों की कमी से बाधित है। कृष्णि का वांछित विकास न होने से आज भी क्षेत्र में लोगों का जीवन-स्तर काफी निम्न है।

अध्ययन प्रदेश के समुचित विकास के लिए कृष्णि का नियोजन आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की भूमि की उर्वराशक्ति को सुरक्षित रखते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। प्रस्तुत अध्ययन उक्त दिशा में किया गया एक निधु प्रयास है । इसमें कृषि-विकास के वर्तमान स्वरूप के विवेचनोपरान्त भावी कृषि विकास हेतु नियोजन प्रस्तुत किया गया है । कृषि के वर्तमान स्वरूप के भौगोलिक विवेचन में मैकमास्टर² द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक अध्ययन के तीनों उपागमों - पारिस्थितिकी, भूमि-उपयोग तथा सांख्यिकीय में से केवल भूमि-उपयोग उपागम को ही अपनाया गया है । आंकड़ों एवं सूचनाओं की उपलब्धि में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण अन्य दो उपागमों पर ध्यान देना सम्भव नहीं हो सका है । प्रस्तुत अध्ययन में ग्राम स्तर पर तहसील मूख्यालय से अप्रकाशित राजस्व अभिनेखों, जिला कृषि कार्यालय और विकास-खण्ड कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों को आधार बनाया गया है ।

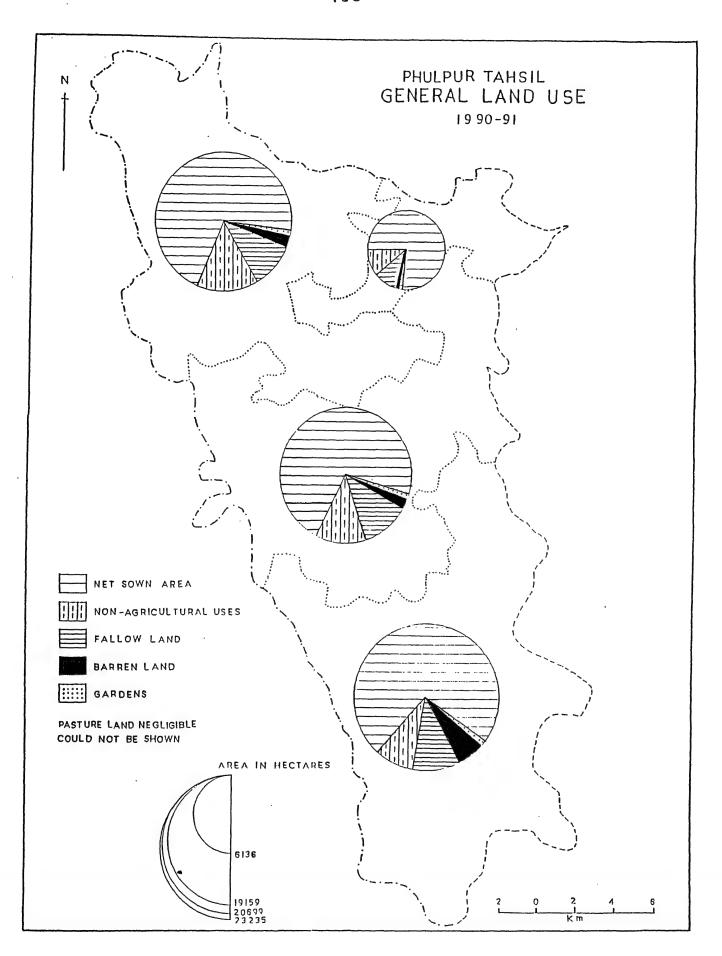
4. 2 तामान्य भूमि-उपयोग

तहतील के तम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रपत का 85. 14 प्रतिव्ञत भाग कृष्ठि योग्य है जितमें गुद्ध बोये गये क्षेत्र के साथ-साथ चरागाह, वर्तमान परती, पुरानी परती एवं कृष्ठि योग्य बंजर भूमि भी तमाहित है । शेष्ठ 14.86 प्रतिव्ञत भाग कृष्ठि के अयोग्य है जितमें उत्तर भूमि, अधिवात एवं अन्य उपयोगों में प्रयुक्त की गयी भूमि तमाहित है (सारणी 4.1) । कृष्ठि योग्य भूमि का यह प्रतिव्ञत अहरौला(1), पवई तथा पूलपुर विकासखण्डों में क्रम्बा: 89.11, 85.85 तथा 85.19 है जो तहतील के औतत से अधिक है । मार्टिनगंज विकासखण्ड में 83.37 प्रतिव्ञत क्षेत्र कृष्ठि योग्य है जो तहतील के औतत से कम है । न्याय पंचायत स्तर पर सबसे अधिक कृष्ठि योग्य भूमि (88.191) पूलपुर विकासखण्ड के सदरपुर बरौली में है जबिक सबसे कम कृष्ठि योग्य भूमि मार्टिनगंज विकासखण्ड के सदरपुर बरौली में है जबिक सबसे कम कृष्ठि योग्य भूमि मार्टिनगंज

सारणी 4.1 तामान्य भूमि-उपयोग, 1990-91

			- 100 400 400 400 400 400 400			(हे क्	वेयर में)
	भूमि विवरण	अहर ो ला <u>।</u> विकासकण्ड	पव ई विकासखण्ड	फूनपुर विकासखण्ड	मारिनगंज विकासिखण्ड	फूलप्र तहस्रील	क्ल भौगोलिक क्षेत्रफल मे प्रतिशत
1.	शुद्ध कृषि कृत भूमि	4745	14626	13886	17112	50369	72.76
2.	चरागाह	9	22	56	51	138	0.20
3.	कृषि योग्य बंजर भूमि	159	711	555	733	2158	3.12
4.	वर्तमान परती	121	1627	1417	897	4067	5.87
5.	पुरानी परती	434	785	408	578	2205	3. 19
	कुल कृषा योग्य भूमि	5468	17771	16322	19371	58932	85. 14
6.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गई भूमि	523	2228	2154	2198	7 103	10. 36
7.	उद्यानों एवं वनों का क्षेत्रपल	88	207	. 260	333	888	1. 28
8.	उसर एवं कृषा अयोग्य भूमि	49	493	423	1333	2298	3. 22
	कुल कृषा अयोग्य भूमि	668	29 28	2837	3864	10297	14.86
	द्विपसनी क्षेत्र	2517	9 48	7529	9016	28210	40. 75
	सकल बोया गया क्षेत्र	5849	23552	20633	24104	74138	107. 09

म्रोत : (1) लेखपाल खप्तरा मिलान, पूलपुर तहसील, पसली वर्ष 1398 (1990-91) (2) वार्षिक अण योजना, जनपद आजमगढ़, 1990-91



(।) शुद्ध बोया गया क्षेत्र

भूमि उपयोग का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष शुद्ध कृष्ठित भूमि है । कृष्ठित भूमि मुख्यतः तिंचाई के साधनों, उर्वरकों, उन्नित्तिणि बीजों, नवीन कृष्ठि-यन्त्रों, नूतन कृष्ठि पद्धित एवं प्राविधिक ज्ञान से प्रभावित होती है जिसका प्रभाव अध्ययन- क्षेत्र के कृष्ठित भूमि पर स्पष्ठतः परिलक्षित होता है । शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत वास्तविक रूप से कृष्ठि किये गये क्षेत्र को समाहित किया गया है । तहसील का शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्ष 1990-9। में 50369 हे क्टेअर था जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रपल का 72.76 प्रतिवात है । कुल भौगोलिक क्षेत्रपल का सब्से अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र 77.33 प्रतिवात अहरीला(1) विकासखण्ड और सब्से कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र 70.66 प्रतिवात पवई विकासखण्ड में है ।

(2) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र

जब किसी क्षेत्र में वर्ष में एक से अधिक पसलें विभिन्न समयों में उगायी जायें तो उसे दिपसली क्षेत्र कहा जाता है जो मिश्रित कृष्ठि से भिन्न है । मिश्रित कृष्ठि में जहां एक ही समय में एक क्षेत्र में साथ-साथ कई पसलें उगायी जाती हैं वहीं एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्र में पसलों के समय अलग-अलग हुआ करते हैं जो मिद्दी की उर्वराशक्ति, सिंचाई तथा आधुनिक कृष्ठि निविष्टि जैसी सुविधाओं का द्योतक है । तहसील में एक बार से अधिक बोया गया कुन क्षेत्र 28210 हे क्टेअर है जो कुन भौगोलिक क्षेत्रपत्न का 40.75 प्रतिश्वात (सारणी 4.1) तथा शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 56.01 प्रतिश्वात है । द्विपसली क्षेत्र का सर्वाधिक उच्च धनत्व 62.55 प्रतिश्वात पवई विकास-खण्ड में है । अवरोही क्रम में पूलपुर, अहरौना(1) तथा मार्टनगंज

विकासखण्ड आते हैं जहाँ पर द्विपसली क्षेत्र का प्रतिमात क्रमम: 54.22, 53.05 तथा 52.69 है।

4. उ पसल प्रतिरूप

विभिन्न फ्तलों के स्थानिक और कालिक वितरण से बने प्रतिरूप को फ्तल प्रतिरूप कहते हैं। उप्तलों के इस वितरण प्रतिरूप को भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक इत्यादि अन्यान्य कारक प्रभावित करते हैं। फूलपुर तहसील में वर्ष में तीन फ्तलें - खरीफ, रबी एवं जायद क्रमशः वर्षा, शरद एवं ग्रीष्म श्रृतुओं में उगायी जाती हैं जिनमें खरीफ एवं रबी की फ्तलें ही मुख्य हैं जो कुल कृष्वित क्षेत्र के क्रमशः 76.25 प्रतिशत तथा 70.37 प्रतिशत भाग पर उगायी जा रही हैं जबकि जायद की फ्तल मात्र 0.57 प्रतिशत भाग पर ही उगायी जाती हैं।

(i) <u>विभिन्न वर्गीय पसलें</u>

अध्ययन प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फ्तलें उगायी जाती हैं। इन्हें परम्परागत रूप से तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है -

क.) खरीफ

मानसून के आगमन के साथ जून-जुलाई * में बोयी जाने वाली फ्सलों को खरीफ के नाम से जाना जाता है। पूलपुर तहसील में खरीफ फ्सल के अन्तर्गत रबी की फ्सलों से अधिक क्षेत्र लगा हुआ है। वर्ष 1990-91 में रबी की कृष्टा के अन्तर्गत 35444

[×]गन्ना तथा कुछ अन्य पसलें सिंचाई करके मई में भी बोघी जाती हैं।

हेक्टेअर भूमि थी जबकि खरीफ के अन्तर्गत 38407 हेक्टेअर भूमि । खरीफ की फ्सलों में चावल, मक्का, जूट, मूँगफ्ली, गन्ना, अरहर, उइद, मूँग आदि मुख्य हैं। तह= सील में वर्ष 1990-91 में कुल कृष्टि योग्य भूमि के 65.17 प्रतिशत भाग पर खरीफ की कृषि की गयी जो सकल बोये गये क्षेत्र का 51.80 प्रतिशत है। प्लपर विकासखण्ड में कुल कृष्टि योग्य भूमि के 75.35 प्रतिशत क्षेत्र पर खरीफ की कृष्टि की गयी जबकि पवर्ई, मार्टिनगंज तथा अहरौला। विकासखण्ड के कुल कृष्ठि योग्य भूमि के क्रम्बा: 71.39. 62.31 तथा 52.30 प्रतिशत भाग पर । अहरौला(I) विकासखण्ड में खरीफ की पसल कम होने का कारण भूमि सतह का निम्न होना है। मधुई तथा टोंस नदियों की बाद के कारण इन भागों में खरीफ की फ्सलें कम उगायी जाती हैं क्यों कि बाद के कारण फ्लों प्राय: नष्ट हो जाती हैं। तुरहन न्यायपंचायत (मार्टिनगंज विकासखण्ड) में कुल कृष्टि योग्य भूमि के 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल पर तथा अम्बारी, बाग तिकन्दरपुर, सुल्तानपुर, सौदमा धानेशवर, बस्ती सदनपुर, मिन्तूपुर (पवई विकास खण्ड); खंजहापुर, सजई अमानबाद, नोनियाडीह, गद्दौपुर बारी, राजापुर, खर-सहन कला (पूलपुर विकासखण्ड) न्यायपंचायतों के 80 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर खरीफ की कृषि की जाती है। गनवारा न्यायपंचायत (अहरौला(I) विकासखण्ड) में सब्से कम 47. 29 प्रतिशत क्षेत्र पर खारीफ की फ्तल उगायी जाती है।

खरीफ में प्रयुक्त की गयी भूमि के 86.65 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्नों की कृष्णि की जाती है। शेषा 13.35 प्रतिशत भाग पर अन्य फ्तलें उगायी जाती हैं। खाद्यान्नों में दलहन का अंश मात्र 5.07 प्रतिशत है। खरीफ में उत्पन्न की जाने

वाली प्रमुख फ्सलें - अनाज, दलहन तथा गन्ना है जिनका अलग-अलग विवरण आगे प्रस्तुत है -

(अ) अनाज

अध्ययन प्रदेश में खरीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल के 81.58 प्रतिशत भाग पर अनाज की कृष्णि की जाती है। अनाजों में सबसे महत्त्वपूर्ण फ्सल चावल है जो खरीफ के अन्तर्गत कुल बोये गये क्षेत्र के 75.29 प्रतिशत भाग पर उगाया जाता है। यह सकल बोये गये क्षेत्र का 39.01 प्रतिशत है (सारणी 4.2)।

सारणी 4.2 खरीफ के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का विवरण, 1990-91

पस्तल	खरीफ में बोये गये कुल क्षेत्र 38407 हेक्टेअर भूमि को ४	सकल बोचे गये क्षेत्र 74138 हेट्टियर का		
खाद्यान्न	86. 65	44. 89		
अनाज	81.58	42.26		
च 🗖 वल	75. 29	39.01		
मक्का	6. 28	3. 25		
दलहन	5. 07	2. 63		
गन्ना	12.00	6. 22		
अन्य	1.35	0.70		
	100,00	51.80		

स्रोत: लेखपाल का खरीफ उपज ब्यौरा, फूलपुर तहसील, फ्सली वर्ष 1398 (1990-91)

मार्टिनगंज विकासखण्ड में सबसे अधिक खरीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के 82.54 प्रतिवात भाग पर चावल की कृष्ठि की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 41.33 प्रतिवात है । सबसे कम अहरौला(I)विकासखण्ड के 59.45 प्रतिवात भाग पर चावल की कृष्ठि की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 29 प्रतिवात है । मार्टिन-गंज विकासखण्ड में चावल अधिक क्षेत्र पर बोने का कारण वहाँ उसर भूमि की अधिकता है जिस पर केवल वर्षाकाल में ही पसल लेना संभव हो पाता है । अहरौला(I)विकास खण्ड में चावल कम क्षेत्र पर बोने का कारण महुई तथा दोंस नदियाँ हैं, वर्षा भृत में बाद के कारण पसल नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है । पवई तथा पूलपुर विकासखण्डों में खरीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के क्रम्वा: 73.88 तथा 73.04 प्रतिवात भाग पर चावल की कृष्ठि की जाती है ।

चावल के बाद मोटे अनाजों में मक्का प्रमुख है जो खरीफ के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि के 6.28 प्रतिवात तथा सकल बोये गये क्षेत्र के 3.25% भाग पर उगाया जाता है। सबसे अधिक मक्का की कृष्ठि पूनपुर विकासखण्ड में 8.75 प्रतिवात भाग पर की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 5.23 प्रतिवात है। सबसे कम पवर्ड विकासखण्ड के 4.68 प्रतिवात भाग पर मक्के की कृष्ठि की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 2.53 प्रतिवात है। पूलपुर विकासखण्ड में मक्का अधिक बोने का कारण यहाँ मक्के की कृष्ठि का सवल परम्परागत रूप एवं मिद्दी का अनुकूल होना है। पवर्ड विकासखण्ड में चावल की कृष्ठि की प्रधानता का कारण मक्के की कृष्ठि का अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल पर बोया जाना है। अहरौला(I) विकासखण्ड में सकल बोये गये क्षेत्र के 4.89 प्रतिवात तथा मार्टिनगंज विकासखण्ड के 2.54 प्रतिवात भाग पर मक्के की कृष्ठि की जाती है।

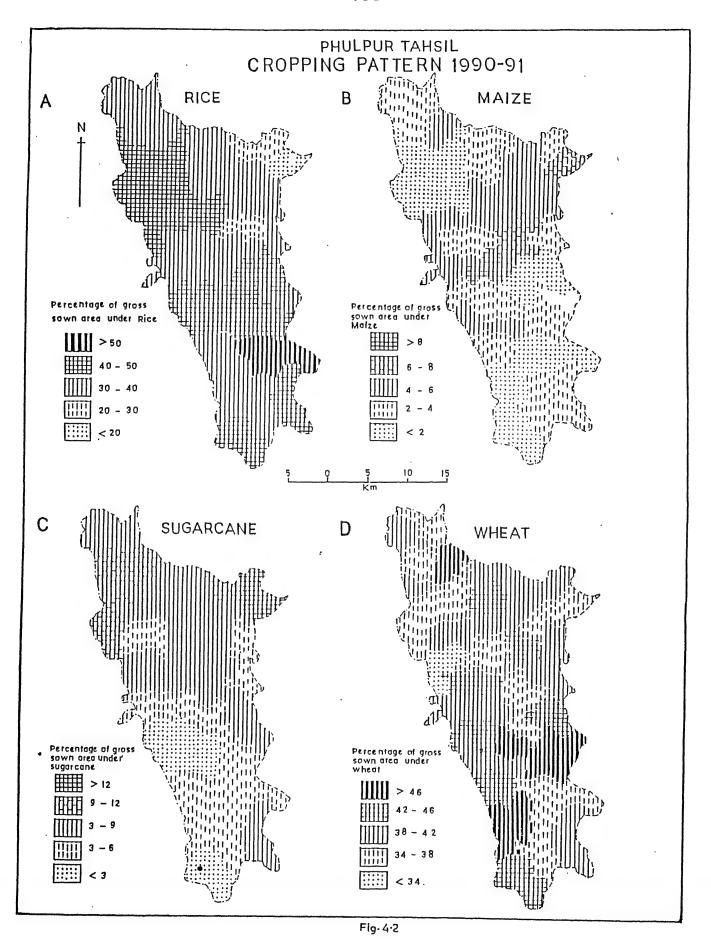
(ब) दलहन

दलहन में बोयी जाने वाली फ्सलों में अरहर, उड़द और मूँग मुख्य हैं। इनकी कृषि मिश्रित ढंग से की जाती है। खरीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के 5.07 प्रतिशत भाग पर दलहन की पसलें उगायी जाती हैं जो सकल बोये गये क्षेत्र का 2.63 प्रतिशत है। विकासखण्ड स्तर पर सब्से अधिक दलहनी फ्सने अहरौना I विकासखण्ड में बोयी जाती हैं जो खरीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र का 8.40 प्रतिशत तथा सकल बोये गये क्षेत्र का 4. 10 प्रतिशत है । सबसे कम मार्टिनगंज विकासखण्ड में 2. 55 प्रति-शत क्षेत्रफल पर दलहन की फ्सलें उगायी जाती हैं जो सकल बोये गये क्षेत्र का 1.28 प्रतिशत है। इसके बाद पूलपुर तथा पवई का स्थान आता है जहाँ सकल बोये गये क्षेत्र के क्रमश: 3.93 तथा 2.94 प्रतिशत भाग पर दलहन की कृष्टा की जाती है। न्याय पंचायत स्तर पर सबसे अधिक दलहन की कृषि मिन्तूपुर (पवर्ड विकासखण्ड) में खरीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के 10.38 प्रतिशत भाग पर की जाती है जबकि सबसे कम । 46 प्रतिशत मार्टिनगंज विकासखण्ड के महुआरा में । मिन्तुपुर न्याय पंचायत में दलहन की अधिक कृष्णि करने का कारण वहाँ की उपयुक्त मिद्री एवं भूमि का उचित दाल है। दालूदार भूमि होने के कारण वर्षा का पानी इनकी जड़ों में नहीं लग पाता है। महुआरा न्याय पंचायत में सबसे कम दलहन की कृष्टि का कारण यहाँ चावल की कृषा की प्रमुखता है।

(त) अन्य पतलें

हारीफ में बोयी जाने वाली मुद्रादायिनी फताों में गन्ने की कृषि प्रमुख है जो हारीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के 12 प्रतिशत तथा सकल बोये गये क्षेत्र के 6.22 प्रतिशत भाग पर उगायी जाती है। विकासहण्ड स्तर पर सब्से अधिक गन्ने की कृषि अहरौला I में हारीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के 19.10 प्रतिशत तथा सकल बोये गये क्षेत्र के 9.33 प्रतिशत भाग पर की जाती है। सब्से कम गन्ने की कृषि मार्टिनगंज विकासहण्ड के 9.22 प्रतिशत भाग पर की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 4.62 प्रतिशत है। इसके बाद पवई तथा पूलपुर का स्थान आता है जहाँ हारीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के क्रम्या: 14.20 तथा 10.62 प्रतिशत भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। न्याय पंचायत स्तर पर सब्से अधिक गन्ने की कृषि पारा मिश्रौलिया (अहरौला(म) विकासहण्ड) में हारीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के 31.42 प्रतिशत भाग पर की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 14.37 प्रतिशत है। इस न्याय पंचायत में गन्ने की कृषि की प्रमुखता का कारण उत्तम मिद्दी एवं सिंचाई के साधनों की अधिकता है। सब्से कम गन्ने की कृषि महुआरा न्याय पंचायत (मार्टिनगंज विकासहण्ड) में की जाती है जो हारीफ के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र का 4.56 प्रतिशत भाग है। सम्प्रति क्षेत्र में

*गन्ना एक वर्षीय पसल है। यह रबी तथा खरीफ दोनों मौसमों में बोया जाता है किन्तू अध्ययन प्रदेश में गन्ने की कृष्णि रबी की अपेक्षा खरीफ में अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है।



गन्ने की कृषि का क्षेत्रफल काफी घटा है। मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है और दूसरी सुविधाओं का भी अभाव है।

खाद्यान्नों के अनावा खरीफ के अन्तर्गत बोयी जाने वाली फ्तलों में वारा, सब्जी तथा तिलहन हैं किन्तु इनमें वारा ही प्रमुख है। तहतील में खरीफ में बोये गये क्षेत्र के 1.35 प्रतिशत भाग पर वारे, सब्जी तथा तिलहन की कृष्ण की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 0.70 प्रतिशत है। मोटे अनाजों में ज्वार-बाजरा की कृष्ण के साथ-साथ सनई तथा पटसन जैती कुछ रेशे वाली फ्तलें भी उगायी जाती हैं। पटसन की कृष्ण अधिकतर गन्ने के खेतों के किनारों पर की जाती है।

(ख) रबी

शीतकाल के प्रारम्भ में अक्टूबर से दिसम्बर तक बोयी जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फ्सलों को रबी की फ्सल के नाम से जाना जाता है। ये फ्सलें मुख्यत: सिंचाई पर आश्रित होती हैं। रबी की फ्सलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों तथा वरसीम मुख्य हैं। अध्ययन प्रदेश में इन फ्सलों की प्रतिरूप सारणी 4.3 से स्पष्टत है।

अध्ययन प्रदेश में खरीफ की फ्ता की तूलना में रबी की फ्ता कि विकास कम हुआ है। खरीफ की कृष्वि सम्पूर्ण तहसील की कृष्वि योग्य भूमि के 65. 17 प्रति-शत क्षेत्र पर की जाती है जबकि रबी की कृष्वि 60. 14 प्रतिशत भाग पर, जो सकल बोये गये क्षेत्र का 47.81 प्रतिशत है। रबी के कुल बोये गये क्षेत्र के 94.38 प्रतिशत पर खाद्यान्न, 2.30 प्रतिशत भाग पर आलू, 2.02 प्रतिशत भाग पर तिलहन तथा शेष्ठा 1.30 प्रतिशत भाग पर अन्य पसलें-चारा तथा सब्जी आदि उगायी जाती हैं।

सारणी 4.3 रबी की पसलों का प्रतिरूप, 1990-91

 फ्तल	रबी में प्रयुक्त कुल क्षेत्रफल 35444 हे क्टेअर का प्रतिद्यात	सकल बोग्ने गये क्षेत्र 74138 हेक्टेअर से प्रतिद्वात		
खाद्यान्न	94.38	45.12		
अनाज	85.81	41.02		
गेहूँ	83. 64	39.99		
अन्य	2.17	1. 03		
दलहन	8.57	4.10		
चना	4. 41	2.11		
म्टर	4. 16	1.99		
अरलू	2.30	1.34		
तिलहन	2.02	1.07		
अन्य	1.30	0.62		
কুল	100.00	47.81		

स्रोत: लेखपाल की रबी पसल ब्यौरा, पूलपुर तहसील, पसली वर्ष 1398 (1990-91) से संगणित

(अ) अनाज

रबी के अन्तर्गत आच्छादित भूमि के 85.8। प्रतिशत भाग पर अनाज की कृष्णि की जाती है। अनाजों में गेहूँ मुख्य है। सी मित क्षेत्र पर गेहूँ तथा जौ की मिश्रित कृष्णि की जाती है जिसे 'गोजई' के नाम से जाना जाता है।

गेहूँ की कृष्ण रबी के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र के 83.64 प्रतिम्नत भाग पर की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 39.99 प्रतिम्नत है । सम्प्रति तहसील में गेहू की कृष्ण की लोकप्रियता का मुख्य कारण सिंचाई, उर्वरक, उन्नितिम्नील बीज एवं नवीन कृष्ण पद्धिति का उपयोग आदि है । विकासखण्ड स्तर पर सब्से अधिक गेहूँ की कृष्ण पूनपुर में सकल बोये गये क्षेत्र के 45.52 प्रतिम्नत भाग पर की जाती है जबिक सबसे कम गेहूँ की कृष्ण पवई में 37.95 प्रतिम्नत भाग पर । पवई विकासखण्ड में गन्ने की कृष्ण की प्रधानता है जिससे गेहूँ की कृष्ण के अन्तर्गत क्षेत्रपल कम है । गन्ने की कृष्ण एक वर्ष की होती है किन्तु एक बार बोये गये गन्ने से दो या तीन वर्षों तक उत्पादन किया जा सकता है । मार्टिनगंज तथा अहरौला(X) विकासखण्डों में सकल बोये गये क्षेत्र के क्रम्मा: 42.57 तथा 38.34 प्रतिम्नत भाग पर गेहूँ की कृष्ण की जाती है ।

न्याय पंचायत स्तर पर बेलवाना, कस्बा फतेहपुर, कौरागहनी, छितर अहमदपुर (मार्टिनगंज विकासखण्ड), महुआरा (फूलपुर विकासखण्ड) में सकल बोये गये क्षेत्र के 45 प्रतिशत से अधिक भाग पर गेहूँ की कृष्टि की जाती है। सबसे कम गेहूँ सुरहन (मार्टिनगंज विकासखण्ड) में 35.14 प्रतिशत भाग पर उगाया जाता है। यहाँ पर सिंचाई के साधनों का समुचित विकास नहीं हो पाया है, साथ ही उसर भूमि की भी अधिकता है।

(ब) दलहन

अध्ययन प्रदेश में दलहनी पसलों का उत्पादन रबी के कुल कृष्ठित भूमि के 8.57 प्रतिशत भाग पर होता है जो सकल बोये गये देख्न का 4.10 प्रतिशत है। रबी के अन्तर्गत बोयी गयी दलहनी पसलों में चना तथा मटर मुख्य हैं। चने की कृष्ठि सकल बोये गये देख्न के 2.11 प्रतिशत भाग पर की जाती है। चने के अन्तर्गत सर्वाधिक बोया गया देख्न मार्टिनगंज विकासखण्ड के जगदीशपुर ददेशिया (3.79%) तथा लसराखुर्द (3.47%) न्याय पंचायतों में है। चने की कृष्ठि के लिए बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। रबी के पसल काल में यदि एक बार भी हल्की वर्षा हो जाय तो चने की कृष्ठि के लिए पर्याप्त है। सबसे कम चने की कृष्ठि पूजपुर विकासखण्ड के खरसहन कला (0.64%) और बहुआरा (0.64%) न्याय पंचायतों में की जाती है। इसका मुख्य कारण यहाँ गेहूँ की कृष्ठि की प्रधानता है।

तहसील में मटर की कृष्णि सक्ल बोये गये क्षेत्र के 1.99 प्रतिशत भाग पर की जाती है। मार्टिनगंज विकासखण्ड में सबसे अधिक सक्ल बोये गये क्षेत्र के 2.11 प्रति शत भाग पर मटर की कृष्णि की जाती है जबकि सबसे कम पूलपुर विकासखण्ड में 1.74 प्रतिशत भाग पर । अहरौला(I)तथा पवई विकासखण्डों में क्रमश: 2.00 तथा 1.84 प्रतिशत क्षेत्र पर मटर की कृष्णि की जाती है। न्याय पंचायत स्तर पर इसकी सबसे अधिक कृष्णि लसरा खुर्द (3.47%) तथा जगदीशपूर ददेरिया (3.21%) में की जाती है जबकि सबसे कम खरसहन कला (1.08%) में।

(स) तिलहन

रबी के अन्तर्गत बोयी जाने वाली तिलहनी फ्तलों में सरतों, राई तथा अलती मुख्य हैं जिनका उत्पादन गेहूँ तथा दलहनी फ्तलों के ताथ मिश्रित कृषि के रूप में किया जाता है। तरतों की कृषि मुख्यत: गेहूँ तथा मदर के ताथ मिश्रित रूप में की जाती है जबकि अलती चने के ताथ। तिलहनी फ्तलों का उत्पादन रबी द्वारा आच्छादित भूमि के 2.24 प्रतिन्नति भाग पर किया जाता है जो तकल बोयी गयी भूमि का 1.07 प्रतिन्नति है। तबसे अधिक तिलहन की कृषि तकल बोये गये क्षेत्र के 1.79 प्रतिन्नति भाग पर फूनपूर विकासखण्ड में की जाती है जबकि तबसे कम मार्टिनगंज विकासखण्ड के 1.23 प्रतिन्नति भाग पर । अहरोला म तथा पवई विकासखण्डों में तिलहन की कृषि क्रमन: 1.66 तथा 1.39 प्रतिन्नति भाग पर की जाती है।

(द) आलू तथा अन्य सिब्जयाँ

तहसील में सकल बोये गये क्षेत्र के 1.34 प्रतिशत भाग पर आलू की कृष्य की जाती है जो रबी के अन्तर्गत बोयी गयी भूमि का 2.30 प्रतिशत है । सिब्जयों की कृष्य सकल बोये गये क्षेत्र के 0.62 प्रतिशत भाग पर की जाती है जो रबी के अन्तर्गत बोयी गयी भूमि का 1.30 प्रतिशत है । आलू की कृष्य सम्मूर्ण तहसील में लगभग समान रूप से वितरित है ।

(ग.) जायद

रबी की फ्सल के बाद तथा खरीफ की फ्सल के पहले ग्रीष्मकालीन संक्रमण काल में जायद की कृष्णि की जाती है। जायद की फ्सलों में उइद, मूँग, खरबूजा,

बूज, ककड़ी तथा अन्य अनेक ग्रीष्म कालीन सिंडजयां मुख्य हैं। सम्मूर्ण तहसील के 287 हे क्टेअर भूमि पर जायद की पसल उगायी जाती है जो सकल बोयी गयी भूमि का 0.49 प्रतिशत है। सबसे अधिक पूलपुर विकासखण्ड में सकल बोयी गयी भूमि के 0.56 प्रतिशत भाग पर तथा सबसे कम मार्टिनंगंज विकासखण्ड के 0.29 प्रतिशत भाग पर जायद की कृष्णि की जाती है। जायद की कृष्णि पूर्णतः सिंचाई पर आश्रित है इसलिए इसकी कृष्णि मुख्यतः नलकूपों वाले क्षेत्रों तथा नहरों के समीपवर्ती भागों में की जाती है। ग्रीष्मकाल में नहरों में जलापूर्ति लगभग अनिश्चित रहती है। अतः इसकी कृष्णि अन्य सिंचाई के साधनों के समीप की जाती है।

(2) फ्तल प्रतिरूप में कालिक परिवर्तन

सारणी 4.4 से स्पष्ट होता है कि पिछले एक दशक में तहसील के पसल प्रतिरूप में कुछ विशिष्ट परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन कृष्टि निविष्ट (Inputs) और नवीन कृष्टि विध्यों के विकास तथा कृष्टकों का पसलों के प्रति जागरूकता के कारण संभव हो सका है।

पसल प्रतिरूप में अधिकतम परिवर्तन खाद्यान्नों में हुआ है । यद्यपि धान पहले तहसील की मुख्य पसल थी किन्तु वर्तमान समय में गेहूँ ने तहसील की मुख्य पसल का स्थान ले लिया है जो सकल बोये गये क्षेत्र के 39.99% भाग पर उगाया जाता है। वर्ष 1979-80 में 26.59 प्रतिशत भाग पर गेहूँ की कृष्णि की गयी । इस प्रकार जहाँ गेहूँ के क्षेत्र में वर्ष 1979-80 की तुलना में 13.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं दलहनी पसलों में सबसे अधिक हास हुआ (सारणी 4.4) । अरहर, चना एवं मदर के क्षेत्र में

<u>सारणी 4.4</u> <u>फ्सल प्रतिरूप में का लिक परिवर्तन</u>

फ् सल	सक्ल बोये गये (1979-80)	भेत्र का प्रतिशत (1990-91)	अन्तर (प्रतिशत में)
धान	38. 26	39.01	+ 0.75
मक्का	5. 63	3. 25	- 2.38
अरहर	4.88	2. 63	- 2.25
गन्ना	7.07	6. 22	- 0.85
गेहूँ	26.59	39.99	+13.40
जौ तथा अन्य मोटे अनाज	9.07	अनु०	अ नु0
ਹਜਾ	3.41	2.11	- 1.30
मटर	3.60	1.99	- 1.61
तिलहन	0.10	1.07	+ 0.97
अंत्रलू	1.39	1.34	- 0.05

अनु० - अनुपल छ्य

म्रोत: (1) सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगद्भ, 1980.

(2) लेखपाल का खरीप, रबी, जायद उपज ब्यौरा, पसली वर्ष 1398 (1990-91) से संगणित

क्रमज्ञा: 2.25, 1.30 तथा 1.61 प्रतिज्ञात का हास हुआ । वर्ष 1979-80 में आलू की कृष्टि 1.39 प्रतिज्ञात क्षेत्र पर की गयी जो वर्ष 1990-91 में घटकर 1.34 प्रतिज्ञात रह गयी । इस प्रकार आलू के क्षेत्र में 0.05 प्रतिज्ञात की कमी हुई । गन्ने का क्षेत्र

7.07 प्रतिष्ठात से घटकर 6.22 प्रतिष्ठात रह गया । तिलहन की कृष्टि में वर्ष 1979-80 की तुलना में वर्ष 1990-9। में 0.97 प्रतिष्ठात की वृद्धि हुई । अध्ययन प्रदेश में सब्से अधिक गेहूँ के क्षेत्र में परिवर्तन होने का कारण सिंचाई के साधनों - नलकूपों तथा नहरों का अधिक विकास होना है ।

4. 4 शहय-संयोजन

शहरा-संयोजन से तात्पर्य एक ही क्षेत्र में अनेक पसलों के साथ-साथ उत्पादन से है। किसी इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख पसलों के समूह को पसल-संयोजन कहते हैं जो वहाँ की प्राकृतिक, आर्थिक तथा कृष्णक की सामाजिक एवं वैयक्तिक गुणों के अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। इस क्षेत्र कि की क्षेत्रीय विशेष्ठताओं को आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार शह्य-संयोजन प्रदेशों का निर्धारण उन पसलों के स्थानिक वर्यस्व के आधार पर किया जाता है जिनमें क्षेत्रीय सह सम्बन्ध पाया जाता है एवं जो साथ-साथ विभिन्न रूपों में उगायी जाती हैं। इन प्रदेशों के अध्ययन से जहाँ एक तरफ क्षेत्रीय कृष्णि विशेष्ठताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वहीं वर्तमान कृष्णि समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित सुझाव दिये जा सकते हैं। जेलती० वीवर महोदय ने शह्य-संयोजन के महत्त्व को बताते हुए कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में पसलों के अलग-अलग महत्त्व को समझने के लिए पसल-संयोजन का अध्ययन आवश्यक है।

किसी भी क्षेत्र के पसल-संयोजन का स्वरूप मुख्यत: उस क्षेत्र विशेष के भौतिक (जलवायु, जल प्रवाह एवं मृदा) तथा सांस्कृतिक (आर्थिक एवं सामाजिक) वातावरण की देन होता है। इस प्रकार यह मानव तथा भौतिक वातावरण के सम्बन्धों को प्रदर्शित करता है।⁷

(।) शस्य-कोटि निर्धारण

शह्य-कोटि से तात्पर्य सकत बोये गये द्देष्त के सन्दर्भ में पसलों का सापेद्विक
महत्त्व निर्धारित करने से है । प्रस्तुत अध्ययन में इसके लिए सकत बोये गये द्देष्त से
सभी पसलों के आच्छादित देखों का प्रतिशत ज्ञात किया गया है । तत्पश्चाद् उन्हें
अवरोही क्रम में रखकर प्रत्येक न्याय पंचायत की शहय-कोटि निर्धारित की गयी है।
पसलों की कोटि निर्धारित करते समय । 00 से कम प्रतिशत वाली पसलों को महत्त्व
नहीं प्रदान किया गया है तथा पसलों की चार कोटियों की गणना की गयी है।

सम्पूर्ण तहसील में प्रथम कोटि पर गेहूँ है जो सकत बोये गये क्षेत्र के 39.99
प्रतिश्चात भाग पर उगाया जाता है। दूसरी कोटि पर वावल है जिसकी कृष्टि
39.01 प्रतिश्चात भाग पर की जाती है। तीसरी तथा वौथी कोटियों में भिन्नता
परिलक्षित होती है। किसी न्याय पंचायत में गन्ना तीसरी कोटि में आता है तो
किसी में मक्का या अरहर, चौथी कोटियों में अरहर, मक्का, गन्ना, चना तथा
मटर आते हैं।

सारणी 4.5 से स्पष्ट है कि 24 न्याय पंचायतों में गेहूँ प्रथम को दि की पसल है। द्वितीय को दि पर ठीक इसके विपरीत स्थिति है। 31 न्याय पंचायतों में गन्ना, 6 न्याय पंचायतों में मक्का तथा बक्सपुर मेजवान न्याय पंचायत में अरहर वृतीय को दि की पसल है। चौथी पसल को दि के रूप में अरहर मुख्य है जो 13 न्याय

पंचायतों में है। कुल ।। न्याय पंचायतों में मक्का, 7 में गन्ना, 4 में चना तथा 3 न्याय पंचायतों में मदर चौथी को दि की पसल है।

सारणी 4.5 पूलपुर तहसील में शस्य कोटि, 1990-91

	न्याय पंचायत	पसल की को I	दियाँ एवं उन 11	का सक्त बोये III	गये क्षेत्र ते 🗶
	man ann ann ann ann ann ann ann ann ann				
1.	पारा मिश्रौलिया	W-39.71	R-20.76	S-14.57	A-5.62
2.	गनवारा	₩-38.78	R-23.85	S- 9.28	M-5.52
3.	माहुल	R-39.87	W-38.60	S- 5.59	M-4.77
4.	शम्शाबाद	₩-37.91	R-16.33	S-12.79	M-6.20
5.	मिन्तूपुर	W-36.18	R+33.98	S- 8.23	A-5.46
6.	रामनगर	W-47.31	R-36.92	S_10.34	A-4.49
7.	सत्तारपुर रज्जाकपुर	₩-41.25	R-32.00	S- 7.48	A-3.13
8.	दोस्तपुर लहुरमपुर	W-42.52	R-37.13	S- 6.28	A-2.83
9.	सुम्हाडीह	R-46.68	W-36.59	S- 6.74	P-2.37
10.	बस्ती सदनपुर	R-44.50	W-39.88	S- 6.97	A-1.64
11.	सुल्ता नपुर	W-36.39	R-35.64	s- 9.99	A-4.06
12.	सौदमा थानेशवर	W-39.21	R-36.62	S- 6.67	A-4.00
13.	बाग सिकन्दरपुर	R-46.44	₩-35.70	5-10.97	A-2.02
14.	सदुल्लाहपूर मैगमा	R-45.86	W-40.17	S- 4.71	A-1.72
15.	अम्बारी	R-44.51	W-34.11	S- 6.18	M-4.26
16.	पदगु ड़िय ा	W-44.21	R-34.86	S- 7.22	M-4.88
17.	ढं जह ा पुर	R-40.65	W-33.65	s- 8.32	A-5.94

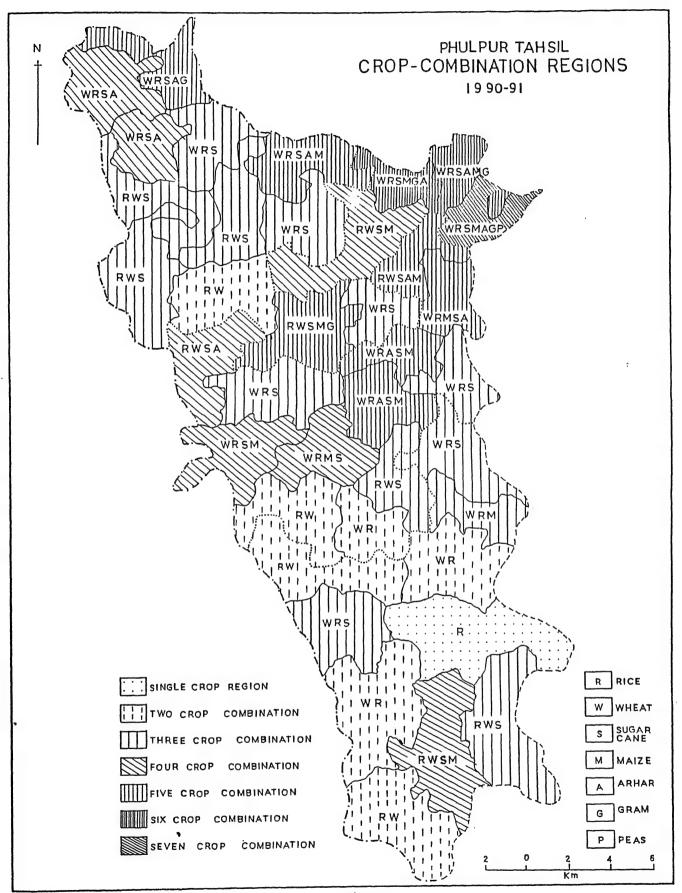
			-	none trush origin speem speem tables against white some series from	
	न्याय पंचायत	पसल की कोटि	याँ एवं उनका	तकल बोये गये	क्षेत्र में ४
		I	II		IV
18.	सजई अमानबाद	W-43.28	R-35.37	S- 6.32	A-4.26
19.	बक्सपुर मेजवान	₩-38.45	R-26.42	A- 7.93	S-7,63
20.	नो नियाडीह	R-35.00	₩-34.74	S- 8.37	A-5, 34
21.	सदरपुर बरौली	W-40.24	R-31.76	M- 5.39	S-5.31
22.	कनेरी	W-41.45	R-39.54	S- 5.31	M-3.61
23.	गद्दौपुर बारी	₩-37.59	R-34.92	S- 7.33	M-7.17
24.	पल्थी दुल्हापुर	W-41.50	R-31.54	M-10.03	S-5.44
25.	राजापुर	W-41.19	R-38.31	s- 4.50	M-4.26
26.	खरसहन कला	R-44.81	₩-43.61	M- 3.57	S-2.81
27.	महुअ हर ह	W-46.03	R-43.32	M- 3.16	S-2.26
28.	पुकवाल	R-49.55	₩-35.33	S- 3.63	M-1.69
29.	तिकरौर सहवरी	W-43.94	R-40.35	s- 6.95	P-2.64
30.	करबा प्रतेहपुर	W-46.59	R-31.56	M- 8.88	S-6.3 0
31.	कौरा गहनी	W-46.07	R-41.08	s- 3.28	G-2.73
32.	पुलेश अहमद बक्त	R-45.72	₩-41.32	M- 4.30	S-2.63
33.	छितर अहमदपुर	W-45.36	R-36.71	S- 4.51	M-2.36
34.	बेलवाना	W-49.09	R-36.54	S- 3.52	G-2.68
35.	कुरुथुवा	₩-47.96	R-43.71	S- 2.55	P-1.65

न्याय पंचायत	पसल की को टियाँ एवं उनका सकल बोये गये क्षेत्र से 🗶
36. जगदीशपुर ददेशिया	R-39.87 W-36.58 S- 5.59 M- 3.82
37. सुरहन	R-50.34 W-35.14 S- 3.98 G- 2.15
38. लसर ा खुर्द	R-41.75 N-39.79 S- 6.91 G- 3.47
पूलपुर तहसील	W-39.99 R-39.01 S- 6.22 M- 3.25
W- गेहूँ R- चावल	S – गन्ना M – मक्का G – चना
P- #c₹	A _ 37E7

स्रोत: लेखपाल का खरीप, रबी तथा जायद उपज ब्यौरा, पूलपुर तहसील पसली वर्ध,

(2) शस्य-संयोजन प्रदेश

शस्य-संयोजन प्रदेश का निर्धारण अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों द्वारा किया गया जिन्होंने अनेक सांख्यिकीय विधियों का प्रतिपादन किया । विदेशी विद्वानों में वीवर⁸, स्काट⁹, जानसन¹⁰, थामस¹¹, कोपैक¹² तथा दोई¹³ की विधियाँ महत्त्वपूर्ण हैं । भारतीय भूगोल वेत्ताओं में शस्य संयोजन का अध्ययन सर्वप्रथम बनर्जी¹⁴ ने पश्चिमी बंगाल के लिए बीवर महोदय की संशोधित विधि को अपनाते हुए किया था । इसके विपरीत हरपाल सिंह¹⁵ ने पंजाब मैदान के मालवा क्षेत्र के शस्य सम्मिश्रण को निर्धारित करते समय बीवर महोदय की विधि को अपनाया।



Fia-4-3

दयाल 16 ने पंजाब मैदान के शस्य संयोजन प्रदेश के सीमांकन हेतु एक नयी विधि अपनाया जिसमें मुख्य पसलों के चयन हेतु 50 प्रतिशत मापदण्ड का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार राय 17, अहमद तथा सिद्दीकी 18, त्रिपाठी तथा अग्रवाल 19 मण्डल 20, अय्यर 21, शर्मा 22, नित्यानन्द 23 एवं हुसेन 24 आदि विद्वानों ने दोई द्वारा प्रस्तावित सूत्र को शस्य संयोजन हेतु भिन्न-भिन्न अध्ययन क्षेत्रों में प्रयुक्त किया है। इनमें दोई तथा वीवर की विधियां अधिक महत्त्वपूर्ण हैं जिन्हें कुछ संशोधनों के साथ अनेक विद्वानों द्वारा प्रयुक्त किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में इन दोनों विद्वानों द्वारा प्रयुक्त किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में इन दोनों विद्वानों द्वारा प्रतिपादित विधियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्यों कि इनकी विधियां वहीं लागू होती हैं जहां सकत बोये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत क्षेत्र के अन्तर्गत ही दो या दो से अधिक पसलों का प्रतिनिधित्व हो। अध्ययन प्रदेश में इन विधियों द्वारा मात्र द्विपसली साहचर्य सम्पूर्ण क्षेत्र में निधारित होता है क्यों कि गेहूँ तथा चावल की पसल ही प्रत्येक न्याय पंचायत में सकत बोये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भाग पर हैं। इन पसलों का यह सिम्मिलत प्रतिशत न्यूनतम 62 तथा अधिकतम 92 है।

अत: अध्ययन प्रदेश को शस्य संयोजन प्रदेशों में विभक्त करने के लिए अलग विधि का प्रयोग किया गया है। यदि किसी न्याय पंचायत में उसके सकल बोये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भाग पर किसी एक पसल का अकेला आधिपत्य है तो उसे एक पसली साहचर्य प्रदेश के अन्तर्गत रखा गया है। साथ ही न्याय पंचायतों के शस्य-संयोजन प्रदेश में उतनी ही पसलों को समाहित किया गया है जिनके द्वारा आच्छादित क्षेत्रों का योग 85 भूतिशत तक है। यह मानक प्रतिशत तहसील के पसलों के क्षेत्रीय

वितरण प्रतिरूप के आधार पर निर्धारित किया गया है।

अाच्छादित हेन्नों के 85 प्रतिव्यत मानक आधार पर तहसील में एक पसली से लेकर 7 पसली तक कुल 7 प्रकार के शहय-संयोजन प्रदेश निधारित हुए हैं जिनमें कुल सात पसलें - गेहूं, वावल, गन्ना, मक्का, अरहर, वना तथा म्टर तिम्मिलत हैं। वित्र 4.3 से स्पष्ट होता है कि सुरहन न्याय पंचायत एक पसली शहय-संयोजन प्रदेश है जहाँ सकल बोये गये हेन्न के 50.34 प्रतिव्यत भाग पर चावल की कृष्टि की जाती है। दिपसली-संयोजन तहसील के 7 न्याय पंचायतों में है जिसका अधिकतम हेन्न मार्टिनगंज विकासखण्ड में है। तीन पसली संयोजन 13 न्याय पंचायतों में है जिनका अधिकतम हेन्न मार्टिनगंज विकासखण्ड में है। तीन पसली संयोजन 13 न्याय पंचायतों में है जिनका अधिकतम हेन्न प्रचायन पंचायतों - पूलपुर तथा मार्टिनगंज विकासखण्डों में हैं। चार पसली-संयोजन कुल 8 न्याय-पंचायतों - पूलपुर विकासखण्ड के 4, पवर्ड विकासखण्ड के 2 तथा अहरौला(I) एवं मार्टिनगंज विकासखण्ड के एक-एक न्याय पंचायतों में हैं। पाँच पसली संयोजन - 6 न्याय पंचायतों पवर्ड तथा पूलपुर विकासखण्ड के 3-3 न्याय पंचायतों में हैं। 6 पसली-संयोजन अहरौला(I) विकासखण्ड के पारा मिश्रौलिया तथा गनवारा न्याय - पंचायतों में है। 7 पसली-संयोजन अहरौला(I) विकासखण्ड के केवल शम्बाबाद न्याय-पंचायतों में है। 7 पसली-संयोजन अहरौला(I) विकासखण्ड के केवल शम्बाबाद न्याय-पंचायतों में है।

(3) शस्य-गहनता

शस्य-गहनता से तात्पर्य एक कृष्णि वर्ष में एक क्षेत्र में एक से अधिक पसलें उगाने से है । शस्य-गहनता भूमि-उपयोग की तीव्रता को दशांती है । किसी क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र की अपेक्षा सकल बोये गये क्षेत्र का अधिक होना शस्य-गहनता का परि-चायक है तथा इनमें धनात्मक सह-सम्बन्ध होता है । किसी क्षेत्र की शस्य-गहनता सिंचाई, उर्वरक तथा भूमि की उर्वराशक्ति आदि पर निर्भर करती है। शहय-गहनता के आकलन के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं जो मुख्यत: शहय-गहनता के शेत्रीय वितरण से सम्बन्धित है। डाँ० जसवीर सिंह ने शहय-गहनता के आकलन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया है -

अध्ययन क्षेत्र की शह्य गहनता की गणना उपर्युक्त सूत्र के माध्यम से की गयी है । तहसील की औसत शह्य-गहनता सूचकांक 156 है किन्तु विकासखण्ड हतर पर इनमें पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है । जहाँ सर्वाधिक शह्य-गहनता सूचकांक 163 पवर्ड विकासखण्ड का है वहीं सब्से कम शह्य-गहनता सूचकांक 152.69 मार्टिनगंज विकासखण्ड का है । पूलपुर तथा अहरौला(ा) विकासखण्डों की शह्य-गहनता सूचकांक क्रमश: 154.22 तथा 153.04 है । शह्य गहनता में यह असमानता सिंचार्ड की सुविधा, मिद्दी की उर्वरता तथा उर्वरकों के प्रयोग में क्षेत्रीय असमानता के कारण है।

4.5 वर्तमान कृषि और हरित-क्रान्ति की भूमिका

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में अनेक प्रयत्न किये जिनमें कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, कृषि अनुसंधान संस्थाओं का विकास, नवीन कृषि उपकरणों के प्रयोग का प्रदर्शन तथा सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग में तीव्र वृद्धि मुख्य है। पिर भी कृषि उत्पादन की गति वृतीय पंचवर्षीय योजना तक सामान्य रही। भारत में कृषि विकास के क्षेत्र में वर्ष 1974-75

के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसे 'हिरित क्रान्ति' के नाम से जाना गया । हिरित क्रान्ति से तात्पर्य कृष्णि-कार्य के तरीकों में सुधार तथा कृष्णि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने से है । हिरित क्रान्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमरीकी विद्वान् डाँठ विलियम गैड (1968) ने अधिक उपज देने वाली तथा शीद्ध पकने वाली पसलों की किस्मों के लिए किया था । हिरित क्रान्ति से न केवल कृष्णि की निराशापूर्ण रिथिति और अनिश्चितता समाप्त हुई विलिक देश खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निभीरता की और अग्रसरित हुआ । हिरितक्रान्ति के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं-

(।) उच्च उत्पादकता एवं शीच्च पकने वाले उन्नतःशील बीज

अध्ययन प्रदेश में पिछले दशकों में अधिकांशत: कृष्ण पुराने किस्मों वाले बीजों की बुवाई करके पर्नम्मरागत निम्न उत्पादकता वाली निर्वाहन कृष्णि करते थे। जिससे कृष्णि उत्पादन कम हो रहा था। वर्तमान समय में देश के अन्य भागों की तरह पूलपूर तहसील में भी एच० वाईं० बीठ (High yielding værieties) किस्म के बीजों का प्रयोग हो रहा है जिससे खादान्न के प्रति एकइ तथा कुल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अध्ययन प्रदेश में धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, चना, मटर तथा आलू की पसलों के सन्दर्भ में तो ९० प्रतिशत से भी अधिक भाग पर एच० वाईं० वीठ किस्म के बीजों का प्रयोग हो रहा है। साथ ही, शीच्च तैयार होने वाली किस्मों (Qlick maturing værities) के प्रयोग से अब वर्ष में एक ही खेत से कई पसलें उगायी जाने लगी हैं।

(2) उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग

कृष्ण की उत्पादकता बद्धाने में उर्वरकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
यदि पाचन शक्ति के बिना मानव को पौष्ठिटक तत्त्व प्रदान किये जायँ तो उनका
प्रभाव स्वास्थ्य पर अनुकूल नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार अच्छे बीज, पौध संरक्षण,
बहु पसली एवं सचन कृष्ण कार्यक्रम रूपी तत्त्वों का प्रभाव तभी हो सकेगा जब भूमि
की उर्वरा शक्ति ठीक हो। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तभी हो सकती है जब
भूमि को पर्याप्त एवं समयानुकूल उर्वरक प्राप्त हों। अन्य बातें सामान्य रहने पर
भूमि में एक दन उर्वरक डालने से खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8 से 10 दन की वृद्धि
होती है। तहसील में यद्यपि अब उर्वरकों का पर्याप्त प्रयोग हो रहा है किन्तु

सारणी 4.6 पूलपुर तहसील में उर्वरकों का वितरण, 1988-89

					(हजार मी० ८न)
	विकासखण्ड	नाइद्रोजन	फारकोरस	पोट । भा	कुल उर्वरक
1.	पवर्ड	1174	426	87	1687
2.	पूलपुर	1114	330	171	1615
3.	मा टिनगंज	991	308	89	1388
4.	अहरौला 🏻	376	116	57	549
			in the state and the state of the state term that is		
	पूनपुर तहसील	3655	1180	404	5239

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1990.

वां छित मात्रा में नहीं । वर्ष 1988-89 में विभिन्न होतों द्वारा तहसील में कुल 5239 हजार मी द्विकटन उर्वरकों का प्रयोग किया गया जिसमें 69.77 प्रतिहात नाई-द्रोजन, 22.52 प्रतिहात फासफोरस तथा 7.7। प्रतिहात पोटास से सम्बन्धित उर्वरक सम्मिलित थे (सारणी 4.6) ।

विकासखण्ड स्तर पर सबसे अधिक उर्वरक का प्रयोग 32.20 प्रतिश्वात पवर्ड में किया गया जबकि सबसे कम 10.48 प्रतिश्वात अहरौला(I) में । अन्य विकासखण्डों - पूलपुर तथा मार्टिनगंज में क्रमश: 30.83 तथा 26.49 प्रतिश्वात उर्वरकों का प्रयोग किया गया ।

तहसील में पसलों को बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का उतना प्रयोग नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए क्यों कि अधिकांश कृष्ठिक निर्धन एवं गरीब हैं। वर्तमान समय में तहसील के प्रत्येक विकासखण्ड में एकम्एक कीटनाशक डिपो कार्यरत हैं जिनकी क्षमता 4 से 8 मी०८न के बीच है।

(3) कृषि का यन्त्री करण

कृषि के यन्त्रीकरण से ता त्पर्य कृषि में लगने वाले पशु एवं मानव शक्ति को मशीनों द्वारा प्रतिस्था पित करने से है । यन्त्रों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमी आयी है । यन्त्रीकरण का ही प्रतिप्ल है कि पाश्चात्य देशों में हुई कृषि क्रान्ति (Agricultural Revolution) की तुलना औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) से की गयी । 25 अध्ययन प्रदेश में आज भी कृषि पर-म्मरागत यन्त्रों एवं पशु श्रम पर आधारित है । इसका मुख्य कारण तहसील में सीमान्त एवं

लघु तीमान्त कृषकों की प्रधानता एवं जोतों के आकार का छोटा होना है । तहतील में द्रैक्टर एवं अन्य नवीन कृष्ठि यन्त्रों का प्रयोग हरितक्रान्ति के बाद ही हुआ । कृष्ठि गणना 1982 के अनुसार तहतील में कुल हलों की संख्या 55142 थी जिनमें 76.33 प्रतिशत देशी हल थे । सम्प्रति तहतील में 450 उन्नतिशील हैरो एवं कल्टीवेटर, 3242 थें सर म्यानें, 129 स्प्रेयर, 13 उन्नतिशील बुवाई यन्त्र तथा 588 द्रैक्टर हैं । 26 तहतील के मध्यवर्ती भागों में कृष्ठि का यन्त्रीकरण अधिक हुआ है । कृष्ठि के यन्त्रीकरण से जहाँ समय तथा श्रम की बचत हुई है वहीं प्रति हेक्टेअर उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । वर्तमान समय में कृष्ठि के यन्त्रीकरण का प्रभाव कृष्ठि पर स्पष्टतः परिलक्षितं होता है ।

(4) सिंचाई

आधुनिक कृष्य में सिंचाई का विशेष्य महत्त्व है । इससे कृष्णित भूमि उप-योग के सभी पक्षों यथा शस्य-गहनता, शस्य-संयोजन एवं प्रति हेक्टेअर उत्पादन में वृद्धि हुई है । सिंचाई के साधनों द्वारा धरातलीय जल को नहरों और भूमिगत जल को नलकूपों, पिम्मंग सेटों एवं कुओं द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता है ।

तम्प्रति तह्तील में वर्ष 1988-89 में 33119 हे क्टेअर भूमि पर तिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी जो तम्पूर्ण कृष्णित भूमि का 64.29 प्रतिशत थी । तह्तील में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक तिंचाई की जाती है जो कुल तिंचित भूमि का 68.90 प्रतिशत है । कुल तिंचित भूमि के 29.86 प्रतिशत भाग पर नहरों द्वारा तथा शेष्ट भूमि पर कुओं, तालाबों एवं अन्य साधनों द्वारा तिंचाई की जाती है ।

सारणी 4.7 पूनपुर तहसील में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र, 1988-89

(हेक्टेअर में)

	-				(0,100	
	तिंचाई के साधन	पवई	पूलपुर	मा टिनगंज	अहर ौला 1	.पूनपुर तहसील
	,					
1.	नहर	2258	1901	4695	1036	9890
	(नहरों की लम्बाई, कि0मी0 में)	110	113	155	37	415
2.	नल कूप	7050	6934	6628	2208	22820
	(राजकीय नलकूपों की संख्या)	11	ı	2	3	17
	<u>.</u>					າ
3.	कुएँ	. 10	75	_	27	112
	(कुअं के तिख्या)	255	782	834	281	2152
	(रहटों की संख्या)	187	419	489	70	1165
4.	तालाब एवं अन्य साधन	6	100	170	4	280
					7070	77116
	कुल सिंचित भूमि	9324	9010	11513	3272	33 19

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1990.

(क) नहरें

तह्तील में वर्ष 1988-89 में कुल कृष्णिकृत भूमि के 19.63 प्रतिशत भाग पर नहरों द्वारा तिंचाई की गयी जो कुल तिंचित भूमि का 29.86 प्रतिशत है । मार्टिन-गंज विकासखण्ड में सबसे अधिक कृष्णिकृत भूमि पर नहरों द्वारा तिंचाई की जाती है जो कुल तिंचित भूमि का 40.78 प्रतिशत है । सबसे कम पूलपुर विकासखण्ड में 21.10 प्रतिशत भाग पर नहरों द्वारा तिंचाई की गयी । पवई तथा पूलपुर विकासखण्डों में

कुल सिंचित भूमि के क्रमश: 24.22 तथा 31.66 प्रतिशत भाग पर नहरो द्वारा सिंचाई की गयी।

तहसील में नहरों की कुल लम्बाई वर्ष 1988-89 में 415 किंग्मीं थी ।
सारणी 4.7 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक नहरों का जाल मार्टिनगंज विकासखण्ड में
है । यहाँ पर नहरों की कुल लम्बाई 155 किंग्मीं है । कुल कृष्णिकृत भूमि के
27.26 प्रतिशत भाग पर नहरों द्वारा सिंग्नाई की जाती है । सबसे कम नहरों की लम्बाई अहरौला(I)विकासखण्ड में 37 किंग्मीं है । पूलपुर विकासखण्ड में नहरों की लम्बाई 113 किंग्मीं है जिसके द्वारा 1901 हेक्टेअर भूमि की सिंग्नाई की जाती है । पवई विकासखण्ड में नहरों की कुल लम्बाई 110 किंग्मीं है जिसके द्वारा

(खः) नलकूप

अध्ययन प्रदेश में विगत दस वर्षों में सिंचाई के साधनों विशेषकर नलकूपों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । नहरों द्वारां सिंचाई कुछ अनिश्चित सी है क्यों कि नहरों में जल की आपूर्ति वर्षा पर निर्भर करती है । इस लिए अध्ययन प्रदेश में सिंचाई के लिए नलकूपों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है । वर्ष 1988-89 में कुल सिंचित भूमि के 68.67 प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की गयी । पूलपुर विकासखण्ड में 76.96 प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की गयी । अन्य विकासखण्डों - पवई, अहरौला(प्र) तथा मार्टिनगंज विकासखण्ड के क्रम्झा: 75.11, 67.48 तथा 57.57 भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की गयी । अध्ययन प्रदेश में

वर्ष 1988-89 में राजकीय नलकूपों की संख्या 17 थी जिनमें 11 पवर्ड विकासखण्ड में थे 1

कुल तिंचित भूमि के 1.17 प्रतिशत भाग पर तिंचाई के अन्य साधनों -कुओं, रहदों तथा तालाबों एवं पोखरों द्वारा तिंचाई की जाती है । आधुनिक वैज्ञानिक युग में इन साधनों का महत्त्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है क्यों कि इनके द्वारा तिंचाई में श्रमशक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं ।

((5) चकबन्दी एवं जोतों का आकार

गाँव स्तर पर सुट्यवस्थित विकास योजना, कृष्ठि में कुश्वलता और अर्थ – ट्यवस्था में सुधार लाने के लिए भूमि के बिखरे हुए जोतों की चकबन्दी आवश्यक है। तहसील में चकबन्दी वर्ष 1972-73 में प्रारम्भ की गयी जिसके माध्यम से लोगों के बिखरे हुए छोटे-छोटे खेतों को बड़े आकार में संगठित किया गया। सिंचाई के लिए नालियों की ट्यवस्था तथा पगडण्डियों की ट्यवस्था होने से कृष्ठि में अपेक्षाकृत सुधार हुआ।

सारणी 4.8 से स्पष्ट है कि तहसील में सीमान्त एवं लघु सीमान्त कृष्ठकों की अधिकता है जो बढ़ती हुई आबादी, संयुक्त परिवार प्रथा के विद्यान तथा भूमि के प्रति लगाव आदि का सिम्मिलित प्रतिपल है। जोत का आश्रय उस समग्र भूमि से है जिसके कुल या आंश्रिक भाग पर कृष्णि उत्पादन एक तकनीकी इकाई के तहत केवल एक च्यक्ति या कुछ-अन्य च्यक्तियों के साथ किया जाता है। तकनीकी इकाई से तात्पर्य उत्पादन के साधनों तथा उसके प्रबन्धन से है। 27

सारणी 4.8 पूलपुर तहसील में जोतों की संख्या एवं आकार, 1981

							भर में)
जोतों की संख्या ए	वं आका	र पवर्ड प	ज़िपुर	मा टिंनगंज ^आ	हरौला 	कुल तहसँ नि	प्र तिप्रात
	संख्य ा क्षेत्रफल	24579 688 l	24983 8122	21057 9323		79383 26505	
		2419 3679	2318 3114	2262 340 7	844 1065	7843 11265	
अर्द्ध सीमान्त (2 से 3 हेक्टेअर)	संख्य ा क्षेत्रफ्ल	717 1578	632 1623	694 1764	240 530		2.50 11.09
मध्यम तीमान्त (3 से 5 हेक्टेअर)	संख्या क्षेत्रफ्ल	353 129 I			136 431	1247 4818	1.37 9.37
वृहद् सीमान्त (5 से अधिक)	संख्या क्षेत्रपन	134 809	153 957	151 1027	48 332	486 3125	0. 52 6. 08
	तीमान्त (। हेक्टेअर ते कम) लघु तीमान्त (। ते 2 हेक्टेअर) अर्द्ध तीमान्त (2 ते 3 हेक्टेअर) मध्यम तीमान्त (3 ते 5 हेक्टेअर) वृहद् तीमान्त (5 ते अधिक) पूलपुर तहतील में कु	तीमान्त संख्या (। हेक्टेअर से कम) क्षेत्रफल लघु तीमान्त संख्या (। से 2 हेक्टेअर) क्षेत्रफल अर्द्ध तीमान्त संख्या (2 से 3 हेक्टेअर) क्षेत्रफल मध्यम तीमान्त संख्या (3 से 5 हेक्टेअर) क्षेत्रफल चृहद् तीमान्त संख्या (5 से अधिक) क्षेत्रफल	तीमान्त संख्या 24579 (। हेक्टेअर से कम) क्षेत्रफल 688। लघु तीमान्त संख्या 2419 (। से 2 हेक्टेअर) क्षेत्रफल 3679 अर्द्ध तीमान्त संख्या 717 (2 से 3 हेक्टेअर) क्षेत्रफल 1578 मध्यम तीमान्त संख्या 353 (3 से 5 हेक्टेअर) क्षेत्रफल 129। वृहद्द तीमान्त संख्या 134 (5 से अधिक) क्षेत्रफल 809	सीमान्त संख्या 24579 24983 (। हेक्टेअर से कम) क्षेत्रफल 6881 8122 लघु सीमान्त संख्या 2419 2318 (। से 2 हेक्टेअर) क्षेत्रफल 3679 3114 अर्द्ध सीमान्त संख्या 717 632 (2 से 3 हेक्टेअर) क्षेत्रफल 1578 1623 मध्यम सीमान्त संख्या 353 367 (3 से 5 हेक्टेअर) क्षेत्रफल 1291 1684 वृहद् सीमान्त संख्या 134 153 (5 से अधिक) क्षेत्रफल 809 957 फूलपुर तहसील में कुल जोतों की संख्या =	सीमान्त संख्या 24579 24983 21057 (1 हे क्टेअर से कम) क्षेत्रफल 6881 8122 9323 लंद्ध सीमान्त संख्या 2419 2318 2262 (1 से 2 हे क्टेअर) क्षेत्रफल 3679 3114 3407 अर्द्ध सीमान्त संख्या 717 632 694 (2 से 3 हे क्टेअर) क्षेत्रफल 1578 1623 1764 मध्यम सीमान्त संख्या 353 367 391 (3 से 5 हे क्टेअर) क्षेत्रफल 1291 1684 1412 वृहद् सीमान्त संख्या 134 153 151 (5 से अधिक) क्षेत्रफल 809 957 1027 फूलपूर तहसील में कुल जोतों की संख्या = 91242	सीमान्त संख्या 24579 24983 21057 8764 (1 हे क्टेअर से कम) क्षेत्रफल 6881 8122 9323 2179 लघु सीमान्त संख्या 2419 2318 2262 844 (1 से 2 हे क्टेअर) क्षेत्रफल 3679 3114 3407 1065 अर्द्ध सीमान्त संख्या 717 632 694 240 (2 से 3 हे क्टेअर) क्षेत्रफल 1578 1623 1764 530 मध्यम सीमान्त संख्या 353 367 391 136 (3 से 5 हे क्टेअर) क्षेत्रफल 1291 1684 1412 431 वृहद् सीमान्त संख्या 134 153 151 48 (5 से अधिक) क्षेत्रफल 809 957 1027 332 फूलपुर तहसील में कुल जोतों की संख्या = 91242	जोतों की संख्या एवं आकार पवर्ड पूलपुर मार्टिनगंज सहरीला तुहसील सीमान्त संख्या २५५७९ २५९८३ २१०५० ८४६४ ७९३३ २१७९ २६५०५ (१ हे क्टेअर से कम) क्षेत्रपल ६८८१ ८४६५ ७९३३ २१७९ २६५०५ लघु सीमान्त संख्या २५१९ २३१८ २८६२ ८४६५ ७८५३ (१ से २ हे क्टेअर) क्षेत्रपल ३६७९ ३११४ ३५०७ १०६५ ११८५६ अर्द्ध सीमान्त संख्या ७१७ १६३५ १७५५ २५० २२८३ (२ से ३ हे क्टेअर) क्षेत्रपल १५७८ १६३५ १७५५ ५३० ५६९९ मध्यम सीमान्त संख्या ३५३ ३६७ ३९१ १५४ ५३० ५६९९ मध्यम सीमान्त संख्या ३५३ ३६७ ३९१ १५४१ ५३१ ५८११ (३ से ६ हे क्टेअर) क्षेत्रपल १२९१ १६८५ १५४१ ५३१ ५८१८ (३ से ६ हे क्टेअर) क्षेत्रपल १२९१ १६८५ १५४१ ५३१ ५८१८ पूलपुर तहसील में कुल जोतों की संख्या = ९१२५२

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ, 1989 से संगणित

कृष्टि गणना 1981 के अनुसार तहसील में कुल जोतों की संख्या 91242 थी जिसके अन्तर्गत 51412 हेक्टेअर क्षेत्र समाहित था । तहसील में सीमान्त जोतों की संख्या सबसे अधिक 87.00 प्रतिशत है जिसके अन्तर्गत 51.55 प्रतिशत क्षेत्र समाहित है। तहसील में वृहद् जोंतों की संख्या सबसे कम है जो कुल जोतों की संख्या का 0.53 प्रति-शत तथा कुल क्षेत्रफल का 6.08 प्रतिशत है।

विकासखण्ड स्तर पर पूनपुर में कून जोतों का 87.80 प्रतिश्चात सीमान्त, 8.15 प्रतिश्चात निद्यम निवान अर्द्धसीमान्त, 1.29 प्रतिश्चात मध्यम सीमान्त तथा 0.54 प्रतिश्चात वृहद् सीमान्त है । सबसे कम मार्टिनगंज में 85.75 प्रति-श्चात नोतें, निद्यु सीमान्त, अर्द्धसीमान्त, मध्यम सीमान्त तथा वृहद् जोतों का प्रतिश्चात क्रमशः 9.21, 2.83, 1.93 तथा 0.62 है । अहरौनार्। में इन जोतों का प्रतिश्चात क्रमशः 87.36,8.41, 2.40, 1.35 तथा 0.48 है जबिक पवर्ड में इन जोतों का प्रतिश्चात क्रमशः 87.15, 8.58, 1.25 तथा 0.48 है ।

4. 6 कृषा-विकास नियोजन

कृषि नियोजन का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष की कृषि सम्बन्धी सम-स्याओं का निराकरण करते हुए उस क्षेत्र का समन्वित विकास करना है । अध्ययन प्रदेश की कृषि विभिन्न जटिल समस्याओं से धिरी हुई है । तहसील के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 72.76 प्रतिशत भाग कृषि योग्य है । साथ ही मात्र 56.01 प्रतिशत भाग पर एक से अधिक फ्लालें उगायी जा रही हैं । जायद की फ्लाल कुल कृषि योग्य भूमि के केवल 0.49 प्रतिशत भाग पर की जाती है । अतः क्षेत्र की कृषि पिछड़ी हुई दशा में है । यह पिछड़ापन अधिक उपज देने वाली किस्मों के उन्नतिशिल बीजों, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं, नवीन कृषि उपकरणों के कम प्रयोग तथा सिंचाई की अपर्याप्तता के कारण है । इन नवीनताओं के कम प्रयोग का कारण क्षेत्र में लघु एवं सीमान्त कृषकों की अधिकता, जोतों के आकार का छोटा होना, अधिहा के कारण कृष्ठकों में नवीन-ताओं की ग्राह्य क्षमता में कमी, परिवहन एवं संचार साधनों का अविकसित अवस्था में होना तथा विपणन केन्द्रों की कमी आदि है। अतः तहसील में कृष्ठि का बहुमुखी विकास एक पसली क्षेत्र को सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग से बहुपसली क्षेत्र में बदलकर, पसल प्रतिरूप में यथासम्भव परिवर्तन, कृष्ठि के गहनीकरण तथा नवीन कृष्ठि-पद्धतियों के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है।

(1) भूमि-उपयोग के वर्तमान स्वरूप में तुधार

अध्ययन प्रदेश में वास्तविक बोये गये क्षेत्र में विस्तार की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। तहसील में कुल 2158 हे क्टेअर भूमि कृष्णि योग्य बंजर, 6272 हे क्टेअर परती एवं 2298 हे क्टेअर भूमि उसर है जिन्हें थोड़े से प्रयास के साथ सिंगाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा कृष्णि योग्य भूमि में बदला जा सकता है।

2) कृषि का ट्यवसायी करण एवं गहनी करण

पसल प्रतिरूप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील की मुख्य पसल गेहूँ
और चावल है जिसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अन्य पसलों - गन्ना,
आलू, तिलहन तथा दलहन आदि का उत्पादन मात्र घरेलू उपयोग तक ही सीमित है।
अत: गन्ना, आलू, तिलहन एवं दलहन पसलों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से करना
होगा जिससे लोगों का जीवन स्तर उँचा हो सके। अध्ययन प्रदेश में इन पसलों के उत्पादन
लिए सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।

ट्यवसायिक पसलों की उपज में वृद्धि से कृष्य आधारित उद्योगों को बढ़ावा

मिलेगा। इन कच्चे कालों की आपूर्ति से किसानों को मुद्रा प्राप्त हो सकेगी दूसरे कृष्णि के व्यवसायी करण से ग्रामीण मण्डियों के विस्तार एवं समन्वय की प्रक्रिया तेज होगी और कृष्णिप्रधान इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

सारणी 4.9 पूनपुर तहसील हेतु प्रस्तावित पसल-चक्र

-	मिद्दी की किहमें	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	वृतीय वर्ष
1.	बतुई मिट्टी	अरहर/मोटे/अनाज/ तरबूज, खरबूजा	मूँगफ्ली/हरा चारा/ मूँग	मक्का/अालू/ सूर्यमुखी
2.	बलुई दोम्ह मिस्टी	हरा चारा/आलू/ सब्जियाँ	मक्का/अरहर अगहनी/ गेहूँ/हरा चारा	
3.	दोमः मिद्टी	धान/गेहूं/गन्ना पौध	गन्ना पेड़ी (Tatoor)	गेहूँ/हराचारा
,4.	मिंद्दी	मक्का /अ ालू /गेहूँ/ मूँग	धान/गेहूँ तिलहन/ गन्ना पौध	गन्ना पेड़ी (Tatoor)

अध्ययन प्रदेश की फ्तल गहनता मात्र 156 है तथा शुद्ध बोये गये क्षेत्र का केवल 56.01 प्रतिशत भाग ही बहुफ्तली है। इसका मुख्य कारण मिद्दी की उर्वरा शिक्त नष्ट होने की कृष्टकों की अवधारणा तथा सिंचाई सुविधाओं का कम विकास है। सिंचाई के मुख्य स्रोत नहरें तथा पिम्मंग सेट हैं। गर्मियों में अधिकांश नहरें सूख जाती हैं और अध्ययन प्रदेश में विद्युत आपूर्ति भी अनिश्चित है जिससे जायद की

पसल नहीं उगायी जा पा रही है। अतः पसल गहनता में वृद्धि के लिए सिंचाई स्विधाओं का विकास तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिए पसल यक्र की महती आवश्यकता है। इसके लिए तहसील की दशाओं के अनुकूल बहुपसली तीन वर्षीय पसल यक्र का सुझाव दिया जा रहा है (सारणी 4.9)।

(३) पशुपालन

तह्सील की अर्थव्यवस्था में कृष्णि की अधिकतम भागीदारी सुनिष्चित करने
तथा लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने में पशुपालन, मत्स्यपालन, एवं कुक्कुटपालन का
महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है। पशुपालन को व्यापारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु
सहकारी डेयरी केन्द्रों की स्थापना तथा दुधारू पशुभों की नस्लों में सुधार करने की
महती आवश्यकता है। तहसील के छोटे एवं बड़े तालाबों में सार्वजनिक एवं व्यक्तिणत
रूप से मत्स्य-पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही, कृष्णि अयोग्य भूमि
पर नये सरकारी जलाशयों का निर्माण करके मत्स्यपालन कराया जाना चाहिए।
आर्थिक एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता देकर तहसील में छोटे-छोटे छरेलू कुक्कुट पालन
केन्द्र खोले जाने चाहिए। वर्ष 1988-89 के आँक्झों के अनुसार तहसील में ।। बीज
गोदाम एवं उर्वरक भण्डार, 42 बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक केन्द्र, 4 कीटनाशक डिपों,
उभ ग्रामीण गोदाम, एक शीत भण्डार, 4 पशु अस्पताल, 9म्युविकास केन्द्र, 6 कृत्रिम
गर्भाधान केन्द्र, 2 मेझ विकास केन्द्र, एक सूअर विकास केन्द्र तथा 70 पोल्द्री यूनिट
कार्यरत हैं। भूमि विकास बैंक मात्र तहसील मुख्यालय पर स्थित है। इसके अतिरिक्त 3 जिला सहकारी बैंक, 14 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा 10 ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं।

(4) आधारभूत कृषि स्विधाओं की उपलब्धाता

अध्ययन प्रदेश में कृषि योग्य भूमि पर प्रति हेक्टेअर उत्पादन बढ़ाने हेतु उचित सुविधाओं में विकास करना आवश्यक है। इन सुविधाओं में सिंचाई गहनता में वृद्धि, उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं, उन्नतिशील तथा शीद्ध पकने वाले बीजों, कृषि की नवीन पद्धतियों आदि के प्रयोग, कृषि का व्यवसायीकरण, भण्डारण तथा विपणन जैसी सुविधाएँ प्रमुख हैं। क्षेत्र के सम्यक् विकास के लिए सुविधाओं में भावी वृद्धि की महती आवश्यकता है।

(क) सिंचाई

तिंचाई किसी क्षेत्र की भूमि उपयोग क्षमता, दो फ्सली क्षेत्र, प्रति है क्टेअर उत्पादन, शस्य स्वरूप तथा शस्य गहनता आदि को स्पष्टतया प्रभावित करती है। अध्ययन प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र के 64.29 प्रतिशत भाग पर तिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगले दस वर्षों में कृषि क्षेत्र में विस्तार तथा कृषि के गहनीकरण को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 85 प्रतिशत भाग पर तिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। तिंचाई के साधनों में नहरों एवं पांच्यंगतेटों, निजी एवं राजकीय नलकूपों में पर्याप्त वृद्धि आवश्यक है। तिंचाई के साधनों में सबसे अधिक वृद्धि की आवश्यकता मार्टिनगंज विकासखण्ड में है जहाँ कुल कृषित भूमि का मात्र 52.20 प्रतिशत भाग ही तिंचित है। मार्टिनगंज विकासखण्ड के जगदीशपुर ददेरिया (41.301), फ्लेश अहमद बक्स (44.261), लहरा खुर्द (50.471), बेलवाना (50.601), कुरुधुवा (50.791) तथा कौरागहनी (51.401) न्याय पंचायतों में तिंचाई के साधनों में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है क्यों कि इन न्याय पंचायतों में कुल तिंचित भूमि का प्रतिशत मार्टिनगंज

विकासखण्ड के औसत से कम है। इन भागों में राजकीय नलकूपों एवं सरकारी वित्तीय सहायता द्वारा व्यक्तिगत नलकूपों के लगाये जाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

पूलपुर विकासखण्ड के महुआरा न्याय पंचायत में सिंचाई के साधनों में वृद्धि अति आवश्यक है क्यों कि कुल कृष्णित भूमि का मात्र 39.82 प्रतिशत भाग ही सिंचित है। तहसील के उत्तरी भाग में यद्यपि पिम्पंगसेटों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तू विद्युत एवं डीजल की आपूर्ति कम होने तथा अनियमित एवं अनिश्चित होने से पसलों की सिंचाई उपयुक्त समय पर नहीं हो पाती है। अतः तहसील में विद्युत तथा डीजल की आपूर्ति नियमित एवं निश्चित करने की आवश्यकता है। तहसील में यद्यपि नहरों का जाल सा बिछा हुआ है किन्तु ये नहरें गर्मियों में सूख जाती हैं और जाड़े में भी इनमें पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं रहती है। अतः गर्मी तथा जाड़े में जलापूर्ति निश्चित की जानी चाहिए जिससे रबी की पसल में उपयुक्त समय पर सिंचाई की जा सके तथा जायद के पसल क्षेत्र में विस्तार किया जा सके।

(ख) उर्वरक एवं उन्नितिशील बीजों का प्रयोग

कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु उर्वरक एवं उन्नितिशील बीजों का प्रयोग अपरि-हार्य हो गया है। कृषि नवीनीकरण (Innovation) की सफलता उर्वरकों के प्रयोग में ही निहित है। उर्वरकों के नाम पर कृष्क मात्र यूरिया तथा डाई नामक रासायनिक खादों का ही प्रयोग अधिक करते हैं जबकि मिद्दी की सम्यक् जाँच करके उसकी आवश्यकतानुसार ही उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए विकासखण्ड स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगमालाओं की स्थापना होनी चाहिए जिससे कृष्टाकों को मिद्दी के स्वभाव के अनुरूप उर्वरकों की किस्मों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके।

सीमान्त एवं लघु सीमान्त कृषक बहुल अध्ययन प्रदेश में उन्नित्तितील बीजों का प्रयोग उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए । इसका मुख्य कारण बीजों का महना होना, समय से उनका उपलब्ध न हो पाना तथा उनकी कम विश्व सनीयता है । प्रतिवर्ध उन्नितिशील बीजों का प्रयोग मात्र ८ से १० प्रतिशत सम्पन्न कृषक ही कर पा रहे हैं । अतः जरूरत इस बात की है कि सरकार द्वारा उन्नितिशील बीज कम मूल्य पर कृष्ठाकों को प्रदान किये जायं तथा इनके प्रयोग के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाय । प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है, कि २० प्रतिशत तक उपज केवल उन्नितिशील बीजों के प्रयोग से ही बढ़ाई जा सकती है ।

(ग) कीट एवं खरपतवार नामक दवार

अधिक उपज देने वाली पसलों की किहमों में बीमारियों तथा कीटों का प्रकोप प्राय: अधिक होता है तथा नहरों द्वारा सिंचाई से क्षेत्र में वृद्धि के कारण खेतों में खरपतवारों की मात्रा में वृद्धि हुई है । इनके निराकरण हेतु कृष्यकों में एक तो इनसे सम्बन्धित दवाओं का ज्ञान नहीं है, दूसरे समय पर ये दवाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तीसरे ये दवाएँ इतनी महँगी होसी हैं कि निर्धन कृष्यकों की क्रय शक्ति के बाहर हैं । इन दवाओं की विक्री कृष्यि सहकारी समितियों एवं कीटनाशक डिपों के माध्यम से की जाती है किन्तु इनका अधिकतम उपयोग सम्मन्न कृष्यक ही कर पा

रहे हैं। अतः कीट एवं खरपतवार नाशक दवाओं के ज्ञान एवं उनसे होने वाले लाभों से कृष्टाकों को सम्यक् रूप से अवगत कराया जाना चाहिए। इसके लिए विकास खण्ड स्तर पर खरीप, रबी तथा जायद के अलग-अलग समय में प्रदर्शनियां लगायी जायं तथा इन दवाओं को समयानुसार सस्ते दरों पर कृष्टाकों को उपलब्ध कराया जाय।

(ध) नवीन कृषि यन्त्र

अध्ययन प्रदेश में नवीन कृष्णि यन्त्रों के प्रयोग द्वारा (कृष्णि का वैज्ञानिक यन्त्रीकरण करके) अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है । केवल बहे कृष्णकों के पास ही देव्हर, नलकूप, पिम्पंगसेट, ध्रेसर, मेस्टर हल, कल्टीवेटर, हैरो, सीड कम फिटिलाइजर द्विल, सिंह हैण्ड हो और पिहयेदार हो आदि नवीन कृष्णि उपकरण उपलब्ध हैं । वर्तमान समय में इनका प्रयोग बद्ध तो अवश्य रहा है किन्तु ये यन्त्र सीमान्त रवं लघु सीमान्त कृष्णकों की क्रय शक्ति क्षमता के बाहर हैं । भारी कृष्णि यन्त्रों के क्रय की सुविधाएँ विकासखण्ड एवं सहकारी सिमितियों के माध्यम से कृष्णकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए । हल्के कृष्णि यन्त्रों के क्रय के लिए सहकारी सिमितियों से निम्न ब्याज दर पर ग्रण प्रदान किया जाना चाहिए । इस पर सरकार की तरफ से कृष्णकों को अनुदान भी दिया जाना चाहिए । इस प्रकार यदि उत्तम नवीन कृष्णि यन्त्र कृष्णकों को मिल जायँ तो वे गहन तथा उन्नतिश्रील कृष्णि कर सकेंगें ।

(ड) फ्तल बीमा योजना

अध्ययन प्रदेश में फ्सल बीमा योजना को लागू करने की आवश्यकता है क्येंकि इससे कृष्ठकों को फ्सल की बुवाई से लेकर कटाई तक कई जोखिमों से होने वाली क्षाति से राहत मिल सकेगी । इस योजना से सीमान्त एवं नद्यु सीमान्त कृषकों को काफी नाभ प्राप्त होगा । यह योजना धान, गेहूं, मोटे अनाज, गन्ना, दलहन तथा तिलहन पसलों पर नागू की जानी चाहिए । पसन बीमा योजना में नद्यु एवं सीमान्त कृषकों के लिए बीमा शुल्क की 50 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाय । साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी कुछ अनुदान दिया जाना श्रेयम्कर होगा ।

(च) कृषि साख

कृषि के समुचित विकास हेतु सिंगाई, उन्नतिशील बीज, उर्वरक, कीट एवं खरपतवार नाशक दवाएँ तथा नवीन कृषि यन्त्रों का प्रयोग आवश्यक है किन्तु इनके क्रय के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है । कृषकों की आधिक स्थिति इतनी सुदृद्ध नहीं है कि वे स्वयं इनका क्रय कर सकें । इनके लिए उन्हें सस्ते व्याज दर पर अण की जरूरत होती है जो उन्हें कृषि अण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । तहसील में अण वितरित करने वाली संस्थाओं में भूमि विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक तथा प्रारम्भिक कृषि अण सहकारी समितियाँ आदि प्रमुख हैं । कृषि सहकारी समितियाँ कुमुबन्ध की शिकार हैं, व्याज की दर भी काफी उँगी हैं तथा अण के लिए जमानतदार देना आवश्यक होता है जो लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए सम्भव नहीं हो पाता । अतः आवश्यकता इस बात की है कि अण वितरण प्रणाली में पर्याप्त सुधार किया जाय । बैंकों द्वारा आसान किस्तों में तथा निम्न ब्याज दर पर समय-समय पर अण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

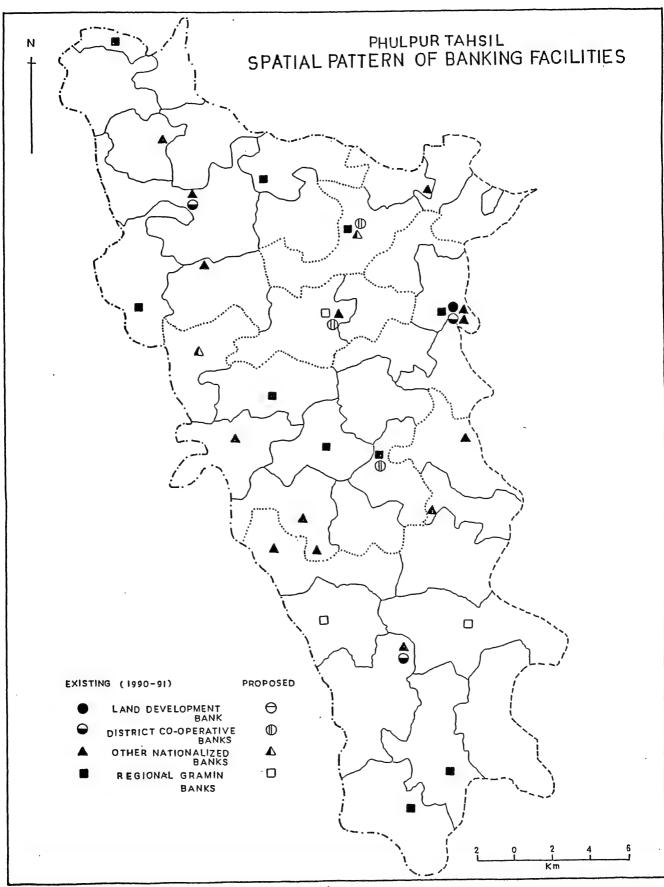


Fig. 4.4

(5) कृष्ण एवं पशुपालन सेवा केन्द्रों का स्थानिक नियोजन

कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी सेवाओं में बीजगोदाम, उर्वरक भण्डार, कीटनाशक डिपो, शीत भण्डार, कृषि सेवा केन्द्र, पशु चिकित्सालय, पशु विकास केन्द्र,
पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, सूअर विकास केन्द्र, भेंड विकास केन्द्र, पौल्द्री यूनिट,
कृषि ग्रण सहकारी समितियाँ तथा बैंक मूख्य हैं। किन्तु इन सुविधाओं को सम्मन्न
कराने वाले सेवा केन्द्रों की तहसील में कमी है। अतः इन सुविधाओं को सम्मन्न
कराने वाले केन्द्रों की अवस्थिति का नियोजन प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है।
इनकी अवस्थिति का प्रस्ताव सम्बन्धित सुविधाओं की कार्याधार जनसंख्या, उनके
बीच परस्पर दूरी तथा क्षेत्र में उनकी रिक्तता को ध्यान में रखकर किया गया है।

उन्नितिशील बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएँ प्रत्येक वर्तमान और प्रस्तावित विकास केन्द्रों पर उपलब्ध होनी चाहिए। सम्पूर्ण तहसील में ८ नये पशु अस्पताल/डिस्पेंसरी-माहुल, खुरासों, अम्बारी, मिन्तूपुर, राजापुर, सुरहन तथा पुलेश में छुलने चाहिए तथा ये पशु अस्पताल कृत्रिम गर्भाधान जैसे प्राविधानों से युक्त होने चाहिए।

तहसील में वित्तीय साधन प्रदान करने वाली इकाइयों की हिथति कुछ संतोष्ठानक कही जा सकती है। कृष्ठि ग्रण प्रदान करने वाली सहकारी समितियों का गठन प्रत्येक न्याय पंचायत एवं प्रस्तावित विकास केन्द्रों पर होना चाहिए(सारणी 3.8)।

विपणन एवं भण्डारण की सुविधाओं के लिए प्रत्येक वर्तमान एवं प्रस्तावित

विकास केन्द्रों पर एक-एक ग्रामीण गोदाम तथा सहकारी क्रय-केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पवई, पूलपुर, मार्टिनगंज एवं अहरौला(1) विकास खण्डों पर एक-एक शीत गोदाम होना चाहिए। इन आवश्यक सुविधाओं के उप-लब्ध होने पर क्षेत्र के कृष्णि विकास को निश्चय ही एक नयी दिशा और गति मिलेगी और प्रदेश एक उन्नतशील कृष्णि-व्यवस्था का प्रारूप प्राप्त कर सकेगा।

----::0::-----

सन्दर्भ

- Pathak, R.K.: Environmental Planning Resources and Development, Chugh Publications, Allahabad, 1990,
 p. 43.
- 2. Mc Master, D.N.: 'A Subsistance Crop Geography of Uganda' The World Land-use Survey - Occasional Papers No. 2, Geographical Publications, 1962, p.IX.
- ितंह, व्रजभूषण: कृष्टि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन, गौरखपुर, 1988, पृष्ठि । 65.
- 4. कुमार, पीठ तथा शर्मा, एस०केठ : कृष्टा भूगोल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1985, पूष्टठ ४०८.
- 5. Dayal, E.: Crop Combination Regions: A Study of the Punjab Plains, Tej Schrift Voor Economische Social Geographie, 1967, Vol. 58, p. 39.
- 6. Hussain, M.: Crop Combination in India, Concept Publishing Company, New Delhi, 1982, p. 61.
- 7. Ahmed, A. and Siddiqui, M.F.: Crop Association Patterns in the Luni Basin, The Geographer, Vol. XIV, 1967, p. 68.
- 8. Weaver, T.C.: Crop Combination Regions in the Middle West; Geographical Review, 44, 1954, p. 175.
- 9. Scott, P.: The Agricultural Regions of Tasmania, Economic Geography, 33, 1957, pp. 109-121.

- 10. Johnson, B.L.C.: Crop Combination Regions in East Pakistan, Geography, 43, 1958, pp. 86-103.
- 11. Thomas, D. : Agriculture in Wales during the Neopleanic War, Cradiff, 1963, pp. 80-81.
- 12. Coppack, J.T. : Crop-live Stock and Enterprises Combinations in England and Wales, Economic Geography, 40, 1964, pp. 65-81.
- 13. Doi, K. : 'The Industrial Structure of Japanese
 Prefecture', Proceedings of I.G.U. Regional
 Conference in Japan, 1957-59, pp. 31,0-316.
- 14. Banerjee, B. : Changing Crop Land of West Bengal, Geographical Review of India, Vol. 24, No.1, 1964.
- 15. Singh, Harpal: Crop Combination Regions in the Malwa Tract of Punjab, Deccan Geographer, Vol. 3, No.1, 1965, pp. 21-30.
- 16. Dayal, E. : Crop Combination Regions; A Case Study of Punjab Plain, Neatherland Journal of Economic and Social Geography, Vol. 58, 1967, pp. 39-47.
- 17. Roy, B.K. : Crop Association and Changing Pattern of Crops in the Ganga-Ghaghara Doab East,
 N.G.I.I., Vol. XIII, 1967, pp. 194-207.
- 18. पूर्वो क्त सन्दंभ संख्या 7, पृष्ठ 68.

- 19. Tripathi, V.K. and Agrawal, V.: Changing Pattern of Crop

 Land use in the Lower Ganga-Yamuna Doab,

 The Geographer Vol. XV, 1968, pp. 128-140.
- 20. Mandal, B.: Crop Combination Regions of North Bihar, N.G.J.I., Vol. XV, pp. 125-137.
- 21. Ayyar, N.P.: Crop Regions of Madhya Pradesh: A Study in Methodology, Geographical Review of India, 1969, pp. 1-19.
- 22. Sharma, T.C.: Pattern of Crop Land-use in Uttar Pradesh,
 Deccan Geographer, 1972, pp. 1-17.
- 23. Nityanand : Crop Combination in Rajesthan, Geographical Review of India, 1982, pp. 61-86.
- 24. पूर्वों क्त संदर्भ संख्या 6, पूष्ठ 61-86.
- 25. दत्त, आर० एवं सुन्दरम्, के०पी०एम० : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस० चन्द्र एण्ड कम्मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1990, पूष्ठ 587.
- 26. तां खियकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1990, पूष्ठ 24.
- 27. Malone, C.C.: Background of Indian Agricultural and and Indian's Intensive Agriculture Programme, New Delhi, 1969.

----::0::-----

अध्याय पाँच

आैद्यो गिक संरचना एवं विकास नियोजन

5. । प्रस्तावना

भारत एक कृष्ण-प्रधान देश हैं । कृष्णि के क्षेत्र में समुन्नत साधनों के प्रयोग से यद्यपि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परन्तु जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की अर्थंट्यवस्था में मात्र कृष्णि का विकास ही पर्याप्त नहीं है । देश के आर्थंक विकास के लिए औद्योगीकरण में प्रगति अपरिहार्य है । इसी लिए अर्थंट्यवस्थाओं की प्रब्लता के सन्दर्भ में कोई निर्णय, उनके निर्माण उद्योग के विकास के स्तर के आधार पर किया जाता है । विश्व के सभी विकसित देश औद्योगिक किस्म के हैं । अधिकांश विश्व का पिछड़ापन मुख्यत: कृष्णि पर अधिक अवलम्बिता के कारण है ।

'उद्योग का शाब्दिक अर्थ किसी भी ट्यवस्थित एवं क्रमबद्ध कार्य से लगाया जाता है। इस प्रकार इसमें मानव के सभी कार्य समाहित हो जाते हैं। किन्तु यहाँ पर उद्योग से तात्पर्य केवल वस्तु-निर्माण प्रक्रियाओं तक ही सीमित है। अतः प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारी रिक अथवा यान्त्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियन्त्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार अथवा विशेष्ठ गुण-धर्म वाली वस्तु में परिणत करना ही उद्योग है। इस अर्थ में अतिसाधारण वस्तुओं जैसे मिद्दी के वर्तन, हाथ से बने जूते आदि के निर्माण से लेकर भारी से भारी तथा जिलतम प्रक्रिया से निर्मित जैसे बड़ी-बड़ी म्हानें, रेलवे इंजन, जहाज आदि सभी उद्योगों के उत्पाद हैं। 2

ग्रामीण क्षेत्रों की कृष्टि आधारित अर्थट्यवस्था के उन्नयन के लिए तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण बद्धती श्रम शक्ति को स्थानीय रूप से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कृष्ठि पर आधारित श्रम प्रधान उद्योगों का विकास आवश्यक हो जाता है। किसी भी विकास-नियोजन में कृष्ठि पर आधारित उद्योगों की भूमिका निर्णायक होती है। इसके द्वारा ही किसी ग्रामीण अर्थन्यवस्था में स्थायित्व आता है तथा उसका बहुमुखी विकास संभव हो पाता है। इससे न केवल ग्रामीण प्रतिभाओं और पूँजी के पलायन पर नियन्त्रण रखा जा सकता है बल्कि कृष्ठि, सिंचाई, परिवहन और संचार आदि क्षेत्रों के विनियोग और उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार पिछड़ी अर्थन्यवस्थाओं के विकास के लिए उनका औद्योगीकरण होना आवश्यक है। साथ ही, औद्योगीकरण को वांछित गति तथा दिशा केवल औद्योगिक विकास-नियोजन से ही दी जा सकती है। किसी भी औद्योगिक नियोजन में विभिन्न तरह के उद्योगों के भावी विकास का कार्यक्रम राष्ट्र, प्रदेश, जिला, तहसील तथा विकासखण्ड स्तर पर तैयार किया जाता है। तहसील स्तर पर मुख्यत: मध्यम एवं लघु स्तरीय उद्योगों का नियोजन ही महत्त्वपूर्ण होता है जिनके विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है।

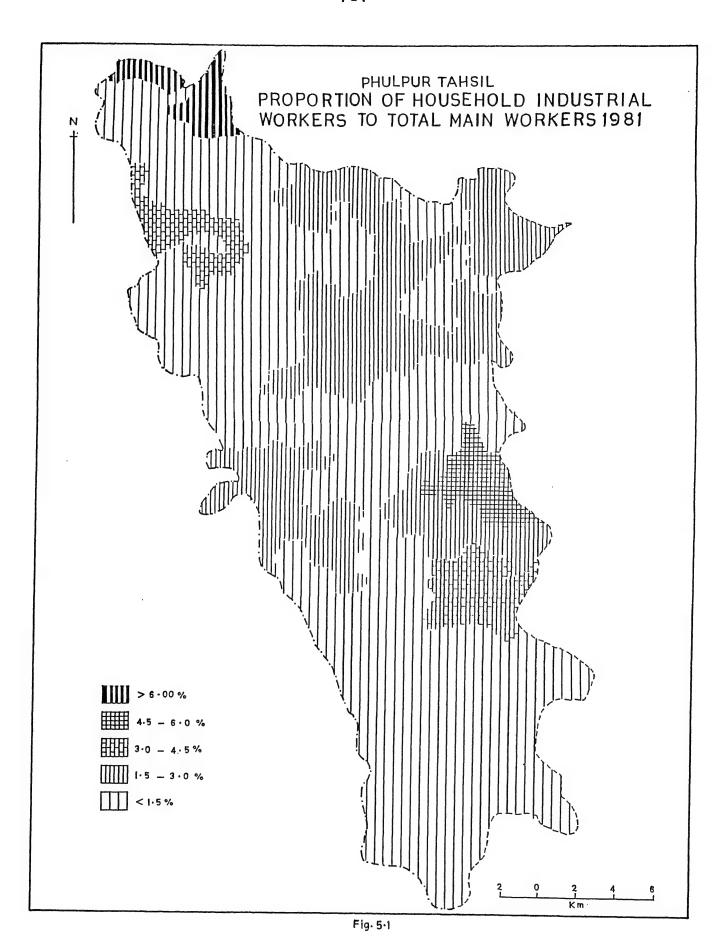
अध्ययन प्रदेश राष्ट्रीय विकास परिष्य द्वारा गठित बीठडीठ पाण्डेय
सिमिति द्वारा निर्धारित औद्योगिक रूप से पिछड़े आजमगढ़ जनपद की एक तहसील है ।
उद्योगों की दृष्टिद से यह तहसील नितान्त पिछड़ी है । उद्योगों के नाम पर यहाँ
मात्र कुछ गृह एवं कुदीर उद्योगों का ही अस्तित्व है और वे भी अपनी शैष्ट्रवावस्था में
हैं । इनमें परम्परागत शिल्प कौशल पर आधारित उद्योगों में स्थानीय कृष्ण उत्पादों
का प्रयोग कर स्थानीय माँग अभिप्रेरित वस्तुओं एवं सामानों का उत्पादन किया
जाता है । अतः प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों, परम्परागत

शिल्प कौशन तथा अन्य औद्योगिक सुविधाओं को ध्यान में रहाते हुए उद्योगों की संभावनाओं एवं उनकी संभावित हिथतियों का आकलन प्रस्तुत करना है।

5. 2 हेन्रीय औद्योगिक संरचना

किसी भी प्रदेश का समुचित नियोजन प्रस्तुत करने के पहले उस क्षेत्र में विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का आकान करना आवश्यक है । औद्योगिक विकास की दृष्टिद से अध्ययन प्रदेश अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । यहाँ पर वृहद् तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों का पूर्णतया अभाव है । औद्योगीकरण के नाम पर मात्र कुछ लद्ध-स्तरीय इकाइयों तथा गृह उद्योगों का ही विकास हो पाया है । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार तहसील की कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 2.08 प्रतिष्ठात भाग उद्योगों में संनग्न है जिसका 1.28 प्रतिष्ठात गृह उद्योगों तथा 0.80 प्रतिष्ठात लद्ध-स्तरीय औद्योगिक इकाइयों में लगा है । विकासखण्ड स्तर पर पवर्ड में सबसे अधिक कुल कार्यशील जनसंख्या 1.50 प्रतिष्ठात भाग गृह उद्योगों में लगी हुई है । मार्टिनगंज विकास खण्ड में सबसे कम कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 1.05 प्रतिष्ठात भाग गृह उद्योगों में तंलग्न है । अन्य विकासखण्डों अहरतेला(1)तथा पूलपुर में कुल मुख्य कार्यशीज जनसंख्या का गृह उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिष्ठात क्रम्बा: 1.33 तथा 1.27 है (सारणी 5.1)।

न्याय पंचायत स्तर पर मित्तूपुर में सब्से अधिक कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 7.8। प्रतिश्वात जनसंख्या गृह कार्यों में लगी हुई है। यहाँ पर गृह उद्योगों में संलग्न जनसंख्या के अधिक होने का कारण यहाँ की कृष्टि का अपेक्षाकृत पिछड़ापन है।



सारणी 5.। पूलपुर तहसील की औद्योगिक संरचना, 1981

न्याय पंचायत	क्ल महय कै। यूजील जनसंख्या	गृह का घरें सलग्न क्ल जनसङ्घर्	गृह का घरें में सर्वन्न जनसंख्या का मृख्य कार्य- शील जनसंख्या से प्रतियात
	2	3	4
। मित्तूपुर	2729	213	7.81
2. रामनगर	2248	8	0.36
 सत्तारपुर रज्जाकपुर 	3205	54	1. 68
 दोस्तपुर लहुरमपुर 	2169	8	0.37
5. तुम्हाडीह	2700	16	0. 59
6. बस्ती सदनपुर	288	97	3.37
 मुल्तानपुर 	1991	23	1.16
 तौदमा थानेश्वर 	2309	5	0. 22
9. बाग सिकन्दरपुर	3443	34	0.99
10. सादुल्लाहपुर	3715	28	0.75
।।. अम्बारी	2826	66	2.34
12. फ्दगुडिया	1640	31	1.89
13. खंजहापुर	2501	17	0. 68
14. सजई अमानबाद	3018	22	0. 73
15. बक्सपुर मेजवा	1591	12	0.75
16. नो नियाडीह	2264	33	1. 46
17. सदरपुर बरौनी	2364	80	3.38

	2	3	4
	2195	14	0. 64
19. गद्दौपुर बारी	2245	30	1.34
20. पल्थी दुल्हापुर	2076	30	1. 45
21. राजापूर	2382	36	1.51
22. खरसहनक्ता	2375	40	1. 68
23. महुअररा	1446	01	0. 07
२४. पुकवाल	1931	48	2. 49
25. सिकरौर	2186	118	5. 40
26. करुबा फ्लेंहपुर	1602	29	1.81
27. कौरागहनी	3496	109	3.12
28. पुलेश अहमद बन्धा	2217	05	0. 23
29. छितर अहमदपुर	3043	36	1.18
30. बेलवाना	2706	20	0.74
उ ।. कुरथुवा	2127	05	0.24
32. जगदीशमुर ददेशिया	3267	33	1.01
33. सुरहन	3 165	47	1. 48
34. लसरा खुर्द	2455	08	0. 33
35. पारा मिश्रौं लिया	2194	40	1.82
36. गनवारा	2200	04	0.18

<u> </u>		2	3	4
37.	माहून	5394	134	2. 48
38.	शम्शा बाद	1951	32	1.64
	पवई विकासखण्ड	38986	583	1.50
	पूलपुर विकासखण्ड	37944	480	1. 27
	मार्टिनगँज विकासखण्ड	38972	410	1. 05
	अहरौना १ विकासखण्ड	15814	210	1, 33
	पूलपुर तहसील	131716	1683	1.28

म्रोत: जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, प्राथमिक जनगणनासार, भाग XIII के जनपद आजमगढ़, 1981 से संगणित

अधिकांश जनसंख्या घरेलू उद्योग-धन्धों जैसे बद्धि गिरी, कुम्भकारी तथा अन्य छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों में लगी हुई है। महुआरा में सबसे कम 0.07 प्रतिशत जनसंख्या गृह उद्योगों में संलग्न है। इसका कारण बहुआरा न्यायपंचायत में अधिकांश जनसंख्या कृष्ठि कार्यों में लगी हुई है तथा गृह उद्योगों का बहुत ही कम विकास हुआ है।

5. 3 नुद्ध स्तरीय इंकाइयाँ

औदोगिक ढाँचे को वृहद् , मध्यम और लघु तीन स्तरों में विभाजित किया

जाता है। ऐसी इकाइयाँ जिनमें यन्त्र एवं सयन्त्र पर 2 करोइ से अधिक पूँजी विनियो जित हो उन्हें वृहद स्तरीय तथा जिनमें 60 नाख से अधिक तथा 2 करोइ से कम पूँजी विनियो जित हो, मध्यम स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत रखा गया है। में नद्युं उद्योगों के सन्दर्भ में पूँजी निवेश की सीमा समय समय पर बदलती रही है। 30 मई 1990 तक नद्युं उद्योगों में संयन्त्र और मशीनरी में पूँजी विनिवेश की सीमा 35 नाख रूपये तक थी किन्तु 3। मई 1990 ई0 से यह सीमा बद्धाकर 60 नाख रूपये कर दी गयी किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों तथा पाँच नाख से कम आबादी वाले कस्बों में सेवा प्रदान करने वाले स्थापित वे सभी उद्यम नद्युं संस्थानों के अन्तर्गत पंजीकृत हो सकते हैं जिनमें संयन्त्र और मशीनरी पर 2 नाख रूपये से कम छर्च हो। 5 अध्ययन प्रदेश में ऐसी ही नद्यं नद्युन्तर उद्योगों का अधिक विकास हुआ है।

लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु जिला उद्योग केन्द्र आजमगढ़ की स्थापना 1979 ईं0 में की गयी किन्तु क्षेत्र के विकास के लिए यह वांछित गति न दे सका जिसकी आवश्कता थी। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यम्पिं को आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु समुचित मात्रा में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए जिससे एक और उद्यमी अपनी आय में वृद्धि कर सके, दूसरी और ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ सके जिसकी लोगों की आवश्यकता है।

अध्ययन प्रदेश में वर्ष 1990-9। तक कुल 26। लद्यु रवं अति लद्यु स्तरीय
औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत थीं। इन पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों में कुल 1062
व्यक्तियों को राजगार प्राप्त है। इन विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कुल 41.38

लाख रूपये की पूँजी विनियो जित है तथा इनके द्वारा प्रतिवर्ध लगभग 75.33 लाख रूपये की विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में खाद्य तेल, इंजी नियरिंग उद्योग, काष्ठकला एवं काष्ठकला उत्पाद, सीमेण्ट जाली उद्योग, मशीनरी उपकरण एवं मशीनरी मरम्मत उद्योग, तिलाई-कद्वाईं उद्योग, रेडीमेट गारमेन्द्स, बेकरी, प्रिन्टिंग प्रेस, ईंट उद्योग तथा बीड़ी उद्योग मुख्य हैं। इनकी संख्या विनियो जित पूँजी तथा उत्पादन सारणी 5.2 में देखी जा सकती है।

सारणी 5.2 पूलपुर तहसील में पंजीकृत लघू उद्योग, 1990-91

	उद्योग का नाम नाम	कार्यरत इकाइया	रोजगार में सलग्न ट्यिं क्त	विनियो जित पूजी (लाख ह्मयेम)	उत्पादन (लृख स्पर्य में)
	1	2	3	4	5
	-r- \s	27		5 75	0 14
1.	खाद्य तेल	27	84	5. 35	9.14
2.	खाद्य पदार्थ	1.1	40	1. 49	2.73
3.	हल्के इंजी नियरिंग उद्योग	37	137	5. 65	12.59
4.	काष्ठ क्ला स्वं काष्ठ क्ला उत्पाद	34	119	3.19	6.30
5.	सीमेण्ट जाली उद्योग	16	45	1.85	3.85
6.	महीनरी उपकरण एवं मरम्मत उद्योग	34	123	5. 01	9.81

1	and and got ton the for and ton	2	3	4	5
7.	तिलाई - कढ़ाई उद्योग	14	55	1. 67	3.38
8.	रेडीमेट गारमेन्द्रत	17	66	1. 69	3. 57
9•	प्ला स्टिक उद्योग	11	50	1.88	3.76
10.	ईc उद्योग	10	118	5. 35	6. 29
11.	प्रिंटिंग प्रेस	3	12	0.70	1. 02
12.	बेकरी उद्योग	4	10	0.35	0. 59
13.	साबुन उद्योग	4	15	0.64	0.71
14.	वर्म उद्योग	3	12	0. 45	1. 15
15.	मो मबत्ती उद्योग	3	12	1.10	1.16
16.	टाइल्स उद्योग	2	12	0. 40	0.60
17.	मताला उद्योग	2	8	0. 22	0. 45
18.	होज़री उद्योग	3	9	0.21	0.56
19.	स्टूडियो	3	6	0.15	0.72
20.	बीड़ी उद्योग	3	16	0.35	1. 29
21.	कारपेट उद्योग	4	34	0.60	1.32
22.	उन, सिल्क एवं सिन्धेटिक वस्त्र उद्योग	5	25	0. 63	1. 22
23.	विद्युत उपकरण, रिम्लि उद्योग आदि	11	54	2. 45	3.12
	पूनपुर तहसील	261	1062	41.38	75. 33

टिप्पणी : विनियो जित पूँजी में भूमि/भवन सम्बन्धी पूँजी सम्मिलित नहीं है। स्रोत : लह्म स्तरीय इकाइयाँ तथा वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की निर्देशिका,

जनपद आजमगढ़, 1990-91.

(।) हल्के इंजी नियरिंग उद्योग

अधिगिक इकाइयों की सख्या, संनग्न व्यक्ति तथा विनियोजित पूँजी एवं उत्पादन की दृष्टि से तहसील का यह सबसे बड़ा उद्योग है। इन औद्योगिक इकाइयों में ग्रिल, चैनलगेट, खिड़की, दरवाजे, लोहे की आलमारियां. कुर्सी तथा मेज आदि का निर्माण होता है। अध्ययन-प्रदेश में इनसे सम्बन्धित 37 लघु एवं अति लघु स्तरीय इकाइयां कार्यरत हैं जो क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनमें 137 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इन औद्योगिक इकाइयों में 5.65 लाख रूपये की पूँजी विनियोजित है तथा 12.59 लाख रूपये मूल्य की विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है। इनसे सम्बन्धित सर्वाधिक 18 इकाइयों का सकेन्द्रण तहसील मुख्यालय पूनपुर में है। इसके अतिरिक्त अम्बारी में 4, पवई में 3, माहुल, मार्टिन-गंज, सिकरौर, मिल्कीपुर में दो-दो तथा पहाडपुर, नेवादा, भरचिकया और बखरा में एक-एक इकाइयां कार्यरत हैं।

(2) मानिरी उपकरण एवं मरम्मत उद्योग

कार्यरत इकाइयाँ एवं संलंगन ब्यक्तियों की दृष्टि से हल्के इंजीनियरिंग
उद्योग के बाद दूसरा स्थान मझीनरी उपकरण एवं मरम्मत उद्योग का है। तहसील में
इससे सम्बन्धित 34 लघु स्तरीय इकाइयाँ कार्यरत हैं तथा इनमें 123 व्यक्तियों को
रोजगार प्राप्त है। मरम्मत सम्बन्धी कार्यों में कृष्टि औजार/मझीनों की मरम्मत,
आदो मरम्मत, इलेक्ट्रिक्न एवं इलेक्ट्रिनिक सामानों की मरम्मत, सिलाई मझीन
मरम्मत प्रमुख हैं। इससे सम्बन्धित लघु स्तरीय इकाइयों का सर्वाधिक संकेन्द्रण पूलपुर
तहसील मूख्यालय पर है जहाँ 17 इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा पवर्ड में 6,

अम्बारी में 3, मार्टिनगंज में 2 तथा दीदारगंज, पहाइपुर, माहुल, छित्तेपुर, बखरा और सिकरौर में एक-एक इकाइया कार्यरत हैं। इन इकाइयों में कुल 5.01 लाख रूपये की पूँजी लगी हुई है और लगभग 9.81 लाख रूपये मूल्य का उत्पादन होता है।

(3) काष्ठ क्ला एवं काष्ठ क्ला उत्पाद उद्योग

अध्ययन प्रदेश में काष्ठ क्ला एवं काष्ठ क्ला उत्पाद सम्बन्धी 34 इकाइयाँ कार्यरत हैं तथा इनमें 119 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इनमें लक्ड़ी की वस्तुओं - मेज, कुर्सी, दरवाजे, चौखट, तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होता है। इनमें 3.19 लाख रूपये पूँजी विनियो जित है तथा 6.30 लाख रूपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इनका सर्वाधिक संकेन्द्रण सिकरौर में है जहाँ 7 इकाइयाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा छित्तेपुर में 6, अम्बारी में 5, पूलपुर में 3, पवई, मार्टिनगंज एवं दीदारगंज में दो-दो, वनगाँव, बासूपुर, नेवादा, दुबरा, मिल्कीपुर, पल्थी तथा कुम्लगाँव में एक-एक इकाइयाँ कार्यरत हैं।

(4) खाद्य तेल उद्योग

अध्ययन प्रदेश में खाद्य तेन की 27 नद्यु स्तरीय इकाइयाँ कार्यरत हैं जिनमें कुन 5.35 नाख रूपये पूँजी का विनियोग हुआ है। ये तभी इकाइयाँ तिम्मिनत रूप ते नगभग 9.14 नाख रूपये मूल्य के तेन खंखनी का उत्पादन प्रतिवदी करती हैं। इस उद्योग का सर्वाधिक 7 इकाइयाँ उदपुर में कार्यरत हैं। इसके अनावा पूनपुर तथा पवर्ड में 5-5, दीदारगंज में 3, तुम्हाडीह में 2 तथा मार्टिनगंज, पुरन्दरपुर, करौंजा, मित्तूपुर, तिकरौर में एक-एक इकाइयाँ कार्यरत हैं।

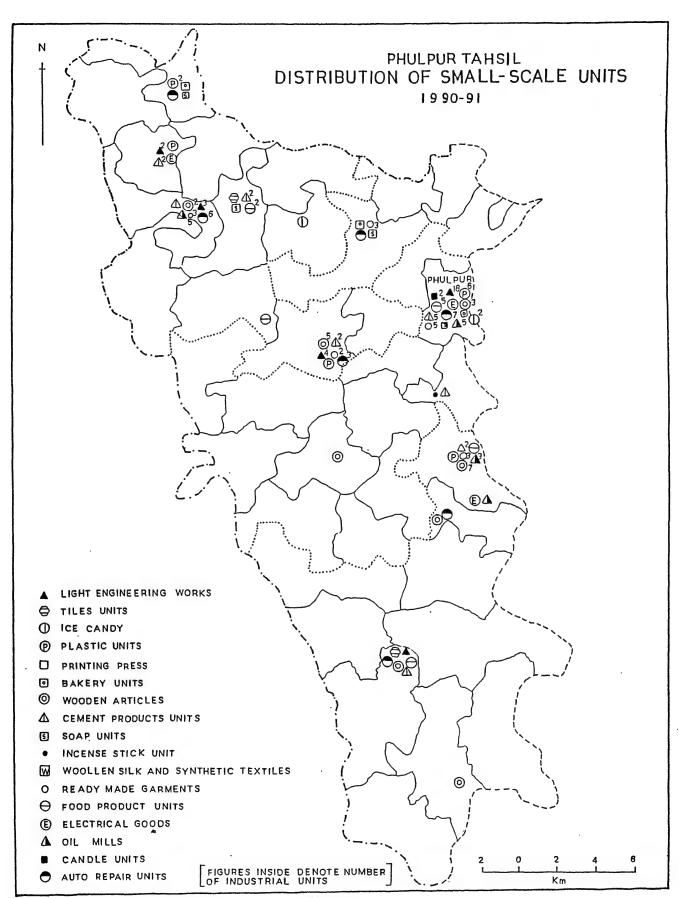


Fig. 5-2

(5) <u>सीमेन्ट जाली उद्योग</u>

अध्ययन प्रदेश में ती मेन्ट के तामानों-जाली, गम्ला, तैनिटरी वेयर, नाँद बनाने तम्बन्धी 16 लघु स्तरीय इकाइयाँ कार्यरत हैं तथा 45 लोगों को रोजगार प्राप्त है। इन उद्योगों में 1.85 लाख रूपये की पूँजी लगी हुई है। इनसे संबंधित पूलपुर में 5, तिकरौर में 3, मार्टिनगंज, अम्बारी, मिल्कीपुर में 2-2, तथा पवई सवं हैदराबाद में 1-1 इकाइयाँ कार्यरत हैं।

(6) रेडीमेट गारमेंद्र उद्योग

तहसील में रेड़ी मेट गार मेंद्र सम्बन्धी । 7इकाइयाँ कार्यरत हैं । इनसें 66 लोगों को रोजगार प्राप्त है । इनमें कुल । 69 लाख रूपये पूँजी का विनियोग हुआ है तथा वार्षिक उत्पादन लगभग 3.57 लाख रूपये का होता है । रेड़ी मेट गार मेंद्र सम्बन्धी पूलपुर में 5, माहुल, सिकरौर, पवई में 3-3, अम्बारी में 2 तथा उद्यपुर में एक इकाई कार्यरत है ।

(7) तिलाई एवं कढ़ाई उद्योग

अध्ययन क्षेत्र में वस्त्रों की तिलाई एवं कट्टाई सम्बन्धी । 4 अति लघु स्तरीय इकाइयां कार्यरत हैं। इनसे 55 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हैं। इनमें । 67 लाख रूपये की पूँजी विनियोजित है तथा वार्षिक उत्पादन 3.38 लाख रूपये है। इस उद्योग का भी सकेन्द्रण पूलपुर में है जहां कुल 5 इकाइयां कार्यरत हैं। पवई में 3, मार्टिनगंज तथा अम्बारी प्रत्येक स्थान पर 2-2 इकाइयां स्थापित हैं। माहुल और उद्युर में एक-एक इकाइयां लगी हुई हैं।

(८) प्लास्टिक उद्योग

तह्मील में प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी कूल ।। लघु स्तरीय इकाइया कार्यरत हैं। पूलपुर में 6, पहाड़पुर में 2 तथा मिल्कीपुर, सिकरौर और उद्यपुर में एक-एक इकाइया स्थापित हैं। इन उद्योगों में 50 लोगों को रोजगार प्राप्त है तथा । 88 लाख रूपये पूँजी का निवेश है।

(१) खाद्य पदार्थ उद्योग

अध्ययन प्रदेश में खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित कूल ।। लघु स्तरीय इकाइयाँ हैं जिनमें पवर्ड, फूलपुर, सुम्हाडीह में 2-2, उद्यपुर, डीहपुर, ब्छारा लारपुर तथा फत्तन-पुर में एक-एक इकाइयाँ अवस्थित हैं। इनमें 40 लोगों को रोजगार प्राप्त है। इस उद्योग में ।. 49 लाख रूपये की पूँजी लगी हुई है तथा वार्षिक उत्पादन 2.73 लाख रूपये का है।

(10) ईट उद्योग

ईंट उद्योग स्थानीय माँग पर आधारित उद्योग है। तहसील में इससे सम्बन्धित कुल 10 इकाइयाँ - सिकरौर, बहादुद्दीनपुर, सुम्हाडीह, फत्तनपुर, पवई, दीदारगंज, पल्थी, कछरा, अम्बारी तथा पलिया में कार्यरत हैं। इस उद्योग में 118 ट्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

(।) प्रिंटिंग प्रेस

प्रिंटिंग प्रेस की संख्या तहसील में 3 हैं जो तहसील मुख्यालय पूलपुर में अवस्थित हैं।

(12) बेकरी उद्योग

तह्सील में बेकरी उद्योग की कूल 4 लद्ध स्तरीय इकाइयाँ कार्यरत हैं। इनमें 10 लोगों को रोजगार प्राप्त है। इनमें ब्रेड तथा विस्कृट का उत्पादन होता है।ये इकाइयाँ माहुल, पूलपूर, पहाइपूर तथा दीदारगंज में कार्यरत हैं।

(13) साबुन उद्योग

कपड़ा धूनने के साबुन बनाने के उद्योगों की संख्या 4 है। ये औद्योगिक इकाइयाँ रामापुर, पहाडपूर, दीदारगंज तथा माहून में एक-एक इकाइयाँ कार्यरत हैं।

(।4) चर्म उद्योग

तह्मील में जूते और चप्पल बनाने सम्बन्धी कुल इकाइयों की संख्या 3 है। ये इकाइयाँ, पूलपुर, अम्बारी तथा मिल्तूपुर में कार्यरत हैं।

(15) मोमबत्ती उद्योग

अध्ययन प्रदेश में मोमबत्ती बनाने की कून 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं। इनमें दो इकाइयाँ पूनपुर तथा एक इकाई औराडाड में अवस्थित है।

(16) टाइल्स उद्योग

इसकी दो इकाइयाँ मार्टिनगंज तथा विलवाई में कार्यरत हैं। इनमें 12 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

(17) मताला उद्योग

मताला पीतने की 2 अति लघु स्तरीय इकाइयाँ पूलपुर तथा पवई में स्थापित हैं। इसमें 8 ट्यक्ति लगे हुए हैं।

(18) <u>उन, सिल्क एवं सिन्धेटिक टेक्स</u>टाइल्स उद्योग

इस उद्योग से सम्बन्धित कुल 5 इकाइयाँ नेवादा में कार्यरत हैं। इनमें कुल 25 लोगों को रोजगार प्राप्त है।

तह्सील में कारपेट उद्योग की 4 इकाइयाँ - माहुल, पल्थी, पवई तथा पूलपुर में कार्यरत हैं।

तहसील में होजरी उद्योग की कुल 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं। फूलपुर में 2 तथा हैदराबाद में। इकाई कार्यरत है।

स्टूडियों की कुल तीन नधु स्तरीय इकाइयाँ-पवर्ड, पूलपूर तथा अझारी में अवस्थित हैं।

वीडी उद्योग की कुल 3 इकाइयाँ - माहुल में दो तथा अम्बारी में एक इकाई स्थापित है।

तह्तील में विद्युत उपकरण की केवल एक इकाई पूलपूर में अव स्थित है। अध्ययन प्रदेश में लाइट हाउस तथा रिफ्लि उद्योग की एक-एक इकाइयाँ पूलपुर में कार्य-रत हैं।

5. 4 गृह उद्योग

जनगणना 1981 के अनुसार गृह उद्योग वह उद्योग है जो परिवार के मुख्यित द्वारा स्वयं और मुख्यत: परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में

(18) उन, सिल्क एवं सिन्थेटिक टेक्सटाइल्स उधोंग

इस उद्योग से सम्बन्धित कुल 5 इकाइयाँ नेवादा में कार्यरत हैं। इनमें कुल 25 लोगों को रोजगार प्राप्त है।

तह्तील में कारपेट उद्योग की 4 इकाइयाँ - माहुल, पल्थी, पवर्ड तथा फूलपुर में कार्यरत हैं।

तहसील में होजरी उद्योग की कुन 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं। पूलपुर में 2 तथा

स्टूडियों की कुल तीन नद्ध स्तरीय इकाइयाँ-पवर्ड, पूलपूर तथा अस्वारी में अवस्थित हैं।

वीडी उद्योग की कुल 3 इकाइयाँ – माहुल में दो तथा अम्बारी में एक इकाई स्थापित है।

तह्सील में विद्युत उपकरण की केवल एक इकाई पूलपूर में अवस्थित है। अध्ययन प्रदेश में लाइट हाउस तथा रिफिल उद्योग की एक-एक इकाइयाँ पूलपुर में कार्य-रत हैं।

5. 4 गृह उद्योग

जनगणना 1981 के अनुसार गृह उद्योग वह उद्योग है जो परिवार के मुख्यित द्वारा स्वयं और मुख्यत: परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव की तीमा के अन्तर्गत और नगरीय क्षेत्रों में उत मकान के अन्दर या अहाते में जितमें परिवार रहता है, चलाया जाता है। मुख्या को तिम्मिलित करके पारि-वारिक उद्योग में अधिकतर कार्यकर्ता परिवार के होने चाहिए। उद्योग इत पैमाने पर नहीं होना चाहिए कि भारतीय कारखाना अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड हो या होने योग्य हो। 6

गृह उद्योग के अन्तर्गत कद्धिगीरी, खाँडसारी उद्योग, तेलघानी उद्योग, जूता निर्माण उद्योग, लोहे के सामानों का उद्योग, मिद्दी के वर्तन, सूत कातने एवं डिलया बनाने का उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग आदि को सिम्मिलित किया गया है। तहसील में ये उद्योग घर पर ही अपंजीकृत रूप में कार्यरत हैं। ये औद्योगिक इकाइयाँ स्थानीय आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। इन उद्योगों से सम्बन्धित समुचित आंक्डे उपलब्ध न होने के कारण इनका विशद विवरण दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को सुदृद्ध करने की महती आवश्यकता है।

5. 5 औद्योगिक संभाट्यता

अध्ययन प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यहाँ की अर्थट्यवस्था के विकास में उद्योगों का उतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना होना चाहिए था। यहाँ की मूख्य कार्यशील जनसंख्या का मात्र 2.08 प्रतिशत जनसंख्या ही उद्योग में लगी हुई है। यहाँ पर उद्योगों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण की कमी है। साथ ही औद्योगिक अवस्थापना के प्रेरक तत्त्वों-वित्तीय संस्थाओं, बाजार की कमी तथा परिवहन एवं संचारसाधनों का अविकसित

अवस्था में होना है।

तहसील में खानिज संसाधनों का पूर्णतया अभाव है। बस ईंट उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। तहसील में धान, गन्ना, गेहूं, आलू आदि पसलों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक मात्रा में होता है। अतः तहसील में कृष्ठि एवं पशुपालन पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं अधिक हैं। कृष्ठि में हरित क्रान्ति आने से कृष्ठि यन्त्रों एवं पशुपालन पर आधारित डेयरी उद्योग के विकसित होने की अधिक गुंजाइश है।

स्थानीय माँग पर आधारित उद्योगों में बेकरी, तिलाई एवं कद्वाई उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक एवं कृष्ठा रक्षक दवाइयों, बिजली के सामानों, कृष्ठा उपकरणों आदि के पर्याप्त विकतित होने की संभावनाएँ हैं क्यों कि तहसील में इन वस्तुओं की माँग अध्यक है। इस प्रकार पूलपुर तहसील में संसाधन-आधारित एवं माँग-आधारित दोनों तरह के उद्योगों के विकास के पर्याप्त अवसर विध्मान हैं। अत: इन उद्योगों के समृचित विकास के लिए औद्योगिक विकास नियोजन आवश्यक है।

5.6 औद्योगिक नियोजन एवं प्रस्ता वित उद्योग

प्रारम्भ से ही देश के औद्योगिक विकास में वृहद् उद्योगों का वर्षिव रहा है किन्तु औद्योगिक विकास में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना में प्राचीन काल से ही ग्रामीण एवं लघु उद्योंगों की प्रभावी भूमिका रही है। औद्योगिक दृष्टित से उन्नत देशों में भी औद्योगिक नियोजन में लघु उद्योगों की भूमिका को स्वीकार किया है। स्थानीय संसाधन तथा माँग के आधार

पर उद्योगों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है -

- (।) संसाधन-आधारित उद्योग
- (2) माँग-आधारित उद्योग

पूलपुर तहसील औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। तहसील के अद्योगिक विकास को गित प्रदान करने के लिए मध्यम/लघु स्तरीय विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति का एक सकारात्मक नियोजन प्रस्तुत है। लघु उद्योगों के माध्यम से ही ग्रामीण उद्योगों एवं औद्योगीकरण के ब्ल मिलेगा। ये उद्योग स्थानीय संसाधनों एवं जनशक्ति का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ये कम से कम पूंजी पर स्थापित किये जा सकते हैं और तहसील की विकास अवस्था के साथ समायोजन करने में समर्थ होंगे।

(।) संताधन-आधारित उद्योग

तहसील की अर्थंट्यवस्था की रींढ कृष्णि है। खनिजों का अभाव है। अतः अध्ययन प्रदेश में उपलब्ध संसाधन आधारित उद्योगों का अधिक विकास हो सकता है। संसाधन आधारित उद्योगों को दो वगों में विभक्त किया गया है –

(क) कृषि आधृत उद्योग

अध्ययन प्रदेश में कृष्ण उत्पादों से सम्बन्धित मध्यम निद्ध स्तरीय इकाइयों की स्थापना आसानी से की जा सकती है। तहसील में कृष्ण आधारित उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल तथा श्रम आसानी से सुलभ होने से न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। इससे जहाँ एक तरफ बेरोजगारों की संख्या में कमी आयेगी, वहीं क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति प्राप्त होगी। कुछ प्रमुख

कृषि आधारित उद्योग इस प्रकार हैं -

(अ) आदा मिल एवं सम्बद्ध उद्योग

अध्ययन प्रदेश में गेहूँ प्रमुख पसल है । इसका औसत वार्षिक उत्पादन 59554 टन है । तह्सील में आटा उद्योग के नाम पर मात्र विद्युत चालित छोटी-छोटी आटा चिक्यां ही कार्यरत हैं तथा कुछ आटा हस्त्वालित चिक्यां द्वारा भी निकाला जाता है । तहसील में गेहूँ के उत्पादन में भावी वृद्धि को देखते हुए सन् 200। तक इन छोटी-छोटी चिक्क्यों के स्थान पर आटा मिल स्थापित किया जाना चाहिए । इनकी प्रस्तावित स्थितियां पवई, पूलपुर, माहूल, अम्बारी, मार्टिनगंज तथा सिकरौर हैं ।

आदा उद्योग के साथ इन पर आधारित अनुष्यंगी उद्योगों की भी स्थापना की जा सकती है। अनुष्यंगी उद्योगों में डब्लरोटी, बिस्कुट एवं केंक आदि बनाने की इकाइयाँ प्रमुख हैं। इनके माध्यम से जहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे वहीं तहसील का बहुमुखी विकास होगा।

(ब) चावल मिल

अध्ययन प्रदेश में धान का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, तहसील में धान का औसत उत्पादन उ4846 दन प्रतिवर्ध है। घरेलू उपयोग हेतु 45% चावल हाथ द्वारा या क्षेत्र में स्थित छोटी-छोटी म्झीनों द्वारा निकाला जाता है। हाथ द्वारा चावल निकालने से अधिकांश चावल दूट जाता है। क्षेत्र में जो छोटी-छोटी चावल की इकाइयाँ कार्यरत भी हैं, उनकी क्षमता बहुत कम है। धान के बदते उत्पादन के साथ अतिरिक्त चावल मिलों को स्थापित करने की आवश्यकता है जिनकी प्रस्ता वित

अवस्थितियां माहुल, अम्बारी, सुरहन तथा फूलपुर विकास सेवा केन्द्रों पर हैं। इन सेवा केन्द्रों के समीपवर्ती भागों में धान का उत्पादन अधिक होता है। साथ ही ये सभी क्षेत्र सडक मार्गो द्वारा प्रमुख केन्द्रों से सम्बद्ध हैं।

इनसे सम्बद्ध अन्य इकाइयाँ जैसे चावल की पैकिंग या भूसी पर आधारित इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। चावल की भूसी से पार्टिकल बोर्ड आदि का निर्माण किया जा सकता है।

(स) दाल व तेल घानी उद्योग

देत्र में दलहन का उत्पादन मात्र घरेलू उपयोग तक ही ती मित है । तहतील में दलहन का औतत वार्षिक उत्पादन 4388 टन है जिनमें अरहर 1625 टन, चना 1431 टन, मटर 1309 टन, मूँग 20 टन तथा उड़द उटन का उत्पादन तमाहित है । दलहन से दाल निकालने का कार्य अधिकांशत: गृह चिक्कयों में किया जाता है जितसे अधिकांश दालें टूट जाती हैं । अत: तन् 2001 तक तहतील में उ छोटी दाल मिनों की स्थापना पूलपुर, पवर्ड तथा बनगाँव में कर दी जानी चाहिए।

अध्ययन प्रदेश में दलहन पर आधारित दालमोट उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। इनमें मूँग तथा चने की दालमोट प्रमुख हैं।

पूनपुर तहसील में तिलहन का उत्पादन कम होता है तथा तेल निकालने की इकाइया छोटी-छोटी हैं। तहसील में ग्रामीण तेल घानियों के अतिरिक्त 27 अति लघु स्तरीय इकाइया भी कार्यरत हैं। प्रस्तावित कृष्णि योजना के तहत तिलहन के

भावी उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएँ हैं। अतः सन् २००। तक अम्बारी, पुष्पनगर तथा माहुल में एक-एक मध्यम स्तरीय तेल मिल स्थापित करने का सुझाव प्रस्तुत है।

(द) चीनी उद्योग

गन्ना तहसील की प्रमुख मुद्रादायिनी फ्सल है जिसका उत्पादन 189518 टन
है। वर्तमान समय में तहसील में गन्ने की मिल का अभाव है। आजमगढ़ जिले में
मात्र एक चीनी मिल सिठयाँव में कार्यरत है जो तहसील से काफी दूर है। तहसील
में गन्ने के उत्पादन में भावी वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। अतः क्षेत्र में गन्ने के
उत्पादन को देखते हुए वर्ष 200। तक माहुल में एक चीनी मिल खोलने का सुझाव प्रस्तुत
है। माहुल सड़क मार्गो द्वारा अन्य क्षेत्रों से सम्बद्ध है। चीनी मिल खोलने से क्षेत्र की
जनता को गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़
होगी।

(य) आनू सरक्षण तथा आनू पर आधारित उद्योग

अध्ययन प्रदेश में यद्यपि आलू का पर्याप्त उत्पादन किया जा रहा है परन्तु इनके संरक्षण का अभाव सा है। तहसील में आलू का औसत उत्पादन 14188 दन है। किन्तु तहसील में मात्र एक शीत भण्डार पूलपुर में कार्यरत है तथा इसकी क्षामता भी बहुत ही कम है। तहसील में आलू के बदते उत्पादन के साथ इनके संरक्षण की पर्याप्त आवश्यकता है क्यों कि ग्रीष्टम तथा वर्षा बत्तु में काफी आलू सड़कर नष्ट हो जाता है। आलू के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए 200। ई० तक 4000 दन क्षामता वाली 3 अति-रिक्त इकाइयाँ पवर्ड, अम्बारी तथा बनगाँव में खोलने का सुझाव प्रस्तुत है।

स्पष्ट है कि पूनपुर तहसील में बड़े पैमाने पर आनू का उत्पादन किया जाता है जिसका अधिकतम प्रयोग छरेलू सब्जी तथा दैनिक नाइते की दूकानों तक ही सीमित है। अध्ययन प्रदेश में आनू के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए इस पर आधा-रित आनू के चिप्स, नमकीन तथा पापड़ आदि बनाने सम्बन्धी गृह उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस उद्योग के माध्यम से जहां कुछ लोगों को रोजगार प्राप्त होगा वहीं गृहिणियों की आर्थिक हिथति भी सुदृढ़ होगी क्योंकि इन आनू से सम्बन्धित उद्योगों में गृहिणियों की अहम् भूमिका होती है। आनू से सम्बन्धित उद्योगों में गृहिणियों की अहम् भूमिका होती है। आनू से सम्बन्धित उद्योगों में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(र) प्रमु एवं कुक्कुट आहार मिश्रण उद्योग

संतुलित आहार के अभाव में तहसील के पशुंधों की दुग्धोत्पादकता काफी कम है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, कूनकुट, सूअर एवं मत्स्य पालन केन्द्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। तहसील में संतुलित आहार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद हैं। तेल मिलों से ख्ली, चावल मिलों से भूसी तथा चावल के अति सूक्ष्म टुक्ड़े, आटा मिलों से चोकर तथा दाल मिलों से दाल की चूनी एवं भूसी से पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार तैयार किया जा सकता है। संतुलित आहार से दुग्ध उद्योग को बद्धावा मिलेगा। इन वस्तुओं के सिम्मक्षण से कुक्कूट, सूअर तथा मछलियों के लिए भी संतुलित आहार तैयार किया जा सकता है। इस तरह के संतुलित आहार उद्योग का विकास पूलपुर तथा पवई विकास सेवा केन्द्रों पर किया जा सकता है।

(ल) चम्हा उद्योग

वर्तमान समय में चमड़े से निर्मित वस्तुओं के उपयोग में जूते, चप्पल, वेल्ट, बैग तथा हैण्डपाइप के वारसल प्रमुख हैं। इनसे सम्बन्धित आधुनिक किस्म की एक इकाई मित्तूपुर विकास सेवा केन्द्र पर स्थापित की जानी चाहिए। मित्तूपुर विकास सेवा केन्द्र पर स्थापित की जानी चाहिए। मित्तूपुर विकास सेवा केन्द्र पर चमड़ा उद्योग गृह उद्योग के रूप में पहले से ही केन्द्रित है।

(व) डेयरी उद्योग

अध्ययन प्रदेश में दुग्धोत्पादन के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं किन्तु तहसील में डेयरी उद्योग का अभाव है। क्षेत्र के अधिकांश दुग्धोत्पादकों को दुध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। शहरी क्षेत्रों में दूध का मूल्य 10 रूपये प्रति लीटर से भी अधिक है वहीं तहसील के ग्रामीण अंचलों में इसका मूल्य 6 रूपये प्रति लीटर है। दुग्धोत्पादकों को दूध का उचित मूल्य न मिलने का कारण क्ष्रक्त प्रबन्धन की कमी है। अतः तहसील में एक डेयरी उद्योग की स्थापना अम्बारी विकास सेवा केन्द्र पर की जा सकती है। इसके माध्यम से जहाँ ग्रामीण अंचलों के दुग्धोत्पादकों को दूध का उचित मूल्य होगा वहीं देश में संचालित 'श्वेत क्रान्ति' (Operation Flood) के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकेगी।

इन उद्योगों के अतिरिक्त कृषा उत्पादकों पर आधारित अन्य छोटी-छोटी इकाइयों जैसे - अचार/मुरक्बा बनाना, म्लालों की पिलाई, सेवई तथा तिरका बनाने सम्बन्धी इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए।

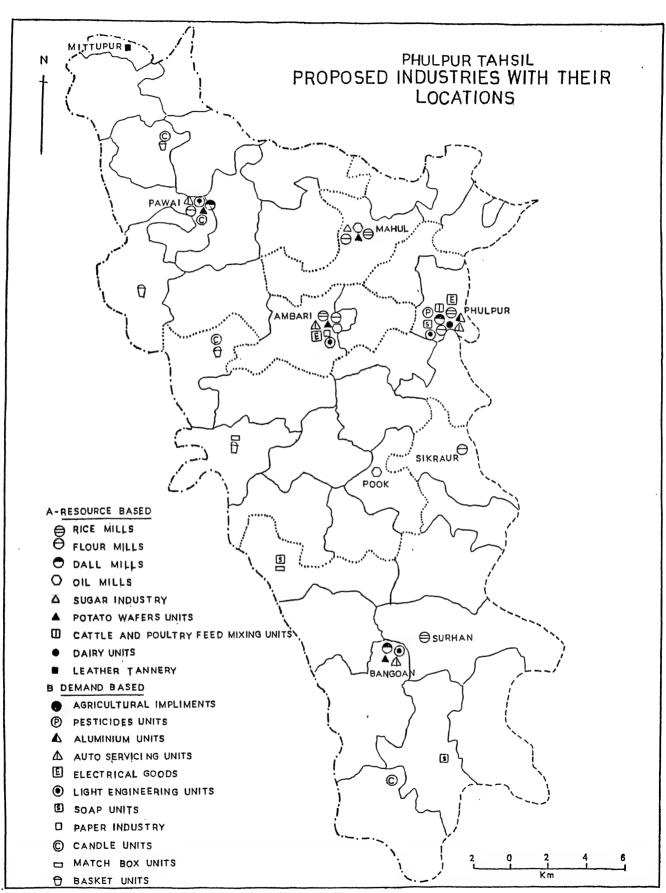


Fig.5.3

(ख) खनिज संताधन उद्योग

वर्तमान समय में तहसील में पक्के मकानों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है जिससे ईंट तथा सीमेण्ट की माँग बहुत अधिक है। सीमेण्ट की आपूर्ति बाहर से हो जाती है जबिक ईंट के निर्माण में पूर्णतया स्थानीय कच्चे माल (मिट्टी) का उपयोग होता है। अतः पक्के मकानों के निर्माण की प्रवृत्ति को देखते हुए प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम उ भद्ठे अवश्य लगाए जाने चा हिए। इससे जहाँ लोगों को पक्के मकानों के लिए ईंट की प्राप्ति होगी वहीं कुछ लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

(2) माँग-आधारित उद्योग

तहसील की अर्थट्यवस्था कृष्ठि पर आधारित है। कृष्ठि में हरित क्रान्ति आने से विभिन्न निर्मित वस्तुओं की माँग बढ़ी है तथा भविष्य में बढ़ते जाने की संभावनाएँ हैं। अतः तहसील में माँग आधारित उद्योग स्थापित करने की महती आवश्यकता है। इसके माध्यम से जहाँ कृष्ठि उपयोग में आने वाले यन्त्रों का निर्माण तथा मरम्मत हो सकेगी वहीं कुछ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रमुख माँग आधारित उद्योग निम्न हैं –

(क) कृष्णि औजार उद्योग

तहसील में कृष्णि की तीव्र विकास होने से नवीन कृष्णि यन्त्रों की माँग काफी बढ़ी है। इन कृष्णि यन्त्रों में थ्रेसर, दवा छिड़कने की म्यानिं, कल्टीवेटर तथा मिट्टी पलटने के हल मुख्य हैं, तहसील में इन यन्त्रों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है क्यों कि अधिकांश यन्त्र आजमगढ़ तथा वाराणकों से मँगाए जाते हैं। अतः
अध्ययन प्रदेश में कृष्णि औजारों की माँग को देखते हुए तहसील में कृष्णि औजार सम्बन्धी
लघु इकाइयाँ पवर्ड तथा पूनपुर में खोलने का सुझाव प्रस्तुत है।

(छ) कृषा रक्षा रसायन उद्योग

अधिक उपज देने वाली तथा शीद्र पकने वाली फ्तलों की किस्मों की तफ्तता उर्वरकों तथा कृष्ठि रक्षा रत्तायनों (दवाइयों) के प्रयोग में निहित है। तहतील में फ्तलों को बीमारियों से बचाने के लिए कृष्ठि रक्षा दवाइयों का प्रयोग बद्धता जा रहा है। इन दवाइयों की आपूर्ति अनिश्चित है तथा इनका मूल्य भी बहुत अधिक होता है। अतः तहतील में कृष्ठि रक्षा रत्तायनों से सम्बन्धित एक लघु स्तरीय उद्योग फूलपुर विकास सेवा केन्द्र पर स्थापित किया जाना चाहिए।

(ग) एल्यूमी नियम उद्योग

पीतल तथा स्टील के बर्तनों की कीमतों में अधिक वृद्धि से घरेलू उपयोग में एल्यूमी नियम के बर्तनों का प्रयोग बढ़ा है। वर्तमान समय में तहसील में एल्यूमी नियम के बर्तनों का प्रयोग काफी तेजी से हो रहा है क्यों कि इनके मूल्य अपेक्षाकृत कम होते हैं। अत: इनके प्रयोग में वृद्धि को देखते हुए फूलपुर कस्बे में एल्यूमी नियम के बर्तन बनाने की एक लघु इकाई खोलने का सुझाव प्रस्तुत है।

(ध) काकरी के बर्तन बनाने का उद्योग

वर्तमान समय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में का करी के बर्तनों का प्रयोग पैज्ञान

की तरह बद रहा है अत: तहसील में का करी के बर्तन बनाने की एक लघु इकाई पूलपुर विकास सेवा केन्द्र पर स्थापित की जा सकती है।

(ड) कृषि उपकरण तथा वाहन मरम्मत केन्द्र

तहसील में नवीन कृष्य यन्त्रों का प्रयोग काफी बढ़ा है किन्तु इनके मरम्मत से सम्बन्धित केन्द्रों का अभाव सा है। अध्ययन प्रदेश में इससे सम्बन्धित इकाइयाँ बहुत ही छोटी-छोटी एवं सुविधा रहित हैं, कृष्यकों को इन उपकरणों के मरम्मत के लिए शाहगंज या फूलपुर कर बे में जाना पड़ता है जिसमें समय तथा धन का व्यय अधिक होता है। अतः इन कृष्यकों के उपकरणों को कम समय तथा निकटस्थ सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कृष्य उपकरण मरम्मत केन्द्र फूलपुर, अम्बारी, माहुल, पवर्ड, बनगाँव, सिकरौर, पव्छनपुर, फुलेश, सुरहन, और सादुल्लाहपुर विकास सेवा केन्द्रों पर खोले जाने चाहिए।

इसी प्रकार विभिन्न वाहनों के मरम्मत के लिए लोगों को शाहगंज (जौनपुर जनपद) या आजमगढ़ जाना पडता है। वर्तमान समय में क्षेत्र में वाहनों का प्रयोग काफी बढ़ा है तथा इनकी संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अत: इन वाहनों के मरम्मत सम्बन्धी केन्द्र फूलपुर नगरीय क्षेत्र में खोला जाना चाहिए। साथ ही कुछ छोटे स्तर के केन्द्र अम्बारी, माहुल, पवई तथा बनगाँव में खोले जाने का प्रस्ताव है।

(च) बिजली के उपकरण सम्बन्धी उद्योग

अध्ययन प्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक बहितयों का विद्युती करण किया जा चुका है जिससे क्षेत्र में विद्युत तार, बल्ब, होल्डर, तथा प्लग आदि की माँग अधिक रहती है। तहसील में इन आवश्यक सामानों की आपूर्ति बाहर से होती है। अतः इन वस्तुओं के निर्माण से सम्बन्धित एक लघु इकाई अम्बारी विकास सेवा स्थापित की जानी चाहिए।

(छ) लक्डी एवं लोहे के सामानों का उद्योग

तहसील में लक्ड़ी के मेज, कुर्सी, खिडकी, दरवाजे तथा चौकी अ का निर्माण गृह उद्योग के रूप में पहले से ही हो रहा है। विद्यालयों श्व कार्यालयों में इन सामानों की माँग अधिक रहती है। अत: इन वस्तुओं के लिए कुछ लघु स्तरीय इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए। इनकी प्र स्थितियाँ पवर्ड, अम्बारी, बनगाँव तथा पूलपुर हैं।

लोहे की कुर्ती, मेज, आलमारी तथा सोफा सेट के निर्माण सम्ब पूलपुर नगरीय क्षेत्र में होना चाहिए क्यों कि वर्तमान समय में बद्धते नगरीय आधुनीकरण के परिप्रेक्ष्य में इसकी माँग और अधिक हो रही है।

((ज) साबुन उद्योग

तहसील में जन धनत्व अधिक है। पहले लोग कपड़ा धुलने के लिए रेह का प्रयोग करते थे किन्तू वर्तमान समय में इसका प्रचलन लगभग समाप्त सा हो गया है। साबुन का उपयोग कपड़ा धुलने तथा स्नान करने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः तहसील में कपड़ा धुलने तथा नहाने के साबुन सम्बन्धी एक मध्यम स्तरीय उद्योग पूलपुर नगरीय क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए तथा लघु स्तरीय इकाइयाँ पुलेश तथा जगदीशमूर ददेरिया में प्रस्तावित है।

(झ) कागज उद्योग

विद्यालयों में छात्रों की भावी तंख्या में वृद्धि होने की काफी तंभावनाएँ हैं। छात्रों की तंख्या में वृद्धि तथा दितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं के विकास के साथ ही कागज की माँग अधिक होगी। अतः तहसील में कागज उद्योग की एक लघु इकाई अम्बारी विकास सेवा केन्द्र पर खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए कच्चा माल बाँस तहसील के ग्रामीण अंचलों से प्राप्त होगा। कागज का निर्माण गन्ने की खोई तथा रद्दी कागज से भी किया जा सकता है। तहसील में गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है जिससे गन्ने की खोई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी।

(अ) मा चिस उद्योग

इसकी प्रस्तावित स्थितियाँ राजापुर तथा पुनेश में है।

(ट) टोकरी उद्योग

तहसील में बाँसों की टोकरी की माँग अधिक है। अत: इस पर आधारित उद्योग राजापुर, बागबहार, खंजहापुर तथा मिल्कीपुर में खोलने का प्रस्ताव है।

(ठ) मोमबत्ती उद्योग

इस उद्योग की प्रस्ता वित अव स्थितिया छंग्डापूर, मिल्कीपुर तथा बेलवाना में हैं।

उपरोक्त प्रस्तावित एवं सम्बद्ध इकाइयों की स्थापना एवं कुश्रल संचालन के माध्यम से ही क्षेत्र का समुचित एवं त्वरित औद्योगिक विकास सम्भव है । इन उद्योगों के विकास के लिए पर्यां प्त पूँजी, उचित तकनीक, साहसी उद्यमी, सही प्रशिक्षण और सरकारी स्तर पर पर्यां प्त प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। उद्यमियों को पूँजी श्रण के रूप में सस्ते एवं आसान किस्तों पर उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण में बैंकों की विशेष भूमिका होती है। उद्यमियों को सम्बन्धित उद्योगों के विषय में उचित जानकारी, सुझाव एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कुछ विशेष कच्चे मालों की सुनिश्चित आपूर्ति भी आवश्यक है। आवश्यक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा सकता है। इन सभी प्राविधानों के साथ क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी और प्रदेश का समुचित औद्योगिक विकास हो सकेगा।

____:0::----

सन्दर्भ

- Qureshi, M.H.: India Resources and Regional Development, NCERT, New Delhi, 1990, p. 37.
- 2. सिंह, कें एन तथा सिंह, जगदीश: आर्थिक भूगोल के मूल तत्त्व, वसुन्धरा प्रकाशन, गौरखपुर, 1984, पूष्ठ 296.
- 3. Pathak, R.K.: Environmental Planning Resources and Development, Chugh Publications, Allahabad, 1990, p. 123.
- 4. औद्योगिक प्रेरणा, उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश, जिला उद्योग केन्द्र, आजमगढ, 1991, पूष्ठ 19.
- 5. भारत, वार्षिकी सन्दर्भ ग्रन्थ, 1990, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पिटयाला हाउस, नई दिल्ली, पूष्ठ 497-502.
- 6. जिला जनगणना हस्तपुरितका, प्राथमिक जनगणनासार, भाग XIIIA जनपद आजमगढ, 1981.

____:0::----

अध्याय छ:

परिवहन एवं संग्रार व्यवस्था

6.। प्रस्तावना

किसी भी क्षेत्र की समृद्धि एवं विकास में कृष्ठि, खनन और उद्योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किन्तु विकास प्रक्रिया में परिवहन एवं संचार साधनों का भी अपना विशेष महत्त्व है। इनके अभाव में विकास प्रक्रिया को मूर्तरूप नहीं दिया जा सकता। विनिम्य आधारित अर्थंट्यवस्था के विकास के लिए परिवहन एवं संचार साधन अनिवार्य शर्त हैं। परिवहन एवं संचारतंत्र क्षेत्रीय विकास की पहली इकाई हैं जो उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। अतः परिवहन एवं संचार को तृतीयक उत्पादक श्रेणी में रखा जाता है। यातायात देश के क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ आर्थिक प्रक्रिया में भी प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। परिवहन एवं संचार किसी क्षेत्र या देश की धमनी एवं शिराएँ हैं जिनसे हो कर प्रत्येक सुधार प्रवाहित होता है। इनके समु-चित विकास के अभाव में किसी भी क्षेत्र या देश का आर्थिक ढाँचा लइख्ड़ा ही नहीं जाता विलक निष्पाण हो जाता है। आर्थिक साम्यावस्था एवं उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग यातायात विन्यास के विकास पर निर्भर करता है। परिवहन साधनों के विकास से ही कृष्णि, औद्योगिक क्षेत्र, राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र का समन्वित विकास संभव हो पाता है। परिवहन एवं संचार माध्यमों से ही इनके विकास में तीव्रता एवं नवीनता प्राप्त होती है। परिवहन के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है जो किसी अविकतित क्षेत्र के आधिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को तीव्रता प्रदान कर सके। किसी भी देश में विनिमय आधारित अर्थं व्यवस्था का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि परिवहन एवं संचार साधनों का समुचित विकास नहीं होता । बीठजे०एल० बैरी (1959) के अनुसार 'परिवहन तंत्र विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों का माप है । विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध परिवहन साधनों की प्रकृति तथा पारस्परिक व्यापार पर आश्रित होता है । इस प्रकार किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक एकता, स्रक्षा आदि में परिवहन एवं संचार साधनों की प्रभावी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता ।

अध्ययन प्रदेश एक पिछड़ी अर्थट्यवस्था का पर्याय है। यहाँ विकास के लिए उत्तरदायी सभी संसाधन वर्तमान हैं किन्तु परिवहन एवं संचार साधनों के समुचित विकास के अभाव में यहाँ की अर्थट्यवस्था पिछड़ी हुई है। तहसील में जल एवं वायु परिवहन का तो अभाव है ही, रेलमार्गों का भी समुचित विकास नहीं हुआ है। रेल परिवहन के नाम पर मात्र कुछ दूरी तक छोटी लाइन का अस्तित्त्व है। केवल कुछ अविकसित सड़कें ही परिवहन के प्रमुख माध्यम हैं। तहसील में संचार ट्यवस्था का भी समुचित विकास नहीं हुआ है। प्रस्तुत अध्याय का मुख्य उद्देश्य तहसील में विद्यमान परिवहन एवं संचारतंत्रों का आकलन कर उनके विकास के लिए समुचित नियोजन प्रस्तुत करना है जिससे क्षेत्र के भावी विकास की सुदृढ़ आधारिक्ता तैयार हो सके।

6. 2 परिवहन के माध्यम

परिवहन के मुख्यत: तीन माध्यम हैं जो पृथ्वी के तीनों मंडलों - वायु, जल तथा स्थल से सम्बन्धित हैं। परिवहन के माध्यम के रूप में इन तीनों मण्डलों का प्रयोग अतीत काल से होता आ रहा है। इनमें जलमण्डल में समुद्र के साथ नौगम्य

निर्दियों तथा नहरों का प्रयोग व्यापार के लिए परिवहन के माध्यम के रूप में हो रहा है जबकि वायुमण्डल मात्र वायुयान परिवहन तक ही सी मित हैं। स्थानीय परिवहन के लिए स्थल का ही सबसे अधिक उपभोग होता है जिनमें रेलमार्ग तथा सड़कें प्रमुख हैं जिनके द्वारा क्षेत्र विशेष्ठ में सामाजिक सेवाओं के पहुँचाने का कार्य सर्वाधिक किया जाता है। तहसील पूलपुर में परिवहन के माध्यमों का वितरण इस प्रकार है –

(1) रेल मार्ग

अध्ययन प्रदेश में रेलमार्ग नगण्य है। बड़ी लाइन का पूर्णतः अभाव है।
तहसील में मात्र उत्तरी पूर्वी रेलवे द्वारा संवालित छोटी लाइन मिटरगेज। का ही
विकास हुआ है। यह रेलमार्ग शाहगंज से प्रारम्भ होकर तहसील में ग्राम मदसार में
प्रवेश कर छंजहापुर (हाल्ट) अम्बारी, खुरासन रोड होते हुए मऊ जनपद तक जाता है।
रेलमार्ग की जनपद में कुल लम्बाई 159 किंग्सींग है जिसका मात्र 11.95 प्रतिशत भाग
ही पूलपुर में स्थित है। इस प्रकार पूलपुर तहसील में रेलमार्ग की कुल लम्बाई लगभग
19 किंग्सींग है। तहसील में खुरासन रोड के अतिरिक्त अम्बारी तथा खंजहापुर
(हाल्ट) दो अन्य रेलवे स्टेशन हैं। तहसील में प्रति लाख जनसंख्या पर रेलमार्ग की
सुविधा मात्र 5.25 किंग्सींग ही उपलब्ध है जबिक आजमगढ़ जनपद तथा उत्तर प्रदेश
राज्य का औसत क्रमाः 6.3। किंग्सींग तथा 7.78 किंग्सींग है। प्रति 100 वर्ग
किंग्सींग हेल में रेलमार्ग की लम्बाई तहसील में जहाँ 2.7। किंग्सींग है वहीं आजमगढ़
तथा उत्तर प्रदेश में क्रमाः 3.83 किंग्सींग तथा 2.93 किंग्सींग है।

यदि रेलमार्ग अभिगम्यता का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि मात्र 0.6।

प्रतिशत गांव ही ऐसे हैं जिनको । कि0मी0 से कम दूरी पर रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध हैं । तहसील में 35 गांव ऐसे हैं जिनको । से 3 कि0मी0 दूरी चलकर रेलवे स्टेशन प्राप्त होते हैं जबकि 47 गांव के लोगों को 3 से 5 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है । शेष्ठा गांव रेलवे स्टेशन से 5 या 5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित हैं ।

(2) सड़क परिवहन

मानव सभ्यता के आदि काल से ही सड़क यातायात वस्तुओं, ट्यक्तियों, सेवाओं एवं विचारों के प्रवाह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सड़क प्रकृति द्वारा प्रदत्त भूमि पर मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम मार्ग है जिसके द्वारा छेतों को गाँवों, गाँवों को कारखानों एवं नगरों से जोड़ना संभ्व हुआ। वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र के समन्वित विकास में सड़कों का विशेष्ठ महत्त्व है। सड़कों के इसी महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध विद्वान जरमी वैध्यम ने कहा था कि "सड़कें किसी देश की रक्तवाहिनी धमनी और शिराएँ हैं, जिनसे होकर समस्त सुधार प्रवाहित होता है।" सड़कों द्वारा प्राप्त लचीलापन, मार्ग परिवर्तन की सुविधा, सस्ती सेवा, समय की वचत और सुरक्षा आदि इसकी प्रमुख विशेष्ठाताएँ हैं जबकि परिवहन के अन्य साधनों में ऐसा संभव नहीं है। एम०एच० कुरैशी ने लोच, विश्वसनीयता एवं गति को सड़क परिवहन की मुख्य विशेष्ठाताएँ बताया है। "

अध्ययन प्रदेश गंगा-धाधरा दोआ ब में स्थित समतल मैदान है । यहाँ सड़कों का निर्माण परिवहन के अन्य साधनों जैसे रेलमार्ग आदि की तुलना में आसानी से

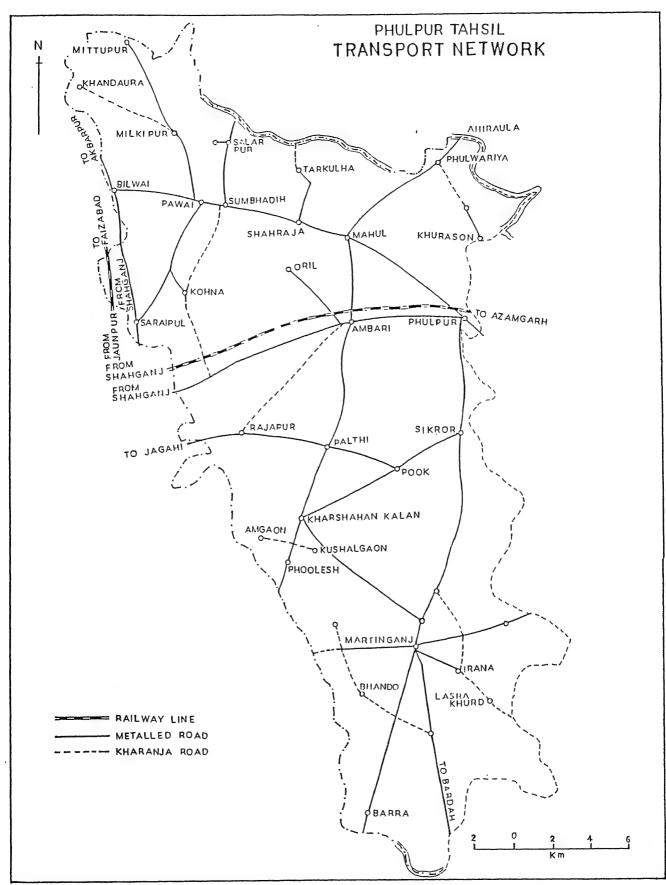


Fig. 6-1

किया जा सकता है। इसके पश्चात् भी अध्ययन क्षेत्र से होकर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जाता। यहाँ की अधिकांश सड़कें या तो अन्तर्जनपदीय सड़कें हैं या ग्रामीण मार्ग। तहसील में सड़कों की कुल लम्बाई 199 कि0मी0 है जिनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बनी सड़कों की लम्बाई 166.93 कि0मी0 है। सड़कों की लम्बाई विकास- खण्ड स्तर पर सारणी 6.। में देखी जा सकती है -

सारणी 6. । पूलपुर तहसील में सड़कों की लम्बाई, 1989

(किंगिं) भें) सड़कों की कुल लम्बाई साठनिठविठ द्वारा निर्मित पक्की सड़कों की लम्बाई विकासखण्ड । पवर्ड 71.00 54.00 2. पूलपुर 60.00 49.80 3. मार्टिनगंज 48.00 46.08 4. अहर**ी**ला(i) 17.05 20.00 तहसील पूलपुर 199.00

स्रोत: सां खियकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1989

इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों के सम्मर्क हेतू कच्ची सड़कें, श्रमदान द्वारा निर्मित मार्ग तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित छड़ंजा मार्ग भी हैं। ये मार्ग अधिकांशत: कच्चे व अर्द्धनिर्मित हैं। इन मार्गों का महत्त्व मात्र बैलगाड़ी, इक्का, द्वैक्टर, रिक्सा व साइकिल जैसे वाहनों के लिए ही है जो विशेष्टकर ग्रामीण अंचलों के सम्मर्क हेतु उपयोगी हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मात्र सड़कें ही तहसील परिवहन की रीद्ध हैं। अत: आगामी परिवहन विश्लेषणों में केवल सड़क परिवहन को ही समाहित किया गया है जिस पर वर्षभर पर्याप्त मात्रा में वाहनों का आवागमन होता रहता है चित्र संख्या 6.।

सारणी 6.2 फूलपुर तहसील में प्रमुख सम्पर्क मार्ग

	सड़ कें	लम्बाई (कि0मी०)
1.	माहुल-पवई-विलवाई मार्ग	15. 40
2.	पवर्ड-मित्तूपुर मार्ग	9.00
3.	सुम्हाडीह-वहाउद्दीनपुर मार्ग	3.00
4.	अम्वारी-ओरिल-आंधीपुर मार्ग	9.00
5.	तुम्हाडीह-सुलेमापुर मार्ग	3. 00
6.	पवर्ड-वागवहार-है।स्ट्दीनपुर मार्ग	6. 50
7.	पवई-वागवहार-कोहड़ा मार्ग	3.30
8.	सलारपुर कालेज से सलारपुर ग्राम तक	1.00
9.	शहराजा-तरकुनहा मार्ग	3.80
10.	फूलपुर-खादा मार्ग	13.20
11.	पूर्वपुर-मार्टिनगंज मार्ग	18. 45
12.	ख्रुरासों रोड मिजवां मार्ग	2. 15
13.	पूलपुर-माहुल मार्ग	6.80
14.	पल्धी शाहगंज से गवाई वाया राजापुर मार्ग	7.00

	सड़ कें	लम्बाई कि0मी0
15.	महुजा नेवादा मार्ग	1.40
16.	दीदारगंज-सरायमीर मार्ग	15. 28
17.	सिकरौर डेमरी, मकदूमपुर, पुरन्दरपुर मार्ग	2.90
18.	छित्तेपुर-करियांवा मार्ग	1.00
19.	पुष्टपनगर पल्थी वाया हड़वा मार्ग	1.70
20.	सुरहन-इसा मार्ग	2, 50
21.	कुशनगांव से खुटौनी मार्ग	3.00
22.	कुशलगाव-आमगाव मार्ग	4. 0 0 '
23.	मार्टिनगंज गम्भीरपुर सेनरवे मार्ग	1.30
24.	छीही फ़ुलवरिया मार्ग	6. 25
25.	अमुआरी नरायनपुर सम्पर्क मार्ग	1.00
26.	माहुल-गौतपुर मार्ग	1.30
27.	अहरौला-अम्वारी मार्ग	8.80

स्रोत: (1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनपद आजमगढ़, सङ्क मास्टर प्लान 1989 से परिकलित

(2) सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1989

6.3 सड़क धनत्व

सड़कों के क्षेत्रीय अध्ययन में लम्बाई की अपेक्षा उनकी सचनता का अधिक महत्त्व है । सड़कों की सचनता से यातायात एवं च्यापार में सुविधा होती है ।

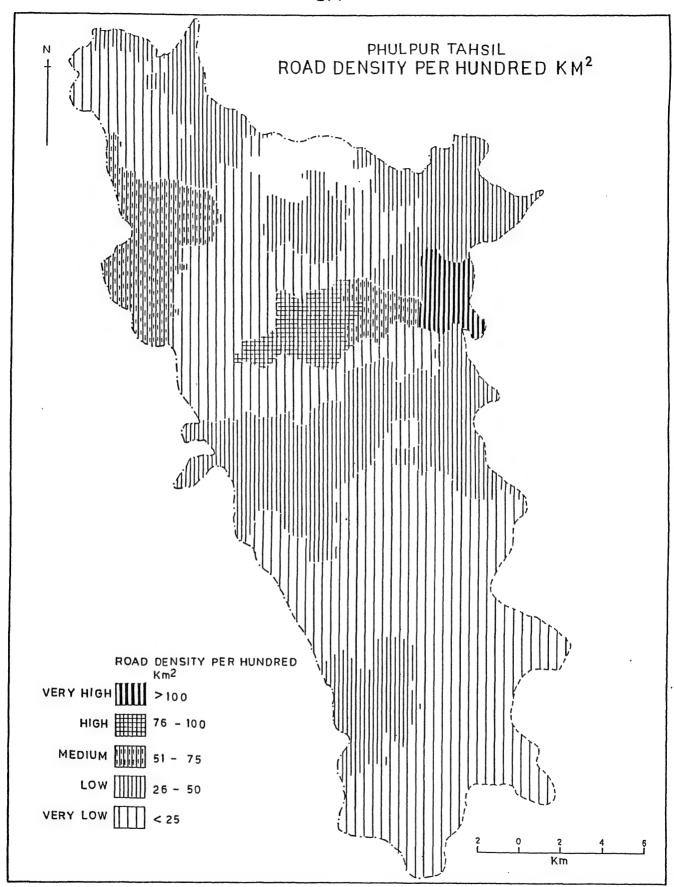


Fig. 6-2

दुर्गम स्थानों के लोग भी आसानी से अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच जाते हैं। सड़क धनत्त्व की गणना दो प्रकार से की जा सकती है - एक तो किसी मानक क्षेत्रफल पर तथा दूसरा, किसी मानक जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई ज्ञात की जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में सड़क धनत्त्व की गणना न्याय पंचायत स्तर पर प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर की गयी है। इसका प्रदर्शन चित्र संख्या 6.2 तथा चित्र संख्या 6.3 में किया गया है। इन मानचित्रों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भागों में सड़कों का धनत्त्व अपेक्षाकृत कम है जबकि पवई तथा पूजपुर विकासखण्डों के निकदस्थ भागों में सड़कों का धनत्त्व अधिक है। सारणी 6.3 से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण तहसील में प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल पर सड़कों की अौसत लम्बाई 28.73 कि0मी0 है जबकि तहसील में प्रति एक लाख जनसंख्या पर सड़कों की अौसत लम्बाई 55.74 कि0मी0 है।

सारणी 6.3 पूलपुर तहसील में न्याय पंचायत स्तर पर सड़कों का धनत्व

***************************************	न्याय पंचाय	п		क्षेत्रपत वर्ग कि0मी0	जनप्तरंख्या 1981	सड़क की लम्बाई कि0मी0	सङ्क धनत् प्रति 100 वर्ग किमी	व किं0मी0 प्रति एक लाख जन- संख्या पर
* ann ann ata	1	a trings come space acres street delay delay delay delay de		2	3	4	5	6
1.	 मिन्तूपुर रामनगर		•	14. 62 16. 82	10902 8067	4.30 6.92	29. 41 41. 14	39. 44 85. 78
	स त्ता रपूर	रज्जाकपुर		20. 02	10901	-	-	
4.	दोस्तपुर ल	हूर मपुर		14.37	7026	4.00	27.84	56.93

10. सादुल्लाहपुर 18.01 11303 2.30 12.77 20.11. अम्बारी 19.77 10278 15.40 77.90 14. वि. संपद्धिया 9.36 6505 6.29 67.20 9.33. खंगहापुर 20.85 8501 2.87 13.76 3.44. सजई अमानवाद 19.49 10421 2.65 13.60 व.5. वक्तपुर मेजवा 11.22 7325 2.50 22.48 3.46. नो नियाडीह 12.50 7370 4.80 38.40 व.5. सदरपुर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 16. केनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 4. 14.84 9004 4.05 27.29 4. 14.85 29.04 5. 15. 16. 67 8580 4.85 29.04 5. 16. 67 8580 4.85 29.04 5. 16. 67 8580 4.85 29.04 5. 16. 67 8580 4.85 29.04 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5.43 32.93 5. 16. 49 10049 5. 43		1	2	3	4	5	_
6. वस्ती सदनपुर 19.36 9113 14.13 72.99 1 7. सुल्तानपुर 13.46 7284 1.00 7.43 8. सौदमा धानेश्वर 18.61 7928 0.85 4.46 9. वाग सिकन्दरपुर 24.37 11612 12.37 50.76 10 10. सादुल्लाहपुर 18.01 11303 2.30 12.77 2 11. अम्बारी 19.77 10278 15.40 77.90 14 12. पद्मुडिया 9.36 6505 6.29 67.20 9 13. खंजहापुर 20.85 8501 2.87 13.76 3 14. सजई अमानवाद 19.49 10421 2.65 13.60 2 15. वक्सपुर मेजवा 11.22 7325 2.50 22.48 3 16. नो नियाडीह 12.50 7370 4.80 38.40 6 17. सदरपुर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 10 18. कनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 14 19. गद्दोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5 20. पल्थी दुल्हापुर 16.09 8891 6.67 14.45 7 21. राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 5 22. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 7 23. महुआरा 12.18 6236 1.36 11.17 व 24. पुक्वाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10		0_		a dear was were with the time the com-		nem man dare anto delle depe delle little	*
7. सुल्तानपुर 13.46 7284 1.00 7.43 8. सौदमा धानेश्चर 18.61 7928 0.85 4.46 9. वाग सिकन्दरपुर 24.37 11612 12.37 50.76 10 10. सादुल्लाहपुर 18.01 11303 2.30 12.77 20 11. अम्बारी 19.77 10278 15.40 77.90 14 12. पद्युडिया 9.36 6505 6.29 67.20 9 13. खंगहापुर 20.85 8501 2.87 13.76 3 14. सजई अमानवाद 19.49 10421 2.65 13.60 2 15. वक्तपुर मेजवा 11.22 7325 2.50 22.48 3 16. नो नियाडीह 12.50 7370 4.80 38.40 6 17. सदरपुर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 16 18. कनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 4 19. गद्दोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 9 10. पल्थी दुल्हापुर 16.09 889 1 6.67 14.45 12 11. राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 9 12. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 12 13. महुआरा 12.18 6236 1.36 11.17 3 14. पुक्वाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 15. तिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10							
8. सौदमा धानेत्वर 18.61 7928 0.85 4.46 9. वाग सिकन्दरपुर 24.37 11612 12.37 50.76 10 10. सादुल्लाहपुर 18.01 11303 2.30 12.77 2 11. अम्बारी 19.77 10278 15.40 77.90 14 12. पदगुडिया 9.36 6505 6.29 67.20 9 13. खंग्रहापुर 20.85 8501 2.87 13.76 3 14. सजई अमानवाद 19.49 10421 2.65 13.60 3 16. नो नियाडीह 12.50 7370 4.80 38.40 6 17. सदरपुर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 16 18. केनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 4 19. गददोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5 20. पल्थी दुल्हापुर 16.09 8891 6.67 14.45 3 21. राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 5 22. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 3 24. पुक्वाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10	6.	वस्ती सदनपुर	19.36	9113	14. 13	72.99	1
9. वाग सिकन्दरपुर 24.37 11612 12.37 50.76 10 10 सादुल्लाहपुर 18.01 11303 2.30 12.77 2 11. अम्बारी 19.77 10278 15.40 77.90 14 12. पदगुडिया 9.36 6505 6.29 67.20 9 13. खंबहापुर 20.85 8501 2.87 13.76 3 14. सजई अमानवाद 19.49 10421 2.65 13.60 3 15. वक्सपुर मेजवा 11.22 7325 2.50 22.48 3 16. नो नियाडीह 12.50 7370 4.80 38.40 6 17. सदरपुर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 16 18. कनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 14 19. गददोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5 19. यददोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5 19. यददोपुर वारी 16.49 10049 5.43 32.93 5 12. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 12. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 12. यहआरारा 12.18 6236 1.36 11.17 13.	7.	सुल्ता नपुर	13.46	7284	1.00	7. 43	
10. सादुल्लाहपुर 18.01 11303 2.30 12.77 2.11. अम्बारी 19.77 10278 15.40 77.90 14.22. पदगुडिया 9.36 6505 6.29 67.20 9.31. खंजहापुर 20.85 8501 2.87 13.76 3.31.	8.	सौदमा थानेशवर	18.61	7928	ره ۵۰	4. 46	
19.77 10278 15.40 77.90 14 2. फटगुडिया 9.36 6505 6.29 67.20 9 13. खंजहापुर 20.85 8501 2.87 13.76 3 14. सजई अमानवाद 19.49 10421 2.65 13.60 3 15. वक्सपुर मेजवा 11.22 7325 2.50 22.48 3 16. नो नियाडीह 12.50 7370 4.80 38.40 6 17. सदरपुर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 16 18. केनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 4 19. गददोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5 20. पल्थी दुल्हापुर 16.09 8891 6.67 14.45 7 21. राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 5 22. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 7 23. महुआरा 12.18 6236 1.36 11.17 3 24. पुकवाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10	9•	वाग सिकन्दरपुर	24.37	11612	12.37	50.76	10
2. फ्ट्रगुडिया 9.36 6505 6.29 67.20 9	10.	सादुल्लाहपुर	18.01	11303	2.30	12.77	2
3. खंजहापूर 20.85 8501 2.87 13.76 3.14. सजई अमानवाद 19.49 10421 2.65 13.60 3.15. वक्सपूर मेजवा 11.22 7325 2.50 22.48 3.16. नो नियाडीह 12.50 7370 4.80 38.40 6.17. सदरपूर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 6.18. केनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 4.19. गददोपूर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5.19. गददोपूर वारी 16.09 8891 6.67 14.45 7.19. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	11.	ी म्बारी	19.77	10278	15. 40	77.90	149
19. 49 10421 2. 65 13. 60 25 विकास मेजवा 11. 22 7325 2. 50 22. 48 35 16. नो नियाडीह 12. 50 7370 4. 80 38. 40 6 17. सदरपूर वरौली 13. 97 9045 14. 82 106. 08 16 18. केनेरी 14. 84 9004 4. 05 27. 29 19. गददोपुर वारी 16. 67 8580 4. 85 29. 04 50. पल्थी दुल्हापुर 16. 09 889 1 6. 67 14. 45 70 10049 5. 43 32. 93 50 10049 5. 43 50 100	12.	फ्दगुडिया	9.36	6505	6. 29	67.20	96
11. 22 7325 2. 50 22. 48 3 16. नो नियाडी	13.	७ंजह	20.85	8501	2.87	13.76	33
16. नो नियाडीह 12.50 7370 4.80 38.40 है। सदरपूर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 16 18. कनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 4. 19. गददोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5. 10. पल्थी दुल्हापुर 16.09 8891 6.67 14.45 के. 11.45 के. 11.45 के. 11.45 के. 12. हि.49 10049 5.43 32.93 5. 12. हि.49 10049 5.43 37.47 के. 12. हि.49 10.49 5.43 37.47 के. 12. हि.49 10.49 5.43 37.47 के. 12. हि.49 10.49 5.43 37.47 के. 12. 18 6236 1.36 11.17 के. 12. 18 6236 1.36 11.17 के. 12. 18 6236 1.36 11.17 के. 12. 13. 13. 14. पुकवाल 15.10 8843 2.67 17.68 3. 15. 16. 17.68 3. 15. 16. 17.68 3. 15. 16. 17.68 3. 1	14.	सजई अमानवाद	19.49	10421	2.65	13.60	25
17. सदरपूर वरौली 13.97 9045 14.82 106.08 16.8. कनेरी 14.84 9004 4.05 27.29 4.9. गद्दोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5.0. पल्थी दुल्हापुर 16.09 8891 6.67 14.45 7.21. राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 5.22. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 7.23. महुआररा 12.18 6236 1.36 11.17 7.24. पुकवाल 15.10 8843 2.67 17.68 3.25. तिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10.25.	15.	वक्सपुर मेजवा	11.22	7325	2.50	22. 48	31
14.84 9004 4.05 27.29 वि 19. गद्दोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 5 20. पल्थी दुल्हापुर 16.09 889 1 6.67 14.45 7 21. राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 5 22. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 7 23. महुआरा 12.18 6236 1.36 11.17 वि 24. पुकवाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. तिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10	16.	नोनियाडीह	12.50	7370	4.80	38.40	65
19. गद्दोपुर वारी 16.67 8580 4.85 29.04 50. पल्थी दुल्हापुर 16.09 889 1 6.67 14.45 70.01 राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 50.02. खरसहन कला 19.56 992 1 7.33 37.47 70.03. महुआररा 12.18 6236 1.36 11.17 70.04. पुकवाल 15.10 8843 2.67 17.68 30.05. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10.05.	17.	सदरपूर वरौली	13.97	9045	14.82	106.08	163
20. पल्थी दुल्हापुर 16.09 889 1 6.67 14.45 7 21. राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 5 22. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 7 23. महुआररा 12.18 6236 1.36 11.17 7 24. पुक्वाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10	18.	कनेरी	14.84	9004	4. 05	27 • 29	41
21. राजापुर 16.49 10049 5.43 32.93 5 22. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 7 23. महुआररा 12.18 6236 1.36 11.17 व 24. पुकवाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10	19•	गद्दोपुर वारी	16. 67	8580	4.85	29 • 04	56
22. खरसहन कला 19.56 9921 7.33 37.47 7 23. महुआररा 12.18 6236 1.36 11.17 3 24. पुकवाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10	20.	पल्थी दुल्हापुर	16.09	889	6. 67	14. 45	75
23. महुआररा 12.18 6236 1.36 11.17 2 24. पुकवाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10	21.	राजापुर	16.49	10049	5. 43	32.93	51
24. पुक्रवाल 15.10 8843 2.67 17.68 3 25. सिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 10	22.	खरसहन क्ला	19.56	9921	7.33	37.47	73
25. तिकरौर 23.26 9827 9.90 42.56 IC	23.	महुआररा	12.18	6236	1.36	11. 17	2
	24.	पुक्वाल	15. 10	8843	2. 67	17-68	30
१६० करबा प्रतेहपुर १३०३७ ६६५८ १०३३ १०९५	25.	तिकरौर	23. 26	9827	9.90	42.56	100
	26.	करबा फतेहपूर	13.37	6658	1.33	9.95	19

	2	3	4	5	6
3				. And the state was seen that the same same	are and all days are and all
कारागहना	21.84	11998	3.06	14.01	25.50
पुलेश	20.38	8604	4. 00	19.63	46. 49
छितर अहमदपुर	18.72	11271	4. 27	22.81	37.88
वेलवाना	24.96	10501	7.73	30.97	73.61
कुर ् या	23. 14	9271	2.93	12.66	31.60
जगदीशपुर ददेरिया	27.53	11388	5. 27	19.14	46. 28
सुरहन	34.71	12447	7. 17	20.66	57.60
नसरा खुर्द	27. 45	10520	2.34	8.52	22. 24
पारामिश्रौ लिया	16.65	7705	5. 00	42.92	64.89
गनवारा	9.69	6400	4. 33	44. 69	67.66
माहुल	26.39	16815	6.36	24.10	37.82
शस्त्रावाद	13.22	8261	4.31	32.60	52. 17
पूनपुर ग्रामाण	692.62	357014	199.00	28.73	55.74
पूलपुर नगरीय	8.98	5136	अनु०	અનુo 	<u> </u>
तहसील पूलपुर	701.60	362150	199.00	28.73	55.74
	ितर अहमदपुर वेलवाना कुरुथुवा जगदीशपुर ददेरिया सुरहन लसरा खुर्द पारामिश्रौ लिया गनवारा माहुल शम्शावाद पूलपुर ग्रामीण	कौरागहनी 21.84 पुनेश 20.38 छितर अहमदपुर 18.72 वेलवाना 24.96 कुरुधुवा 23.14 जगदीशपुर ददेरिया 27.53 सुरहन 34.71 लसरा छुर्द 27.45 पारामिश्रौलिया 16.65 गनवारा 9.69 माहुल 26.39 शम्भावाद 13.22 पूलपुर ग्रामीण 692.62 पूलपुर नगरीय 8.98	पुनेश 20.38 8604 छितर अहमदपुर 18.72 11271 वेलवाना 24.96 10501 छुरुथुवा 23.14 9271 जगदीशपुर ददेरिया 27.53 11388 सुरहन 34.71 12447 लसरा छुर्द 27.45 10520 पारामिश्रौलिया 16.65 7705 गनवारा 9.69 6400 माहुल 26.39 16815 शम्भावाद 13.22 8261 पूलपुर ग्रामीण 692.62 357014 पूलपुर नगरीय 8.98 5136	कौरागहनी 21.84 11998 3.06 पुलेश 20.38 8604 4.00 िकतर अहमदपुर 18.72 11271 4.27 वेलवाना 24.96 10501 7.73 कुरुध्वा 23.14 9271 2.93 जगदीशपुर ददेरिया 27.53 11388 5.27 सुरहन 34.71 12447 7.17 लसरा छुर्द 27.45 10520 2.34 पारामिश्रौलिया 16.65 7705 5.00 गनवारा 9.69 6400 4.33 माहुल 26.39 16815 6.36 शम्मावाद 13.22 8261 4.31 पूनपुर ग्रामीण 692.62 357014 199.00 पूनपुर नगरीय 8.98 5136 अनु0	कौरागहनी 21.84 11998 3.06 14.01 पुलेश 20.38 8604 4.00 19.63 छितर अहमदपुर 18.72 11271 4.27 22.81 वेलवाना 24.96 10501 7.73 30.97 कुरुथुवा 23.14 9271 2.93 12.66 जगदीशपुर ददेरिया 27.53 11388 5.27 19.14 सुरहन 34.71 12447 7.17 20.66 लसरा छुर्द 27.45 10520 2.34 8.52 पारामिश्रौलिया 16.65 7705 5.00 42.92 गनवारा 9.69 6400 4.33 44.69 माहुल 26.39 16815 6.36 24.10 शम्यावाद 13.22 8261 4.31 32.60 पूतपुर ग्रामीण 692.62 357014 199.00 28.73 पूतपुर नगरीय 8.98 5136 अनु0 अनु0

[·] स्रोत : (।) जिला जनगणना हस्तपुंस्तिका, आजमगढ़, भाग XIII B , 1981.

सड़क दनत्व के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को तीन भागों में बाँटा गया है -

इस वर्ग में उन न्यायपंचायतों को रखा गया है जहाँ पर सड़कों का धनत्व

⁽²⁾ मानश्चित्र तंख्या 6.। से परिकलित

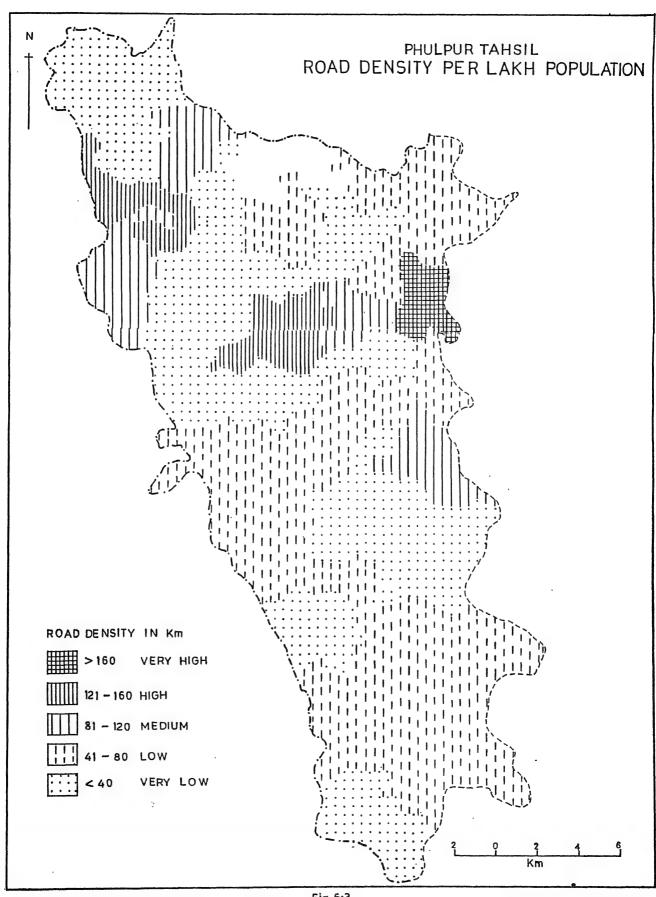


Fig. 6.3

प्रति 100 वर्ग किंग्मी० पर 67 किंग्मी० या इससे अधिक है । इसमें बस्ती सदनपुर, अम्बारी, पदगुड़िया तथा सदरपुर बरौली न्याय पंचायतें आती हैं । इन न्याय पंचायतों में सड़कों का धनत्व अधिक होने का कारण आजमगढ़-शाहगंज मार्ग से इनकी सम्बद्धता है ।

(2) मध्यम धनत्व के क्षेत्र

इस वर्ग के अन्तर्गत उन न्याय पंचायतों को रहा गया है जहाँ पर सड़कों का धनत्व प्रति 100 वर्ग किं0मीं पर 33 से 66 के बीच है । इसमें पारामिश्रौ लिया, गनवारा, रामनगर, वाग सिकन्दरपुर, नोनियाडीह, पल्थी दुल्हापुर, खरसहनक्षा तथा सिकरौर आदि न्याय पंचायतें आती हैं।

(3) न्यून धनत्व के क्षेत्र

इस वर्ग के अन्तर्गत वे न्यायपंचायतें आती हैं जो सड़कों के धनत्व की दृष्टिट से पिछड़ी हुई हैं, जहाँ पर सड़कों का धनत्व प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल पर 33 कि0मी0 से कम है । इसमें माहुल, शम्शाबाद, मिन्तूपुर, दोस्तपुर लहुरमपुर, सुम्हा-डीह, सौदमाथानेश्वर, सादुल्लाहपुर, छंजहापुर, सजई, अमानबाद, वक्सपुर मेजवा, केनेरी, गद्दौपुर बारी, राजापुर, महुआरा, पुकवाल, फ्तेहपुर, कौरागहनी, फुलेश, छितर अहमदपुर, वेलवाना, कुरुथ्वा, जगदीशपुर ददेरिया, सुरहन तथा लसरा छुर्द आदि न्याय पंचायतें आती हैं।

सारणी 6.3 से यह भी स्पष्ट है कि सन्तारपुर रज्जाकपूर न्याय पंचायत

में सड़कों का अभाव है। सर्वाधिक सड़कों का धनत्व सदरपुर वरौली न्याय पंचायतों में 106.08 कि0मी0 प्रति 100 वर्ग कि0मी0 है।

6. 4 सड्क अभिगम्यता

सइक मार्गों की सद्यनता उनकी अभिगम्यता से अधिक सुरूपष्ट होती है। इसके द्वारा सड़कों की सद्यनता तथा गमनागमन की सुविधा का बोध होता है। सड़क अभिगम्यता से तात्पर्य यथासंभव कम समय तथा कम शक्ति नष्ट कर निर्वाध गति से सुगमतापूर्वक किसी गन्तव्य रथन तक पहुँचने से है। इसकी तीव्रता से किसी क्षेत्र के विकास का स्तर एवं सड़क जान की प्रभावोत्पादकता का मापन होता है। 5

तामान्यतया तइक की अभिगम्यता परिवहन मार्ग ते एक विशेष दूरी द्वारा प्रकट की जाती है। इस दूरी का मापन नितान्त व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। भारत में सड़कों की अभिगम्यता के मापन के सन्दर्भ में नागपुर तथा बम्बई योजना द्वारा अभि-गम्यता मानदण्ड निर्धारित किया गया (सारणी 6.4) है।

<u>सारणी ६. ५</u> नागपुर और बम्बई योजना⁶ द्वारा निर्धारित सड़क अभिगम्यता मानदण्ड

	क्षेत्र विवरण	किसी भी गाँव की अधि किसी भी सड़क से	कतम दूरी (कि0मी0 में) मुख्य सङ्क से
1.	नागपुर योजना		
	। कृषि क्षेत्र	3. 22	8.05
	2. कृषि इतर ध्रेन	8. 05	32.10
2.	बम्बई योजना		
	 विकसित कृषि क्षेत्र 	2.41	6. 44
	2. अर्द्ध विकसित कृषि क्षेत्र	4.83	12.87
	3. अविकसित कृषि क्षेत्र	8.05	19.37

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क परिवहन के विकास में उक्त मानदण्डों को ही अपनाया गया है किन्तु अत्यन्त कृष्णि प्रधान एवं विकासशील पूलपुर तहसील के सन्दर्भ में यह मानदण्ड वास्तविकता से बहुत दूर हो जाता है। इसके लिए दो तथ्य मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं -

- यह मानदण्ड आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित है,
- मानदण्ड अपेक्षाकृत बहुत पहले निर्धारित किया गया था जबिक आज भौगोलिक परिवेश काफी बदल चुका है ।

पूनपुर तहसील की सड़कों की अभिगम्यता मापन के सन्दर्भ में उक्त मानदण्ड को नहीं अपनाया जा सकता । अत: व्यवहारिक अभिगम्यता को ध्यान में रखते हुए पूनपुर तहसील में निम्नलिखित को अभिगम्य माना जा सकता है -

- किसी भी पक्की सड़क से । कि0मी० की दूरी पर स्थित बस्तियाँ,
- मुख्य पक्की सड़क से 3 किंOमी 0 की दूर पर स्थित बस्तियाँ।

इस मानदण्ड के आधार पर पूलपुर तहसील में विकासखण्ड स्तर पर सड़क अभिगम्य क्षेत्रों का परिकलन किया गया है । इससे अधिक दूर स्थित क्षेत्रों को अगम्य माना गया ।

सारणी 6.5 से स्पष्ट है कि तहसील की औसत सड़क अभिगम्यता 68.69 प्रतिशत है तथा 31.31 प्रतिशतः भाग अगम्य क्षेत्र है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक अभिगम्यता 73.17 प्रतिशत पूलपुर में है जबकि सबसे कम सड़क अभिगम्यता 60.66 प्रतिष्ठात अहरौला (i) में है । अन्य विकासखण्डों - पवई तथा मार्टिनगंज में सड़क अभिगम्यता क्रमण्ञ: 68.77 तथा 65.98 प्रतिष्ठात है ।

सारणी 6.5 पुलपुर तहसील में पक्की सड़क अभिगम्यता, 1989

	 विकासखण्ड	(प्रतिशत में) अभिगम्य क्षेत्र
1.	पवर्ड	68.77
2.	पूलपुर	73. 17
3.	मा टिनगंज	65.98
4.	अहरौला(I)	60. 66
Star ear :	पूनपुर तहसील	68. 69

स्रोत: सां खियकीय पत्रिका, जनपद-आजमगढ़, 1990 से संगणित

राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 29.7 प्रतिशत गांव भारतवर्ष में प्रत्यक्ष रूप से पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं वहीं राज्य में मात्र 18.2 प्रतिशत गांव प्रत्यक्ष रूप से पक्की सड़कों से सम्बद्ध हैं। परन्तु जनपद एवं तहसील स्तर पर भिन्नता पायी जाती है। जनपद स्तर पर अध्ययन से ज्ञात होता है कि 24.89 प्रतिशत गांव प्रत्यक्ष रूप से पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं जबकि पूलपुर तहसील में 26.5 प्रतिशत गांव। विकासखण्ड स्तर पर पूलपुर में 31.1 प्रतिशत गांव प्रत्यक्ष रूप से पक्की सड़कों से जुड़े हैं जो रोष्ट्रीय स्तर से भी अधिक हैं। सब्से कम 13.11 प्रतिशत गांव अहरौला(1)विकासखण्ड में पक्की सड़कों से सम्बद्ध हैं।

6.5 सड़क सम्बद्धता

सड़क परिवहन के विश्लेषण में सड़कों की आपस में सम्बद्धता का विशेष महत्त्व है। सड़क सम्बद्धता से मार्ग जाल के विकास-स्तर तथा सहनता का बोध होता है। जिस सड़क की सम्बद्धता जितनी ही अधिक होगी उसकी सहनता तथा अभिगम्यता भी उतनी ही अधिक होगी। सड़क सम्बद्धता परिवहन मार्ग ज़ल की सहनता को ही नहीं वरन् परिवहन मार्गों की तकनीकी स्तर जनित वाहनों के गमनागमन तथा यातायात हानत्व को भी प्रतिबिम्बित करता है। फूलपुर तहसील के सन्दर्भ में यह सम्बद्धता दो तरीके से ज्ञात की गयी है - एक प्रमुख सेवा केन्द्रों के सन्दर्भ में तथा दूसरी सड़क जाल संरचना के परिप्रेक्ष्य में।

(।) सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता

सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता किसी भी क्षेत्र में परिवहन तंत्र के विकास के स्तर को इंगित करती है। सामान्यतः किसी भी क्षेत्र में गमनागमन एवं आर्थिक गतिवालिता इन्हीं सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता के परिप्रेक्ष्य में होती है। अध्ययन प्रदेश में सड़कों की यह सम्बद्धता केवल पक्की सड़कों से ली गयी है। प्रस्तृत विवलेषण में तहसील के 40 निर्धारित सेवा केन्द्रों में से केन्द्रीयता सूचकांक की दृष्टिंद से 16 उच्चस्तरीय सेवा केन्द्रों को ही चुना गया है (देखिये सारणी 3.6)।

इन निर्धारित सेवा केन्द्रों की आपस में पक्की सड़कों से सम्बद्धता को ज्ञात करने के लिए मानचित्र 6.। के आधार पर 'कनेक्टी विटी मैद्रिक्स' (Connectivity Matrix) का निर्माण किया गया है (सारणी 6.6) ।

महत्त्वपूर्ण सेवा केन्द्रों से पक्की सडकों की सम्बद्धता मैद्रिक्स

-		•					 -	-												
ဒ္ဓင	Ha	AM	BN	四四	MP	Ā	KN	NG	0.01	スド	E E	MID	大压	KH	SU	KP TP	To-	SC		Service Centre
PΗ	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	₽H		Phulpur
MA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	AM	-	Ambari
BN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	BN	_	Bangaon
PW	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	PW	_	Pawai Khas
M₽	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	MP	***	Milkipur
MK	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	MK	_	Mahul Khas
KN	1	0	0	0	0	0	О	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	KN	-	Kaura Gahni
PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	₽N	-	Pook
PP	0	0	0	0	0	1	0	0	Ò	0	0	0	0	0	0	0	1	PP	_	Pakkhanpur
KHK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	KH	ζ_	Kharsahan Kal
FP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	FP	-	Phules
MTP	0	Ò	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MT	-	Mittupur
KHP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	KH	P_	Khanj ahanpur
KН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KН		Khandaura
ຮບ	0	0	1	0	0	О	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	SU	****	Surhan
RP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RP		Rajapur
												No diseased State or own		······································			ga gayay,@ment		- Pare	allery Miler Base Approphisms of the right — Mile Williams (Miles Williams)
Total	3	4	1	2	2	4	2	2	1	4	1	1	1	0	3	1	32			

सारणी 6.6 से स्पष्ट है कि तहसील में सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम और उनकी सड़क सम्बद्धता में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। तहसील में अधिकतम सम्बद्ध और अभिगम्य क्षेत्र अम्बारी और छारसहनकला हैं जो 4-4 सेवा केन्द्रों से सीधे जुटे हैं। सम्बद्धता की दृष्टि से पूलपुर (तहसील मुख्यालय) दूसरे स्थान पर हैं जो प्रत्यक्षतः तीन विकास केन्द्रों से सम्बद्ध है। पवई, मिल्कीपुर, कौरागहनी तथापूक दो दो केन्द्रों से जुड़े हैं। वनगांव, पुलेश, मिन्तूपुर, खंग्रहापुर तथा राजापुर एक-एक सेवा केन्द्रों से पक्की सड़कों से जुड़े हैं। खंडीरा किसी भी सेवा केन्द्र से प्रत्यक्षतः नहीं जुड़ा हुआ है।

(2) सड़क-जाल सम्बद्धता

हत विश्लेषण पद्धति में किसी सड़क जाल को एक ग्राप्त के समान माना गया है, जिनमें बिन्दु तथा बाहु दो मुख्य तत्त्व हैं। किसी भी सड़क जाल में जितने भी उद्गम, संगम तथा अन्तिम या प्रमुख सेवा केन्द्र होते हैं उन्हें बिन्दु तथा इनको सीधे जोड़ने वाली सड़कों को बाहु के रूप में माना जाता है। इसमें बिन्दुओं के बीच की दूरी अर्थांच् बाहुओं की लम्बाई पर ध्यान न देकर उनकी मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। पूलपुर तहसील में पक्की सड़कों के जाल के सन्दर्भ में प्रमुख बिन्दुओं की संख्या 16 है तथा इनको जोड़ने वाली बाहुओं की संख्या 17 है। इन बिन्दुओं के माध्यम से सड़क जाल सम्बद्धता को दशनि वाले अल्पा(α) बीटा(β) तथा गामा(γ) निर्देशांकों की गणना की गयी है जिनके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष की यातायात व्यवस्था का विश्लेषण एवं उनका उचित मुल्यांकन किया जाता है।

अल्पा सूचकांक का प्रयोग ऐसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है जहाँ परिवहन तन्त्र कई अलग-अलग रूण्डों में विभक्त हों। परन्तु प्रस्तुत अध्याय में स्थिति ठीक इसके विप-रीत है। यहाँ पर परिवहन तन्त्र मात्र एक ही है। अतः इसका प्रयोग प्रस्तुत अध्ययन में उपयुक्त न होगा। अल्का निर्देशांक की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है -

$$C = \frac{e - v + g}{2v - 5}$$

जहाँ α = अल्फा निर्देशांक

e = बाहुओं नी संख्या

v = बिन्दुओं की संख्या

प्रत्येक मार्ग जाल की सम्बद्धता सूत्र से गणना करने पर निर्देशांक 0 से 1.00 के मध्य आता है । पूर्णतः सुसम्बद्ध मार्ग जाल का सूचकांक 1.00 तथा पूर्णतः असम्बद्ध मार्ग जाल का मान 0 आता है । इसमें 100 से गुणा करके सड़क सम्बद्धता को प्रतिशत में भी ट्यक्त किया जाता है ।

बीटा (८) सूचकांक किसी मार्ग जाल के बिन्दुओं और बाहुओं के अनुपात को इंगित करता है। इस सूचकांक के अनुसार असम्बद्ध मार्ग जाल का मान 1.00 से कम, एक ही चक्र में विभिन्न केन्द्र बिन्दुओं को मिलाने वाले मार्ग जाल का मान 1.00 तथा केन्द्र बिन्दुओं के मध्य कई विकल्प वाले मार्ग जाल का मान 1.00 से अधिक आता है। इस सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जा सकती है?—

$$\beta = \frac{e}{v}$$

जहाँ β = बीटा सूचकांक

e = बाहुओं की संख्या

v = बिन्दुओं की संख्या

तह्तील में सड़क जाल के सन्दर्भ में बीटा सूचकांक का मान 1.06 है जो यह स्पष्ट करता है कि सड़क जाल बहूत ही कम सम्बद्ध है।

गामा (५) सूचकांक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अध्ययन क्षेत्र की परिवहन दशा को अच्छी तरह जानी जा सकती है। गामा सूचकांक भी किसी मार्ग जाल के बाहुओं और बिन्दुओं को प्रकट करता है। इस सूचकांक की गणना निम्न सूत्र से की जाती है9-

$$\gamma = \frac{e}{3(v-2)}$$

जहाँ γ = गामा सूचकांक

e = बाहुओं की संख्या

v = बिन्दुओं की संख्या

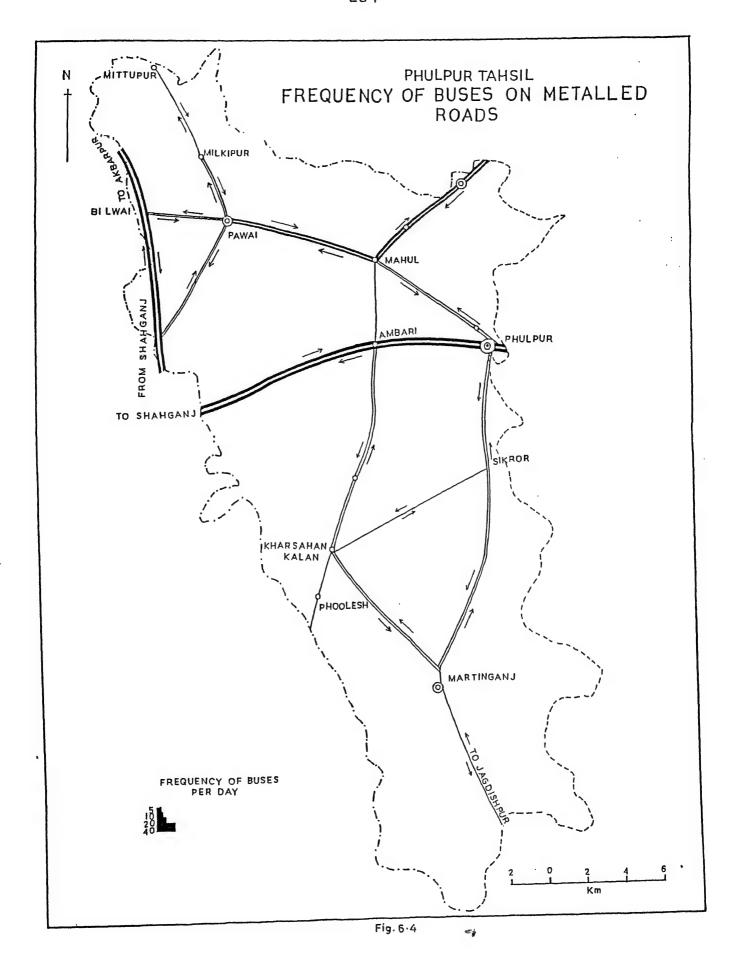
इस सूचकांक का मान ० से 1.00 के मध्य आता है । यदि सूचकांक का मान 1.00 से कम आता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि मार्ग जान अभी अविकसित अवस्था में है । यदि सूचकांक 1.00 आता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि उस क्षेत्र का परिवहन तन्त्र विकसित अवस्था में है । यदि गामा सूचकांक का मान 1.00 से अधिक आता है तो इसका अर्थ हुआ कि क्षेत्र विशेष्ठ का परिवहन तन्त्र अत्यधिक विकसित अवस्था में है ।

तहसील में सड़क जाल का गामा सूचकांक 0.40 है, जिससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र का परिवहन तन्त्र अभी अविकसित अवस्था में है।

6.6 यातायात प्रवाह

यातायात प्रवाह से तात्पर्य किसी भी परिवहन मार्ग पर वस्तुओं और व्यक्तियों के गमनागमन प्रतिरूप से हैं। यातायात प्रवाह का अध्ययन विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का प्रवाह प्रतिरूप समझने के लिए किया जाता है जिससे विभिन्न प्रदेशों के व्यापारिक अन्तर्सम्बन्धों का आकलन किया जा सके। इसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं, यात्रियों के उद्गम और गन्तव्य स्थान और उनकी परिवहन दूरी, परिवहन मार्ग पर प्रतिदिन का कुल यातायात धनत्व तथा विभिन्न मार्गखण्डों के यातायात संचना का पता लगाया जाता है। इस प्रकार यातायात प्रवाह से प्रादेशिक आर्थिक कार्यकलाप, आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध प्रतिरूप एवं आर्थिक विकास का स्तर द्वात किया जा सकता है।

पूलपुर तहसील की अर्थंट्यवस्था मुख्यतः कृष्ठि पर आधारित है। यहाँ के गांवों से सिब्जियां, अनाज तथा अन्य कृष्ठि उत्पादों को पूलपुर, अम्बारी, माहुल और पवई आदि ग्रामीण मण्डियों को भेजा जाता है। तहसील से बाहर भेजे जाने वाले कृष्ठि उत्पादों को भुख्यतः पूलपुर नगरीय क्षेत्र से भेजा जाता है। इसके साथ ही इन बाजारों से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का प्रवाह गांवों की और होता रहता है।



तहसील में कृष्णि उत्पादों का एकत्रीकरण इक्कों, जीपों, वैलगाड़ियों, उँदों, रिक्काों तथा साइकिलों द्वारा होता है। मौसम के अनुसार यातायात प्रवाह में अन्तर आता रहता है।

यातायात प्रवाह में यात्रियों के अन्तर्जनपदीय तथा अन्तप्रदिशिक आवागमन को आधार बनाया गया है। यात्रियों का यह प्रवाह सड़कों पर चलने वाली व्यक्ति-गत और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों के माध्यम से मापने का प्रयास किया गया है। सड़कों पर चलने वाली बसों की संख्या व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधा-रित है। बसों की कुल संख्या में बसों के आने और जाने दोनों को समाहित किया गया है। पूलपुर तहसील में बसों का यातायात प्रवाह चित्र संख्या 6.4 में देखा जा सकता है।

मानचित्र संख्या 6.4 से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मात्र कुछ ही मार्ग ऐसे हैं जहाँ पर यातायात प्रवाह अच्छा है जैसे शाहगंज-पूलपुर मार्ग, ब्लिवाई-शाहगंज मार्ग जिस पर प्रतिदिन 40 से 50 बसें चलती हैं जिसमें अधिकतर अन्तप्रदिशिक बसे हैं। इसके पश्चात् माहुल-अहरौला मार्ग पर 16 बसें प्रतिदिन गुजरती हैं। माहुल-अम्बारी मार्ग पर 12 बसें प्रतिदिन गुजरती हैं। शेष्ठा मोर्गों की स्थिति बस यातायात प्रवाह के सन्दर्भ में अच्छी नहीं है १ अतः परिवहन के साधनों के विकास की महती आवश्य-कता है।

6.7 परिवहन नियतेजन एवं प्रस्ता वित मार्ग

तहसील में जल एवं वायु परिवहन का तो पूर्णत: अभाव है । रेल परिवहन
----×प्रदेश के दक्षिणी भागों में मार्गों पर व्यक्तिगत रूप से चलने वाली जीपों का अधिक
प्रचलन है ।

भी लगभग नगण्य है। कुल मिलाकर सड़क परिवहन ही यातायात का प्रमुख माध्यम है। सड़कों का धनत्व एवं गम्यता कम होने से सड़क परिवहन की त्थिति भी संतोध-जनक नहीं कही जा सकती। पक्की सड़कों एवं छहंजा मागों की त्थिति भी अच्छी नहीं है। क्षेत्र में अधिकांश पक्की सड़कें दूरी हुई हैं तथा सड़कों पर जगह-जगह गद्धदे हैं जिनसे यातायात काफी कठिन हो जाता है। परिवहन तंत्र के अवरद्ध हो जाने पर आर्थिक तन्त्र के अन्य सभी भागों में विकास कार्य स्क जाता है। तहसील के विकास के लिए यह आवश्यक है कि परिवहन की सुविधाओं में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार एवं वृद्धि की जाय तथा अगम्य क्षेत्रों को अभिगम्य बनाया जाय। तहसील में परिवहन नियोजन सम्बन्धी सभी सुद्धाव आगामी 10 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये गये हैं।

(1) रेलमार्ग

रेलमार्गों के सन्दर्भ में यह सुझाव प्रस्तुत है कि शाहगंज-मऊ रेलमार्ग को बड़ी लाइन में बदला जाय तथा इस मार्ग को सीधे गोरखपुर जनपद से जोड़ा जाय । इससे वस्तुओं, ट्यक्तियों या सेवाओं के संचार में काफी सुविधा होगी । क्षेत्र का सम्बन्ध दूसरे क्षेत्रों से हो सकेगा और इस प्रकार विकास के नये आयाम छुलेंगे ।

(2) सम्पर्क मार्ग

तहसील में सड़क परिवहन के विकास हेतु वर्तमान पक्की सड़कों में सुधार किया जाना चाहिए। नयी पक्की सड़कें, ख्हंजा मार्ग तथा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जो वर्षभर परिवहन योग्य हों, बनाये जायं। यातायात के नियोजन की दृष्टिद से वृहद, मध्यम तथा लद्यु ग्रामों को क्रमण्ञ: पक्की सड़कों, ख्हंजा मार्गों तथा सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़ा जाय।

(क) प्रस्तावित पक्की सड़कें

तहसील में मुख्य सम्पर्क मार्गों के दोनों पट रियों को और चौड़ा किया जाय तथा सड़कों के किनारे इंट की सोलिंग बिछाई जाय । जो सड़कें टूटी हैं, उखड़-खा बड़ हैं उन्हें ठीक किया जाय । तहसील में यातायात को ध्यान में रखते हुए सन् 200। तक कुल 95.25 कि0मी0 अतिरिक्त पक्की सड़कों की आवश्यकता होगी (चित्र संख्या 6.5) । इनमें प्रमुख सम्पर्क मार्ग सारणी 6.7 में उल्लिखित हैं।

तहसील में प्रस्तावित पक्की सङ्गें

	सम्पर्कमार्गका नाम	लम्बाई (कि0मी0)
1.	मिल्कीपुर-खण्डौरा मार्ग	5. 00
2.	तुम्हाडीह-खंजहापूर मार्ग	9. 25
3.	अम्बारी-राजापुर मार्ग	9.00
4.	पुनेश-लप्तरा खुर्द बाया वनगांव मार्ग	15. 25
5.	खंजहापुर-राजापूर मार्ग	5. 00
6.	अम्बारी-सिकरौर मार्ग	12. 25
7.	पवई-अम्बारी मार्ग	12.50
8.	पूनपुर-अहरौला मार्ग	10.00
9•	माहुल-खंजहापुर मार्ग	11.00
	कुल सड़कों की लम्बाई	95. 25

(ख) प्रस्तावित खड्जा मार्ग

पूनपुर तहसील में प्रत्येक बस्ती किसी न किसी कच्चे मार्ग या पगडण्डी

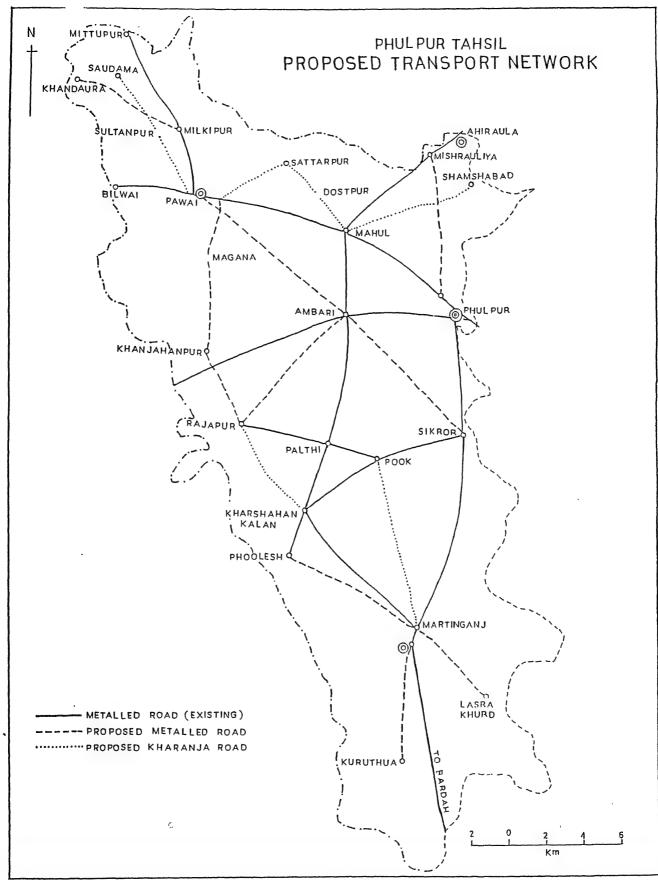


Fig. 6.5

दारा विकासकेन्द्रों या पक्की सड़कों से अवश्य जुड़ी हुई हैं। परन्तु ये कच्चे मार्ग या पगडण्डियां वर्ष भर परिवहन योग्य नहीं रहती हैं। वर्षा के दिनों में इन कच्चे मार्गों पर पानी भर जाता है, आवागमन दुर्लंभ हो जाता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि इन कच्चे मार्गों और पगडण्डियों को उँचा करके छहंजा बिछाकर किसी न किसी पक्की सड़क से जोड़ा जाय। इसके लिए तहसील में कुल 47.20 कि0 मीठ छहंजा मार्ग प्रस्तावित है (सारणी 6.8)।

<u>सारणी 6.8</u> प्रस्तावित खड्जा मार्ग

	मार्ग	लम्बाई (कि0मी0)
1.	गद्दोपुर वारी-पूनपुर वाया वक्तपुर मेजवा मार्ग	8.00
2.	पुष्टपनगर-सुरहन मार्ग	9.80
3.	माहूल-शम्शाबाद मार्ग	8.00
4.	सौदमा थानेश्वर-पवर्ड मार्ग	8.00
5.	राजापुर-खरसहन कला मार्ग	6.00
6.	सत्तारपुर रज्जाकपुर-दोस्तपुर लहुरमपुर मार्ग	3.00
7.	सत्तारपुर रज्जाकपुर-सुम्हाडीह मार्ग	4. 40
	कूल प्रस्तावित रहजा मार्ग की लम्बाई	47. 20

6. ८ संचार-व्यवस्था

विकतित संचार सेवार अध्विक औद्योगिक समाज की अनिवार्य आवश्यकतार

हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मनुष्य की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यमों से सम्बन्धित है। संचार के माध्यमों से ही सूचनाओं व ज्ञान का प्रचार व प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक गाँव से दूसरे गाँव, एक नगर से दूसरे नगर यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश तक किया जाता है। राजनैतिक जीवन, सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृष्टि, उन्नत शैक्षिक प्रविधिया, विज्ञापन, उद्योग, मनोरंजन आदि सभी क्रियाएं संचार के माध्यमों से ही सफ्लतापूर्वक संचालित हो रही हैं। संचार के इसी महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्याय में संचार सेवाओं के वर्तमान स्वरूप एवं उनके विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया. है। संचार माध्यमों को व्यक्तिगत संचार तथा जनसंचार दो भागों में विभक्त किया गया है।

(।) व्यक्तिगत संचार

डाक, तार तथा दूरभाष आदि व्यक्तिगत संगर के माध्यम हैं जो अपनी
सेवाओं द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँगते हैं। सम्प्रति तहसील
में 42 डाक्टर, 8 डाक एवं तारदर, 23 व्यक्तिगत दूरभाष केन्द्र तथा 10 सार्वजनिक
दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं। पवर्ज विकासखण्ड में सबसे अधिक 15 डाक्टर हैं। अहरौला(i)
विकासखण्ड में मात्र 3 डाक्टर कार्यरत हैं। अन्य विकासखण्डों पूलपूर तथा मार्टिनगंज
में इनकी संख्या क्रम्मा: 13 और 11 हैं। सर्वाधिक 3 डाक एवं तारदर पूलपुर विकासखण्ड में हैं जबकि सबसे कम एक मार्टिनगंज विकासखण्ड में। अन्य विकासखण्डों पवर्ज
तथा अहरौला में क्रम्मा: दो-दों डाक एवं तारदर कार्यरत हैं। वर्तमान समय में तहसील
में 10 सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र और 23 व्यक्तिगत दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं।

सारणी 6.9 तहसील में उपलब्ध टयक्तिगत संचार सेवार, 1989

***	संचार सेवा	उपलब्ध गाँवों व	का प्रतिशत
विकासखण्ड/सृविधाएँ	गाँव में	३ किं०मी० 3 संकमदूरी अ पर	कि0मी0 से धिक दूरी पर
पवर्ड			
ड ा क्टार	8.67	43.93	47. 40
डाक एवं तारधर	1.16	16.18	82.66
सार्वजनिक दूरभाष	0. 59	8.09	91.32
पूनपुर			
डाक्टार	7.93	66.46	25.61
डाक एवं तारघर	1.83	20.12	76.05
सार्वजनिक दूरभाष	2. 44	13.41	84. 15
मा टिनगंज			
ड िकटार	11.34	71.13	17.53
डाक एवं तारघर	1.03	12.37	86.60
सार्वजनिक दूरभाष	5. 15	17.53	77.32
<u>अहरौला(i)</u>			
इंग्क्टिर	4.91	52.46	42.63
डाक एवं तारधर	3. 28	22.95	73.77
सार्वजनिक दूरभाष	2.02	12.12	85.86
		aria curu dada dum ariu tuma ariu, tama tama tama dan ariur dalah t	
तहसील		_	
डा कहार		57 . 7 8	
डाक एवं तारधर		17.57	
सार्वजनिक दूरभाष	2. 02	12.12	85.86

म्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1989 से संगणित

(क) डाकधर

वर्तमान समय में तहसील में कूल 42 डाक्टर कार्यरत हैं। सारणी 6.9 से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जहाँ 8.48 प्रतिप्रात गाँव के लोगों को गाँव में ही डाक्टर की सुविधा उपलब्ध है वहीं 57.78 प्रतिप्रात गाँव के लोगों को 3 कि0मी0 के भीतर डाक्टर की सुविधा है। 33.74 प्रतिप्रात गाँव के लोगों को इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए इससे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। डाक्टर की स्थिति के सन्दर्भ में मार्टिनगंज तथा पूलपुर विकासखण्डों की दशा संतोष्ट्रजनक कही जा सकती है जहाँ क्रम्या: 71.13 तथा 66.46 प्रतिप्रात गाँव के लोगों को 3 क्कि0मी0 तक की दूरी तय करने पर यह सुविधा उपलब्ध हो पाती है। डाक्टरों की अवस्थित की दृष्टि से पवर्ड विकासखण्ड की स्थित संतोष्ट्रजनक नहीं कही जा सकती है क्यों कि यहाँ पर इनकी अवस्थित दूर-दूर है।

(ख) डाक एवं तारधर

सारणी 6.9 से स्पष्ट है कि तहसील में मात्र 1.62 प्रतिशत गाँवों में डाक एवं तारघर की सुविधा उपलब्ध है । 17.47 प्रतिशत गाँव के लोगों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 3 कि0मी0 तक की दूरी तय करनी पड़ती है जबकि 80.8। प्रति-शत गाँव के लोगों को डाक एवं तारघर की सुविधा प्राप्त करने में 3 कि0मी0 से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है । डाक एवं तारघर के सन्दर्भ में अहरौला(i) विकासखण्ड की स्थिति अन्य विकासखण्डों की अपेक्षा संतोष्ठ्यनक कही जा सकती है जहाँ पर 3.28 प्रतिशत गाँवों में यह सुविधा उपलब्ध है जबिक 22.95 प्रतिशत गाँव

के लोगों को 3 कि0मी0 तक की दूरी तय करनी पड़ती है । मार्टिनगंज विकासखण्ड की स्थिति संतोष्टाजनक नहीं कही जा सकती है क्यों कि 86.60 प्रतिशत गाँव के लोगों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 3 कि0मी0 से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है।

(ग) सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र

वर्तमान समय में तहसील में कुल 10 सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं।
सारणी 6.9 से स्पष्ट है कि 2.02 प्रतिव्ञत गाँवों में यह सुविधा उपलब्ध है। 12.12
प्रतिव्ञत गाँव के लोगों को 3 किं0मीं तथा 85.86 प्रतिव्ञत गाँवों के लोगों को यह
सुविधा प्राप्त करने के लिए 3 किं0मीं से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। इस
सन्दर्भ में मार्टिनगंज विकासखण्ड की स्थिति कुछ संतोष्ठजनक कही जा सकती है जहाँ
5.15 प्रतिव्ञत गाँवों में यह सुविधा प्राप्त है जबिक 17.53 प्रतिव्ञत गाँव के लोगों को
3. किं0मीं तथा 77.32 प्रतिव्ञत गाँव के लोगों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 3
किं0मीं से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। पवई विकासखण्ड की स्थिति
काफी असंतोष्ठजनक है जहाँ मात्र एक सार्वजनिक दूरभाष्ठ केन्द्र कार्यरत है और 91.32
प्रतिव्ञत गाँव के लोगों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 3 किं0मीं से अधिक की
दूरी तय करनी पड़ती है।

(2) जनसंचार

जनसंचार का आश्वय सूचनाओं और मनोरंजन के माध्यमों द्वारा ट्यापक प्रचार-प्रसार करना है। परम्परागत समाज में जहाँ जनसंचार के माध्यमों के रूप भें नाटक, राम्लीला एवं कठपुतलियों का उपयोग होता था वहीं आज जनसंचार के माध्यमों में रेडियों, दूरदर्शन, सिनेमा तथा समाचार पत्र-पत्रिकाएँ एवं विद्धापन मुख्य हैं जो सूचना, ज्ञान, विचारों, भावनाओं तथा भिल्प कलाओं का संकेत, चिह्नों, शब्दों, चित्रों तथा आरेखों द्वारा बड़ा ही प्रभावी प्रसारण करते हैं। अकाश-वाणी, दूरदर्शन तथा सिनेमा संगीत के माध्यमों से अपने कार्यक्रमों को और अधिक रोचक बना देते हैं। सामाजिक भिक्षा, नियमित भिक्षा तथा जीवनपर्यन्त भिक्षा में इनकी प्रभावी भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं सिनेमा लोगों का मनोरंजन करते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से संसार के अन्य देशों के समाचार, खेलों के विवरण, संगीत, विद्वापन तथा अन्य घटनाओं को आसानी से जाना जा सकता है।

पूलपुर तहसील के सम्पूर्ण भूभाग पर यद्यपि रेडियों का प्रसारण पहुँचता है
किन्तु क्षेत्र की अधिकांश जनता गरीब होने के कारण इनके कार्यक्रमों से वंचित रहती है
क्यों कि उनके पास रेडियों सेट नहीं हैं। क्षेत्र की लगभग 65 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप से इसका लाभ उठा रही है।

दूरदर्शन भी जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। लोगों को स्वस्थ मनो-रंजन उपलब्ध कराने में दूरदर्शन की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। रेडियों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृष्णि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को केवल सुन सकते हैं वहीं दूरदर्शन के माध्यम से इन विभिन्न कार्यक्रमों को सुनने के साथ देख भी सकते हैं जो कि ज्यादा लोकप्रिय भी है। देश में वर्ष 1992 तक 90 प्रतिशत जनता को दूरदर्शन की सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रहा गया है वहीं दूरदर्शन के सन्दर्भ में अध्ययन प्रदेश की स्थिति काफी बदतर है। तहसील में एक भी दूरदर्शन द्रांसमीटर नहीं है। द्रांसमीटर की बात तो दूर रही लोगों के पास दूरदर्शन सेट भी उपलब्ध नहीं है। ये सुविधाएँ मात्र कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही हैं जो सम्पन्न वर्ग के हैं।

सिनेमाद्यर भी जनतं वार एवं मनोरंजन के तशक्त माध्यम हैं। वर्तमान समय में केवल एक सिनेमाद्यर तहसील के मुख्यालय पर स्थित है तथा क्षेत्र की एक सीमित जन-संख्या ही इसके द्वारा लाभान्वित हो रही है।

मुद्रण भी जनसंचार का एक प्रमुख स्तम्भ है । 12 इनमें दैनिक समाचार पत्र एनं पत्र पित्रकार ति पिति की बाती हैं । तक्कीन में बारणानी, पैवानार तका लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्र-दैनिक जागरण, जनमोर्चा, स्वतन्त्र भारत, आज तथा नवभारत टाइम्स ही पहुँच रहे हैं किन्तु अध्ययन प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कम होने के कारण लोगों में समाचारपत्रों के प्रति जागरूकता कम है ।

6. 9 संचार नियोजन

किसी क्षेत्र के विकास में संचार माध्यमों की प्रभावी भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। तहसील में इनके विकास के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं -

ा. सन् २००। तक प्रत्येक बस्ती में नियमित डाक वितरण व्यवस्था हो जानी

- चाहिए। यह सुझाव तभी प्रभावी हो सकता है जब 3 कि0मी0 की दूरी के अन्दर एक वितरण कार्यालय (Delivary Office) स्थित हो।
- 2. तहसील की प्रत्येक बस्ती में कम से कम एक पत्र पेटिका अवश्य लगायी जानी चाहिए तथा यह पत्रपेटिका शाम को प्रतिदिन खुलनी चाहिए जिससे पत्र समय से पहुँच सकें।
- 3. सार्वजनिक दूरभाषा की सुविधा प्रत्येक गाँव सभा में होनी चाहिए। बहुधा गाँवों में चोरी, डकैती, मारपीट आदि की घटनाएँ होती रहती हैं किन्तु इनकी सूचना पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में काफी विलम्ब हो जाती है। दूरभाषा के माध्यम से ऐसी सूचनाएँ शीझता से भेजा जा सकती हैं और समय रहते उन पर उचित कार्यवाही की जा सकती है। इसका उपयोग ग्राम्वासी आवश्यक सूच-नाएँ भेजने एवं ट्यापार आदि के लिए भी कर सकते हैं।
- 4. सन् 2001 तक प्रत्येक 5 कि0मी० से कम दूरी पर तारद्यर की सुविधा उपलब्ध हो जानी चाहिए।
- 5. सन् 2001 तक प्रत्येक गाँव सभा में कम से कम दो देनी विजन सेट गाँव के प्रमुख स्थानों पर लगाए जाने चाहिए जिससे अधिकाधिक जनता दूरदर्शन के कृष्टि, विक्षा तथा समाज सुधार से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को देखकर लाभान्वित हो सकें।
- 6. सिनेमाधरों के सन्दर्भ में यह सुझाव प्रस्तुत किया जाता है कि सन् 2001 तक

पूलपुर नगरीय क्षेत्र में दो तथा पवई विकासखण्ड में एक सिनेमाधर खुल जाना चाहिए जिससे लोगों को मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

7. प्रत्येक गाँव-सभा में एक वायनालय की ट्यवस्था होनी चाहिए जिससे गाँव के लोग दैनिक समाचारपत्रों एवं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से देश में हो रही ट्यं नाओं से परिचित हो सकें। जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें भी गाँव के शिक्षित ऐसे समाचार से अवगत करा सकते हैं। इनमें प्रकाशित कृष्णि, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवनोपयोगी दूसरी सूचनाओं से ग्रामीण जन काफी लाभ उठा सकते हैं। उनके बचे हुए समय का भी इससे अच्छा उपयोग हो सकेगा।

References

- Cannon, A.M.C.: New Railway Construction and the Pattern of Economic Development of East Africa, Transportation I.B.G. No. 36, June 1967, p. 21.
- 2. Berry, B.J.C.: Recent Studies Concerning the Role of Transportation in the Space Economy, A.A.A.G. Vol. 49, 1959, p. 329.
- 3. Thomas, R.L.: Transportation and Development of Malaya, A.A.A.G. Vol. 65, No. 2, June 1975, p. 279.
- 4. Quresh, M.H.: Resources and Regional Development, N.C. E.R.T. New Delhi, 1990, p. 66.
- 5. तिंह, जगदीश : परिवहन तथा व्यापार भूगोल, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लख्नऊ, 1977, पूष्ठ 48.
- 6. Pathak, R.K.: Environmental Planning Resources and
 Development, Chugh Publication, Allahabad,
 1990, p. 181.
- 7. Babu, R.: Micro Level Planning: A Case Study of Chhibramau Tahsil, Unpublished Ph.D. thesis, Geography Department, Allahabad University, 1981, p. 244.
- 8. Ibid, p. 245.
- 9. Ibid.
- पूर्वो क्त सन्दर्भ 6, पूष्ठ 56.
- 11. Parakh, Bhal Chandra, Sadashiva: India Economic Geography, N.C.E.R.T., New Delhi, 1990, p. 151.
- 12. India-1990-A Reference Annual; Ministry of Information and
 Broadcasting, Government of India, New
 Delhi.

अध्याय सात

प्रमुख सामाजिक सेवाएँ एवं उनका नियोजन

7.। प्रस्तावना

विभिन्न सामाजिक सेवाओं में प्रिक्षा तथा स्वास्थ्य जैती मूनभूत सेवाओं का विशेष महत्त्व है जिनके द्वारा ही मनुष्य का सर्वाणीण विकास सम्भव है । सामाजिक सुविधाओं से सम्बन्धित विनियोग को सामान्यतया अनुत्पादक विनियोग समझा जाता रहा है, किन्तु अब मानव की कार्यक्षमता के विकास में सहायक होने के कारण इस तरह का विनियोग अपरिहार्य, महत्त्वशील तथा उत्पादक विनियोग के अन्तर्गत गिना, जाने लगा है । सामाजिक सुविधाओं का नियोजन आर्थिक विकास का एक अनिवार्य अंग बनता जा रहा है । मानव का भौतिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धक विकास प्रिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से प्रत्यक्षतः प्रभावित है । इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतिय संविधान निर्माताओं ने प्रिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्राविधानों को नाग-रिकों के मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में समाहित किया । 2 इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार ने छठीं पंचवर्षीय योजना में संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारम्भ किया । 3 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के कम्मजेर वर्ग के लोगों को आवश्यक सामाजिक सुविधार उपलब्ध कराना है ।

प्रस्तुत अध्याय में मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सर्वप्रमुख दो आवश्यकताओं-शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को नियोजन हेतु चुना गया है । शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव के सामाजिक तथा आर्थिक विकास को इंगित करते हैं। इनके माध्यम से ही उपलब्ध संताधनों का समुचित तरी के से अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। विक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के अभाव में किसी भी राष्ट्र या देश का उत्थान सम्भव नहीं है।

इस बात में कोई सटेह नहीं है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात नियोजन के फ्लस्वरूप देश का आर्थिक विकास हुआ किन्तू वांछित गति से नहीं। हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने जिस समतावादी समाज की परिकल्पना के लिए विकास-योजनाएँ प्रारम्भ की थी उसका वास्तविक स्वरूप उभर कर सामने नहीं आया । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के चार दशकों से भी अधिक समय बीतने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं समाज के, विभिन्न वर्गों के मध्य सामाजिक तथा आर्थिक विष्यमता में कमी नहीं आयी बल्कि इसमें उत्तरे। -त्तर वृद्धि ही हुई है। आज भी गाँवों की दो तिहाई जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है जो न तो राष्ट्र और न ही समाज के हित में है। किसी भी क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए मानव शक्ति का विकास करना आवश्यक है और मानव शक्ति का सम्पूर्ण विकास शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निहित है । दुर्भाग्यवश भारत में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को त्वरित गति प्रदान करने वाली ऐसी सामा-जिक सेवाओं को योजनाओं में बहुत कम स्थान मिल पाया है। अतः प्रस्तुत अध्याय का मुख्य उद्देश्य अध्ययन-क्षेत्र के अनुकून शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के सम्यक विकास हेतु यू क्तिसंगत योजना प्रस्तुत करना है। इन सामाजिक सुविधाओं का नियो-जन प्रस्तुत करने के पहले इनके वर्तमान स्वरूप का अध्ययन आवश्यक है।

7.2 विक्षा

प्रिक्षा का वास्तविक अर्थ मनुष्य का सर्वागीण विकास करना है। वर्तमान

समय में सामाजिक, राजनैतिक, ट्यावसायिक तथा तकनीकी वातावरण में अपने को अनुकूल बनाने के लिए तथा प्राकृतिक सम्मदा व वैज्ञानिक उपल ब्यियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए मानव का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा राष्ट्र की उन्नति की भित्ति है, जनतन्त्र की नींव है, व्यक्ति के उन्नति और समाज के सुद्दी-करण का साधन है। जिस राष्ट्र की मिक्षा समन्त होगी वह राष्ट्र समुद्ध तथा शक्तिशाली होगा। व्यक्ति का विकास भान-अर्जन एवं संगय से ही सम्भव है, समाज की प्रगति तथा राष्ट्र की उन्नति इसी पर निर्भर है। वी०के० थप नियान और डी० वीं रमना के शब्दों में 'अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नवीन, आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक विधियों तथा तकनीकों का प्रयोग विक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। "4 अतः पिक्षा का भावी नियोजन कृष्ठि, उद्योग अथवा क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। विकास-प्रक्रिया का अभिन्न अंग होने के नाते नियोजन में शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी क्षेत्र के सर्वागीण विकास-हेतु नियोजन प्रस्तुत करने के पहले क्षेत्र विशेष्ठा में स्थानीय विक्षा का स्तर, विक्षण संस्थाओं की स्थानिक अवस्थिति तथा प्रौद विक्षा का प्रसार एवं निरक्षारता उनमूनन आदि तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा ।

7.3 साक्षरता

प्राकृतिक शक्तियों के नियन्त्रण एवं संरक्षण में सुट्यवस्थित एवं न्यायपूर्ण समाज का सृजन करने में शिक्षा सभी उपकरणों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । साक्षरता ही किसी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है । जिस प्रदेश की साक्षरता जितनी ही अधिक होगी वहाँ का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर उतना ही उँचा होगा। किसी देश की विकास योजनाएँ एवं प्रिक्षा नीति साक्षरता के विकास पर ही संचालित की जाती हैं। साक्षरता किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान एवं प्रजातांत्रिक स्थायित्व को आधार प्रदान करने के लिए महत्त्व-पूर्ण उपकरण हैं।

साक्षरता शब्द को विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से पारिभाषित किया गया है। भारतवर्ध में वर्ध 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षर ऐसे ट्यिक्तयों को स्वीकार किया गया जो 4 वर्ष से उमर आयु-वर्ग के हों तथा जो कम से कम साधारण पत्र लिख व पढ़ सकें। परन्तु वर्तमान समय में उक्त परिभाषा परिवर्तित कर दी गयी है। अब जो ट्यिक्त किसी एक भाषा में साधारण बातचीत को समझ, पढ़ व लिख सकें-साक्षर माने जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग ने किसी भी भाषा में साधारण सदेश को समझने के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निधारण का आधार माना है। वह ट्यिक्त जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं है। साक्षर होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सम्बन्धित ट्यिक्त ने अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त की है या निम्नतम स्तर की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है।

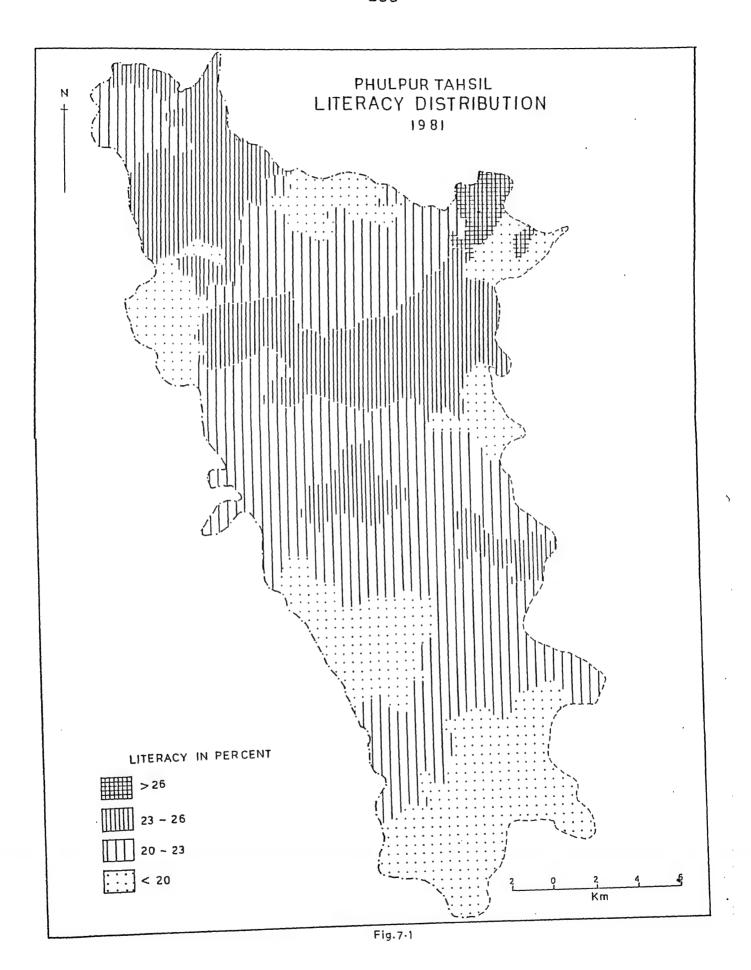
<u>सारणी ७.।</u> <u>पूनपुर तहसील में साक्षरता का प्रतिव्यत</u>

	न्याय पंचायत	कुल साक्षरता	पुरन्त	महिला
1.	मिन्तूपूर	24.72	77.88	22.12.
2.	रा मनगर	24. 43	77.78	22. 22

	न्याय पंचायत	कुल साक्षारता	पुरम	 महिला
3.	सत्तारपुर रज्जाकपुर	19.60	76.84	23. 16
4.	दो स्तपुर लहुरमपुर	22.30	85.13	14.87
5.	तुम्हाडीह	20.06	78.61	21.39
6.	बस्ती सदनपुर	23.00	78.91	21.09
7.	सुल्त ा नपुर	24. 15	78. 40	21.60
8.	सौदमा थानेशवर	22.01	77. 25	22.75
9.	बाग सिकन्दरपुर	19.84	80.60	19.40
10.	सादुल्लाहपुर मैगना	25.36	69.24	30.76
11.	अम्बारी	23.60	79.60	20. 40
12.	फ्दगु डिय ा	24. 18	72.35	27.65
13.	७ं जह ा पुर	20. 22	84. 29	15.71
14.	तजई अमानबाद	20.61	84.08	15.92
15.	बक्सपुर मेजवा	24. 83	66.85	23. 15
16.	नोनिया डीह	23.60	73.66	22. 24
17.	सदरपुर बरौनी	25.79	70.72	29. 28
18.	कनेरी	18. 26	81.20	18.80
19.	गद्दोपुर बारी	22.14	82.47	17.53
20.	पल्धी दुल्हापुर	23.50	82.34	17.66
21.	राजापुर	22.98	73.97	26. 03
22.	खरसहन क्ला	22.77	75.79	24. 21
23.	महुआ रा	20.62	68.90	31.10
24.	पुकवाल	20.71	70.56	29. 44
25.	तिकर ौ र	22.01	72.17	27.83

न्याय पंचायत	कुल साक्षरता	पुरम्ब	महिला
26. कस्बा फ्लेंडपुर	23. 64		
27. कौरा गहनी	22.60	69.87	30.13
28. पुलेश अहमद व का	17.53	80.31	19.69
29. छितर अहमद वका	19.77	78.19	21.81
30. वेलवाना	22.71	73.75	26. 25
उ।. कुरधुवा	18.78	78.69	21.31
32. जगदीशपुर ददेरिया	18.71	79.92	20, 08
33. सुरहन	20.79	78.75	21, 25
34. नसरा खुर्द	17.99	83.94	16.06
35. पारा मिश्रौलिया	28. 43	72.20	27.80
36. गनवारा	22.86	78.47	21.53
37. माहुल पनाही	20. 15	81.94	18.06
38. शमाबाद	19.15	80.85	19.15
पूनपुर तहसील	22.15	76.97	23. 03
पूनपुर तहसील ग्रामीण	21.81	76. 23	23.77
पूनपुर तहसील नगरीय	46.53	61.80	38. 20
अ ए ज म गढ	25.10	75.83	24.17
उत्तर प्रदेश	27.36	73.41	26. 59
भारत	36.17	65.34	34.66

स्रोत: जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, प्राथमिक जनगणना सार, आजमगढ़, भाग 🗷 छि। १९८१ से संगणित



तम्पूर्ण ताक्षरता की व्याख्या के आधार पर भारतवर्ध की ताक्षरता (36.17 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश की ताक्षरता (27.36 प्रतिशत) दर से अधिक है । जनपद आजगाद की ताक्षरता दर 25.10 प्रतिशत है जो देश एवं राज्य की औतत ताक्षरता दर से न्यून है । यही स्थिति अध्ययन क्षेत्र की ताक्षरता दर में भी पायी जाती है जहाँ पर मात्र 22.15 प्रतिशत व्यक्ति ही ताक्षर हैं । पूलपुर तहतील को शिक्षा की दिष्टित से पिछड़ी हुई कहा जा तकता है क्यों कि यहाँ ताक्षरता दर देश, राज्य एवं जनपद की ताक्षरता दर से अपेक्षाकृत कम है । यही स्थिति पुरुषों एवं स्त्रियों की ताक्षरता दर के तन्दर्भ में भी परिलक्षित होती है । तहतील में ताक्षरता का विवरण विक्र संख्या 7.1 में दिखाया गया है ।

यदि न्याय पंचायत स्तर पर साक्षरता का अध्ययन किया जाय तो सर्वाधिक साक्षरता (28.43 प्रतिज्ञात) पारामिश्रौ लिया में पायी जाती है । यहाँ पर साक्षरता दर अधिक होने का कारण पिक्षा की समुचित व्यवस्था तथा विद्यालयों का पास-पास स्थित होना है । किन्तु फिर भी यह देश की औसत साक्षरता दर 36.17 प्रतिज्ञात से काफी कम है । सबसे कम साक्षरता 17.53 प्रतिज्ञात फुलेश अहमद बक्श की है(सारणी 7.1) । अतः क्षेत्र के लिए पिक्षा के विकास की एक सशक्त सकारात्मक योजना की आवश्यकता है ।

7. 4 औपचारिक विद्वा का स्वरूप

अौपचारिक शिक्षा का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से लिया जाता है जिसके अन्तर्गत नियमित ढंग से शिक्षा देने वाले शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाएँ आती हैं। औपचारिक विक्षा का अध्ययन प्राथमिक विद्यालय, जूनियर बेसिक स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल शीर्धकों के अन्तर्गत किया जा रहा है। अध्ययन प्रदेश में महाविद्यालय, पालिटेक्निक तथा तकनीकी स्कूलों का अभाव है।

(।) प्राथमिक स्कूल

तहतील में वर्ष 1988 तक कुल 226 प्राथमिक विद्यालय कार्यरत थे। प्राथमिक स्कूलों का वितरण सम्पूर्ण तहतील में लगभग समान रूप से है। तहतील के कुल 495 आबाद गाँवों में 224 प्राथमिक स्कूल कार्यरत हैं, शेष्ठ दो प्राथमिक स्कूल पूलपुर नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। नगरीय क्षेत्र में एक नर्सरी स्कूल भी कार्यरत है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक स्कूलों का धनत्व प्रति हजार जनसंख्या पर मात्र 0.55 है। प्राथमिक स्कूलों का धनत्व क्षेत्र के पश्चिमी भागों में अधिक है।

वर्ष 1987-88 में जूनियर बेतिक विद्यालयों में कुल 47843 छात्र पंजीकृत थे
जिनमें 38530 छात्र तथा 9313 छात्राएँ थीं। इस प्रकार तहसील में स्कूल छात्र अनुपात
1:212 है जो राज्य के अनुपात 1:167 से अधिक है किन्तु जनपद स्कूल-छात्र अनुपात
1:278 से कम है (सारणी 7.2)। वर्ष 1987-88 में इन विद्यालयों में पिक्षकों की
कुल संख्या 736 थी जिनमें पिक्षिकाओं की संख्या मात्र 139 थी। सारणी 7.2 से
स्पष्टद है कि तहसील में स्कूल-पिक्षक अनुपात मात्र 1:3 है तथा पिक्षक-छात्र अनुपात
1:65 है जो जिले के स्कूल-पिक्षक अनुपात 1:5 से कम तथा पिक्षक-छात्र अनुपात 1:56
से अधिक है।

सारणी 7.2

फूलपुर तहसील में विद्यालयों की वर्तमान रूपरेखा, 1987-88

	18-Mg7	इ.स.च्या		म	म्कून- मिक्षक अनुपात		भिक्ष	निस्कि-छात्र अनुपात	 नुपात
विद्यालय का स्तर	राज्य	राज्य जिला	品	राज्य	जिला	गीन	तहसील राज्य	जिल Г	ਜਵਸੀਜ
।. जूनियर बेसिक स्कून	166.97	277.62 211.69	211.69	9 3 1	4.92	3.26	ت الله الله	56.46 65.00	65. 00
2. सी नियर बेसिक हकून	166.37	236.72	245.27	5.41 6.76	92.9	6.30	30.70	35.02	38.95
3. ៩೯೮೪ ಕಿಶಿಂತರ್ ಕಥ್ಗ	769.20	850.15	850.15 716.22 22.01 29.34	22.01	29.34	21.94	34.93	28.41	32.64
	8 8 8 8 8	 	! ! ! !	1 1 1 1	 	; ; ; ;	1 1 1 1	1 1 1 1 1	8 8 1 1
अन्० = अन्पलन्दा									

(2) सां खियकीय पत्रिका, जनपद-आजमगढ, 1989 से संगिणित

स्रोत : (१) उत्तर प्रदेश वार्धिकी 1987-88, निदेशक, सूचना स्वंजनसम्मकं विभाग, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी गाँव से जूनियर बेसिक स्कूलों की दूरी 1.5 कि0मी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए । तहसील में कुल 49.90 प्रतिश्चात बस्तियों के बच्चों को गाँव में या । कि0मी0 से कम दूरी पर स्कूल उपलब्ध हैं । 45.06 प्रतिश्चात बस्तियों के बच्चों को । से 3 कि0मी0 की दूरी तय करने के बाद तथा 5.04 प्रतिश्चात बस्तियों के बच्चों को 3 से 5 कि0मी0 की दूरी तय करने के पश्चात् जूनियर बेसिक स्कूल उपलब्ध हो पाते हैं ।

(2) सी नियर बे सिक स्कूल

अध्ययन क्षेत्र में कुल 37 सी नियर बेसिक स्कूल 1987-88 में कार्यरत थे जिनमें बालकों के 30 तथा बालिकाओं के 7 स्कूल समाहित हैं। इन स्कूलों का वितरण पूरे तहसील में लगभग समान रूप से हैं (चित्र संख्या 7.2)। जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1989 के अनुसार वर्ष 1987-88 में इन विद्यालयों में कुल 9075 विद्यार्थी पंजीकृत थे जिनमें छात्रों की संख्या 7705 तथा छात्राओं की संख्या 1370 थी।

तह्तील में ती नियर बेतिक विद्यालयों में स्कूल-धात्र अनुपात ।:245 है जो जिले एवं राज्य के अनुपात क्रम्झः ।:237 एवं ।:166 से अधिक है । इन विद्यार्थियों के अध्यापन में 233 विद्वाक कार्यरत हैं जिनमें विद्वाक्षियों की संख्या 63 है । तह्तील में स्कूल-विद्वाक अनुपात ।:6 है जो जिले के अनुपात ।:7 से कम एवं राज्य के अनुपात ।:5 से अधिक है । तह्तील में विद्वाक-विद्वार्थी अनुपात ।:39 है जो जिले के 1:35 तथा राज्य के 1:31 अनुपात से अधिक है (सारणी 7.2) ।

सामान्य तौर पर सीनियर बेसिक विद्यालयों की दूरी किसी भी गाँव से 5 कि0मी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बालकों के विद्यालयों के सन्दर्भ में यह अभिगम्यता कुछ ठीक कही जा सकती है। जिला सांख्यिकीय पित्रका 1989 के अनुसार तहसील में 49.9 प्रतिव्ञात बिस्तियों के बच्चों को गाँव में या। कि0मी0 से कम दूरी पर सीनियर बेसिक विद्यालय उपलब्ध हैं जबिक 45.06 प्रतिव्ञात बिस्तियों के बच्चों को। से 3 कि0मी0 तथा 15.04 प्रतिव्ञात बिस्तियों के बच्चों को 3 से 5 कि0 मी० की दूरी तय करनी पड़ती है। बालिकाओं के विद्यालयों के सन्दर्भ में विद्यालयों की अभिगम्यता ठीक इसके विपरीत है। तहसील में 3.03 प्रतिव्ञात बिस्तियों की बालिकाओं को गाँव में या। कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध हैं। 19.6 प्रतिव्ञात बिस्तियों की बालिकाओं को त से 5 कि0मी0 तथा 17.57 प्रतिव्ञात बिस्तियों की बालिकाओं को 3 से 5 कि0मी0 की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध हैं। को 59.80 प्रतिव्ञात बिस्तियों की बालिकाओं को 5 कि0मी0 से अधिक दूरी विद्याल हेता विद्याल करनी पड़ती है।

(3) हायर मेकेण्डरी स्कूल

हायर सेकेण्डरी स्कूलों में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों को सिम्मिलत किया गया है। वर्ष 1987-88 के आकड़ों के अनुसार तहसील में कुल 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल कार्यरत थे जिनमें बालिका विद्यालयों की संख्या मात्र एक जो हाई स्कूल है अम्बारी (पवई विकासखण्ड) में स्थित है। तहसील में हाई स्कूल विद्यालयों की संख्या 6 तथा इण्टरमीडिएट कालेजों की संख्या 12 है। तहसील के सभी हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज ग्रामीण अंवलों में ही स्थित हैं। पूलपुर नगरीय क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल अथवा इण्टरमी डिएट कालेज नहीं है। जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1989 के अनुसार इन विद्यालयों में कुल 12892 विद्यार्थी पंजीकृत थे जिनमें बाल्किकाओं की संख्या 739 तथा बालकों की संख्या 12153 थी। हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के सन्दर्भ में स्कूल छात्र अनुपात 1:716 है जो जिला एवं राज्य के अनुपात क्रम्या: 1:850 तथा 1:769 से अच्छी स्थिति में है (सारणी 7.2)। इन विद्यालयों में कुल 395 विद्याल कार्यरत हैं जिनमें विद्यालयों की संख्या मात्र 13 थी। तहसील में स्कूल-विद्याल अनुपात 1:22 है जो जनपदीय विद्याल 1:29 से कम तथा राज्य विद्याल अनुपात 1:22 के बराबर है। तहसील में विद्याल विद्याल विद्याल 1:33 है जो जिले के अनुपात 1:28 से अधिक तथा राज्य विद्याल विद्याल 1:35 से कम है (सारणी 7.3)।

हायर सेकेण्डरी विद्यालय किसी भी बहती से 8 कि0मी0 से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। इस सन्दर्भ में तहसील की स्थिति संतोष्ठानक कही जा सकती है। बालकों के सन्दर्भ में 8.48 प्रतिष्ठात बह्तियों के छात्रों को तथा 0.20 प्रतिष्ठात बह्तियों की छात्राओं को। कि0मी0 से कम दूरी पर स्कूल उपलब्ध हैं। 23.85 प्रतिष्ठात बह्तियों के छात्रों तथा 5.86 प्रतिष्ठात बह्तियों की छात्राओं को। से 3 कि0मी0 की दूरी पर यह सुविधा उपलब्ध है। 18.38 ४ बह्तियों के छात्रों तथा 4.85% बह्तियों की छात्राओं को 3 से 5 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। 49.29 प्रतिष्ठात बह्तियों के छात्रों तथा 89.09 प्रतिष्ठात बह्तियों की छात्राओं को 5 कि0मी0 से अधिक दूरी चलकर हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राप्त होते हैं।

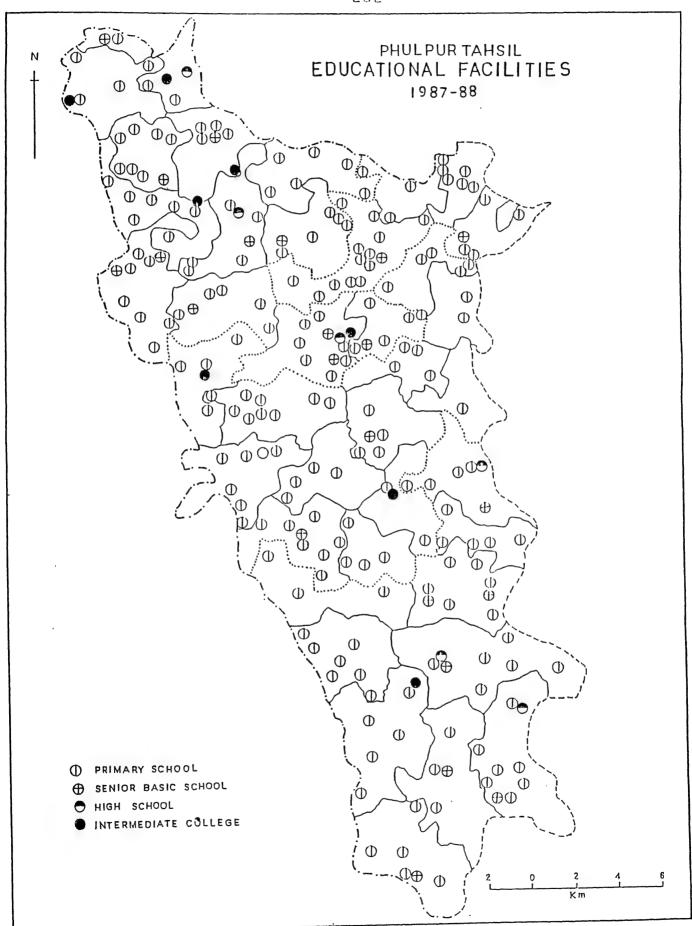


Fig 7.2

(4) उच्च प्रिक्षा केन्द्र, पालिटेक्निक तथा तकनीकी प्रिक्षण संस्थान

तहसील में महाविद्यालय, पालिटेक्निक तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का अभाव है। महाविद्यालय न होने से क्षेत्र में उच्च शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। तकनीकी शिक्षा के अभाव में क्षेत्र का वांछित विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः तहसील में महाविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की महती आव-श्यकता है।

7.5 अनौपचारिक विक्षा

सभी नागरिकों को राष्ट्रीय विकास में समान रूप से सहभागी बनाने के लिए सरकार ने विक्षा के अन्तर्गत प्रौट विक्षा का एक विव्रद कार्यक्रम तैयार किया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साक्षरता स्तर में वृद्धि तथा सामाजिक चेतना को जागृत करना है । स्वैच्छिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा विक्षितों के योगदान द्वारा इस कार्यक्रम को गति मिली है । नई राष्ट्रीय विक्षानीति के निर्देशों के अनुसार सरकार ने प्रौट विक्षा का 'राष्ट्रीय साक्षरता मिन्नन' नामक एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है जिसका उद्देश्य ।5 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना है । जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1989 के आकड़ों के अनुसार यद्यपि जनपद के 459 ग्रामों के 900 केन्द्रों पर प्रौट विक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है किन्तु खेद का विषय है कि पूत्रपुर तहसील के किसी भी बस्ती में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

7.6 वर्तमान विधा की समस्याएँ

किसी भी देख्न या प्रदेश के लिए शैक्षिक नियोजन प्रस्तुत करने के पहले उस

क्षेत्र में ट्याप्त शैक्षिक समस्याओं का आकलन अति आवश्यक है जिससे भावी योजना में उनका निदान एवं निराकरण किया जा सके। अध्ययन क्षेत्र में ट्याप्त शिक्षा की कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं -

- सम्प्रति अधुनिक विद्वा पद्धति की सबसे प्रमुख समस्या विद्वा का स्तरीय द्वास है । यह ऐसे छात्र-छात्राओं को जन्म दे रही है जिनकी अभिरुचि विद्वा की तरफ नहीं है । उनका प्रमुख उद्देश्य किसी प्रकार परीक्षा उत्तीर्ण करना है जिससे कि क्षेत्र में नकल की समस्या विकराल रूप धारण करती चली जा रही है । इसके लिए अभिभावक, विद्वाक तथा विद्वार्थी सभी समान रूप से उत्तर-दायी हैं ।
- 2. प्रदेश के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि विद्यालयों में प्रवेश के समय छात्रों से अनेक तरह के शुल्क लिए जाते हैं जिससे अभिभावकों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
- उ. प्रदेश के 35 प्रतिशत से अधिक जूनियर बेसिक स्कूल आवासीय समस्या से प्रसित हैं। इन विद्यालयों के छात्र छुने आसमान या वृक्षों के नीचे या झोपड़ियों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्षा के दिनों में इन झोपड़ियों से रिसकर पानी जमीन पर आने लगता है और विद्यालय बन्द कर दिये जाते हैं। इसके अति-रिक्त उन्हें पीने का पानी, टाटपदिट्याँ तथा ब्लैक बोर्ड आदि प्राथमिक सुविधाएँ भी उपलब्धा नहीं हैं।
- 4. अध्यापकों को कक्षाओं में पढ़ाने में रुचि नहीं है। अधिकांश अध्यापक छर

पर ही द्यूशन करते हैं या किसी को चिंग से सम्बद्ध हैं और छात्रों को द्यूशन या को चिंग में पद्धने के लिए बाध्य करते हैं।

- 5. जूनियर बेतिक स्कूलों के अध्यापक विद्यालय के निकट के ग्राम के होते हैं जिससे वे तमय से विद्यालय नहीं आते हैं और अपने हारेलू कार्यों में लगे होते हैं।
- 6. सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ है कि बहुत से विद्यालयों में सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का सही दंग से उपयोग नहीं हो रहा है।
- 7. ग्रामीण अंचलों में बालिका विद्यालय न होने से बालिकाओं की विक्षा बाधित हो रही है।
- वर्तमान विक्षा में रोजगारपरक ट्यावसायिक विक्षा का पूर्णतः अभाव है।
 इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर हो रही बृद्धि है।
- 9. प्रदेश के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि हार्ड स्कूल तक आते-आते छात्रों का एक बड़ा समूह विद्यालय छोड़ देता है। कुछ संस्थाओं के प्राचार्यों के साथ साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि कक्षा । से 10 तक आते-आते लगभग 50 प्रतिशित छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं।

अतः विकास के लिए विकास पद्धति में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। स्कूलों में अध्ययन कक्षाें एवं अध्यापकों में वृद्धि, रोजगार परक व्यावसायिक विक्षा, मेधावी एव निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने, छात्रों को

विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ने से रोकने की महती आवश्यकता है। विद्यालयों में सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान का अधिकतम एवं उचित ढंग से उप-योग तथा प्रभावी अनुशासन की भी आवश्यकता है।

7.7 विद्यालयों का शैक्षाणिक एवं स्थानिक स्तर

पिक्षण-पिक्षार्थी अनुपात का अभी तक कोई अभीष्ट मापदण्ड तय नहीं किया जा सका है किन्तु पिक्षाविदों द्वारा भारत के सन्दर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में पिक्षक छात्र अनुपात कम से कम 25 तथा अधिकतम 40 से 50 उचित बताया गया है । इसी प्रकार सेकेण्डरी विद्यालयों के लिए यह अनुपात 20 से 30 तक निर्धारित किया गया है । राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय किसी भी बस्ती से 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए जबकि मिडिल स्कूल की अधिकतम दूरी 5 कि0 मी0 तथा हाई स्कूल विद्यालयों की दूरी 8 कि0मी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए 18

किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का शैक्षणिक नियोजन प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीय या राज्य के मानक स्तरों को सदैव आधार स्वरूप नहीं रखा जा सकता है किन्तु इन मानक स्तरों की पूर्णत्या अवहेलना भी नहीं की जा सकती । किसी भी क्षेत्र का खिक्षणिक मानक स्तर उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। अतः राष्ट्रीय एवं राज्य के मानकों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सारणी 7.3 में पूलपुर तहसील के लिए शैक्षणिक मापदण्डों का निधारण किया गया है । शिक्षण संस्थाओं की अवस्थित के सद्धर्भ में एक उचित मापदण्ड होना चाहिए । पूलपुर तहसील में इस अवस्थितिक मापदण्ड का निधारण शैक्षिक इकाईयों की कार्यात्मक

सारणी 7.3 पूनपुर तहसील के लिए शैक्षाणिक मापदण्ड

विद्यालय का स्तर	विक्षि-छात्र अनुपात	स्कून-छात्र अनुपात
 जूनियर बेतिक स्कूल सीनियर बेतिक स्कूल 	1:35 1:25	1:150
उ. हायर सेकेण्डरी स्कूल	1:20	1:120

रिक्तता को ध्यान में रखते हुए बहितयों की जनसंख्या, परिवहन के साधनों की सूलभता तथा उनकी विशिष्ट जनसंख्या आधार के सन्दर्भ में किया गया है । इस प्रकार कोई भी जूनियर बेसिक विद्यालय किसी भी बहती से 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए । सीनियर बेसिक विद्यालयों की दूरी किसी भी बहती से 4 कि0मी0 से अधिक तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के सन्दर्भ में यह दूरी 6 कि0मी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

7.8 वैक्षाणिक नियोजन

किसी प्रदेश का शैक्षाणिक नियोजन क्षेत्र में उसके वर्तमान स्वरूप एवं भविष्य में उसकी आवश्यकता पर निर्भर है। तहसील में शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन पीछे किया जा चुका है तथा भावी आवश्यकता का परिकलन बद्धती हुई जनसंख्या एवं तहसील के शैक्षाणिक मापदण्डों के आधार पर किया जा सकता है। अतः तहसील की भावी जनसंख्या का अनुमान लगाना आवश्यक हो जाता है जिससे छात्रों की बद्धती हुई संख्या के सन्दर्भ में शैक्षाणिक सुविधाओं का नियोजन प्रस्तुत किया जा सके।

(।) जनसंख्या प्रदेशिण एवं छात्रों की भावी संख्या

कोई सावधि नियोजन किसी क्षेत्र के विकास में तभी प्रभावी हो सकता है जब उसके निर्माण में क्षेत्र की भावी जनसंख्या वृद्धि को भी ध्यान से रखा जाय । किसी प्रदेश के भावी जनसंख्या वृद्धि के अनुमान को जनसंख्या प्रक्षेषण के नाम से जाना जाता है । विभिन्न विद्वानों ने जनसंख्या प्रक्षेषण सामान्य रूप से आयु समूह संख्वा, पिछली जनमदर एवं मृत्यूदर आदि आधारों पर किया है किन्तु किसी प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है । जनसंख्या-आकार परिवर्तन मात्र जनमदर एवं मृत्युदर पर ही आधारित नहीं होता है बल्क जनसंख्या प्रवास भी जनसंख्या के आकार परिवर्तन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं । वहसील के जनसंख्या प्रक्षेपण में उक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी ध्यान में रखा गया है –

- (क) जनसंख्या प्रक्षेपण में तहसील की औसत जनसंख्या वृद्धि को सभी विकासखण्डों के लिए आधार माना गया है।
- (छ) इस बात को भी ध्यान में रह्या गया है कि समय के साथ लोग परिवार-नियोजन के विभिन्न 'साधनों का प्रयोग करेगें किन्तु जनसंख्या वृद्धि वर्तमान दर से चलती रहेगी।

(ग) जनसंख्या वृद्धि चक्रवृद्धि दर से होगी।

जनसंख्या प्रक्षेपण में सर्वप्रथम जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की गणना की गयी है। वर्ष 1951 की जनगणना को आधार वर्ष तथा 1981 की जनगणना को अन्तिम वर्ष की जनसंख्या के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह गणना गिब्स 10 द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सूत्र से की गयी है -

$$r = \frac{(P_2 - P_1)/t}{(P_2 - P_1)/2} \times 100$$

जहाँ म = वार्षिक औसत वृद्धि दर

P₁ = प्रारम्भिक जनसंख्या आकार

P2 = अन्तिम जनसंख्या आकार

t = सम्याविध

उपर्युक्त सूत्र द्वारा गणना करने पर तहसील की औसत वार्षिक वृद्धि दर । 54 प्रतिशत आती है । पुन: सभी विकासखण्डों की वर्ष 200। तक की भावी जनसंख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की गयी है । -

$$A = P(1 + \frac{r}{100}) t$$

जहाँ A = प्रक्षेपित जनसंख्या

p = वर्तमान जनसंख्या

t = वर्तमान जनसंख्या तथा प्रद्वोपित जनसंख्या के बीच की अविधि

r = औसत वार्धिक वृद्धि दर

वर्ष 200। तक तहसील की जनसंख्या बद्धकर 492524 हो जाने का अनुमान है जिनमें नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 6985 तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 485539 हो जाने की संभावना है (दे0 सारणी 7.4)।

सारणी 7.4 पूनपुर तहसील में वर्ष 2001 में संभावित जनसंख्या

	विकासखण्ड	जनसङ्या, वर्ष ।९८।	जनसंख्या 200। तक
1.	पवर्ड	110683	150528
2.	पूलपुर	104186	141693
3.	मा टिंनगंज	102486	139381
4.	अहरौला(1)	39660	. 53937
		Mil 400 Mil 400 Mil 400 Mil 500 Mil 50	
	पूलपुर नगरीय क्षेत्र	5136	6985
	तहसील की कुल जनसंख्या	362150	49 25 24

आयु की तरंचना के अन्तर्गत छात्रों की तंख्या तम्बन्धी आबड़े अप्राच्य होने ते विद्यालयों के स्तर के अनुसार भावी छात्र तंख्या का अनुमान लगाना किठन हो गया है। विद्यालयों के स्तर में केवल जूनियर बेतिक स्कूल, तीनियर बेतिक स्कूल तथा हायर ते केण्डरी स्कूलों को तिम्मिलत किया गया है। वर्ष 200। तक जूनियर बेतिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कुल जनतंख्या का 13.2। हो जाने का अनुमान है। तीनियर बेतिक स्कूल तथा हायर ते केण्डरी स्कूलों के तम्बन्ध में यह अनुमान क्रमा: 0.03 प्रतिशत तथा 3.56 प्रतिशत का है।

(2) विद्यालय स्तर के अनुसार नियोजन

सारणी 7.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 200। तक जूनियर बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 65066 हो जाने का अनुमान है। बढ़े हुए छात्रों के लिए 208 नये स्कूलों तथा 1123 नये अध्यापकों की आवश्यकता होगी। सीनियर बेसिक स्कूलों में 3353 नये छात्रों के बढ़ने का अनुमान है जिसके लिए 68 अतिरिक्त स्कूलों तथा 274 नये अध्यापकों की आवश्यकता होगी। हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 4641 अतिरिक्त विद्यार्थियों के बढ़ने की संभावना है जिनके लिए 32 नये स्कूलों तथा 482 नये अध्यापकों की ट्यवस्था करनी होगी।

<u>सारणी 7.5</u> विद्यालयों की भावी रूपरेखा, वर्ष 2001

विद्यालय का स्तर	वर्तमा न	7 मुख्य 200 200 यु	अ ति रिक्त वृद्धि		न्य े 1002 कुष्ट	E .	वर्तमान न	वर्ष 200 वर्ष	अतिरिक्त
 जूनियर बेतिक स्कूल सीनियर बेतिक स्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूल 	9313	65066 12666 17533	3353	37	105	68	233	507	•

(क) जुनियर बेसिक स्कूल

तम्पूर्ण तह्तील में वर्तमान तमय में 226 जूनियर बेतिक स्कूल कार्यरत हैं ज़िनका वितरण तह्तील में लगभग तमान रूप से है । भावी जन्तंख्या के विकास के साथ छात्रों के उचित प्राथमिक विकास के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वर्ष 200। तक 208 नये रुकूल और खोले जायं जिनमें 5 पूलपूर नगरीय क्षेत्र में तथा 203 रुकूल ग्रामीण अंचलों में रिथत होने चाहिए। अतः वर्ष 200। तक प्रत्येक बस्ती में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय अवश्य खुल जाने चाहिए।

(ख) सी नियर बेसिक स्कूल

तारणी 7.3 में दिये गये मानकों के सन्दर्भ में छात्रों की भावी संख्या में वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2001 तक 68 नये विद्यालय खोले जाने चाहिए जिनमें नगरीय क्षेत्र में 2 तथा 66 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हों। सीनियर बेसिक स्कूलों की कार्या- तमक रिक्तता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो अतिरिक्त विद्यालय वर्ष 2001 तक अवश्य खुल जाने चाहिए।

(ग) हायर सेकेण्डरी स्कूल

छात्रों की बद्रती हुई संख्या तथा तहसील में अपनाये गये मापदण्डों के अन्तर्गत वर्ष 200। तक कुल 32 अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता होगी। इनमें 18 हाई स्कूल तथा 14 इण्टरमी डिस्ट कालेज छोले जाने चाहिए। 14 इण्टरमी डिस्ट कालेजों में । पूलपुर नगरीय क्षेत्र में तथा 13 ग्रामीण अंचलों में छोले जाने चाहिए। 13 ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में से 5 विद्यालय बालिकाओं की विक्षा के लिए होने चाहिए। इन अतिरिक्त विद्यालयों की अवस्थिति चित्र संख्या 7.3 में देखी जा सकती है।

(घ) उच्च पिक्षा केन्द्र

सम्प्रति तहसील में एक भी महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण वर्तमान समय

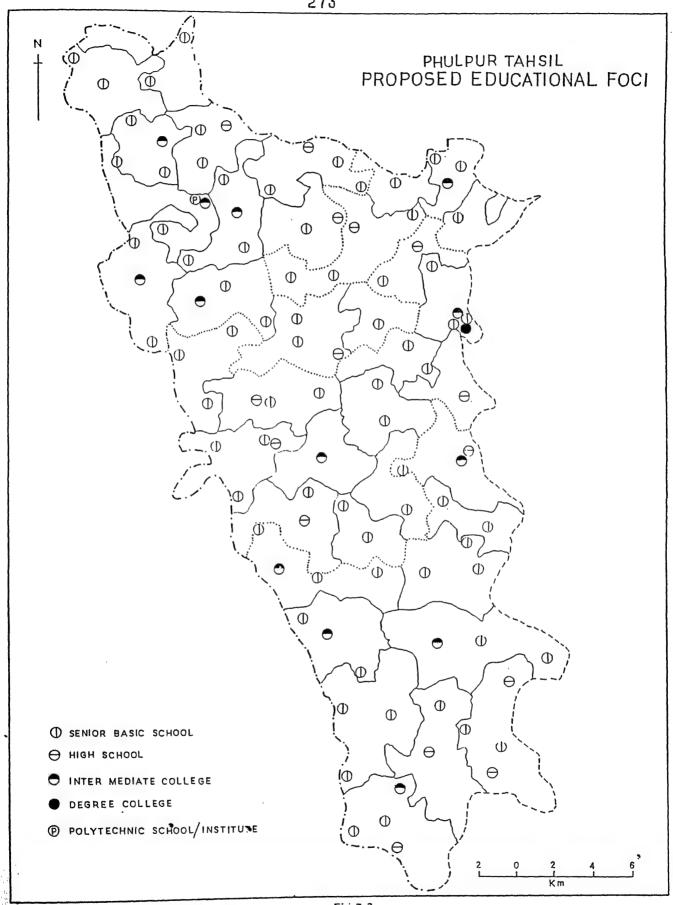


Fig.7-3

में उच्च हिशा पूर्णतः बाधित हो रही है। उच्च हिशा प्राप्त करने हेतु छात्रों को दूर-दूर महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता है। अतः कार्यात्मक रिक्तता तथा भावी छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पूलपुर नगरीय क्षेत्र में वर्ष 200। तक एक महाविद्यालय अवश्य छुल जाना चाहिए।

(इ) तकनीकी पिक्षण संस्थान

पूलपुर तहसील में तकनीकी विक्षण संस्थाओं का पूर्णतया अभाव है। इसके लिए छात्रों को आजमगढ़ या फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में जाना पड़ता है जहाँ पर ये संस्थान अवस्थित हैं। अत: तहसील में औद्योगीकरण तथा कृष्य के विकास के लिए वर्ष 200। तक एक तकनीकी विक्षण संस्थान पवई विकासखण्ड में खोला जाना चाहिए। क्यों कि पवई विकासखण्ड सड़क मार्गों द्वारा अन्य क्षेत्रों से सम्बद्ध है तथा यहाँ अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

(च) अनौपचारिक शिक्षा

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार तहसील की 77.85 प्रतिष्ठात जनसंख्या
अशिक्षित है । अतः तहसील की साक्षरता में वृद्धि करने हेतु अनौपचारिक विक्षा दिये
जाने की महती आवश्यकता है । दुर्भाग्यवश तहसील के किसी भी बस्ती में अभी तक
ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । अनौपचारिक विक्षा में प्रौद्ध महिलाओं की
विक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिर क्यों कि तहसील में 1981 की जनगणना के
अनुसार 89.86 पृतिष्ठात महिलार अशिक्षित हैं । नारी विक्षा के सम्बन्ध में महात्मा
गाँधी का विचार उल्लेखनीय है - "यदि आप एक पुरुष्ठा को शिक्षित करते हैं तो एक
व्यक्ति को शिक्षित करते हैं । यदि एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार

को शिक्षित करते हैं।" क्षेत्र के सार्थक शैक्षाणिक विकास के लिए गाँधीजी के इन विचारों का सही अथों में क्रियान्वयन होना चाहिए। साथ ही साथ प्रौद्ध शिक्षा व्यवसायपरक होनी चाहिए। 15 से 35 वर्ष के अशिक्षित युवक कृष्ठकों को जल्दी पकने वाली तथा उच्च उत्पादकता वाली पसलों, उर्वरकों के प्रयोग, पसल चक्र तथा कृष्ठि यन्त्रों के प्रयोग से सम्बन्धित शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इसी आयु वर्ग की महिलाओं को बच्चों के पोष्णण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी, पीने के पानी की स्वच्छता तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब वर्ष २००। तक लगभग प्रत्येक बस्ती में एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाय।

7.9 स्वास्थ्य सेवार

स्वास्थ्य सेवाओं से तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो मनुष्य को स्वस्थ,
रोगरहित एवं सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायक होती हैं। ये सुविधाएँ किसी
भी प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड हैं। व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता उसके स्वास्थ्य
में ही निहित हैं। स्वस्थ मनुष्य ही समाज की आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति में
सहायक हो सकते हैं। इसी लिए कहा गया है कि 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि का
निवास होता है'। इसी लक्ष्य को केन्द्रबिन्दु मानकर कल्याणकारी राज्यों ने मानव
स्वास्थ्य के लिए अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया। भारत सरकार
की 1978 की 'अलमा अता' छोष्णा के अनुसार 'सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य
के लक्ष्य को पूरा करने का राष्ट्रीय संकल्य लिया गया है। 12 सातवीं पंचवधींय
योजना में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का प्रसार इसी उद्देश्य

के साथ किया गया था। 13 किन्तु सातवीं पंचवधींय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं हो सका। अतः आठवीं पंचवधींय योजना में भी इन कार्यक्रमों को सफल बनाने का उद्देश्य रखा गया है। किसी भी क्षेत्र की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं का नियोजन प्रस्तुत करने से पहले उस क्षेत्र की वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं का आकलन करना आवश्यक हो जाता है।

7. 10 स्वास्थ्य सुविधाओं का वर्तमान प्रतिरूप

वर्तमान समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के मुख्य आधार मातृ- विश्वा कल्याण केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय / औष्ट्रधालय तथा पंजीकृत व्यक्तिगत क्लीनिक आदि हैं। सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1990 के अनुसार तहसील में वर्ष 1988-89 में कुल चिकित्सालयों/औष्ट्रधालयों की संख्या 10 थी जिनमें। एलोपैथिक, 2 यूनानी, 3 आयुर्वेदिक तथा 3 होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के हैं। तहसील में कुल 20 डाक्टर हैं जिनमें 12 एलोपैथिक, 3-3 आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक तथा 2 यूनानी चिकित्सा के डाक्टर हैं। समस्त उपलब्ध शैष्याओं की संख्या 133 हैं जिनमें 106 शैष्याएं एलोपैथिक चिकित्सा की हैं। यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा की 12-12 तथा होम्योपैथिक चिकित्सा की 3 शैष्याएं हैं। तहसील में सामुदायिक केन्द्रों का अभाव है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की कुल संख्या 15 है जिनमें उपलब्ध शैष्याएं 106 तथा कार्यरत चिकित्सकों की संख्या 12 है। तहसील में परिवार एवं मातृ-शिष्ट्रा कल्याण केन्द्रों की संख्या 4 तथा उपकेन्द्रों की संख्या 87 है। इसके बावजूद अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। तहसील में प्रतिलाख जनसंख्या पर

चिकित्सालयों अधिधालयों का अनुपात मात्र 2.76 है जबकि राज्य का अनुपात 6.5 है । 14 जहाँ राज्य में औसतन प्रति 4000 जनसंख्या पर एक चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध है वहीं तहसील में एक चिकित्सक पर 18108 व्यक्ति आते हैं । कुल उपलब्ध शैय्याओं का अनुपात प्रति 1000 व्यक्ति पर 0.37 है जबकि राष्ट्रीय औसत 0.72 है । 15

7. ।। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यद्यपि स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया गया फिर भी ग्रामीण क्षेत्र पूर्णत्या उपेक्षित रहे हैं। सरकार ने आयु-वेंदिक, सिद्ध, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा अन्य गैर रलोपैधिक उपचार पद्धतियों की उपेक्षा कर पश्चात्य पद्धति पर स्थापित स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ही सीमित मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया। फताः रलोपैधिक चिकित्सा पर निर्भरता धीरे-धीरे बद्धती गयी तथा परम्परागत स्वास्थ्य सुविधाएँ पूर्णत्या उपेक्षित रहीं। 1970 के दशक में हरिजनों द्वारा चलाए गये 'जच्चा-बच्चा सेवा बहिष्कार' अभियान के परिणामस्वरूप गाँवों में सरकार ने समन्वित ढंग से मान्-विश्वा कल्याणकेन्द्रों का एक सुविधाविहीन ढाँचा छहा किया। 16 वर्तमान समय में क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लोगों को सामान्य रोगों के लिए भी कस्बों एवं शहरों में जाना पड़ता है क्योंकि सामान्यत्या ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल नहीं उपलब्ध हैं, यदि कहीं हैं भी तो उसमें कुश्न डाक्टर नहीं हैं। तहसील में ग्रामीण स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं -

- तहसील के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इन क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केन्द्र कार्य भी कर रहे हैं वे उपेक्षा के विकार हैं। ग्रामीण अंचलों के इन केन्द्रों पर कोई भी चिकित्सक रहना पसन्द नहीं करता है।
- तहसील में यद्यपि पर्याप्त रूप से खाद्यान्न, साग-सब्जी, दूध-फ्ल आदि उपलब्ध हैं किन्तु उचित ढंग से प्रयोग न होने के कारण लोगों को अपेक्षित संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है जिससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है।
- गाँवों के मकानों में गन्दे पानी के निकास की कोई उचित व्यवस्था नहीं हैं। नालियों के अभाव में नापदान का गन्दा पानी गलियों में जगह-जगह इक्द्ठा होकर सड़ता रहता है जिसमें मच्छर एवं अन्य कीटाणु पनपते हैं तथा अनेक संकामक रोगों का कारण बनते हैं।
- 4. गाँवों के मकानों में वातायन की व्यवस्था बहुत ही कम देखने को मिलती है।

 रसोई में खाना पकाते समय वातायन के अभाव में धुआँ बाहर नहीं निकल

 पाता है जो घरेलू महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है।
- 5. तहसील में पेय जल के साधनों में कुआ तथा हैण्डपम्म हैं। कुए बिल्कूल छुलें हैं। उनमें पेड़ों की पित्तिया गिरकर सड़ती रहती हैं तथा वर्षा का पानी भी जाता है जिससे लोगों को दूषित पानी प्राप्त होता है जो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वर्षभर में कभी भी कुओं में लाल दवा आदि नहीं डाली जाती है, न ही उनकी सफाई की जाती है।

हैण्डपम्प यद्यपि इन समस्याओं से परे हैं किन्तु जल निकास की उत्तम व्यवस्था न होने से जगह-जगह जल भराव की समस्या बनी रहती है।

- 6. तहसील के ग्रामीण अंचलों में शौंचालयों का नितान्त अभाव है। बहुधा लोग शौंच के लिए बाहर ही जाते हैं। शौंचालयों के अभाव में गाँव के किनारेकिनारे शौंच के कारण वातावरण प्रदूषित हो जाता है एवं अनेक बीमारियों को जनम देता है।
- 7. सरकार ने गाँवों में बच्चा पैदा कराने के लिए परम्परागत अप्रशिक्षित दाइयों की जगह प्रशिक्षित नहों की नियुक्ति कर दी है। किन्तु पर्याप्त उपकरणों एवं प्रसवगृह के अभाव में इन नहों (Midwifes) की कार्यक्षमता पर प्रश्न- चिह्न लगता जा रहा है।
- 8. अध्ययन क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के देखरेख और उनके पौदिदक आहार की समस्या बहुत ही गम्भीर है। यहाँ तक कि अधिकांश गर्भवती महिलाओं को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है, पौदिदक आहार की बात तो दूर रही।
- 9. इसके बावजूद जो बच्चे माँ के गर्भ से स्वस्थ जन्म नेते हैं वे भी कुपोषण, पौष्टिदक आहार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में रोग-ग्रस्त हो जाते हैं।

तहसील में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों-बुखार, खाँसी, चेचक, कालरा, चर्मरोग, कुठ रोग, इन्फ्लूएन्जा,

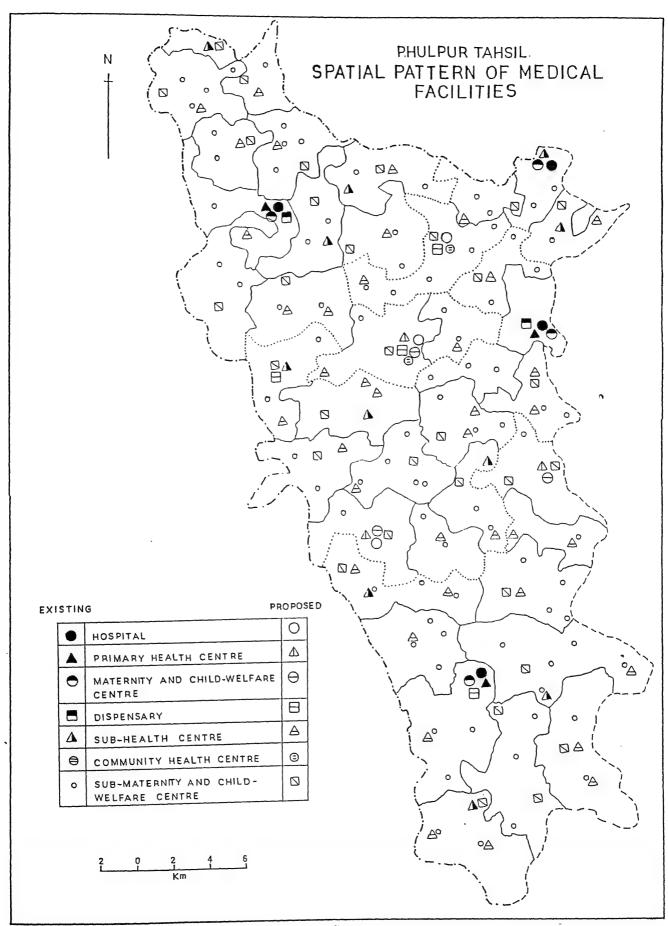


Fig.7.4

मलेरिया, फाइलेरिया आदि के शिकार हो जाते हैं। इलाज के अभाव में इनमें से कुछ बीमारियों के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अतः इन बीमारियों की रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु समन्वित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है।

7.12 चिकित्सा सुविधाओं का सामान्य मापदण्ड

सातवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं में प्रसार एवं उसके सुदृद्धीकरण तथा 'सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य' की राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में ही तैयार की गयी । तत्कालीन स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 आबादी के पीछे एक उपकेन्द्र तथा एक मानृ विश्वा कल्याण केन्द्र, 3000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10,000 आबादी के पीछे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना है । 17 किन्तु इस मानक स्तर पर तहसील चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ी हुई है । यहाँ 25000 आबादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है । मानृ एवं विश्वा कल्याण केन्द्रों के सन्दर्भ में तहसील की स्थिति कुछ संतोष्ट्यनक कही जा सकती है । मुख्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों को मिनाकर लगभग 4000 जनसंख्या के पीछे एक मानृ विश्वा कल्याण केन्द्र कार्यरत है । तहसील में सामुद्रायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव है । यहाँ पर अभी तक एक भी सामुद्रायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत नहीं है ।

7. 13 स्वास्थ्य सेवाओं का नियोजन

तहसील में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की अपर्याप्तता को.

देखते हुए इनके समुचित विकास हेतु एक सकारात्मक नियोजन की आवश्यकता है, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को सन् 2000 तक प्राप्त किया जा सके । इसके सन्दर्भ में स्वास्थ्य सुविधा सम्पन्न केन्द्रों की संख्या और उनकी भावी स्थिति का नियोजन राष्ट्रीय मापदण्डों के तहत उनकी कार्यात्मक रिक्तता, अवस्थिति एवं परिवहन सुविधा के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

तह्मील में सन् 200। तक 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 6 औष्ट्रधालयों/ चिकित्सालयों, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 120 उपकेन्द्रों, 7 मुख्य मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों सहित 120 उपकेन्द्रों के खोले जाने की आवश्यकता है । इनकी स्था-निक अवस्थितियाँ चित्र संख्या 7.4 में प्रदर्शित की गयी है ।

उक्त नयी इकाईयों की योजना के अतिरिक्त फूलपुर विकासखण्ड में स्थित एलोपैथिक अस्पताल की क्षामता में वृद्धि करने का सुझाव प्रस्तुत है, साथ ही आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। फूलपुर में स्थित यह अस्पताल 200। तक समस्त सामान्य आधुनिक सुविधाओं, म्झीनों एवं उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेदिक, यूनानी तथा हो म्योपैथिक अस्पतालों में भी पर्यांप्त सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। पूलपुर तहसील में अभी तक एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चीकृत नहीं किया जा सका है जहाँ समस्त आधुनिक सुविधार प्राप्त हों।

जनसंख्या की भावी वृद्धि तथा वर्तमान सुविधाओं की अपर्याप्तता को देखते हुए वर्ष 200। तक तहसील में 3 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आव-श्यकता होगी। इनकी अवस्थितियाँ अम्बारी, खरसहन कला तथा सिकरौर में होनी वाहिए।

मात् पिष्णु कल्याण केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के सन्दर्भ में तहसील की वर्तमान स्थिति संतोष्ठानक नहीं कही जा सकती । भावी जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए उ अतिरिक्त मुख्य केन्द्रों तथा उउ उपकेन्द्रों की और आवश्यकता होगी । मुख्य केन्द्रों के लिए इनकी प्रस्तावित स्थितियाँ अम्बारी, खरसहन कला तथा सिकरौर हैं।

आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने के अतिरिक्त तहसील में प्रचलित भारतीय चिकित्सा पद्धितयों के विकास का भी पर्याप्त ध्यान रखना होगा ।
तहसील की अधिकांश जनता की चिकित्सा परम्परागत भारतीय पद्धित से ही हो
रही है । हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी इन चिकित्सा पद्धितयों के समुचित
प्रयोग की बात को दुहराया गया है । 'देश में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैधिक,
योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि विभिन्न पद्धितयों से इलाज करने वाले निजी चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि हुई है । परम्परागत तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धितयों के
बीच नियोजित और चरणबद्ध तरीके से सार्थक सामं जस्य लाने के लिए भी सुविचारित
प्रयास करने होंगे । '18

7. 14 जनसंख्या नियन्त्रण

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि किसी भी क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है जिससे लोगों का जीवन-स्तर गिरता है जो पिछड़ेपन का कारण बनता है। जनसंख्या नियन्त्रण के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित, जागरूक तथा विवेक-शील होना अति आवश्यक है। अतः जनसंख्या नियन्त्रण में शिक्षा को उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी जितनी परिवार नियोजन केन्द्रों को। फूनपुर तहसील की कुल जनसंख्या वर्ष 1951 में 404304 थी जो वर्ष 1981 में बढ़कर 648022 हो गयी जिसमें वर्तमान फूलपुर की 362150 जनसंख्या समाहित थी। इन 30 वर्षों में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.54 प्रतिशत रही। इस दर से वर्ष 2001 तक तहसील की जनसंख्या बढ़कर 492524 हो जाने की अनुमान है। यदि तहसील का बहुमुखी विकास करना है तथा लोगों का जीवन स्तर उमर उठाना है तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लानी होगी। यह कार्य परिवार कल्याण केन्द्रों एवं संचार माध्यमों जैसे ट्याख्यानों एवं प्रदर्शनयों के आयोजन, फिल्म-प्रदर्शन, रेडियो एवं दूरदर्शन के विद्वापनों दारा आसानी से किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में परिवार नियोजन केन्द्रों की कमी है । तहसील में मात्र 4 परिवार नियोजन केन्द्र पवर्ड, पूलपुर, मार्टिनगंज तथा अहरौला(1)विकासखण्ड केन्द्रों पर कार्यरत हैं । अतः जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त परिवार – नियोजन केन्द्रों को खोलने की आवश्यकता होगी । किन्तु परिवार नियोजन केन्द्रों को खोलने मात्र से ही इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता । इन केन्द्रों के

संगलन हेतु कुन्नल, सुयोग्य एवं समर्पित डाक्टरों एवं स्वास्थ्य किम्यों का होना भी जरूरी है। इस कार्यक्रम को सफ्ल बनाने के लिए क्षेत्र की जनता में भी जागरूकता लानी होगी। अध्ययन प्रदेश के अधिकांश शिक्षित परिवार इन कार्यक्रमों की महत्ता को जानते हुए भी सामाजिक-धार्मिक परिवेश एवं प्रतिबद्धता के कारण इन कार्यक्रमों को नहीं अपना पा रहे हैं। अशिक्षित वर्ग तो सामाजिक रूद्धिवादिता से पहले से ही ग्रस्त है और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों से उसका कोई सरोकार नहीं। आपरेशन आदि से भी वह भयभीत रहता है। सीमित परिवार हेतु लोगों को बन्ध्यीकरण के साथ-साथ परिवार नियोजन के अन्य साधनों से भी अवगत कराया जाना ग्राहिए। इसके लिए जनता में जागरूकता लानी होगी और उसके लिए शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम है। अतः शिक्षा का सम्यक् विकास जनसंख्या-नियंत्रण की एक अपरिहार्य शर्त है।

----:0::----

तन्दर्भ

- Thapaliyal, B.K. and Ramanna, D.V., 1977, Planning for Social Facilities, 10th Course on D.R.D.N.K.D. Hyderabad, Sept.-Oct., p. 1 (Unpublished Paper).
- 2. Ibid, p. 1.
- 3. Draft Five Year Plan, 1978 (1978-83) Planning Commission, Government of India, New Delhi, p. 106.
- 4. पूर्वोक्त सन्दर्भ-।, पृष्ठ ।.
- 5. चादना, आर०सी०, 1987, जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पि ब्लिसर्स, नई दिल्ली, पूठठ 179.
- 6. भारतीय जनगणना १९८१, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, प्राथमिक जनगणना सार भाग ऋमा ब जनपद आजमगढ़।
- 7. Report of the Education, 1966, p. 234.
- Pathak, R.K., Environmental Planning Resources and Development, Chugh Publication, Allahabad, 1989, p.153.
- 9. Singh, R.N. and Maurya R.S., Migration of Population in India in Maurya S.D. (Ed.) Population and Housing Problems in India, Vol.1, pp. 176-189.
- 10. Gibbs, J.P. (Ed.) Urban Research Method, 1966, p. 107.
- 11. Ibid, p. 107.
- 12. भारत 1990, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस नई दिल्ली, पूष्ठ 172.

- 13. उत्तर प्रदेश वाधिनी, 1987-88, सूचना एवं जन्सम्पर्न विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पूष्ठ 330.
- 14. वहीं, पूष्ठ 331.
- 15. सन्दर्भ तंख्या 10, पूष्ठ 161.
- 16. गौरीशंकर, 1989, ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याएँ, ग्रामीण विकास संकल्पना उपागम एवं मूल्यांकन प्रमोद सिंह एवं अमिताभ तिवारी, पूठठ 167.
- 17. पूर्वोक्त सन्दर्भ संख्या 10 स्वं।।, पूष्ठ 331-335 स्वं।।।.
- 18. मिश्र, एस०के0, 1992, भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्वास्थ्य रक्षा, योजना, गणतंत्र दिवस 1992, विशेष्ट्यांक:, पूष्ठ 28.

----::0::-----

परि बिष्ट - I

पारिभाषिक शब्दावली

• 0	•
अका र्यशील	जनसङ्घा

: Non-Working Population

अर्थट्यवस्था

: Economy

अधः ८पकन प्रक्रिया

: Trickledown Process

अधिवास

: Settlement

अन्तराल

: Spacing

अन्तः संस्तरित

: Intra-Bedded

अनौपचारिक विधा

: Non-Formal Education

अल्पका लिक

: Short-Term(ed)

अवसीमा जनसंख्या

: Threshold Population

अविकसित

: Undeveloped

आकारकीय

: Morphological

आधारभूत कार्य

: Basic Function

अानुभविक

: Empirial

उत्पतन बिन्दु

: Take Off

उपभोक्ता वस्तुएँ

: Consumer Goods

औद्योगिक क्रान्ति

: Industrial Revolution

औपचारिक विक्षा

: Formal Education

कार्यशील जनसंख्या

: Working Population

कार्यात्मक आकार

: Functional Size

कार्यात्मक अंक

कायांत्मक सूचकांक

काशतकार

कुटीर उद्योग

केन्द्रापतारी

केन्द्राभिसारी

केन्द्रित सकेन्द्रण

केन्द्रीय कार्य

केन्द्रीयता

केन्द्रीयता अंक

केन्द्रीयता सूचकांक

कृषि क्रानित

कृषा योग्य भूमि

कृष्णि साख समितियाँ

कृषा श्रमिक

खादी एवं ग्रामोद्योग

गहनता /गहनी करण

गणितीय धनत्व

ग्रामीण अधिवात

गुणा त्मक

गैर-आवाद

: Functional Score

: Functional Index

: Cultivator

: Cottage Industry

: Centrifugal

: Centripetal

: Centralized Concentration

: Central Function

: Centrality

: Centrality Score

: Centrality Index

: Agricultural Revolution

: Culturable Land

: Agricultural Credit Socitie:

: Agricultural Labourer

: Khadi and Village Industry

: Intensity/Intensification

: Arthematic Density

: Rural Settlement

: Qualitative

Un-Inhabited

गृह उद्योग

: Household Industry

चकबन्दी

: Consolidation

जनसंख्या प्रतिरूप

: Population Pattern

जनसंख्या प्रदेषण

: Population Projection

जनसंख्या नियन्त्रण

: Population Control

जनां किकीय

: Demographic

जोत आकार

: Holding Size

तकनीकी प्रिधा

: Technical Education

तात्का लिक

: Immediate

तिनहन

: Oil Seeds

थोक च्यापार केन्द्र

: Whole Sale Trade Centre

दलहन

: Pulses

दिपसनी क्षेत्र

: Double Cropped Area

दीर्घका लिक

: Long Term(ed)

नगरीय अधियात

: Urban Settlement

नगरीयकरण

: Urbanisation

नगरीय केन्द्र

: Urban Centre

निकटतम पडोसी

: Nearest Neighbour

निविष्टिट

: Inputs

पदानुक्रम

: Hierarchy/Ranking

प रिमाणा त्मक

: Quantitative

परिपेह य

: Perspective

परिप्रेक्षय नियोजन

: Perspective Planning

पश्च जल प्रभाव

: Back Wash Effect

पिछडी अर्थेट्यवस्था

: Backword Economy

पुजी

: Capital

प्रकीर्णन

: Dispersal

पुखण्ड/विभागीय

: Sectoral

प्रतिमान

: Model

पवेशी जनसंख्या

: Entry Population

प्रशास निक संगठन

: Administrative Organisation

प्रस्ता वित

: Proposed

प्रसार प्रभाव

: Spread Effect

प्राथमिक

: Primary

प्रादेशिक

: Regional/Spatial

प्रौढ शिक्षा

: Adult Education

फ्सल-प्रतिरूप

: Cropping Pattern

फ्सल वीमा योजना

: Crop Insurance Scheme

पुटकर बाजार

Retail Trade

बस्ती प्रतिरूप

Settlement Pattern

बस्ती अन्तराल

: Settlement Spacing

बहुवगीय

: Multi Group

बहु-स्तरीय

: Multi Level

बहु-विभागीय

: Multi Sector

वृहद् स्तरीय

: Macro Level

वृहद् उद्योग

: Large-Scale Industry

भण्डारण

: Storage

मध्यम स्तरीय

: Meso-Level

माध्य

: Mean/Average

मान/भार

: Weight

मानक

: Standard

मानदण्ड

: Norm

माँग आधारित

: Need Based

मुख्य कार्यशील जनसंख्या

: Main working Population

यातायात प्रवाह

: Traffic Flow

रणनी ति

: Strategy

रूदिवादी

: Traditional

लघु उद्योग

: Small-Scale Industry

लिंगानुपात

: Sex-Ratio

व्यावतायिक संरचना

: Occupational Structure

वा णिज्यी करण

: Commercilisation

विक सित

: Developed

विकासशील

: Developing

विकास-केन्द्र

: Growth Centre

विकास-ध्रव

: Growth Pole

विकेन्द्रित संकेन्द्रण/केन्द्रीकरण

: Decentralized Concentration

विनियोजन

: Investment

विशिष्ट करण

: Specialization

शस्य-को टि

: Crop-Rank

शस्य-गहनता

: Crop Intensity

शस्य-संयोजन

: Crop Combination/Association

शीर्ध अधोगामी उपागम

: Top Down Approach

मुद्ध बीया गया क्षेत्र

: Net Sown Area

वैक्षाणिक नियोजन

: Educational Planning

स्था निक

: Spatial

स्थानिक कारक

: Spatial Factor

स्वयंपोधी

: Self-Supporting

सघन

: Compact

सडक अभिगम्यताः

: Road Accessibility

सडक सम्बद्धता

: Road Connectivity

(vii)

संसाधन आधारित उद्योग

: Resource Based Industry

ਸੰਮਾਰਧੁਰਾ

: Possibility

समयावधि आधारित

: Temporal

समा कलन

: Integration

समा क लित

: Integrated

सर्वगत

: Ubiquitous

सामा जिक सेवाएँ

: Social Services

सापेक्षा आर्द्रता

: Relatue Humidity

सीमान्त कार्यशील जनसंख्या :

: Marginal Working Population

सीमान्त कृष्णक

: Marginal Cultivator

सूचका क

: Index

सूक्ष म्रन्लघु स्तरीय

: Micro Level

सेवा केन्द्र

: Service Centre

सेवा क्षेत्र/प्रदेश

: Service Area/Region

मे वित जनमंख्या

: Served Population

सैद्धा नितक

: Theoretical

सके-द्रण

: Concentration

संचयी कायों त्पादन

: Cumulative

संचार च्यवस्था

: Communication System

संतप्त जनसंख्या

: Saturation Population

संरचना तमक

: Structural

सां कियकीय विधियां

Statistical Method

हरित क्रान्ति

. Green Revolution

परिभिष्ट - 2

(**क**)

पूलपुर तहसील में 'खरीफ' के अन्तर्गत प्रयुक्त क्षेत्रफल, 1990-91

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		्रहे क्टे	अर में)
न्या	य पंचायत	चावल	मक्का	क्त धा न्य	दलहन	खाद्यान्ती का योग	गन्ना	चा रा	खरीप का योग
Ī		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मित्तूपुर	541	41	582	87	669	131	38	838
2.	रा मनगर	625	72	697	76	773	175	26	974
3.	सत्ता रपर रज्जा कर्पुर	706	54	760	69	829	165	22	1016
4.	दोस्तपुर लहुरमपुर	668	51	719	51	770	113	15	898
5.	तुम्हाडीह	907	23	930	30	960	131	8	1099
6.	बस्ती सदनपुर	1003	24	1027	37	1064	197	21	1242
7.	सुल्ता नपुर	571	59	630	65	695	160	22	877
8.	सौदमा थानेशवर	788	43	831	86	917	165	28	1110
9•	बाग सिकन्दरपुर	1241	46	1287	54	1341	293	2	1636
10.	सादुल्लाहपूर मैगना	935	33	968	35	1003	96	13	1112
11.	अम्बारी	1045	100	1145	71	1216	145	27	1388
12.	फदगुडिया	343	48	39 l	31	422	71	3	496
13.	खं जहा पुर	767	81	848	112	960	157	16	1 133
14.	सजर्इ आजमगद्व	839	63	402	101	1003	150	7	1160
15.	बक्तपुर मेजवान	270	78	348	72	420	78	5	503
16.	नो नियाडीह्			593	81	674	127	12	803
17.	सदरपुर बरौनी	389	66	455	54	509	65	12	586
18.	क्नेरी	745	68	313	33	846	100	10	956
19.	गद्दौपूर बारी	667	137	804	74	878	140	13	1031

 I		2	3	4	5	6	7	8	9
20.	पल्धी दुल्हापुर	475	151	626	64	690	82	6	778
21.	राजापुर	783	87	87 0	70	940	92	7	1039
22.	खारसहन क्ल ा	1118	89	1207	22	1229	70	3	1302
23.	महुआ रा	480	35	515	8	523	25	-	548
24.	पुकवाल	819	28	847	18	865	60	18	943
25.	तिकर ौ र	889	24	913	18	931	153	2	1086
26.	कस्बा फ्तेंहपुर	546	119	665	25	690	109	4	803
27.	कौ रा गहनी	978	49	1027	14	1041	78	5	1124
28.	पुलेश अहमद बका	903	85	988	29	1017	52	7	1076
29.	छितर अहमदपुर	700	45	745	42	787	86	7	880
30.	बेनवाना	1226	45	1271	32	1303	118	10	1431
31.	कुरुधुवा	1015	16	1031	3	1034	54	2	1090
32.	जगदीशपुर ददेशि	9T 1148	110	1258	73	1331	161	29	1521
33.	सुरहन	1391	36	1427	48	1475	110	22	1607
34.	लसरा खुर्द	1167	59	1226	24	1250	193	10	1453
35.	परा मिश्रौ लिया	218	36	254	59	3 13	153	21	487
36.	गनवारा	203	47	250	34	284	79	16	379
37.	मा हुल	1070	128	1 19 4	80	1274	151	22	1147
38.	शम्शा बाद	208	79	287	67	354	163	28	545
		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			·	-	-		
	पूनपुर तहसील	28918	2413	31331	1949	33280	4608	519	38407

स्रोतः लेखपाल खरीप उपज ब्यौरा, पूलपुर तहसील, जनपद आजमगढ, १९९०-१। से संगर्गणत

परिविष्ट-2

(ড়া)

पूनपुर तहसील में 'रबी' के अन्तर्गत प्रयुक्त क्षेत्रपल, 1990-91

	(हे क्टेअर में)										
	<u>-</u> थाय पं रा यत	(F)	त ज ड ,	यना	मटर	दल्हन का योग	खायानों कायोग	हिं स	तिलहन	सब्जी	रबी का योग
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	मित्तूपुर	576	621	54	35	89	710	33	4	29	748
2.	रा मनगर	801	831	49	37	86	917	28	2	31	^974
3.	सन्ता रपुर रज्जा कपुर	910	9 28	53	47	100	1028	38	12	39	1 183
4.	दो स्तपुर लहुरमपुर	765	769	35	33	68	837	27	2	28	896
5.	तुम्हाडीह	711	714	35	46	81	795	42	9	46	838
6.	बस्ती सदनपुर	899	901	29	34	63	964	22	3	22	1002
7.	सुल्ता नपुर	583	588	51	33	84	672	20	5	23	707
8.	सौदमा थानेशवर	844	872	50	33	83	955	30		225	1036
9.	बाग सिकन्दरपुर	954	959	30	38	68	1027	25	3	24	1031
10.	सादुल्लाहपुर मैगना	819	827	26	33	59	886	21	12	22	920
11.	अम्बारी	801	812	46	49	95	907	21	2	29	952
12.	फ्दगुडिया	435	435	14	16	30	465	10	2	10	482
13.	ढ ंजहा पुर	635	635	32	36	68	703	26	26	2	746
	सजई अमानबाद			37	35	72	1103	36	42	9	1200
15.	बक्सपूर मेजवान°	393	*398	30	16	46	444	15	11	3	509
16.	नो नियाडीह	527	537	37	34	71	608	22	21	10	705
17.	सदरपुर बरौली	493	506	21	24	45	551	16	28	7	631
18.	कनेरी	781	790	36	33	69	859	21	25	-	9.18

		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19.	गद्दौपुर बारी	718	721	28	41	69	790	27	28	2	870	
20.	पल्थी दुल्हापुर	625	627	21	24	45	672	22	29	12	721	
21.	राजापुर	842	842	26	36	62	904	31	30	14	999	
22.	खरसहन क्ला	1088	1095	16	27	43	1138	26	28	8	1185	
23.	महुअ 🛚 र ୮	510	512	7	17	24	536	11	8	2	551	
24.	पुकव ा ल	584	603	22	19	41	644	44	47	6	704	
25.	तिकर ौ र	968	999	49	56	105	1104	25	33	7	1111	
26.	कर्बा फतेहपुर	806	815	36	37	73	888	22	26	7	9 17	
27.	कौरा गहनी	1097	1118	65	43	1 08	1226	24	25	8	- 1250	
28•	पुलेश अहमद बक्श	816	828	13	30	43	871	17	19	1	893	
29.	छितर अहमदपूर	865	889	44	49	93	982	25	26	4	1018	
30.	बेलवाना	1647	1732	90	81	171	1903	47	47	9	1618	
31.	कुरुधुवा	925	927	29	25	64	991	20	20	3	1020	
32.	जगदीशपुर ददेरिया	1053	1088	109	92	202	1290	49	49	2	1350	
33.	सू रहन	971	996	60	59	119	1115	30	32	6	1150	
34.	नसरा खुर्द	1112	1132	97	97	194	1326	41	42	5	1337	
35.	पारा मिश्रौ लिया	417	437	36	23	59	496	20	16	3	558	
36.	गनवारा	330	345	36	14	50	395	12	21	-	470	
37.	मा हुल	1036	1045	50	48	98	1143	33	36		1290	
38•	शम्शा बाद	483	509	65	32	97	606	24	24	2	725	
4760 1200 4000 6	पूनपुर तहसील	29645	30414	1565	1473	3037	33451	996	995	460	35444	

टिप्पणी: कुल धान्य में जौ का क्षेत्रपल भी समाहित है। इसका क्षेत्रपल काफी कम होने के कारण आँकोड़े अलग से प्रस्तुत करना उचित नहीं प्रतीत हुआ।

म्रोत: लेखपाल 'रबी' उपज ब्यौरा, पूलपुर तहसील, जनपद आजमगढ़, 1990-9। से संगणित